

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



मार्च 2022

खंड 76 अंक 3

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितिकंठ पट्टनायक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बरन दास
पुलस्त्य बंधोपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक का संप्रेषण शक्तिकांत दास	1
क्रिप्टोकॉरेन्सी - एक आकलन टी रबी शंकर	9

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	19
केंद्रीय बजट 2022-23: कुछ सुखद राजकोषीय अंकगणित	51
भारतीय बैंकों के लिए हरित संक्रमण जोखिम	63
एनबीएफसी के भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य अनुक्रम की व्याख्या	75
क्या भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति है?	87

वर्तमान सांख्यिकी

95

हाल के प्रकाशन

148

भाषण

मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक का संप्रेषण
शक्तिकांत दास

क्रिप्टोकॉरेसी - एक आकलन
टी रबी शंकर

मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक का संप्रेषण*

शक्तिकांत दास

राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन पर 62वें एनडीसी पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ अपने कुछ विचार साझा करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मुझे खुशी हो रही है। एनडीसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन और अभ्यास में उत्कृष्ट केंद्र होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है। भारत के साथ-साथ अन्य देशों के सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के अधिकारियों के समूह को देखकर अच्छा लगा जो इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरे अनुभव में, इस तरह के अंतर-अनुशासनात्मक और अंतर-क्षेत्रीय मेल-मिलाप, विचारों को जानने और विकसित करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं।

केंद्रीय बैंक आधुनिक मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के केंद्र में हैं। अपने व्यापक अधिदेश को पूरा करने के लिए उनके पास कई साधन हैं जिनमें समष्टि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने हेतु प्रमुख उपकरण के रूप में मौद्रिक नीति शामिल है। इस प्रक्रिया में, केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक नीति संचालन के माध्यम से लंबी अवधि के ब्याज दरों, समग्र आर्थिक गतिविधि और अंततः कीमतों को प्रभावित करते हैं। उनका लक्ष्य उत्पादन और रोजगार में उतार-चढ़ाव को कम करते हुए समय के साथ मूल्य स्थिरता (निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति) प्राप्त करना है। समय के साथ, केंद्रीय बैंकों के कार्य और प्राथमिकताएं घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय विकास और प्रचलित राजनीतिक-आर्थिक विमर्श के अनुरूप विकसित हुई हैं। फिर भी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अधिकतम टिकाऊ स्तर को प्राप्त करने की अपनी तलाश में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना हमेशा किसी केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पड़ाव रहा है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में यह उपयुक्त रूप से परिलक्षित

होता है जो रिज़र्व बैंक के व्यापक अधिदेश का वर्णन इस प्रकार करता है:

“भारत में, बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करने और मौद्रिक स्थिरता हासिल करने के साथ-साथ आम तौर पर अपने लाभ के लिए देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करने हेतु आरक्षित निधियों के रखरखाव के लिए एक रिज़र्व बैंक गठित करना समीचीन है”।

आज के अपने भाषण में, मैं उन विचारों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करूंगा जिन्होंने भारतीय मौद्रिक नीति को आकार दिया। मौद्रिक नीति केवल एक विज्ञान नहीं है जहां हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी साधन को बदल देते हैं। यह नए उपकरणों को बनाने और प्रत्याशित और विकसित चुनौतियों के जवाब में नीतिगत कॉल लेने और उन्हें विशेष रूप से संकट के समय में विवेक और स्पष्टता के साथ संप्रेषण करने की एक कला भी है। प्रभावी मौद्रिक नीति के लिए निर्णयता, समय और संप्रेषण महत्वपूर्ण हैं। आज अपने संबोधन में, मैं मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक संप्रेषण के पहलुओं पर ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूँ।

भारत में मौद्रिक नीति का विकास

प्रारंभिक चरण

रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति ढांचे का विकास हमारे देश के आर्थिक और वित्तीय विकास के साथ-साथ हुआ है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने नियोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाई। इसलिए, मौद्रिक नीति मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की विकास आवश्यकताओं के लिए ऋण की उपलब्धता और उस तक पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित थी। इसके बाद, 1960 और 1970 के दशक में घाटे के वित्तपोषण, कृषि क्षेत्र में लगातार आपूर्ति के झटके, 1973 और 1979 के वैश्विक तेल मूल्य झटके और 1973 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ थीं।¹ इन अवधियों के दौरान, मुद्रास्फीति नियंत्रण मोटे

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण - 4 मार्च 2022 - राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में दिया गया।

¹ ब्रेटन वुड्स प्रणाली - 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद - अर्ध-स्थिर विनिमय दरों और नियंत्रित पूंजी प्रवाह की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन, जिसने 1930 के दशक की महामंदी में योगदान दिया, को दोहराने से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों द्वारा अपनाया गया था।

तौर पर सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण और चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण और बैंक द्वारा सट्टा उद्देश्यों के लिए ऋण देने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक के नैतिक दबाव पर आधारित था।

मौद्रिक लक्ष्यीकरण

बढ़ते राजकोषीय प्रभुत्व के बीच उच्च मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में, सुखमोय चक्रवर्ती समिति (1985) की सिफारिशों पर एक नियम-आधारित मौद्रिक लक्ष्यीकरण ढांचा अपनाया गया था। इस ढांचे में, आरक्षित निधि का उपयोग परिचालन लक्ष्य के रूप में किया गया था, जबकि व्यापक निधि, मुद्रास्फीति और विकास उद्देश्यों के अनुरूप मौद्रिक विस्तार को विनियमित करके मुद्रास्फीति नियंत्रण के मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में कार्य करता था।² फिर भी, निरंतर विस्तारित राजकोषीय नीति के कारण, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) दोनों को 1980 के दशक में उत्तरोत्तर बढ़ाना पड़ा और वे 1990 के दशक की शुरुआत तक अपने चरम स्तर पर थे।³ सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से संसाधनों की पूर्व-प्राप्ति ने अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थान कम कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में व्यापार और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और विदेशी पूंजी प्रवाह में परिणामी वृद्धि, वित्तीय नवाचारों और बाजार-आधारित वित्तपोषण की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव के मद्देनजर, मौद्रिक लक्ष्यीकरण ढांचा जो मुद्रा के बीच एक स्थिर संबंध की धारणा पर टिका हुआ था, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में उत्पादन और कीमतें जांच के दायरे में आईं।

² आरक्षित निधि रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई प्राथमिक तरलता को संदर्भित करता है, और यह देश में बैंकों द्वारा बाद में क्रेडिट निर्माण का आधार बनता है। आरक्षित निधि को प्रचलन में स्थित मुद्रा, आरबीआई के पास बैंक की शेष राशि और आरबीआई के पास अन्य जमा राशि (दूसरे शब्दों में, आरबीआई की देनदारियां) के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्था में निधि की आपूर्ति बैंकिंग प्रणाली (वाणिज्यिक के साथ-साथ सहकारी बैंक और आरबीआई) की देनदारी है और इसे जनता के पास मुद्रा, उनकी मांग और बैंकों के पास जमा राशि और आरबीआई के पास अन्य जमा राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

³ जहाँ एसएलआर को, उच्च उधार आवश्यकताओं, सरकार के अनियंत्रित व्यय से उत्पन्न मुद्रास्फीति की चुनौतियों, जिन्हें सीआरआर में वृद्धि के माध्यम से प्रबंधित किया गया था, के वित्तपोषण के लिए अग्रसक्रिय संसाधन जुटाने के लिए बढ़ाया गया था।

बहुसंकेतक दृष्टिकोण

प्रचलित मौद्रिक लक्ष्यीकरण ढांचे की प्रभावकारिता पर प्रश्नों के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1998 में बहुसंकेतक (एमआई) दृष्टिकोण अपनाया।⁴ एमआई दृष्टिकोण में, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए मात्रा चैनलों (मुद्रा आपूर्ति) की तुलना में ब्याज दर पर अधिक जोर दिया गया था। नीतिगत दृष्टिकोणों को तैयार करने हेतु विभिन्न बाजारों (मुद्रा, पूंजी और सरकारी प्रतिभूति बाजारों) में ब्याज दरों के साथ-साथ मुद्रा पर उच्च आवृत्ति डेटा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण, वित्तीय स्थिति, व्यापार, पूंजी प्रवाह, मुद्रास्फीति दर, विनिमय दर और अन्य के साथ आउटपुट डेटा को जोड़ा गया। दूसरे शब्दों में, नीतिगत बल क्रेडिट की मात्रा के बजाय क्रेडिट के मूल्य (यानी, ब्याज दर) पर स्थानांतरित हो गया। तदनुसार, अल्पकालिक ब्याज दरें आरबीआई के मौद्रिक नीति रुख को संकेत देने में महत्वपूर्ण साधन बन गईं। आरबीआई के चलनिधि संचालन को नीतिगत रुख के साथ बाजार दरों को संरेखित करने के लिए तैयार किया गया था। वैश्विक वित्तीय संकट से पहले कम मुद्रास्फीति और उच्च संवृद्धि प्रदान कर एमआई दृष्टिकोण ने अच्छा काम किया।

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में और, विशेष रूप से, 2013 के टेपर टैंट्रम प्रकरण के बाद, एमआई ढांचे की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई क्योंकि लगातार उच्च-मुद्रास्फीति और धीमी संवृद्धि सह-अस्तित्व में आने लगी थी। संकेतकों के एक बड़े समूह पर अपने ध्यान के साथ एमआई दृष्टिकोण ने मौद्रिक नीति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सांकेतिक अवलंब प्रदान नहीं किया। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के संदर्भ में परिभाषित मुद्रास्फीति-सह-

⁴ अधिक बाजारोन्मुखी मौद्रिक नीति ढांचे में बदलाव ने संस्थागत परिवर्तन भी लाए क्योंकि रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति को संभालने वाले विभाग को 1 जनवरी 1998 को तत्कालीन क्रेडिट प्लानिंग सेल से प्रभावी मौद्रिक नीति विभाग के रूप में नामित किया गया था।

सीपीआई, मौद्रिक नीति के लिए सांकेतिक अवलंब होना चाहिए। भारत ने जून 2016 में आरबीआई अधिनियम के संशोधन के साथ औपचारिक रूप से लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) अपनाया। संशोधित अधिनियम मौद्रिक नीति में आरबीआई की भूमिका को निम्नानुसार बताता है: “मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जहाँ संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए”।

संशोधित अधिनियम ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि एक तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मौद्रिक नीति ढांचा होना आवश्यक है और यह कि मौद्रिक नीति ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाएगा। विधान के तहत मूल्य स्थिरता को संख्यात्मक रूप से हेडलाइन सीपीआई के लिए 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ ± 2 प्रतिशत की सहन सीमा के साथ परिभाषित किया गया है। एफआईटी व्यवस्था में लचीलापन, मुद्रास्फीति के लिए आपूर्ति-पक्ष के अस्थायी आघातों को समायोजित करने या उसके पार देखने संबंधी प्रावधानों से आता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य को पूरा करने में विफलता को औसत हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो लगातार तीन तिमाहियों के लिए 2 से 6 प्रतिशत की सीमा से कम या अधिक है, न कि किसी भी उदाहरण के लिए जहां मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक/नीचे आती है। यह मौद्रिक नीति को दर निर्धारण व्यवहार में अनुचित अस्थिरता से बचने में मदद करता है जो संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। रेपो दर को नीति दर के रूप में परिभाषित किया गया था और अनिवार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से रेपो दर निर्धारित करने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों सदस्यों के साथ आरबीआई में एक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की गई थी। एमपीसी संकल्प जिसमें सदस्यों के वोटिंग पैटर्न के साथ एमपीसी बैठक के तुरंत बाद संख्यात्मक अनुमान, रेपो दर निर्णय और उसके औचित्य सहित विकास और मुद्रास्फीति पर समिति के मूल्यांकन और दृष्टिकोण शामिल हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के अपने स्वयं के मूल्यांकन और उनके निर्णय के औचित्य को शामिल करने वाले विवरण बैठक के 14 दिनों के बाद कार्यवृत्त में जारी किए जाते हैं।

स्पष्ट रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य और सीमा, एमपीसी की स्थापना, लक्ष्य को पूरा करने में विफलता को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट जवाबदेही तंत्र, विस्तृत समाधान और कार्यवृत्त में व्यक्तिगत आकलन के त्वरित खुलासे ने भारत में मौद्रिक नीति निर्माण की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत किया है। कुल मिलाकर, जीएफसी के बाद एक समग्र दृष्टिकोण के आसपास एक आम सहमति बन गई है जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के साथ-साथ समष्टि-वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित है। यह तथ्य दिलचस्प है कि भारत सहित सभी देशों में नीतिगत ढांचे में विकास और परिशोधन के बावजूद, अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) के रूप में केंद्रीय बैंकों का कार्य बरकरार है। हालांकि, व्यापक उद्देश्यों के भीतर, मुद्रास्फीति, संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता पर सापेक्ष जोर मौद्रिक नीति व्यवस्थाओं के साथ-साथ व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में भिन्न होता है। यद्यपि वैश्विक अनुभव - एक अतिरिक्त नीतिगत उद्देश्य के रूप में वित्तीय स्थिरता के साथ - अभी भी विकसित हो रहा है, रिजर्व बैंक हमेशा समष्टि-विवेकपूर्ण नीति उपकरण के सक्रिय उपयोग के माध्यम से वित्तीय स्थिरता जोखिमों को उचित महत्व देता रहा है।

2016 में अपनी स्थापना के बाद से एफआईटी ढांचे ने अच्छा कार्य किया है, भले ही इस अवधि में अर्थव्यवस्था को झटके का सामना करना पड़ा हो। पिछले कुछ वर्षों में ढांचे के लचीलेपन और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया था क्योंकि हम इस सदी के संकट- कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। लचीले ढांचे ने एमपीसी को संवृद्धि के समर्थन में उदार मौद्रिक नीति रुख जारी रखने की अनुमति दी, भले ही मुद्रास्फीति ने बड़े आपूर्ति झटके और अन्य बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति सीमा के ऊपरी छोर को रुक-रुक कर छू लिया या उससे अधिक हो गया। इसे सटीक और भविष्यदर्शी संप्रेषण के माध्यम से सुगम बनाया गया था - क्योंकि एफआईटी अनिवार्य रूप से एक दूरदर्शी ढांचा है। नीतिगत उपायों और निर्णयों के औचित्य को स्पष्टतापूर्वक संप्रेषित करने पर जोर दिया गया जो बदलती बाजार प्रत्याशाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

संप्रेषण की भूमिका

वैश्विक संदर्भ

केवल कुछ दशक पहले, केंद्रीय बैंक गोपनीयता में डूबे हुए थे और उनके काम को गूढ़ और आम लोगों की पहुंच से बाहर देखा जाता था। केंद्रीय बैंकों ने इतने खुले या पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया था और शायद यह मानते थे कि नीतिगत प्रभाव बाजार को आश्चर्यचकित करने से आते थे। उनका संप्रेषण अक्सर अस्पष्ट, रहस्यमय और अपारदर्शी होता था, जिसे अक्सर “रचनात्मक अस्पष्टता” का नाम दिया जाता है।⁵ यूएस फेड के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन के प्रसिद्ध उद्धरण को कौन भूल सकता है: “जब से मैं एक केंद्रीय बैंकर बन गया हूं, मैंने बड़ी असंगति के साथ बड़बड़ाना सीखा है। यदि मैं आपको अनावश्यक रूप से स्पष्ट प्रतीत होता हूं, तो आपने मेरी कही हुई बात को गलत समझा होगा”⁶

इसके विपरीत, आज केंद्रीय बैंकों के संप्रेषण उनकी स्पष्टता, सटीकता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। यह परिवर्तन मुख्यतः दो कारणों से हुआ है। पहला, जैसे-जैसे केंद्रीय बैंक अपने संचालन के क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्र होते गए, उन्हें जनता का विश्वास हासिल करने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होने की भी आवश्यकता थी। दूसरा, केंद्रीय बैंकों ने बाजार की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति के एक साधन के रूप में संप्रेषण का तेजी से उपयोग किया है जो कि मौद्रिक नीति संकेतों के कुशल और प्रभावी संचरण के लिए आवश्यक है।⁷ दूरदेशी आर्थिक कारकों - फर्मों और उपभोक्ताओं का व्यवहार - इन चरों में केवल वर्तमान परिवर्तनों के बजाय ब्याज दरों, कीमतों और आय की उनकी भविष्य की प्रत्याशाओं से अधिक प्रभावित होता है। तदनुसार, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में प्रत्याशाओं को प्रबंधित करने के लिए - अप्रत्यक्ष और स्पष्ट दोनों - आगे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस

प्रकार, संप्रेषण आधुनिक केंद्रीय बैंकों के टूलकिट का एक अत्यंत शक्तिशाली घटक है।

हालाँकि, संप्रेषण भी एक दोधारी तलवार है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, प्रमुख केंद्रीय बैंकों की समन्वित प्रतिक्रिया ने संकट के सबसे बुरे प्रभाव को टालने में मदद की। श्री मारियो ड्रैगी की यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में घोषणा ने जुलाई 2012 के यूरोजोन ऋण संकट के बीच यूरो को संरक्षित करने के लिए “जो कुछ भी आवश्यक है” करने के लिए बाजार की भावनाओं को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर, मई 2013 के दौरान अपने भविष्य की मौद्रिक नीति पथ पर यूएस फेड के संप्रेषण ने वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़े हुए उतार-चढ़ाव के टेपर टेंट्रम प्रकरण को ट्रिगर किया क्योंकि घोषणा से बाजार सतर्क हो गए थे। इसलिए, अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए संप्रेषण को संतुलित और अच्छी तरह से टेलीग्राफ करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ, महामारी के माध्यम से लगभग दो वर्षों तक जीने के बाद, अब केंद्रीय बैंक संप्रेषण के लिए जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सहित कई अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति में व्यवधान, सख्त श्रम बाजार, समय पर इन्वेंट्री प्रबंधन की नाजुकता और भू-राजनीतिक गड़बड़ी के कारण बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रही हैं। केंद्रीय बैंक एक बाध्यता में हैं - यदि वे मुद्रास्फीति, जो शायद सामान्य स्थिति बहाल होने पर कम हो सकती है, को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक रूप से कार्य करते हैं तो वे “मंदी की शुरुआत” का जोखिम उठाते हैं; दूसरी ओर, यदि वे बहुत कम और बहुत देर से कार्य करते हैं, तो उन्हें “पिछड़ जाने” के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उन्हें बाद में बहुत कुछ करना पड़ सकता है, जो संवृद्धि के लिए हानिकारक होगा। इस बीच, दुनिया भर के वित्तीय बाजार बेहद अस्थिर हो गए हैं क्योंकि वे भविष्य की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने केंद्रीय बैंकों की चुनौतियों और दुविधाओं को और बढ़ा दिया है। इन अनिश्चितताओं के बीच, केंद्रीय बैंकों को आसन्न संप्रेषण चुनौतियों को देखते हुए इष्टतम आधार खोजना होगा।

⁵ ग्रीनस्पैन, एलन। (2007) द एज ऑफ टर्बुलेंस: एडवेंचर्स इन ए न्यू वर्ल्ड। न्यूयॉर्क: पेंगुइन प्रेस।

⁶ नवंबर-दिसंबर 1987 में अमेरिकी कांग्रेस की एक उपसमिति से बात करते हुए

⁷ देखें, उदाहरण के लिए, बिलंडर और अन्य (2008), “सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी: ए सर्वे ऑफ थ्योरी एंड एविडेंस”, एनबीईआर वर्किंग पेपर 13932

हमारा हालिया दृष्टिकोण

रिज़र्व बैंक में, हम अपनी विविध जिम्मेदारियों और हमारे कार्यों के व्यापक प्रभावों को देखते हुए संप्रेषण के महत्व के प्रति सचेत हैं। हमने नीति निर्माण पर विभिन्न हितधारकों के साथ समय-समय पर बातचीत करके परामर्शी दृष्टिकोण का पालन किया है। इसने विशेष रूप से महामारी के दौरान उपयुक्त नीति प्रतिक्रियाओं के निर्माण में हमारी बहुत मदद की है। हम सूचनासंपन्न नीतिगत निर्णयों के लिए दोतरफा संप्रेषण में विश्वास करते हैं। इस उद्देश्य के साथ, हम विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं, बैंकों, शैक्षणिक निकायों और अनुसंधान संस्थानों, व्यापार और उद्योग संघों, और कई अन्य लोगों के साथ विस्तृत बातचीत करते हैं। हमने न केवल बहुप्रचारित मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के लिए बल्कि अन्य नीतियों के लिए भी इस दृष्टिकोण का पालन किया है। हम यह भी मानते हैं कि विश्वसनीयता बनाने और हमारी नीतियों में व्यापक विश्वास पैदा करने के लिए संप्रेषण को तदनु रूप कार्यों से समर्थित होने की आवश्यकता है। हम जवाबदेही और पारदर्शिता की सर्वोत्तम परंपराओं में अपने कार्यों के औचित्य का विश्लेषण करते हैं, जो मौद्रिक नीति निर्माण के लिए एक आधुनिक बाजार-आधारित दृष्टिकोण की पहचान है।

हमारी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में, हमने विविध साधनों - एमपीसी संकल्प और कार्यवृत्त, मेरे विस्तृत उत्तर-नीति वक्तव्यों के साथ-साथ विकासात्मक और विनियामक उपायों पर वक्तव्य, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे और मेरे सहयोगियों के भाषण, और हमारे अन्य प्रकाशन, विशेष रूप से द्वि-वार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) – के माध्यम से प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए संप्रेषण का सक्रिय रूप से उपयोग किया है। हमारी नीतियां, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर सापेक्ष जोर हमेशा सभी प्रासंगिक कारकों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होती हैं; और हम समझ में स्पष्टता को सुगम बनाने के लिए मीडिया के साथ बातचीत के माध्यम से अपने नीतिगत निर्णयों को संप्रेषित करने का एक बिंदु बनाते हैं। 2019 के दौरान जब हमने दरों में कटौती और रुख को 'सुविचारित' से 'तटस्थ' और फिर 'समायोजन' में बदलने का एक चक्र शुरू किया, तो साथ में संप्रेषण स्पष्ट था। विभिन्न अवसरों पर, हमने कहा था कि संवृद्धि का समर्थन करने के लिए "निर्णायक

और समयबद्ध तरीके से कार्य करना महत्वपूर्ण है"; "कुल मांग को बढ़ावा देने के लिए, और विशेष रूप से, निजी निवेश गतिविधि"; और बाजार मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसी तरह की अन्य घोषणाएं।

मार्च 2020 में एक महामारी के रूप में कोविड-19 की घोषणा के साथ, संप्रेषण अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया क्योंकि हमारे पास मीडिया और बाजार सहभागियों के साथ केवल डिजिटल इंटरफ़ेस था, जबकि साथ ही संकट के सामने आने पर हमें कई आपातकालीन पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय करने पड़े। 27 मार्च 2020 के गवर्नर के वक्तव्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महामारी के प्रकोप ने न केवल एमपीसी बैठक की तारीख को आगे बढ़ाया, बल्कि "नीतिगत रेपो दर में 75 आधार अंकों की एक बड़ी कमी" भी की, जिसका उद्देश्य था " (i) वायरस के नकारात्मक प्रभावों को कम करना; (ii) संवृद्धि को पुनर्जीवित करना; और सबसे बढ़कर, (iii) वित्तीय स्थिरता बनाए रखना"। "यह याद रखना सार्थक है कि कठिन समय कभी खत्म नहीं होता; केवल मजबूत लोग और मजबूत संस्थान ही कार्य करते हैं" - इस वक्तव्य ने महामारी का मुकाबला करने के लिए कई अन्य उपायों को उजागर किया। संदेश स्पष्ट था - हमें दृढ़ रहने, लचीलापन बनाए रखने और स्थिति से निपटने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, करने की आवश्यकता है।

ये निर्णायक और समयबद्ध उपाय, जो बाजार को काफी हद तक स्थिर करते हुए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाते हैं, मुद्रा और बॉण्ड बाजार इंस्ट्रुमेंट्स पर कम मूल्यांतर और कॉरपोरेट बॉण्ड में उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिलक्षित होते हैं। आशावाद को दोहराते हुए, मेरे 17 अप्रैल 2020 के वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि "हालांकि सामाजिक भेद हमें अलग करता है, हम एकजुट और दृढ़ हैं। आखिरकार, हम उपाय करेंगे; और हम सहेंगे"। मई 2020 में, यह महसूस करते हुए कि "महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव शुरू में अनुमान से अधिक गंभीर हो रहा है", एमपीसी ने नीति रेपो दर को 40 आधार अंकों से और कम करने का निर्णय लिया। गवर्नर के वक्तव्य का समापन "आज की परीक्षाएं पीड़ादायक हो सकती हैं, लेकिन साथ में हम जीतेंगे" शब्दों के साथ समाप्त हुआ।

महामारी की चरम सीमा पर रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया शीघ्र और निर्णायक थी। मार्च 2020 से 100 से अधिक उपाय किए गए। इसके अलावा, दो अवसरों पर - मार्च और मई 2020 - एमपीसी की बैठकें निर्धारित समय से पहले आयोजित की गईं; जबकि दो अन्य एकल वक्तव्य गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र के बाहर दिए गए थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के शुरुआती दिनों में और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। चक्रांतर एमपीसी बैठकों और एकल वक्तव्य, अग्रसक्रिय कार्रवाई की दिशा में आरबीआई की तत्परता दर्शाती है। हम शायद दुनिया के एकमात्र केंद्रीय बैंक थे, जिसने बैंकिंग और वित्तीय बाजार संचालन और भुगतान प्रणालियों में व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगे लगभग 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ एक विशेष संगरोध सुविधा स्थापित की थी।

अक्टूबर 2020 में, आपूर्ति-पक्ष के दबावों ने मुद्रास्फीति को 2 से 6 प्रतिशत की सहिष्णुता सीमा से ऊपर ले लिया था और मौद्रिक नीति के रुख को जारी रखने पर बाजार की चिंताएं थीं, यहां तक कि उत्पादन अपने पूर्व-महामारी स्तर से काफी नीचे था। इन परिस्थितियों को देखते हुए और “कम से कम चालू वित्तीय वर्ष और अगले वर्ष के दौरान जब तक जरूरी हो समायोजनकारी मौद्रिक नीति रुख ...” जारी रखने के अपने इरादे को बताते हुए एमपीसी ने समय-आधारित भावी-संकेत के साथ स्थिति-आधारित भावी-संकेत को पूरक करके अपने आगे के मार्गदर्शन को मजबूत किया। आपूर्ति पक्ष के दबाव में कमी के रूप में एमपीसी के आकलन के अनुरूप 2020-21 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में कमी आई। भावि-संकेत के समय-आधारित तत्व ने बाजार की प्रत्याशाओं और मौद्रिक नीति के रुख के संभावित उलटफेर के उस समय निर्मित होने वाली अनुचित प्रत्याशाओं को कम करने में मदद की।

स्पष्ट भावी-संकेत देने वाला संप्रेषण, जिसकी भूमिका और प्रकृति लगातार विकसित हो रही है, अप्रैल 2021 में संक्रमण की दूसरी लहर के समय सामने आई। एमपीसी ने स्थिति और समय-आधारित दोनों भावी-संकेतों से स्थिति-आधारित मार्गदर्शन को वापस ले लिया, यह महसूस करते हुए कि “महामारी के सातत्य

के बाद आर्थिक-बहाली की मजबूती को देखते हुए यह पूरी तरह से भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है।” आरबीआई ने एक द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) की शुरुआत की, जिसने 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम के आकार पर बाजार की चिंताओं और बॉण्ड बाजार में ब्याज दरों पर इसके प्रभाव को दूर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद की एक निश्चित राशि के लिए एक अग्रिम प्रतिबद्धता प्रदान की। इस उपाय ने जो इस स्पष्ट मान्यता के साथ जुड़ा है कि प्रतिफल वक्र एक सार्वजनिक वस्तु है और उसका व्यवस्थित संवर्धन बाजार के सहभागियों और रिज़र्व बैंक दोनों की साझा जिम्मेदारी है, सभी हितधारकों को लाभ की उम्मीदों के अनुरूप लाभान्वित किया और अन्य वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क प्रदान किया।

संप्रेषण की चुनौतियों में महामारी अवधि के नीति पथ को, जब और जैसी स्थिति की मांग हो, फिर से संयोजित करने की भी अपनी भूमिका होती है। पूर्व-निर्दिष्ट समाप्ति तिथियों के साथ घोषित आरबीआई के संकटजन्य उपायों के लिए, बाजार की उम्मीदें स्थिर रहीं और जब संप्रेषण चुनौतियां न्यूनतम थीं तो इन उपायों को स्वतः वापस ले लिया गया। दूसरी ओर, जब और जैसे, निरंतर स्वरूप की नीतियों या उपायों की शुरुआत होती है तो सचेत, सूक्ष्म और सुविचारित संप्रेषण की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे मामलों में, बाजार के कुछ क्षेत्रों की प्रत्याशाएँ इनके अनुरूप नहीं हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक का आकलन - उदाहरण के तौर पर, फरवरी 2021 के गवर्नर के नीति वक्तव्य - ने वीआरआरआर को फिर से शुरू करने के औचित्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाते हुए, मौद्रिक नीति के उलट होने की उन आशंकाओं को साफ किया किया, जो जनवरी 2021 में परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन को फिर से शुरू करने के कारण बन रहे थे। इसी तरह, 14-दिवसीय मुख्य वीआरआरआर नीलामी के आवधिक उन्नयन के माध्यम से अगस्त 2021 में चलनिधि पुनर्संतुलन को चालू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि चलनिधि की स्थिति “वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए समष्टि आर्थिक संवृद्धि के साथ तालमेल बिठाती है”। उसी भावना में, अक्टूबर 2021 में “चलनिधि

के मौजूदा प्रलम्बित प्रभाव, जीएसटी मुआवजे के लिए अतिरिक्त उधार की आवश्यकता न होने और प्रणाली में चलनिधि के अपेक्षित विस्तार ...” को देखते हुए जी-एसएपी परिचालन बंद कर दिया गया था।

जैसा कि मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ, मुझे संक्षेप में बता देना चाहिए कि हम अपनी महामारी के विरुद्ध कार्रवाई में अन्य केंद्रीय बैंकों से कैसे भिन्न हैं। पहला, हमने पारंपरिक नीतिगत विकल्प समाप्त होने से पहले ही यानी, ब्याज दरों की शून्य निचली सीमा तक पहुंचने से पहले ही अपरंपरागत उपाय किए हैं। दूसरा, हमारे परिचालन में शामिल प्रतिपक्ष केवल बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) थे, क्योंकि लक्षित क्षेत्रों को प्रदान की गई चलनिधि उनके माध्यम से प्रसारित की गई थी। तीसरा, हमने अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तक सीमित कर दिया है और कई अन्य केंद्रीय बैंकों के विपरीत, हमारे उधार कार्यों में आरबीआई के संपार्श्विक मानकों को कम नहीं किया गया है। चौथा, हमारे अधिकांश उपायों की घोषणा निरंतर-स्वरूप के होने के बजाय पूर्व-निर्धारित समाप्ति तिथियों के साथ की गई थी। इससे हमारी घोषणाओं की विश्वसनीयता मजबूत हुई है। पांचवां, “सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रतिफल वक्र के संवर्धन” को बताते हुए और इसके लिए सुविधा प्रदान करते हुए, हमने मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने वाले कुछ ईएमई केंद्रीय बैंकों के विपरीत पूरी तरह से द्वितीयक बाजार में परिचालन किया है, जिसने सरकार को सीधे वित्तपोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार में परिचालन हेतु आपातकालीन प्रावधान किए हैं। छठा और अंत में, हमने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की नीतिगत कार्रवाइयों में मौजूदा विचलन के बीच, अपने घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता के आधार पर अपने समायोजनकारी रुख को जारी रखा है। इस प्रकार, हमने मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक अधिदेश से समझौता किए बिना, एफआईटी ढांचे में अंतर्निहित लचीलेपन का उपयोग किया है और अपनी मौद्रिक नीतियों को लागू किया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारे कार्यों का मकसद भाषणों, उत्तर-

नीति- प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया बातचीत के माध्यम से बताया गया था।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मौद्रिक नीति के सिद्धांत और व्यवहार में केवल ‘परिवर्तन’ ही स्थिर रहा है। मौद्रिक नीति के सर्वोत्तम अभ्यास के गठन से संबंधित अभी तक कोई अंतिम शब्द नहीं है। मौद्रिक नीति के परिचालन में भारत और दुनिया भर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं और बाजार विकसित हुए हैं और नीति निर्माताओं ने एक जटिल आर्थिक प्रणाली में आर्थिक एजेंट कैसे संवाद करते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की है।

विश्व स्तर पर, मौद्रिक नीति का विकास नियमों और विवेक के व्यावहारिक मिश्रण के लिए वर्तमान आम सहमति से निपटने से पहले, अधिक निर्देशात्मक और विवेकाधीन होने से सख्त नियम-आधारित अभिशासन में बदल गया है। इस प्रक्रिया में, संप्रेषण को महत्व मिला है, हालांकि यह दोनों तरीकों से काम करता है – जहाँ बहुत अधिक संप्रेषण बाजार को भ्रमित कर सकते हैं वहीं बहुत कम संप्रेषण से बाजार, केंद्रीय बैंक की नीतिगत इरादे के बारे में केवल अनुमान लगा सकता है। इसलिए, केंद्रीय बैंकों को एक बहुत ही महीन रेखा पर चलना होगा। चूंकि मौद्रिक नीति प्रत्याशाओं⁸ को प्रबंधित करने की एक कला है, इसलिए केंद्रीय बैंकों को न केवल घोषणाओं और कार्यों के माध्यम से, बल्कि वांछित सामाजिक परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु अपनी संप्रेषण रणनीतियों के निरंतर परिशोधन के माध्यम से, बाजार की प्रत्याशाओं को आकार देने और स्थिर करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हालाँकि, यह एक पुनरावर्ती प्रक्रिया है और केंद्रीय बैंक केवल क्रमिक रूप से इसमें सुधार कर रहे हैं।

धन्यवाद । स्वस्थ रहें । नमस्कार !

⁸ माइकल डी. वुडफोर्ड(2003), इंटररेस्ट एंड प्राइसेस: फाउंडेसंस ऑफ ए थियरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

क्रिप्टोकॉरेन्सी - एक आकलन*

टी रबी शंकर

श्री गोयल, अध्यक्ष आईबीए, श्री मेहता, मुख्य कार्यपालक आईबीए, प्रोफेसर फाटक, पुरस्कार जूरी के अध्यक्ष, जूरी के सदस्य, एमडी और सीईओ और बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, देवियों और सज्जनों

मैं आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार के विजेताओं को बधाई देकर शुरू करता हूँ। इतने सम्मानित दर्शकों और विद्वान लोगों से भरी सभा के बीच होना और क्रिप्टोकॉरेन्सी से कैसे निपटें जैसे समसामयिक मुद्दे के बारे में बात करने में सक्षम होना, यह वास्तव में ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है। क्रिप्टो तकनीक और वेब 3.0 न केवल प्रौद्योगिकी समुदाय बल्कि वित्तीय उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है। अपने समर्थकों के अनुसार भविष्य में वित्त कैसे आगे बढ़ता है इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्रिप्टोकॉरेन्सी में यह क्षमता है। वास्तव में, इस बारे में खुली अटकलें हैं कि क्या वित्त का जैसा स्वरूप हम जानते हैं और बैंकिंग का जैसा स्वरूप हम जानते हैं वह क्रिप्टोकॉरेन्सी के उदय से बच पाएगा अथवा नहीं। इस वार्ता में मैं आपको क्रिप्टोकॉरेन्सी के बारे में अपने आकलन और हमारी वित्तीय प्रणाली के लिए उनका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा।

परिचय

जैसा कि आप में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे, क्रिप्टोकॉरेन्सी और अन्य क्रिप्टो उत्पादों (जैसे अपूरणीय टोकन या एनएफटी) को ऐसे नवाचारों के रूप में देखा जा रहा है जो विकेंद्रीकृत वित्त या डीएफआई की शुरुआत करेंगे, जो पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को बाधित करने के लिए तैयार ब्लॉकचैन एप्लिकेशन हैं। ब्लॉकचैन का मूल उद्देश्य, या आमतौर पर वितरित खाता बही, जिस तकनीक पर ये क्रिप्टो-उत्पाद चलते हैं, वित्तीय मध्यस्थता बनाने के लिए होते हैं, और इसलिए बैंक बेमानी हो जाते हैं।

आम आदमी के ध्यान से जो बात बच सकती है, वह यह है कि क्रिप्टो सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, वे एक विचारधारा को भी शामिल करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के एक वीडियो में बिटकॉइन की सफलता के बारे में बात की गई है, पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकॉरेन्सी, “स्वस्थ असहमति, अत्यधिक लालच, उच्च आदर्शवाद, और इसे न पाने का डर”¹। उसी एफटी वीडियो में यह भी कहा गया है कि, “क्रिप्टो में केंद्रीकृत प्राधिकरण के अभाव में अराजकतावाद का एक प्रमुख तत्व शामिल है”। क्रिप्टो उत्पादों के वर्ग को मूल रूप से स्थापित वित्तीय प्रणाली और बड़े पैमाने पर सरकार को ही बायपास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ उत्साही लोग तो यह भी दावा करते हैं कि क्रिप्टोकॉरेन्सी पैसे और राज्य को अलग कर सकती है, जैसे चर्च और राज्य को अलग करना। कुछ लोग इसे ‘स्वतंत्रता’ धन के रूप में संदर्भित करते हैं। या, जैसा कि नसीम निकोलस तालेब ने टाइम² पत्रिका में लिखा है, बिटकॉइन एक ऑरवेलियन भविष्य के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी है। इस प्रकार, एक नियामक दृष्टिकोण से, क्रिप्टो को केवल एक अन्य प्रकार की मुद्रा या संपत्ति या वस्तु के रूप में मानना पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे एक संभावित सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया जाना चाहिए।

क्रिप्टोकॉरेन्सी संबंधी मूल बातें

आइए संक्षेप में, और बहुत सामान्य शब्दों में, क्रिप्टोकॉरेन्सी की मूल बातें समझें।

जब कोई लेन-देन कागजी मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता को केवल यह जांचना होता है कि मुद्रा नकली नहीं है। इस प्रकार, यह रिसीवर है जो भुगतान के लिखत को प्रमाणित करता है। यह व्यवस्था आम तौर पर काम करती है, उन कुछ उदाहरणों को छोड़कर जब रिसीवर नकली मुद्रा का पता लगाने में विफल रहता है। डिजिटल लेनदेन के मामले में, भुगतान का प्रमाणीकरण एक बैंक जैसे मध्यस्थ द्वारा किया जाता है, क्योंकि लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण होता है। यह व्यवस्था भी काम करती है क्योंकि बैंक प्रमाणित करता है कि प्रेषक के पास लेनदेन को कवर करने के लिए उसके खाते में पर्याप्त शेष राशि है।

* 14 फरवरी, 2022 को भारतीय बैंक संघ के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कारों में श्री टी रबी शंकर, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

¹ <https://www.ft.com/video/ccb48782-82f9-44ef-97c7-dcfa02431123>

² <https://time.com/5486673/bitcoin-venezuela-authoritarian/>

कुछ लोगों ने महसूस किया कि बैंकों द्वारा मध्यस्थता परिहार्य है। या तो उन्हें लगा कि बैंक भरोसेमंद नहीं हैं, या उन्होंने माना कि बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली लागत अत्यधिक है, या वे अपने लेनदेन को ट्रैक करने में सहज नहीं थे। इस विचार से प्रेरित कि नकदी बोलने की आजादी (फुटनोट 3 देखें) का उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, उनका समाधान अपनी निजी मुद्रा और एक लेनदेन व्यवस्था या नेटवर्क बनाना था जो बैंकों या किसी अन्य वित्तीय या सामाजिक संस्थान को दरकिनार कर देता था। उन्हें जिस मूल समस्या से पार पाना था, वह इस प्रकार थी - चूंकि बैंक जैसी विश्वसनीय संस्था की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक धन (कोड की कुछ पंक्तियाँ) की नकल आसानी से की जा सकती है, नेटवर्क इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगा कि एक ही मुद्रा को बार-बार खर्च नहीं किया गया है। इसे 'दोहरे खर्च की समस्या' कहा गया है।

इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने वाला पहला 'व्यक्ति' था सतोशी नाकामोटो, एक काल्पनिक व्यक्ति या कई व्यक्ति या कॉर्पोरेट या कोई अन्य संस्था, जिसे अभी तक कोई नहीं जानता है। और बिटकॉइन का जन्म हुआ। उन्होंने ब्लॉकचेन बनाकर ऐसा किया। ब्लॉकचेन पर, जब कोई लेन-देन होता है, तो इसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों पर प्रसारित किया जाता है। नए लेनदेन का एक सेट, जिसे ब्लॉक कहा जाता है, एक सहमत सर्वसम्मति प्राप्त तंत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और फिर मान्य लेनदेन ब्लॉक को ब्लॉक की पिछली श्रृंखला में जोड़ा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जिससे दोहरा खर्च करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक बाद के ब्लॉक को बदलना शामिल होगा। बिटकॉइन के बाद कई अन्य भी आए जैसे ईथर, कार्डानो, डॉगकोइन, टीथर, स्टेलर आदि। सामूहिक रूप से उन्हें क्रिप्टोकॉरेंसी कहा जाता है। उपसर्ग 'क्रिप्टो -' इस तथ्य को संदर्भित करता है कि क्रिप्टोग्राफी का उपयोग लेनदेन का सृजन करने या इसे प्रमाणित करने के लिए किया जाता है।

क्रिप्टोकॉरेंसी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: -

ए. क्रिप्टोकॉरेंसी विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ हैं जहाँ लेनदेन को प्रतिभागियों द्वारा स्वयं सर्वसम्मति से प्रमाणित किया जाता है। वे वित्तीय प्रणाली और उसके सभी

नियंत्रणों को बायपास करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सरकारों द्वारा उनका पता नहीं लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त या फ्रीज नहीं किया जा सकता है।

बी. वे गुमनाम हैं - लेन-देन सत्यापित होते हैं, लेकिन लेनदेन के उद्देश्य या प्रतिपक्ष नहीं हैं।

सी. वे सीमाहीन हैं - यानी, वे बिना किसी भौतिक अस्तित्व के इंटरनेट पर काम करते हैं।

जबकि बिटकॉइन एक दशक पहले 2008 में शुरू हुआ था, 5 साल पहले तक, सभी क्रिप्टोकॉरेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण केवल \$ 20 बिलियन (फरवरी 2017) था। फरवरी 2020 में यह बढ़कर 289 बिलियन डॉलर हो गया और उसके बाद नवंबर 2021 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। वर्तमान में (09 फरवरी, 2022) यह 1.98 ट्रिलियन डॉलर है। इस बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 42 फीसदी है, शीर्ष दो क्रिप्टोकॉरेंसी की हिस्सेदारी 61 फीसदी है जबकि शीर्ष पांच में 71 फीसदी की हिस्सेदारी है। क्रिप्टो कॉरेंसी की कुल संख्या 17,436 है और क्रिप्टो एक्सचेंजों की कुल संख्या 458 है।³

क्रिप्टोकॉरेंसी का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन

एक संक्षिप्त, और कुछ हद तक सरल, क्रिप्टोकॉरेंसी के परिचय के साथ, अब हम क्रिप्टोकॉरेंसी की सटीक प्रकृति और उनके निहितार्थों पर गहराई से विचार करेंगे, विशेष रूप से इस विषय पर भारत में वर्तमान बहस के संदर्भ में। प्रारंभिक बिंदु है कि निम्नलिखित पर एक स्पष्ट समझ प्राप्त करना है (ए) क्रिप्टोकॉरेंसी वास्तव में क्या है, (बी) क्रिप्टोकॉरेंसी कौन सी उपयोगी आर्थिक भूमिका निभाती है, और (सी) इससे समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिम क्या हैं, यदि कोई हों तो?

(i) क्रिप्टोकॉरेंसी वास्तव में क्या है?

एक क्रिप्टोकॉरेंसी को मुद्रा के रूप में डिज़ाइन किया गया है, लेकिन क्या यह वास्तव में मुद्रा की तरह कार्य करता है जैसा कि हम इसे समझते हैं। सबसे पहले, मुद्रा में हमेशा एक जारीकर्ता होता है, आमतौर पर संप्रभु की तरह एक विश्वसनीय इकाई। यहां

³ इस जानकारी का स्रोत 09 फरवरी, 2022 को <https://coinmarketcap.com> है।

तक कि जब सोने का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, तब भी सोने के सिक्कों को एक संप्रभु संस्था द्वारा जारी किया जाना होता था। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से, एक मुद्रा हमेशा या तो आंतरिक मूल्य वाली वस्तु रही है या एक ऋण लिखत। क्रिप्टोकॉरेसी मुद्रा की इस समझ के अनुरूप नहीं है क्योंकि उनके पास जारीकर्ता नहीं है, वे ऋण या वस्तुओं का लिखत नहीं हैं और न ही उनका कोई आंतरिक मूल्य है। मुद्रा को विश्वास की आवश्यकता होती है, न कि हर उस चीज़ पर जिस पर भरोसा किया जा सकता है वह मुद्रा है। इसलिए भले ही तकनीक (जैसे कि ब्लॉकचेन में) क्रिप्टोकॉरेसी के लिए विश्वास प्रदान करती है, वे उस क्रिप्टोकॉरेसी के निजी और बंद वातावरण में मुद्रा की भूमिका सबसे अच्छे से निभा सकते हैं। ये बड़े समाज के लिए स्वचालित रूप से मुद्रा नहीं बनते और न ही बनने चाहिए।

कुछ देश क्रिप्टोकॉरेसी को वित्तीय संपत्ति के रूप में मानते हैं। यह भी एक समस्या है क्योंकि सभी वित्तीय संपत्तियों में अंतर्निहित नकदी प्रवाह होता है और किसी व्यक्ति की देयता होने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टोकॉरेसी न तो किसी व्यक्ति की देनदारी है और न ही उनके पास कोई अंतर्निहित नकदी प्रवाह है। परिभाषा के अनुसार, वे वित्तीय संपत्ति नहीं हैं।

क्रिप्टोकॉरेसी को कमोडिटी के रूप में मानने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वस्तुएं मूर्त हैं और उनकी उपयोगिता है; क्रिप्टोकॉरेसी में दोनों ही नहीं हैं। उनमें से कुछ की तुलना सोने से करने का कुछ अजीब प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधनों की तरह उनकी आपूर्ति को सीमित कर रहा है, या खनन के माध्यम से उनका सृजन किया जा रहा है। डिजाइन द्वारा आपूर्ति सीमित करना प्रकृति में सीमित आपूर्ति (जैसे सोना) के समान नहीं है क्योंकि (ए) डिजाइन को हमेशा संशोधित किया जा सकता है और इसलिए ऐसी सीमा कृत्रिम है, और (बी) भले ही एक क्रिप्टोकॉरेसी में सीमित आपूर्ति हो, वह सीमा सभी क्रिप्टोकॉरेसी के लिए काम नहीं करती है। इसके अलावा यह तथ्य कि सोने का खनन किया जाता है इसलिए वह अपने आप पैसा बना जाता है, इसे पैसा बनाने के लिए एक संप्रभु संस्था द्वारा मुहर लगाई जाती है और इसे जारी किया जाता है।

यदि क्रिप्टोकॉरेसी शब्द के सामान्य अर्थों में न तो एक मुद्रा है, न ही एक वित्तीय संपत्ति और न ही एक भौतिक संपत्ति है, तो

वे क्या हैं? समर्थकों ने उन्हें डिजिटल संपत्ति के रूप में संबोधित करने की बात कही है। यहां तक कि यह भी संदिग्ध है क्योंकि क्रिप्टोकॉरेसी का कोई अंतर्निहित उपयोग नहीं है, जैसे कार हायरिंग सॉफ्टवेयर या कोर बैंकिंग सिस्टम या स्मार्टफोन के लिए। यह मूल रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है (बिना किसी व्यावहारिक उपयोग के) जिसने इतना प्रचार किया है कि लोग उस इलेक्ट्रॉनिक कोड के स्वामित्व अधिकार खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई और इसे अधिक कीमत पर खरीद लेगा। विनिमय के माध्यम के रूप में जो शुरू हुआ वह सट्टा संपत्ति के समान प्रतीत होता है।

मूल्य के भंडार के रूप में, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकॉरेसी ने अब तक प्रभावशाली रिटर्न दिया है, लेकिन 17 वीं शताब्दी के नीदरलैंड में ट्यूलिप ने भी ऐसा ही किया। क्रिप्टोकॉरेसी बहुत हद तक एक सट्टा या जुआ अनुबंध की तरह है जो पोंजी योजना की तरह काम करता है। वास्तव में, यह तर्क दिया गया है कि 1920 में चार्ल्स पोंजी द्वारा तैयार की गई मूल योजना सामाजिक दृष्टिकोण से क्रिप्टोकॉरेसी से बेहतर है ⁴। यहां तक कि पोंजी योजनाएं भी आय अर्जित करने वाली संपत्तियों में निवेश करती हैं। एक बिटकॉइन एक ज़ीरो-कूपन परपेचुअल के समान है; यह ऐसा है जैसे आपने एक बांड खरीदने के लिए पैसे का भुगतान किया है जो कोई ब्याज नहीं देता है और जो कभी भी मूलधन का भुगतान नहीं करेगा। समान नकदी प्रवाह वाले बॉन्ड का मूल्य शून्य होगा, जिसे वास्तव में, एक क्रिप्टोकॉरेसी के मौलिक मूल्य के रूप में तर्क दिया जा सकता है। यदि सब कुछ अंततः अपने संतुलन मूल्य पर वापस आ जाता है, तो क्रिप्टोकॉरेसी में निवेशकों के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं है।

(ii) क्रिप्टोकॉरेसी क्या उपयोगी सामाजिक या आर्थिक भूमिका निभाती है?

यदि क्रिप्टोकॉरेसी का उद्देश्य वास्तव में वित्त में क्रांति लाना है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वे वित्त में क्या सटीक भूमिका निभाते हैं। एक इक्विटी शेयर एक व्यवसाय को जोखिम पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है, एक बांड कंपनी / सरकार को पैसे

⁴ <https://www.ft.com/content/83a14261-598d-4601-87fc-5dde528b33d0>

उधार लेने में सक्षम बनाता है, एक म्यूचुअल फंड खुदरा निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है, डेरिवेटिव उपयोगकर्ताओं को अपने जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है इत्यादि। प्रत्येक वित्तीय लिखत एक बुनियादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौजूद है जो निवेश परिसंपत्ति के रूप में इसके उपयोग से काफी अलग है। क्रिप्टोकॉरेंसी द्वारा निभाई गई मूल भूमिका क्या है? चूंकि यह मुद्रा होने का दावा करती है, क्या यह मुद्रा के कार्य करती है? इसका उत्तर यह है कि कई क्रिप्टोकॉरेंसी की अस्थिरता उन्हें विनिमय के एक कुशल माध्यम के रूप में रोकती है। इसके अलावा, स्पष्ट रूप से यह मानने का कोई आधार नहीं है कि लोग उन पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना वे कानूनी निविदा मुद्राओं में करते हैं। जबकि बिटकॉइन का उपयोग करने वाले व्यवसायों का वास्तविक प्रमाण है, वास्तव में कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है; सभी संकेतों से मुद्रा के रूप में उनका उपयोग नगण्य प्रतीत होता है।

क्या क्रिप्टोकॉरेंसी मूल्य के भंडार के रूप में उपयोगी हैं? कुछ क्रिप्टोकॉरेंसी के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए, यह तर्क दिया गया है कि वे हैं। करीब से देखने पर इस तर्क का खुलासा हो जाता है। मूल्य के किसी भी भंडार के बारे में सोचें - वे या तो मुद्राएं हैं, या वित्तीय संपत्ति या वस्तुएं हैं जो मूर्त हैं और जिनका आंतरिक मूल्य है (जैसे कला के कार्यों में चित्रों का ऐतिहासिक, सुंदर होने और दुर्लभ होने के कारण मूल्य होता है)। हमने देखा है कि क्रिप्टोकॉरेंसी इनमें से कोई भी नहीं है। अपने वर्तमान मूल्यांकन के बावजूद, यदि बहुत सारे लोगों ऑप्ट-आउट करने का निर्णय लेते हैं, तो संपूर्ण मूल्य आसानी से गिर जाएगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा।

एक क्रांतिकारी नवाचार के बारे में की जा रही सभी बातों के संबंध में, क्रिप्टोकॉरेंसी स्वयं वित्त क्षेत्र में किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैं जो वर्तमान में पूरी नहीं हो रही है या मौजूदा जरूरतों को अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। नवाचार, यदि बिल्कुल, वितरित खाता बही का है, जो समर्थकों के दावों के विपरीत फल-फूल सकता है, भले ही दुनिया भर में क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो।

(iii) किसी समाज या अर्थव्यवस्था के लिए क्या जोखिम हैं, यदि कोई हैं?

क्रिप्टोकॉरेंसी के मूलभूत जोखिम दो हैं - उनका इरादा निजी मुद्रा होना है और उन्हें केवाईसी, एएमएल/सीएफटी आदि जैसे वित्तीय अखंडता मानकों के संबंध में सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए संरचित किया गया है। आइए हम इन दो बिंदुओं में से प्रत्येक की थोड़ी और गहन जांच करें।

अर्थव्यवस्था पर निजी मुद्राओं या मुद्रा जैसे उत्पादों का प्रभाव

ऐतिहासिक रूप से, निजी मुद्राओं के परिणामस्वरूप अस्थिरता पैदा हुई है और इसलिए सदियों से फीएट मुद्राओं में विकसित हुई है। निजी मुद्राओं में प्रतिगामी कदम केवल इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी समाज के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने के कारण होने वाली अव्यवस्था के लिए बिना किसी विचार के इसे (इसने हमेशा यह किया है, वास्तव में) अनुमति देती है। प्रत्येक निजी मुद्रा अंततः कुछ हद तक रुपये की जगह ले लेगी। नतीजतन, मुद्रा के रूप में रुपये की भूमिका कम हो जाएगी। एक या एक से अधिक निजी मुद्राओं की अनुमति के साथ, देश में समानांतर मुद्रा प्रणाली होगी। इस प्रकार, क्रिप्टोकॉरेंसी की बढ़ती स्वीकृति के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था का प्रभावी 'डॉलरीकरण' होगा⁵। डॉलरीकरण, यह अच्छी तरह से समझी गई बात है कि, मुद्रा आपूर्ति या ब्याज दरों को नियंत्रित करने की अधिकारियों की क्षमता को कमजोर कर देगा, क्योंकि मौद्रिक नीति का रुपये से भिन्न मुद्राओं या भुगतान लिखतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ऐसा होगा उस समय भारत न केवल अपनी मुद्रा, अपनी संप्रभुता की एक परिभाषित विशेषता, बल्कि अर्थव्यवस्था पर अपना नीति नियंत्रण भी खो देगा। मौद्रिक नीति के लिए कर्षण के नुकसान के साथ, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्षमता भौतिक रूप से कमजोर हो जाएगी।

⁵ यह वास्तविक डॉलरीकरण हो सकता है यदि अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और यह मानने का एक अच्छा कारण है कि अनुमति मिलने पर वे लोकप्रिय होंगे।

एक विकल्प को देखते हुए, लोग अपनी जमा राशि का कम से कम एक हिस्सा यूएस डॉलर या यूरो जैसी परिवर्तनीय मुद्राओं में रखना पसंद कर सकते हैं। इन परिवर्तनीय मुद्राओं में कीमत वाली क्रिप्टोकॉरेसी ऐसा अवसर प्रदान करेगी। यदि निजी मुद्राओं को अनुमति दी जाती है, तो रुपये में जमा राशि जुटाने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता, और इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। परिवर्तनीय मुद्राओं में ऋण सृजन मौद्रिक नीति के लिए अभेद्य होगा। चरम मामले में जहां जमा और क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकॉरेसी में स्थानांतरित हो जाता है, इसका परिणाम होगा एक कमजोर या गिरती हुई बैंकिंग प्रणाली जो वित्तीय स्थिरता को खराब करेगी।

पहले से ही संकेत हैं कि क्रिप्टोकॉरेसी में निजी सीमा-पार प्रवाह हो रहा है। यदि इस प्रवृत्ति को वैध किया जाता है, तो इन क्रिप्टोकॉरेसी में व्यापार भुगतान, व्यक्तिगत प्रेषण या सीमा पार निवेश से संबंधित प्रवाह का एक हिस्सा बनाया जाएगा। चूंकि वे गैर-आरक्षित मुद्राएं हैं, इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो बाहरी क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इस तरह के क्रिप्टोकॉरेसी भुगतान पूंजी खाता नियमों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। यह पूंजी खाता व्यवस्था की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि पूंजी प्रवाह पर नीति नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और विनिमय दर प्रबंधन पर इसका परिणाम गंभीर व्यापक आर्थिक स्थिरता के मुद्दों को उठाता है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि निजी मुद्राओं के साथ चिंता केवल बिटकॉइन या केवल क्रिप्टोक्यूरेक्स तक ही सीमित नहीं है। चिंता किसी भी निजी मुद्रा तक फैली हुई है, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक, चाहे क्रिप्टो-आधारित हो या नहीं। स्टेबलकॉइन्स (जो केवल क्रिप्टोकॉरेसी हैं और जो कम अस्थिर हैं) को विश्व स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, संभवतः क्योंकि वे बिटकॉइन की तुलना में अधिक स्थिर हैं। हमें वास्तव में स्टेबलकॉइन्स के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए क्योंकि वे अस्थिर क्रिप्टोकॉरेसी की तुलना में मुद्रा के रूप में अधिक प्रभावी होंगे। जैसा कि ऊपर उद्धृत एफटी वीडियो में कहा गया है, “यदि परिसंपत्तियां और देयताएँ बेमेल थीं, तो जोखिम को कम करने के बजाय आधिकारिक मुद्राओं से जुड़े स्टेबलकॉइन्स बढ़ेंगे।”

वैश्विक वित्तीय अखंडता मानकों पर प्रभाव

क्रिप्टोकॉरेसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे स्थापित मध्यस्थता और नियंत्रण व्यवस्था⁶ को बायपास करते हैं जो वित्तीय लेनदेन की अखंडता सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि अपने ग्राहक को जानें, धन-शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण की मुकाबला करना (सीएफटी) संबंधी विनियमावली आदि। तथ्य यह है कि वे गुमनाम, विकेन्द्रीकृत सिस्टम हैं जो विशुद्ध रूप से संचालित होते हैं, क्रिप्टोकॉरेसी को विशेष रूप से अवैध / गैरकानूनी लेनदेन के लिए आकर्षक बनाते हैं जिन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बड़े पैमाने पर फ़िल्टर किया गया है। 2021 में क्रिप्टोकॉरेसी का उपयोग करने वाले कुल अपराध \$14 बिलियन (वॉल स्ट्रीट जर्नल, 06 जनवरी, 2022) होने का अनुमान लगाया गया था। यह राशि अपने आप में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन पिछले दो दशकों में श्रमसाध्य रूप से निर्मित एएमएल/सीएफटी ढांचे के निहितार्थ काफी महत्वपूर्ण हैं।

क्रिप्टोकॉरेसी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अनुमति देने के अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम हैं। हमने पहले ही नोट कर लिया है कि क्रिप्टोकॉरेसी के मूल्यांकन का कोई आधार नहीं है। चूंकि मूल्यांकन काफी हद तक विश्वासों पर आधारित होता है, न कि अंतर्निहित मूल्य पर, यह निवेशकों को बड़े पैमाने पर धन हानि (यदि इसे व्यापक रूप से अपनाया जाता है) के माध्यम से किसी देश की मौद्रिक स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव पड़ता है, भले ही इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति न हो।

क्रिप्टो अवसंरचना का सामाजिक रूप से बेकार ऊर्जा उपयोग व्यापक चर्चा का विषय रहा है। प्रतिदिन लगभग 900 नए बिटकॉइन के लिए \$45 मिलियन प्रति दिन की बिजली की आवश्यकता होती है (फुटनोट 5 देखें)। कुछ अनुमानों के अनुसार, 2019 में बिटकॉइन का बिजली उपयोग पूरे स्विट्जरलैंड देश⁷ के बराबर है।

अब तक हमने जो देखा है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि भारत में क्रिप्टोकॉरेसी को वैध बनाने की अनुमति दी जाए।

⁶ एकमात्र औचित्य “ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देना ... बिना किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से जाना” प्रतीत होता है जैसा कि बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोटो द्वारा अपने पेपर में उल्लेख किया गया है। (<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>)

⁷ <https://www.bbc.com/news/technology-48853230>

फिर भी, क्रिप्टोकॉरेंसी को अनुमति देने और उन्हें सख्त नियमों के अधीन करने के लिए विभिन्न तर्क दिए गए हैं। अगले भाग में हम इन तर्कों की वैधता की जांच करेंगे।

क्या भारत में क्रिप्टोकॉरेंसी को अनुमति दी जानी चाहिए और इसका विनियमन होना चाहिए

क्रिप्टोकॉरेंसी को विनियमित करने के लिए दिए जा रहे बुनियादी तर्क इस प्रकार हैं:

डी. ब्लॉकचैन या डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक आशाजनक तकनीक है जहां भारतीयों की वैश्विक बढ़त हो सकती है। क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से भारत में डीएलटी तकनीक का अवशोषण प्रभावित होगा।

ई. अधिकांश प्रमुख देश क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के विनियमन पर विचार कर रहे हैं।

एफ. कई भारतीय पहले से ही क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश कर चुके हैं और इस पर प्रतिबंध लगाने से उनके लिए धन की हानि हो सकती है।

जी. किसी भी मामले में प्रतिबंध प्रभावी होने की संभावना नहीं है क्योंकि इसकी प्रकृति से क्रिप्टोकॉरेंसी को अज्ञात तरीके से हासिल किया जा सकता है और व्यापार किया जा सकता है।

क्रिप्टोकॉरेंसी आमतौर पर एक ब्लॉकचैन पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, बिटकॉइन ब्लॉकचैन का मूल कॉइन (या टोकन) है, या, ईथर एथेरियम ब्लॉकचैन की मूल मुद्रा है। उन्हें लेन-देन के निपटान के लिए खाते की इकाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या उन्हें ब्लॉकचैन में किए गए काम को पुरस्कृत करने के लिए टोकन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खनन के लिए। ब्लॉकचैन के मूल कार्य के लिए इन दोनों में से कोई भी कार्य आवश्यक नहीं लगता है। यदि लेनदेन को केंद्रीय रूप से प्रमाणित किया जाता है, तो बिना किसी मूल क्रिप्टोकॉरेंसी के ब्लॉकचैन को बनाए रखना संभव होना चाहिए। सर्वसम्मति तंत्र के माध्यम से निजी प्रमाणीकरण के मामले में भी, खातों को रखा जा सकता है और किसी भी कानूनी निविदा मुद्रा में पुरस्कार दिए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, देशी क्रिप्टोकॉरेंसी बनाना ब्लॉकचैन को लागू करने का सिर्फ एक तरीका है; इसे

ब्लॉकचैन तकनीक के केवल एक उपयोग के मामले के रूप में देखा जा सकता है। यह तर्क देने के लिए कि क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से ब्लॉकचैन तकनीक का अवशोषण रुक जाएगा, इसलिए यह कहना है कि मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाने से जैव प्रौद्योगिकी में नवाचारों को मार दिया जाएगा या परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने से एक अनुशासन के रूप में परमाणु भौतिकी को नुकसान होगा। ब्लॉकचैन तकनीक के कई अन्य उपयोग हैं या अधिक सामान्य रूप से, वितरित लेजर तकनीक, जिसमें एक आभासी मुद्रा का निर्माण शामिल नहीं है। इस प्रकार, दावा है कि ब्लॉकचैन तकनीक को पनपने के लिए क्रिप्टोकॉरेंसी की अनुमति दी जानी चाहिए, यह संधारणीय नहीं है।

क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई) इस तरह के प्रतिबंधों का सहारा नहीं ले रही हैं। एई में अपनाई जाने वाली प्रथाओं की नकल करते हुए अक्सर सुधारों के लिए एक स्वीकार्य मार्ग होता है, जहां तक क्रिप्टोकॉरेंसी का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत को एई के समान नहीं रखा गया है। हमें इस संभावना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि इन निजी मुद्राओं का उपयोग वैश्विक रणनीतिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। यदि, उदाहरण के लिए, कुछ निजी मुद्रा रुपये को काफी हद तक बदल देती है, तो उस क्रिप्टोकॉरेंसी का प्रबंधन करने वाला कॉर्पोरेट (या उस कॉर्पोरेट पर नियंत्रण करने वाला देश) भारत की आर्थिक नीति को व्यावहारिक रूप से नियंत्रित कर सकता है। ऐसे कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से एई के हित में हो सकता है कि उन पर प्रतिबंध न लगाया जाए, जैसा कि नीचे दिया गया है।

ए. लगभग सभी क्रिप्टोकॉरेंसी की कीमत डॉलर (या संभावित रूप से मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में से कोई भी) के संदर्भ में है। व्यापक रूप से अपनाने से वास्तव में इन मुद्राओं का व्यापक उपयोग होगा। इसलिए क्रिप्टोकॉरेंसी परिवर्तनीय मुद्राओं के लिए खतरा नहीं है क्योंकि वे रुपये के लिए खतरा हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं है। क्रिप्टोकॉरेंसी के मामले में एई के उदाहरण का अनुसरण करना प्रभावी रूप से राष्ट्रीय मुद्रा के हित के खिलाफ काम करने के बराबर होगा।

- बी. अधिकांश क्रिप्टोकॉरेंसी का स्वामित्व आई के व्यवसायों के पास है; इसलिए, क्रिप्टोकॉरेंसी को बेहतर ढंग से अपनाने से उनकी वृद्धि और रोजगार में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण रूप से, यह आई के लिए फायदेमंद हो सकता है यदि क्रिप्टोकॉरेंसी उभरती बाजार (ईएम) मुद्राओं की जगह लेती है क्योंकि इससे आई को ईएमई पर बेहतर रणनीतिक नियंत्रण मिलेगा।
- सी. आई के पास अधिक परिपक्व बाजार हैं जो क्रिप्टोकॉरेंसी से संभावित व्यवधान का सामना कर सकते हैं। इसलिए, वे प्रतीक्षा करने और देखने की बेहतर स्थिति में हैं।
- डी. आई के पास तेज कानूनी प्रणालियां हैं और इसलिए क्रिप्टो के दुरुपयोग की चिंताओं को कानूनी प्रणालियों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। दूसरी ओर, भारत में, उपभोक्ता शोषण के किसी भी बड़े मामले का कानूनी रूप से निवारण नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, 2000 के दशक के मध्य में डेरिवेटिव की गलत बिक्री)।
- इ. आई के पास क्रिप्टो कंपनियों को नियंत्रित करने की राजनीतिक शक्ति है। हालिया उदाहरण जहां अमेरिका ने अमेरिका में तेल पाइपलाइन के हैकर्स से बिटकॉइन बरामद किए हैं, यह एक उदाहरण है कि क्रिप्टोकॉरेंसी की पता न लगा पाने की क्षमता के दावों के बावजूद, आई सरकारें रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग करती हैं। भारत या अधिकांश अन्य देशों में ऐसे लाभों की कमी होगी।

एक और तर्क अक्सर सामने आता है कि इतने सारे भारतीयों ने पहले से ही क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश किया है और क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से उनके लिए धन का नुकसान होगा। ऐसे तीन कारण हैं जो इस तरह के तर्क से उचित नहीं लगते हैं। एक, भारत में प्रतिबंध लगाने का मतलब यह नहीं है कि निवेशकों को पैसा गंवाना होगा, क्योंकि उन्हें उचित निकास प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों ने इन लिखतों में निवेश किया है, वे इसमें शामिल जोखिमों से पूरी तरह अवगत हैं। रिजर्व बैंक करीब एक दशक से निवेशकों को जोखिमों के प्रति आगाह कर रहा है।

सरकार की एक अंतर-मंत्रालयीन समिति ने सिफारिश की है कि क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पिछले तीन वर्षों से व्यापक रूप से की गई थी, क्योंकि यह तथ्य था कि क्रिप्टोकॉरेंसी विनियमित उत्पाद नहीं हैं और कोई निवेशक सुरक्षा मानदंड नहीं हैं। जिन निवेशकों ने इन लिखतों का अधिग्रहण किया है, उन्होंने अपने जोखिम पर अपनी आंखें खोलकर ऐसा किया है और किसी भी नियामक व्यवस्था की गारंटी नहीं देते हैं। तीसरा, इन लिखतों में कितने निवेशकों ने निवेश किया है और निवेश की राशि क्या है, इसका औचित्य साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है। नवंबर में अनौपचारिक रूप से एकत्र किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीयों द्वारा क्रिप्टो निवेश कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है (हालांकि विकास की गति इसे भविष्य में चिंता का विषय बना सकती है)। इस डेटा ने ⁸ दिखाया कि पांच में से चार निवेशक ने खातों में ⁹ ₹10,000 से कम का निवेश किया, जिसमें औसत होल्डिंग आकार ₹1,566 था। धन हानि, यदि संभव हो तो, इन निवेशकों के केवल एक छोटे से अंश को प्रभावित करने की संभावना है।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्रित स्वामित्व, क्रिप्टोकॉरेंसी की विशेषता प्रतीत होता है। द टेलीग्राफ ¹⁰ में प्रकाशित जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार: “उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, सभी बिटकॉइन का लगभग 13 प्रतिशत सिर्फ 100 से अधिक व्यक्तिगत खातों के हाथों में है।” उन्हें “क्रिप्टो व्हेल” कहा जाता है। इस तरह के केंद्रित स्वामित्व, आमतौर पर सृजनकर्ताओं या प्रारंभिक निवेशकों द्वारा, जिसे वैकल्पिक मौद्रिक प्रणाली (या कम से कम होने की उम्मीद) कहा जाता है, उस प्रणाली को हेरफेर के लिए प्रवण बना देगा।

उस क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिबंध के प्रभावी होने की संभावना नहीं है, यह एक सतही तर्क है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि प्रतिबंध के

⁸ रिजर्व बैंक इस डेटा की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसे अनौपचारिक रूप से एकत्र किया गया था और इसे मान्य नहीं किया गया है। इन निष्कर्षों को केवल सांकेतिक के रूप में लिया जा सकता है, यदि बेहतर डेटा उपलब्ध कराया जाता है तो सुधार किया जा सकता है।

⁹ एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं। इसलिए निवेशकों की संख्या खातों की संख्या से कम होने की संभावना है।

¹⁰ <https://www.telegraph.co.uk/technology/2021/01/22/weird-world-bitcoin-whales-2500-people-control-40pc-market/>

बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी एक व्यापक घटना है, और इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी को वैध और विनियमित किया जाना चाहिए। यदि क्रिप्टोकॉरेन्सी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कानून का पालन करने वाले अधिकांश निवेशक निवेश से दूर हो जाएंगे। वे कुछ तत्व जो निवेश करना जारी रखेंगे, अनिवार्य रूप से एक अवैध गतिविधि को अंजाम देंगे। इस तरह के अपवादों को इसे अमान्य करने के बजाय प्रतिबंध की आवश्यकता को सुदृढ़ करना चाहिए।

कुछ लोगों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निजी मुद्राओं को 'मध्यम विनिमय' के रूप में अनुमति देने में उठाई गई चिंताएं वैध हैं। इसलिए, उन्हें कानूनी निविदा के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन उन्हें निवेश संपत्ति के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क किसी वास्तविक विश्वास से अधिक आशा के साथ दिया गया है। उन्हें मुद्रा के रूप में अनुमति नहीं देना अभी भी मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जा रही क्रिप्टोकॉरेन्सी की राशि होगी। लेन-देन की मांग की तुलना में 'मूल्य का भंडार' मांग मुद्रा की मांग का एक अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे समझने के लिए केवल सावधि जमा की मात्रा की तुलना लेन-देन जमा से करने की आवश्यकता है। यदि क्रिप्टोकॉरेन्सी का उपयोग मूल्य के भंडार के रूप में किया जाता है, तो वही चिंताएं फिर से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, रुपये के मूल्य के विपरीत, जो मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में इसकी स्थिति से जुड़ा हुआ है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का मूल्य पूरी तरह से इस उम्मीद पर टिकी हुई है कि अन्य लोग भी इसका मूल्यांकन करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। चूंकि मूल्यांकन काफी हद तक उन विश्वासों पर आधारित होता है जो अच्छी तरह से तय नहीं होते हैं, यह किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव डालने के लिए बाध्य है, भले ही इसे कानूनी निविदा के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं है।

अन्य कारण हैं कि क्रिप्टोकॉरेन्सी को विनियमित करना व्यर्थ क्यों होगा। जैसा कि चर्चा की गई है, क्रिप्टोकॉरेन्सी मुद्राएं, या वित्तीय संपत्ति या वास्तविक संपत्ति या यहां तक कि डिजिटल संपत्ति नहीं हैं। इसलिए, इसे किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। किसी ऐसी चीज को विनियमित करना संभव नहीं है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता।

क्रिप्टोकॉरेन्सी आमतौर पर वैश्विक उत्पाद हैं जिनकी परिभाषित विशेषता यह है कि वे आधिकारिक नियंत्रण से बाहर हैं

और उन्हें देश-विशिष्ट नियामकों द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) का वित्तीय स्थिरता संस्थान क्रिप्टो को विनियमित करने में कठिनाइयों की पहचान करता है - जैसे कि क्रिप्टो लेनदेन की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, एफएटीएफ के 'ट्रैवल रूल' को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधानों की अनुपस्थिति, 'अनहोस्टेड वॉलेट' की समस्या, तथ्य कि पी2पी लेनदेन में एएमएल-सीएफटी नियमों आदि के अधीन कोई भी इकाई शामिल नहीं है। मान लीजिए कि भारत क्रिप्टोकॉरेन्सी को विनियमित करने का निर्णय लेता है। यह गलत बिक्री के मामले को कैसे नियंत्रित करेगा और उसका निवारण कैसे करेगा क्योंकि इसकी न तो बहीखाता तक पहुंच है और न ही किसी ऑडिट ट्रेल तक। चूंकि क्रिप्टोकॉरेन्सी (जैसे, बिटकॉइन) के लिए प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानना हमेशा संभव नहीं होता है, नियामक कार्रवाई किस पर निर्देशित की जाएगी? यदि किसी भी कारण से पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाती है तो निवेशकों के लिए क्या संभावित नियामक निवारण मौजूद है? ये बहुत ही असुविधाजनक निहितार्थ वाले प्रश्न हैं जिनका संतोषजनक समाधान नहीं है।

निष्कर्ष

हमने देखा है कि क्रिप्टो-प्रौद्योगिकी सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए एक दर्शन पर आधारित है। क्रिप्टोकॉरेन्सी को विशेष रूप से विनियमित वित्तीय प्रणाली को बायपास करने के लिए विकसित किया गया है। सावधानी के साथ उनका इलाज करने के लिए ये पर्याप्त कारण होने चाहिए। हमने यह भी देखा है कि क्रिप्टोकॉरेन्सी को मुद्रा, परिसंपत्ति या कमोडिटी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है; उनके पास कोई अंतर्निहित नकदी प्रवाह नहीं है, उनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है; कि वे पोंजी योजनाओं के समान हैं, और इससे भी बदतर हो सकते हैं। औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उन्हें दूर रखने के लिए ये पर्याप्त कारण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वे वित्तीय अखंडता, विशेष रूप से केवाईसी शासन और एएमएल/सीएफटी नियमों को कमजोर करते हैं और कम से कम संभावित रूप से असामाजिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, वे मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक प्राधिकरण, बैंकिंग प्रणाली, और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता को

बर्बाद कर सकते हैं (और यदि सबसे अधिक संभावना होगी)। वे किसी देश की वित्तीय संप्रभुता को खतरे में डालते हैं और इन मुद्राओं या सरकारों को नियंत्रित करने वाली निजी कंपनियों द्वारा रणनीतिक हेरफेर के लिए इसे अतिसंवेदनशील बनाते हैं। इन सभी कारकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिप्टोकॉरेसी पर प्रतिबंध लगाना शायद भारत के लिए सबसे उचित विकल्प है। हमने उन तर्कों की जांच की है जो वकालत करते हैं कि क्रिप्टोक्यूरेंक्स को विनियमित किया जाना चाहिए और पाया कि उनमें से कोई भी बुनियादी जांच के लिए खड़ा नहीं है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ¹¹ में लिखते हुए एंड्रियन चेन ने 2013 तक उल्लेख किया था कि बिटकॉइन सट्टा लालच के एक अजीब

मिश्रण पर बनाया गया है जो एक यूटोपियन साइबरलिबर्टेरियन विचारधारा द्वारा समर्थित है और इसकी तुलना एक डिजिटल गोल्ड रश से की गई है। वास्तव में, हाइपरबोल क्रिप्टो दुनिया के सभी पहलुओं विशेषता है। क्रिप्टो मैसेजिंग तर्कसंगत या विवेकपूर्ण आधार पर निर्देशित होती प्रतीत नहीं होती है। 'फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव' ¹² जैसे विषयों के साथ वैश्विक विज्ञापन हमारे अपने 'लग जा रे... कुछ तो बदलेगा' में कुछ हद तक परिलक्षित होते हैं। यदि क्रिप्टोकॉरेसी के बारे में समझ प्रचार से ऊपर उठती है और तर्क और व्यावहारिकता में निहित होती है तो यह हमें बेहतर सेवा उपलब्ध कराएगी।

¹¹ मच एंडो अबाउट बिटकॉइन, ऑप-एड, न्यूयॉर्क टाइम्स, 26 नवंबर, 2013)।

¹² जोडी रोसेन (न्यूयॉर्क टाइम्स, 02 फरवरी, 2022)।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

केंद्रीय बजट 2022-23: कुछ सुखद राजकोषीय अंकगणित

भारतीय बैंकों के लिए हरित संक्रमण जोखिम

एनबीएफसी के भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों में
उचित मूल्य अनुक्रम की व्याख्या

क्या भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति है?

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

जारी भू-राजनीतिक संकट ने वैश्विक व्यापार-आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के बारे में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, यहां तक कि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे-वैसे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें कई-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गयी हैं, और वित्तीय बाजार बड़े पैमाने पर बिकवाली से प्रेरित हैं। इस कष्टकर समय में, भारतीय अर्थव्यवस्था प्लवन का अनुभव कर रही है क्योंकि यह महामारी की तीसरी लहर से उबर रही है। मांग की स्थिति में सुधार के साथ-साथ उपभोक्ता और कारोबारी विश्वास बढ़ रहा है। आपूर्ति पक्ष पर नजर डालें तो, सुदृढ़ कृषि क्षेत्र और औद्योगिक एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में निरंतर वापसी बहाली को विस्तार दे रही है।

भूमिका

वैश्विक आर्थिक संभावनाएं बहुत अधिक अनिश्चितता से भरी हुई हैं और भू-राजनीतिक संघर्ष से अधोगामी जोखिमों से घिरी हुई हैं तथा दुनिया भर में इसका असर हो रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब देश अभी भी महामारी से जूझ रहे हैं। भू-राजनीतिक जोखिम में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक वित्तीय बाजारों में तेज अस्थिरता अपरिपक्व वैश्विक वसूली को बाधित कर सकती है। यह झटका ऐसे समय में भी लगा है, जब कई देशों में महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के सामान्य होने के साथ, वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ और सख्त हो सकती हैं। अभिग्रहण छोर पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) हैं, जो पहले से ही मुद्रा मूल्यहास, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली और धीमी वृद्धि से जूझ रही हैं।

* यह लेख योगेश एचसी, शशिधर एम. लोकरे, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, हर्षिता केशन, सत्यार्थ सिंह, कृष्ण मोहन कुशवाहा, रमेश बलिराम गोलाईत, प्रशांत कुमार, जोबिन सेबेस्टियन, सक्षम सूद, सत्यम कुमार, जितेंद्र सोकल, जिविन जोस, अवनीश कुमार, आशीष संतोष खोबरागड़े, रमेश कुमार गुप्ता, रोहन बंसल, देब प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

पिछले महीने में कुछ नरमी के बाद जब तीसरी लहर अपने चरम पर थी तब फरवरी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रही। 15 मार्च 2022 तक, हालांकि, तीसरी लहर तेजी से कम हो गई, जिसमें दैनिक संक्रमणों का 7-दिन का औसत 3,500 से नीचे गिर गया। टीकाकरण के मोर्चे पर, 96.0 प्रतिशत वयस्क आबादी को पहली खुराक के साथ टीका लगाया गया है, जबकि 82.3 प्रतिशत को दोनों खुराकें दी गई हैं। अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने से उपभोक्ता विश्वास के पुनर्निर्माण में मदद मिली है, जैसा कि अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) उपभोक्ता रुख सूचकांक में परिलक्षित होता है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों घटकों में महामारी की पहली लहर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

खुदरा और मनोरंजन गतिविधि, किराना और औषधालयों, पार्कों, कार्यस्थलों और ट्रांजिट स्टेशन के आसपास गतिशीलता महामारी के पहले के स्तरों से ऊपर है। फरवरी 2022 में नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर पर चढ़ने के साथ, बीमा और खुदरा क्षेत्रों में बहाली में तेज वृद्धि के साथ, जॉब मार्केट में तेजी बनी रही। लंबी अवधि की सुस्ती के बाद ऑटो उद्योग में रोजगार में पुनर्बहाली हुई है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आतिथ्य और वित्तीय सेवाओं में भर्ती मजबूत रही। फरवरी 2022 में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह लगातार दूसरे महीने ₹1.3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। ई-वे बिल जारी करने की रफ्तार तेज रही।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों ने खाद्यान्न उत्पादन को रिकॉर्ड 316.1 मिलियन टन रखा। मुख्य विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) फरवरी में लगातार 8वें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा और नए ऑर्डर और उत्पादन में तेजी से एक महीने पहले इसमें मामूली सुधार हुआ। कारोबारी विश्वास में सुधार के साथ, मुख्य सेवाएं पीएमआई लगातार सातवें महीने विस्तार के क्षेत्र में रही। फरवरी का माल निर्यात लगातार बारहवें महीने में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया और 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य आश्चर्यजनक दूरी के भीतर प्रतीत होता है। डिजिटल स्पेस के माध्यम से भुगतान तेजी से बढ़ा। रिजर्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को दो प्रमुख पहलें शुरू की: (i) UPI123Pay, जो फीचर फोन

उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प प्रदान करेगा; और (ii) डिजी साथी जो कि डिजिटल भुगतान उत्पादों में उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को हल करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन है।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे घटनाक्रम को दर्शाता है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में भारत में वित्तीय स्थितियों की समीक्षा की गयी है, जबकि अंतिम खंड में आलेख का निष्कर्ष दिया गया है।

II. वैश्विक हालात

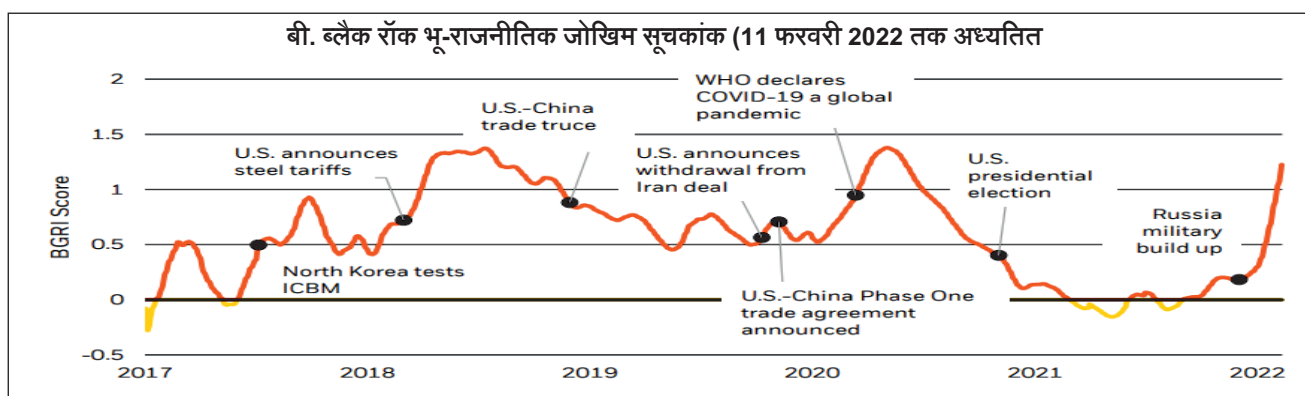
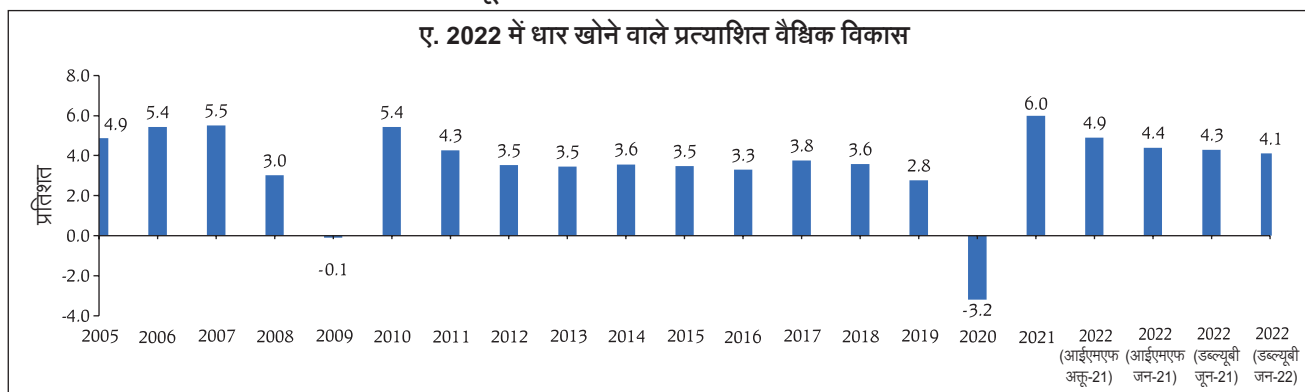
यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था विकट प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही है। तेल की कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं, वित्तीय बाजार बढ़त पर हैं, जो सुरक्षित निवेश आस्तियों, विशेष रूप से सोने में बड़े पैमाने पर

खरीदारी से प्रेरित हैं। ऐसी उथल-पुथल के बीच, तीव्र मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता जोखिमों के साथ वैश्विक संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण खराब होता जा रहा है।

चल रहे संघर्ष के शीघ्र समाधान के अभाव में, वैश्विक सुधार पर इस संकट का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे 2022 और उससे आगे के लिए वैश्विक संवृद्धि के अधोमुखी संशोधन की आवश्यकता हो सकती है (चार्ट 1)।

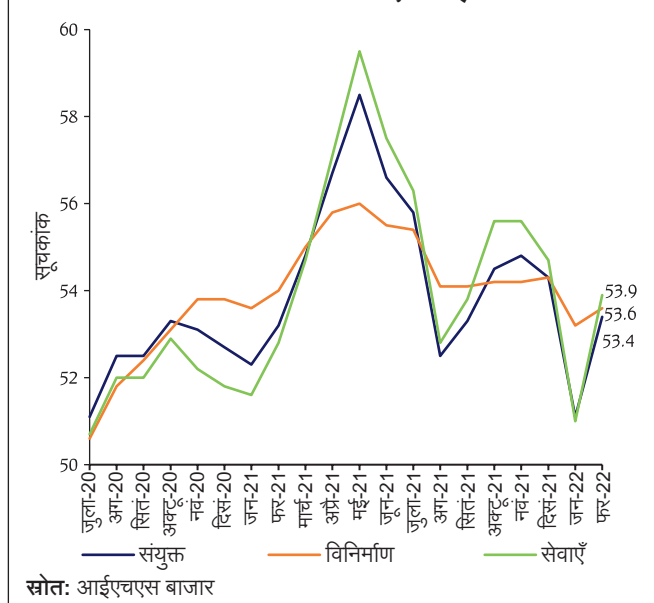
फरवरी के लिए वैश्विक समग्र पीएमआई 53.4 पर रहा जो कि जनवरी के डेढ़ साल के निचले स्तर 51.1 से ऊपर आया था, क्योंकि नए ऑर्डर और रोजगार में तेजी आई, और कारोबार संबंधी आशापूर्ण दृष्टि लगभग रिकॉर्ड उच्च स्तर तक जा पहुंचा (चार्ट 2)। विनिर्माण और सेवाओं दोनों ने गति पकड़ी, जिसमें सेवा क्षेत्र ने पिछले 11 महीनों में दसवीं बार विनिर्माण क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। जापान को छोड़कर अधिकांश देशों ने आर्थिक गतिविधियों

चार्ट 1 भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक विकास



स्रोत : आईएमएफ, विश्व बैंक; ऑक्सफोर्ड अर्थव्यवस्था और ब्लैक रॉक निवेश संस्थान

चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई

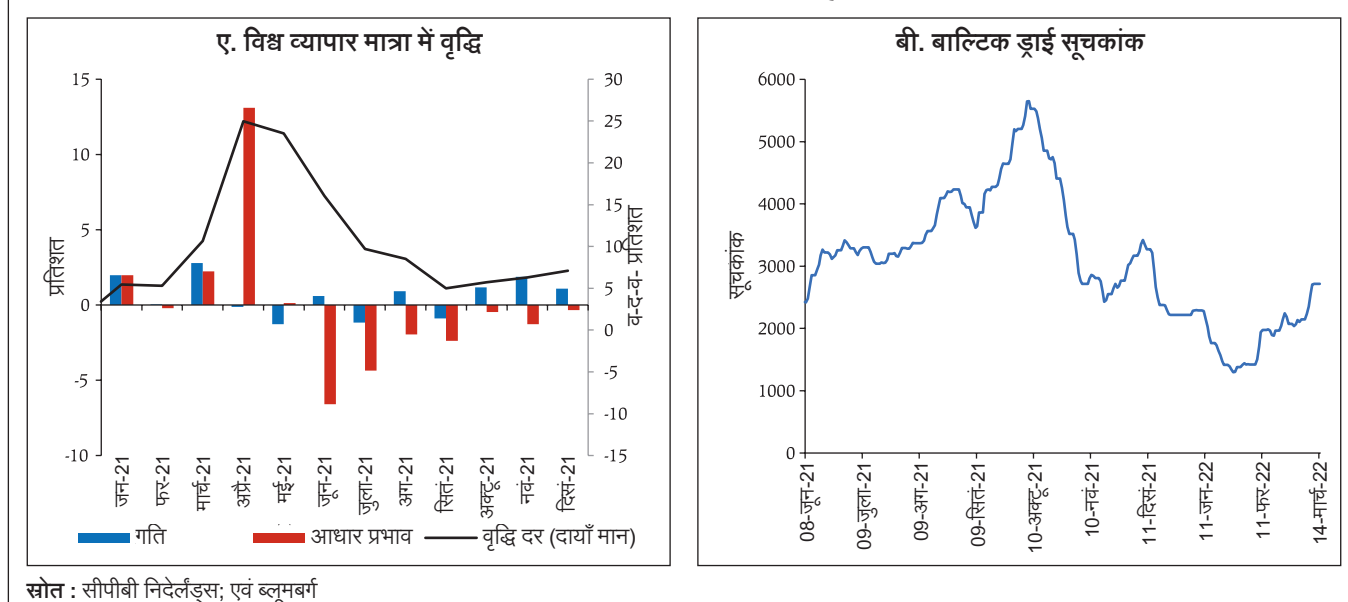


में विस्तार का संकेत दिया, जिसने पिछले अगस्त के बाद से अपनी सबसे तेज दर पर उत्पादन संविदा देखा। 5 मार्च को, चीन ने वर्ष 2022 के लिए लगभग 5.5 प्रतिशत के अपने वृद्धि लक्ष्य की घोषणा की - जो 30 वर्षों में सबसे कम है - क्योंकि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव संपत्ति संकट और कमजोर खपत के दबाव को बढ़ाते हैं।

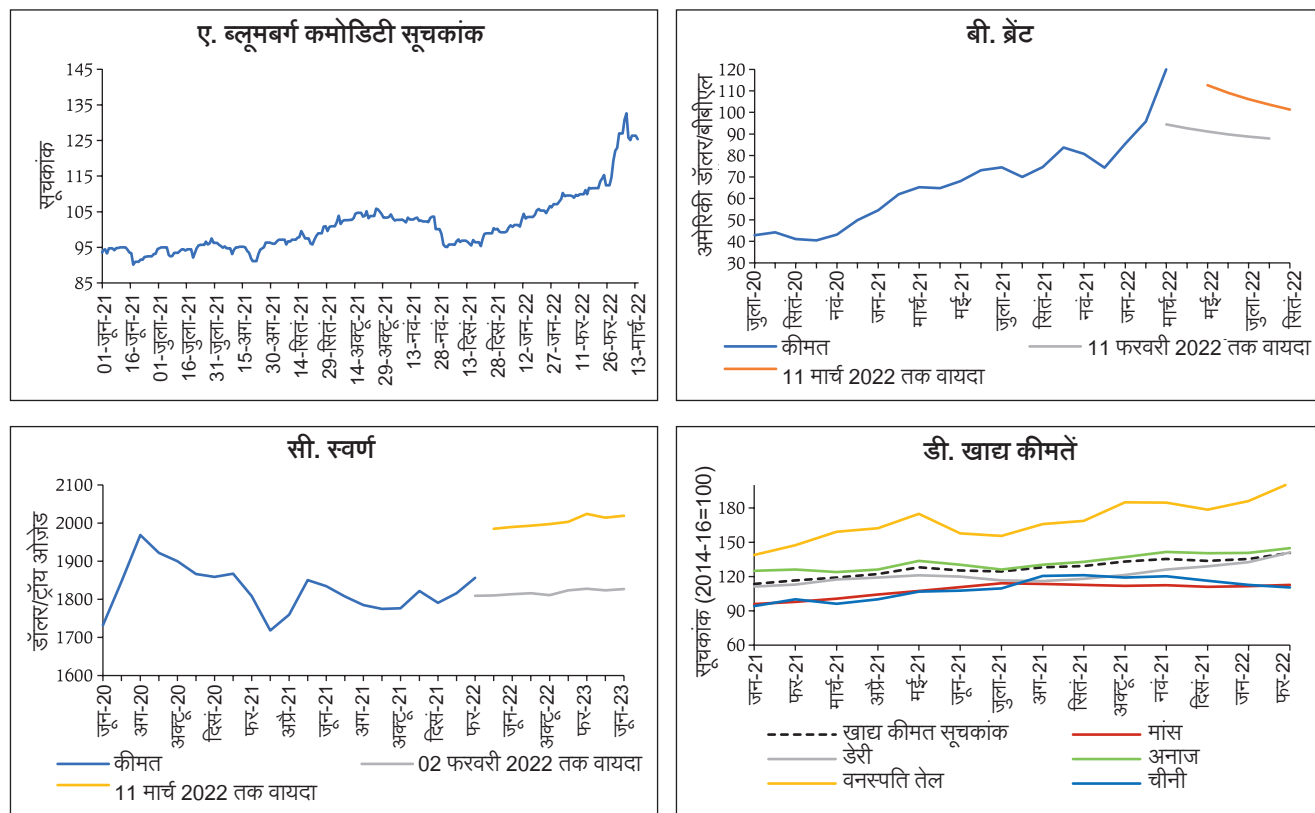
बाहरी मोर्चे पर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के वैश्विक व्यापार अपडेट 2022 से पता चलता है कि वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के दौरान वैश्विक व्यापार वृद्धि में तेजी आई, जबकि तात्कालिक अनुमान से पता चलता है कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही के दौरान व्यापार वृद्धि धीमी हो जाएगी। सीपीबी वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर के मासिक डेटा से इसकी पुष्टि होती है (चार्ट 3ए)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक माप है, ने फरवरी 2022 में बढ़त को दर्शाया और भू-राजनीतिक दबावों के कारण काला सागर में विशेष रूप से रूसी और यूक्रेनी बंदरगाहों में नए व्यवधानों के कारण यह बढ़ना जारी है (चार्ट 3 बी)।

ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में उछाल जारी रहा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में 120 अंक को तोड़कर सात साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 4ए)। आपूर्ति की कमी बढ़ने से कच्चे तेल, निकल, एल्युमीनियम और गेहूं की कीमतों में तेजी आई। जुलाई 2021 की मासिक आपूर्ति बढ़ाने की योजना पर टिके रहने से ओपेक प्लस ने पूरी तरह से आपूर्ति के नुकसान और ओपेक प्लस के युद्ध के जोखिम के जोखिम के साथ, कच्चे तेल की कीमतें दस साल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जो मार्च की शुरुआत में यूएस डॉलर 118 प्रति बैरल को छू लिया (चार्ट 4 बी)।

चार्ट 3: विश्व व्यापार और नौपरिवहन खर्च



चार्ट 4: कमोडिटी और खाद्य कीमतें



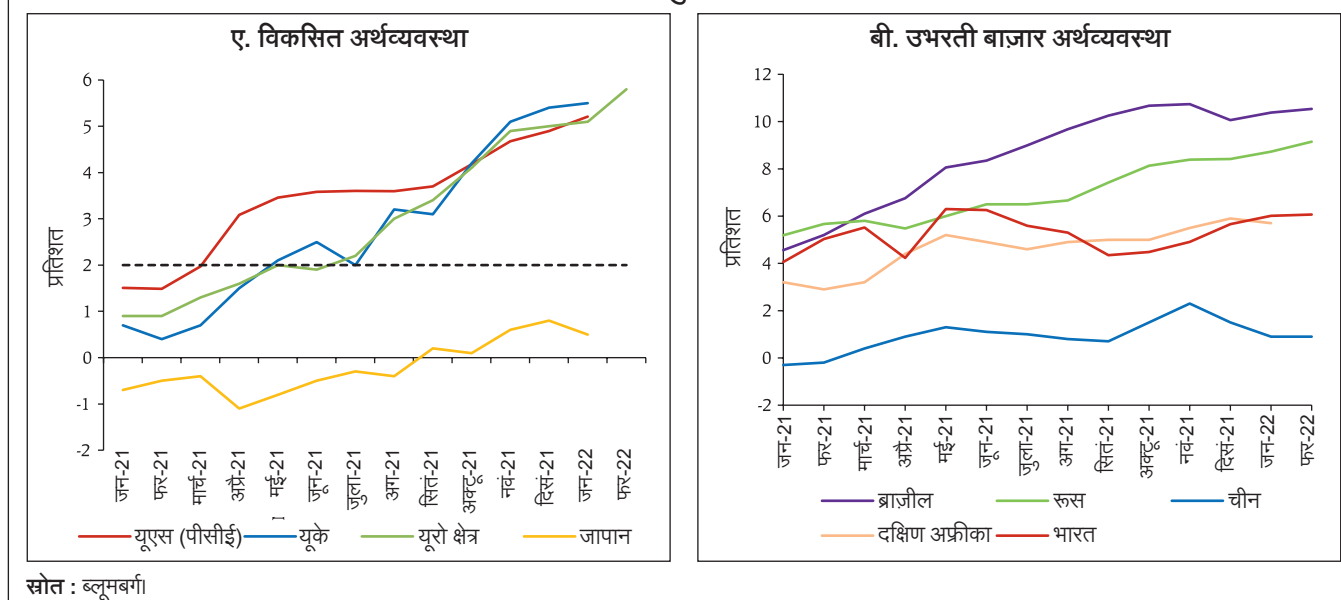
स्रोत : ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिक शीट; और एफएओ।

फरवरी से सुरक्षित निवेश की मांग सोने की कीमतों को बढ़ा रही है (चार्ट 4सी)। फरवरी 2022 में 140.7 पर एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक जनवरी की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक था और अब तक के उच्चतम स्तर पर था, जो बड़े पैमाने पर वनस्पति तेलों और डेयरी उप-सूचकांक द्वारा संचालित था (चार्ट 4डी)।

तप आपूर्ति श्रृंखला, उच्च ऊर्जा, खाद्य और पण्य वस्तुओं की कीमतों और घटते वेतन दबावों की पृष्ठभूमि में लागत दबाव के तेज होने के साथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी रही (चार्ट 5)। फरवरी 2022 में यूएस सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 40 साल के उच्च स्तर 7.9 प्रतिशत हो गई। मूल सीपीआई मुद्रास्फीति भी फरवरी में 6.4 प्रतिशत के करीब 40 साल के उच्च स्तर पर थी, जिसमें मुख्य योगदान आश्रय, और इस्तेमाल की गई कारों और ट्रकों का था। मजदूरी का दबाव, जैसा कि 1983 के बाद से 2021 के लिए 4.5 प्रतिशत की सबसे तेज वार्षिक वेतन वृद्धि में परिलक्षित होता है, किराये की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य

सूचकांक मुद्रास्फीति में जनवरी 2022 में सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 40 साल में सर्वाधिक है। साथ ही, मूल पीसीई मुद्रास्फीति एक साल पहले की तुलना में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 1983 के बाद सबसे अधिक है। फरवरी 2022 में 5.8 प्रतिशत के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि, विशेष रूप से तब प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति बढ़ी। जापान की मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आवास लागत में कमी और कम मोबाइल शुल्क के कारण जनवरी में कम हुई, जो 2 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रही। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील की मुद्रास्फीति बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई, जबकि चीन की मुद्रास्फीति 0.9 प्रतिशत पर स्थिर रही। दूसरी ओर, फरवरी 2022 में रूस की वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 9.15 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी 2016 के बाद सबसे अधिक है, जो अब केंद्रीय बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से दोगुने से अधिक है। पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और कच्चे माल की कमी के बीच मुद्रास्फीति जोखिम ऊपर की ओर झुका हुआ है।

चार्ट 5: मुद्रास्फीति



फरवरी के उत्तरार्ध से दुनिया भर के निवेशकों को चिंतित करने वाले भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में अनियंत्रित गिरावट हो रही है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में, एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स मार्च 2021 के स्तर तक गिर गया, जो उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) स्टॉक इंडेक्स दोनों में गिरावट की वजह से हुआ था, हालांकि बाद में अधिक तेजी से गिर गया। यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स ने फरवरी में एई के बीच सबसे खराब प्रदर्शन किया, जो रूस की ऊर्जा आपूर्ति पर क्षेत्र की भारी निर्भरता को दर्शाता है जबकि रूसी स्टॉक इंडेक्स ने ईएमई में सबसे खराब प्रदर्शन किया। रूस के शेयर बाजारों में 28 फरवरी से कारोबार ठप है (चार्ट 6ए)।

बॉन्ड बाजारों में, यूएस 10-वर्षीय खजाना प्रतिफल ने बाद के महीने में अपने अपट्रेंड को उलट दिया क्योंकि खजाना प्रतिभूतियों की मांग सुरक्षा की वजह से बढ़ी और आक्रामक दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें मार्च की शुरुआत में कांग्रेस के समक्ष फेड अध्यक्ष के बयान के बाद कम हुईं (चार्ट 6बी)। सुरक्षित निवेश की मांग के बीच फरवरी की दूसरी छमाही से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जबकि कुछ कमोडिटी निर्यातकों को छोड़कर, ईएमई मुद्राएं विपरीत दिशा में चली गईं। विशेष रूप से, रूसी रूबल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे कमजोर मूल्य पर गिर गया, जो

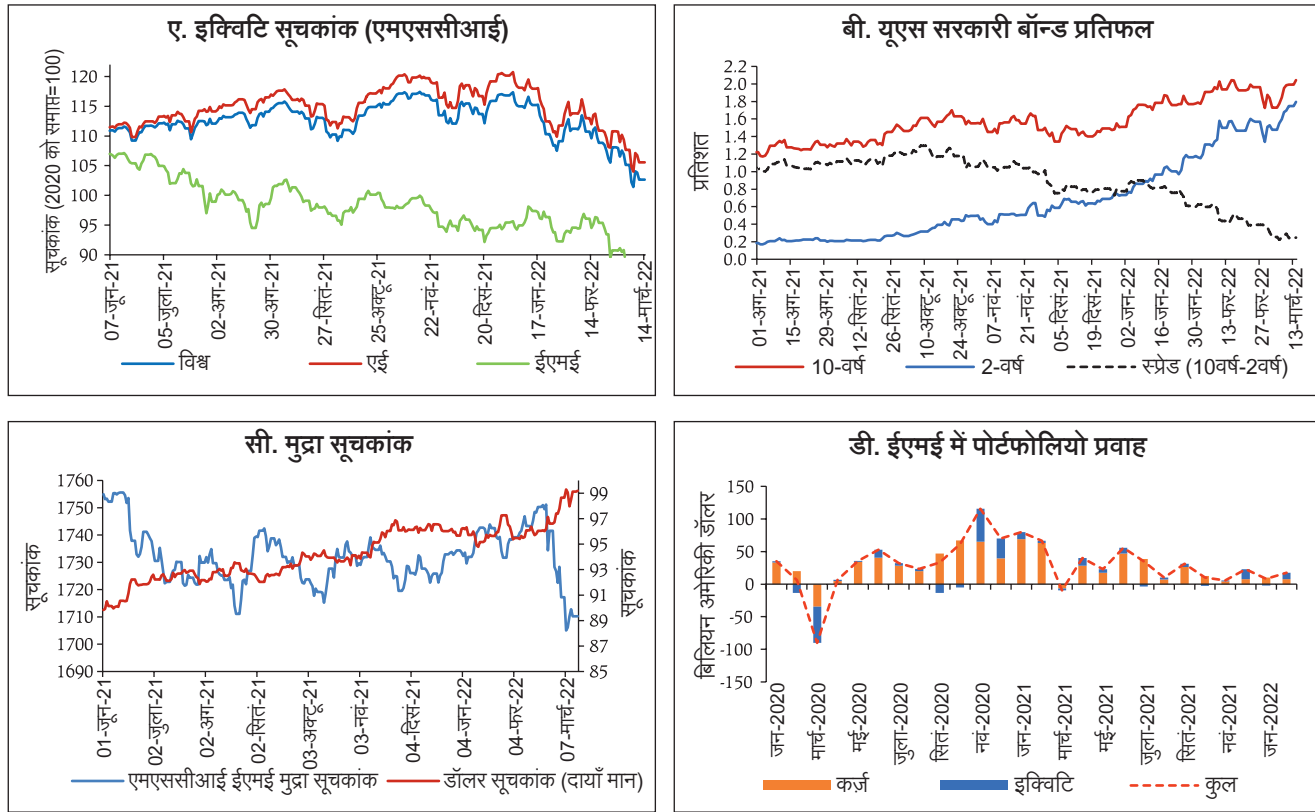
फरवरी के अंतिम सप्ताह में 30 प्रतिशत से अधिक मूल्यहास हुआ है (चार्ट 6सी)।

वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल के बावजूद, जनवरी में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में फरवरी 2022 में ईएमई को पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार, सख्त मौद्रिक स्थितियों, भू-राजनीतिक टकरावों और महामारी से कुछ ईएमई में धीमी बहाली के संबंध में निवेशकों की बढ़ती चिंताओं के बीच चीन के बाहर उभरती बाजार प्रतिभूतियों (स्टॉक और बॉन्ड) में विदेशी निवेश कम हो गया (चार्ट 6डी)। साथ ही, अधिकांश ईएमई ने मार्च के पहले सप्ताह में, विशेष रूप से ऋण खंड में निवल पूंजी बहिर्वाह देखने को मिला।

पिछले एक सप्ताह में वैश्विक वित्तीय बाजारों में बेतहाशा उतार-चढ़ाव के कारण अस्थिरता सूचकांक, जो मार्च 2020 के आसपास महामारी की शुरुआत में चरम पर था, और भी अधिक बढ़ गया (चार्ट 7 और सारणी 1)।

फरवरी और मार्च में अब तक (14 तारीख तक) मौद्रिक नीति की कार्रवाइयां सामान्यीकरण या विराम की दिशा में तैयार की गई थीं। फेड ने आस्ति खरीद को बंद कर दिया है और मार्च में निकालने के लिए तैयार है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अपने

चार्ट 6 : वित्तीय बाज़ार

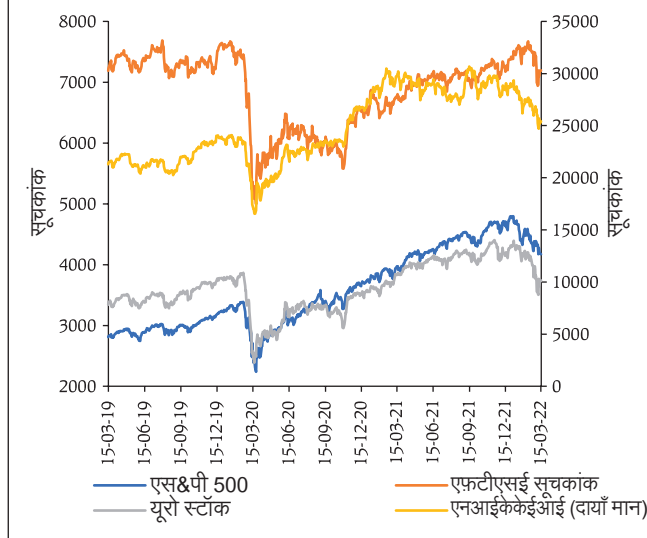


स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

चल रहे आसित खरीद कार्यक्रम (एपीपी) का समर्थन किया है, जबकि तीसरी तिमाही में एपीपी के तहत निवल खरीद के संभावित

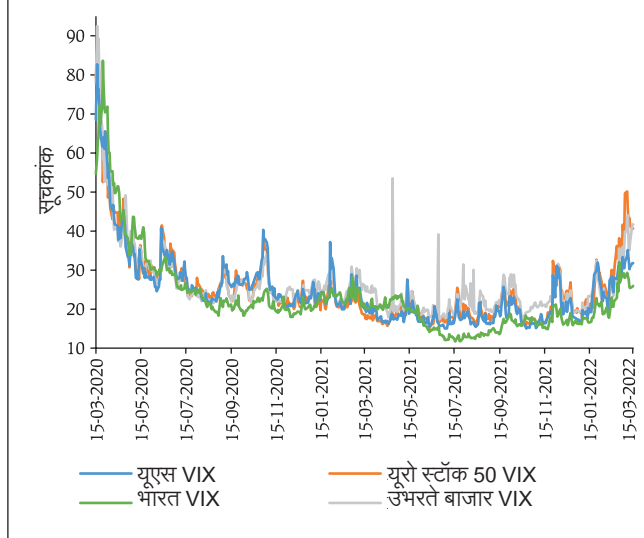
निष्कर्ष की घोषणा की है कि क्या मध्यावधि मुद्रास्फीति दृष्टिकोण कमजोर नहीं होगा। रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड और बैंक ऑफ

चार्ट 7 ए. वैश्विक इक्विटी



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 7 बी. परिवर्तन मान



सारणी 1 : वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू)

	जन-21	फर-21	मार्च-21	अप्रै-21	मई-21	जून-21	जुला-21	अग-21	सितं-21	अक्टू-21	नव-21	दिसं-21	जन-22	फर-22
विश्व ईपीयू	180	140	119	126	152	181	199	213	202	192	223			
यूएस ईपीयू	216	154	177	123	130	113	130	124	120	110	135	357	302	334
यूरोप ईपीयू	232	185	217	179	141	153	197	187	206	198	247	298	259	

नोट: यूरोप ईपीयू में 5 यूरोपीय देश शामिल हैं – जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, और स्पेन। सूचकांक के आंकड़े बेकर, ब्लूम एवं डी (2016) पर आधारित हैं।

स्रोत: www.policyuncertainty.com

कनाडा ने फरवरी 2022 और मार्च 2022 में क्रमशः 25 बीपीएस की दर से दरें बढ़ाईं। अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी अपनी नीति को कड़ा करना जारी रखा, जिसमें मेक्सिको भी शामिल है जिसने फरवरी में अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की। 28 फरवरी 2022 को एक आपातकालीन कदम के तौर पर बैंक ऑफ रूस ने बाह्य परिवेश में गिरावट और मुद्रा मूल्यहास और उच्च मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के कारण अपनी प्रमुख दर को 10.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया (चार्ट 8)। दूसरी ओर, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार दो महीने की ढील के बाद रुक गया, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्की ने लगातार दूसरे महीने ठहराव को बनाए रखा।

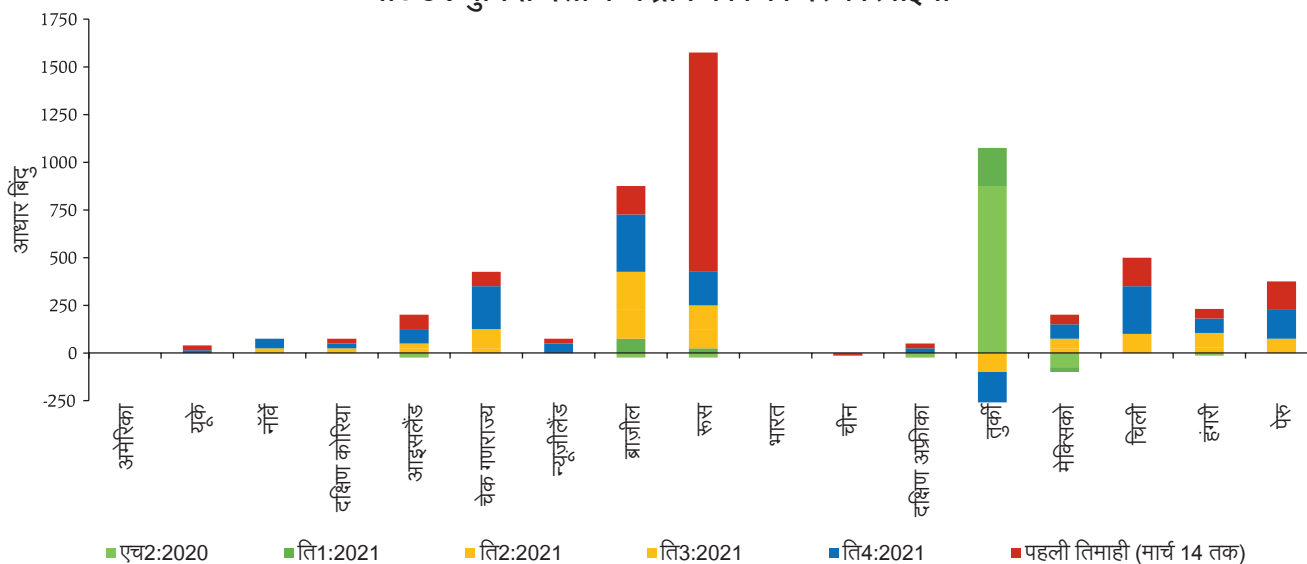
बहाली को पटरी पर बनाए रखने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की कड़ी चुनौती का

सामना करना पड़ रहा है। बढ़ी हुई अनिश्चितता में घिरे आर्थिक दृष्टिकोण के साथ, ईएमई के लिए जोखिम तेज हो गए हैं क्योंकि पूंजी बहिर्वाह, वैश्विक चलनिधि सख्त होने और बिगड़ते भू-राजनीतिक माहौल से बाहरी परिस्थितियां तेजी से कम अनुकूल होती जा रही हैं।

III. घरेलू घटनाक्रम

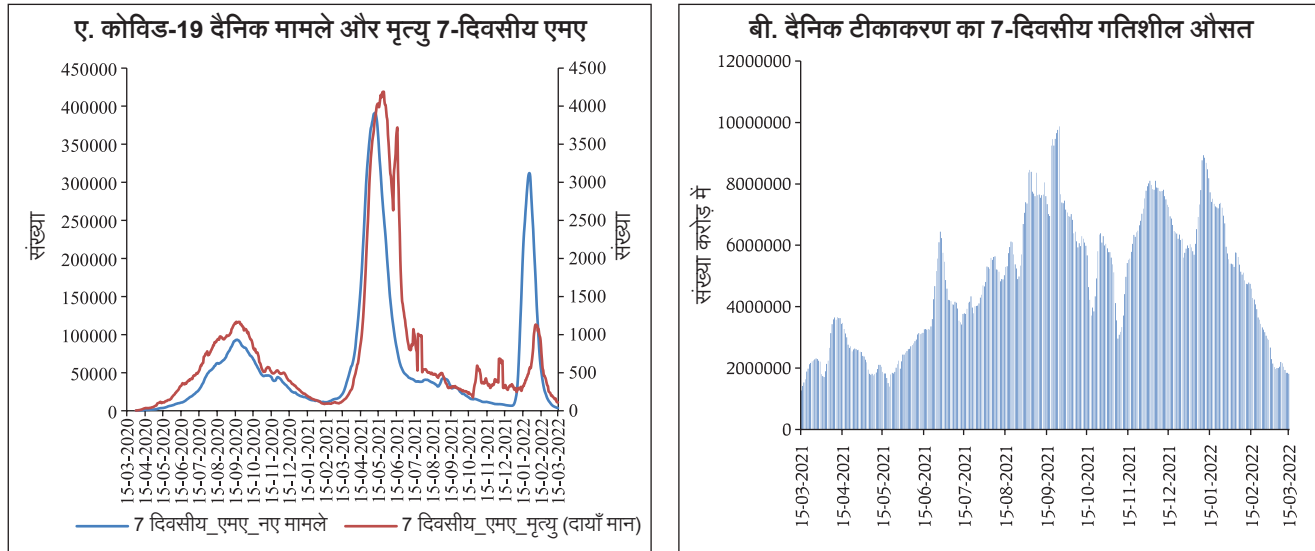
दैनिक कोविड -19 मामलों में तेजी से गिरावट हुई है और 21 जनवरी 2022 से दैनिक संक्रमण कम हो गया है और 15 मार्च 2022 को 3,000 से कम हो गया है, जो 20 जनवरी, 2022 को 3.47 लाख और वयस्क आबादी का 82.3 प्रतिशत है और 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के 3.4 करोड़ से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है, जिसकी वजह से महामारी की तीसरी लहर थम गई है (चार्ट 9)। अधिकांश स्थानों पर लोगों और सामानों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। सेवा क्षेत्र के

चार्ट 8 : चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दर कार्रवाइयां



स्रोत : केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

चार्ट 9 : कोविड-19 के मामले और टीकाकरण

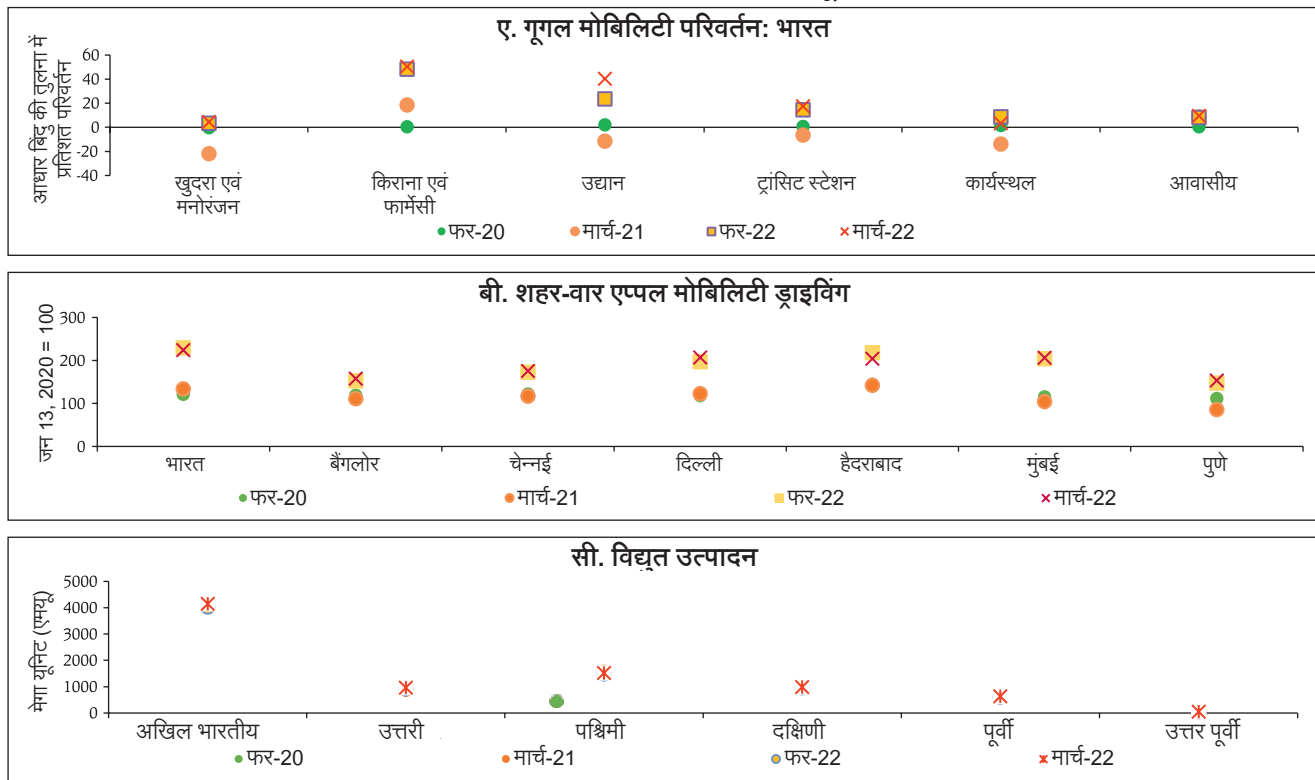


स्रोत : ब्लूमबर्ग।

आउटलेट जैसे रेस्तरां और सिनेमा हॉल धीरे-धीरे सामान्य संचालन फिर से शुरू कर रहे हैं।

एक साल पहले की तुलना में मार्च 2022 में गतिशीलता संकेतक से महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलता है (चार्ट 10ए)। मार्च में (4 मार्च तक) एप्पल मोबिलिटी इंडेक्स भी अधिक था

चार्ट 10: आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव



स्रोत : गूगल; सीईआईसी; और पोसोको।

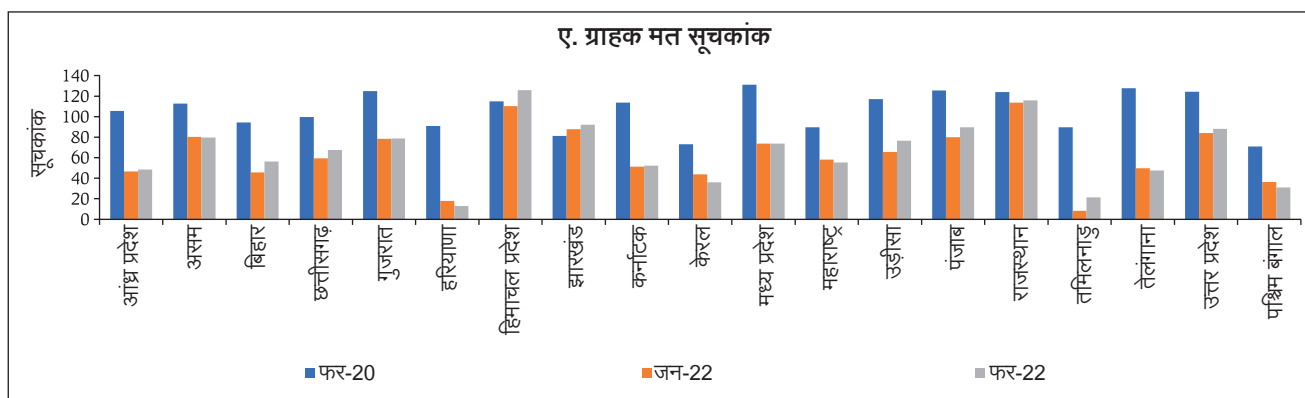
(चार्ट 10बी)। गतिशीलता में सुधार और सेवा क्षेत्र के आउटलेट के खुल जाने से मार्च में बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई, जो पिछले महीने के स्तर और महामारी से पहले के स्तर से अधिक थी (चार्ट 10सी)।

परिणामस्वरूप, फरवरी 2022 में अधिकांश राज्यों में उपभोक्ता रुख में सुधार हुआ (चार्ट 11)।

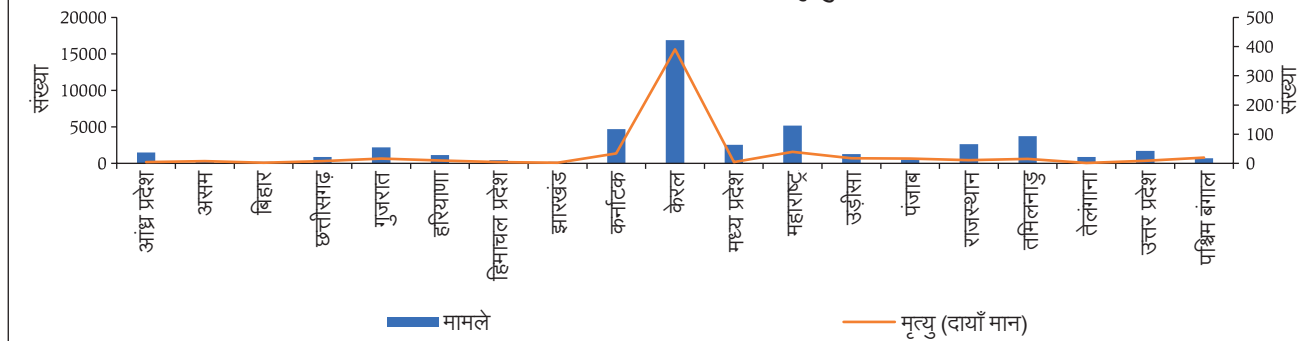
कुल मांग

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 28 फरवरी को जारी दूसरे अग्रिम राष्ट्रीय आय अनुमानों (एसएई) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) से 30 आधार अंकों की गिरावट है। स्तर के संदर्भ में वास्तविक जीडीपी वर्ष 2019-20 के

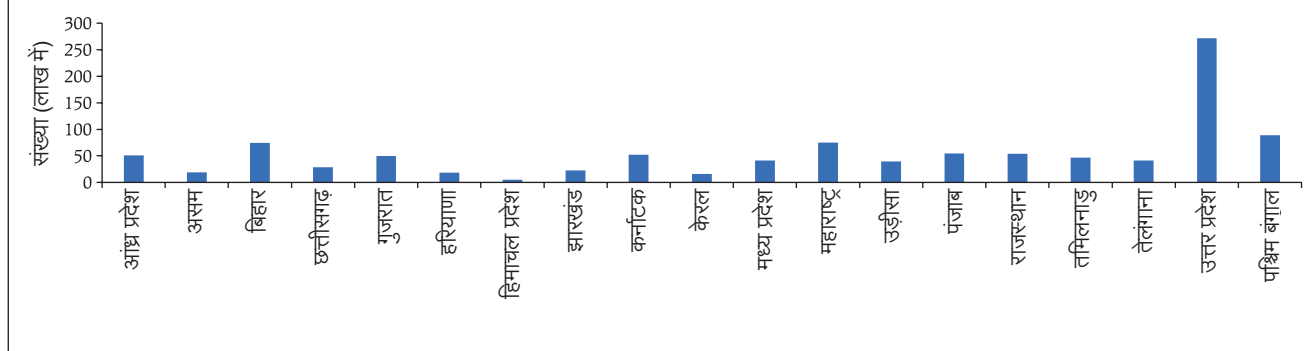
चार्ट 11: राज्य-वार ग्राहक मत और टीकाकरण



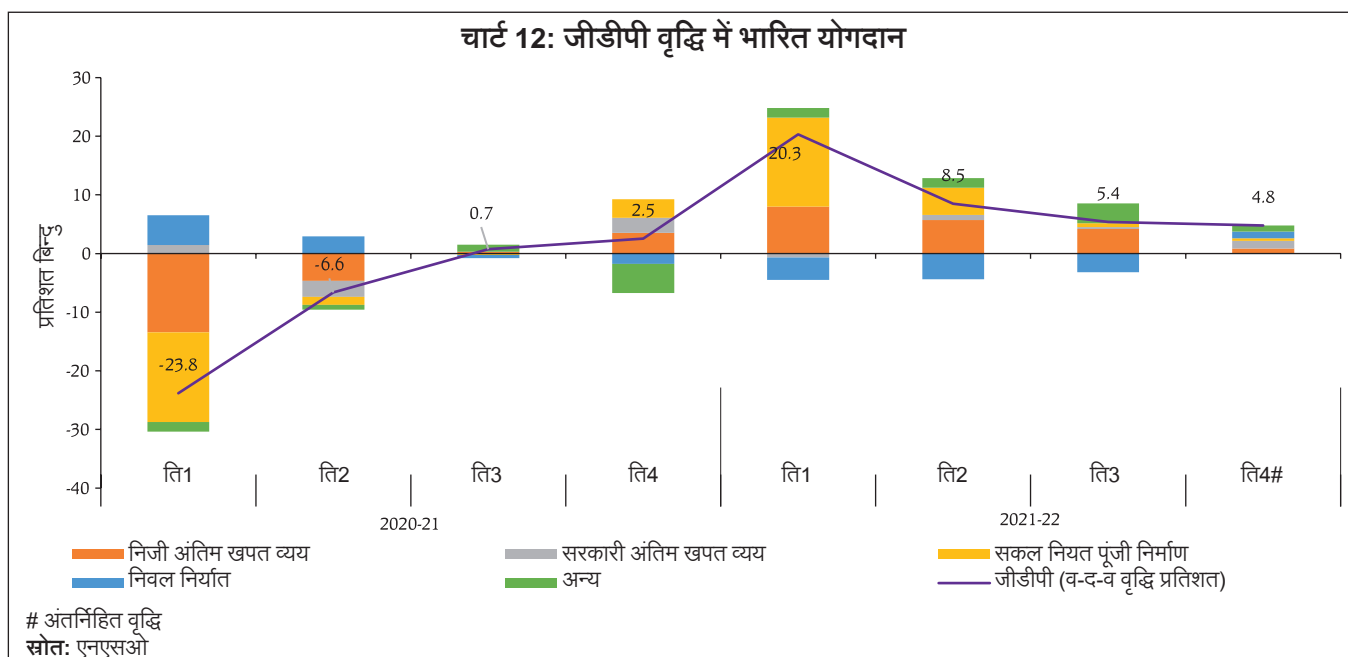
बी. फरवरी 2022 में कोविड 19 के मामले और मृत्यु: दैनिक औसत



सी. फरवरी 2022 में राज्य-वार टीकाकरण



स्रोत : सीईआईसी

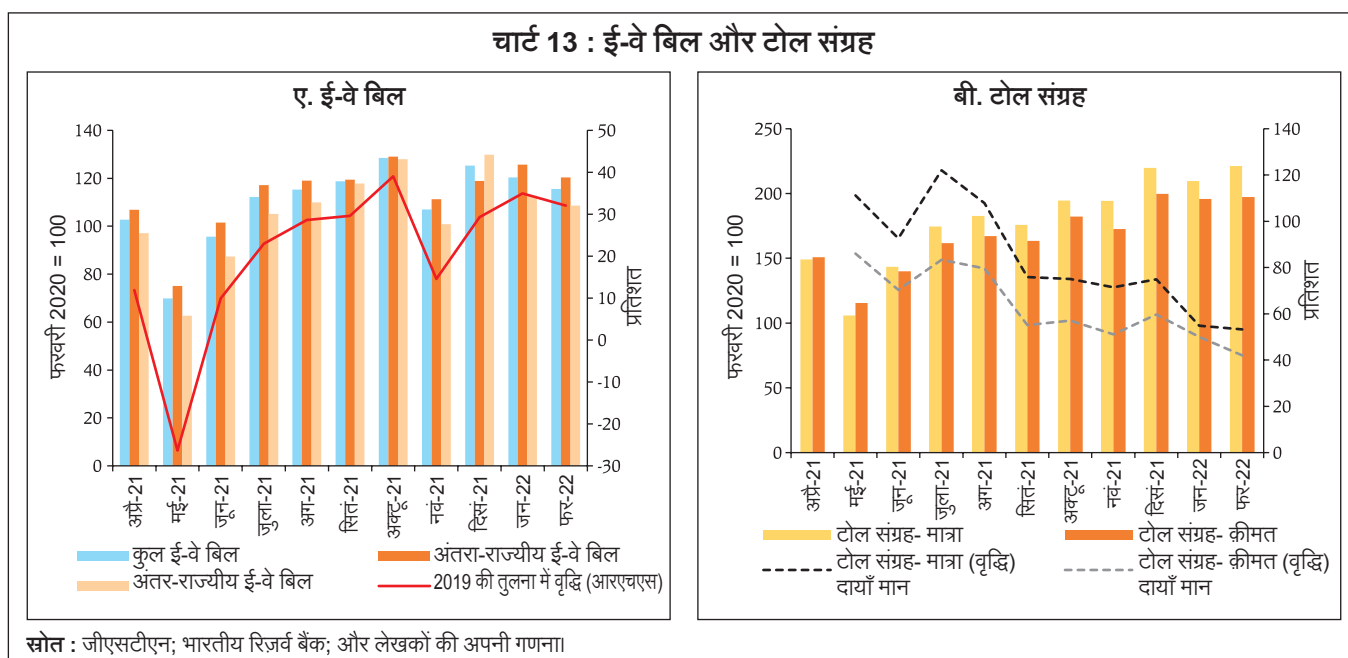


महामारी के पहले स्तर से 1.8 प्रतिशत से अधिक हो गया। बहाली व्यापक रूप से आधारित थी क्योंकि निजी खपत सहित कुल मांग के सभी घटक महामारी से पहले के अपने-अपने स्तर को पार कर चुके हैं।

वास्तविक जीडीपी के घटकों के संबंध में, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ने वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। निर्माण गतिविधि में गिरावट

के साथ, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) घटकर 2.0 प्रतिशत रह गया। निर्यात और आयात दोनों में वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने के लिए स्थिर गति बनी रही (चार्ट 12)।

ई-वे बिल जनरेशन महामारी से पहले के स्तरों से ऊपर रहा (चार्ट 13 ए)। आधारभूत प्रभाव के घटने के बावजूद फरवरी 2022 में टोल संग्रह में भी वृद्धि हुई (चार्ट 13बी)।

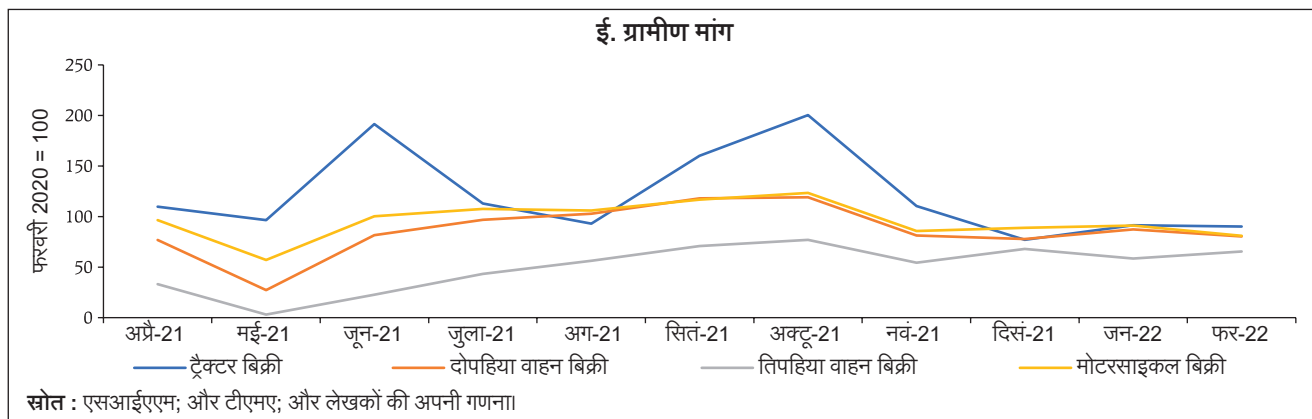
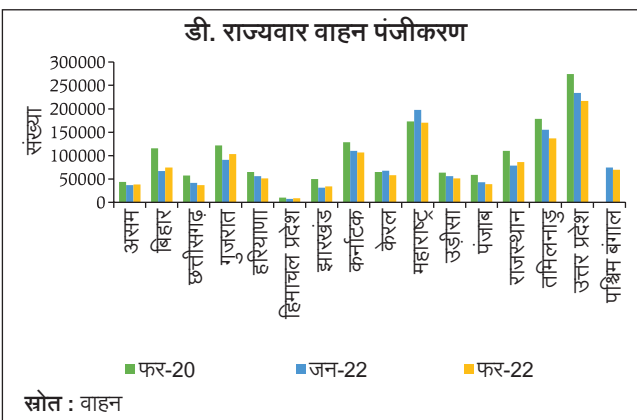
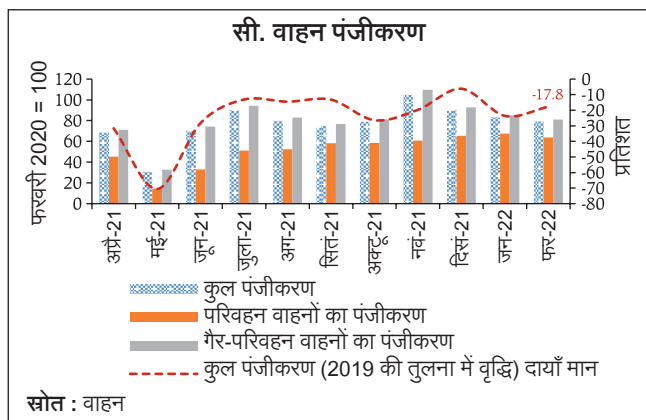
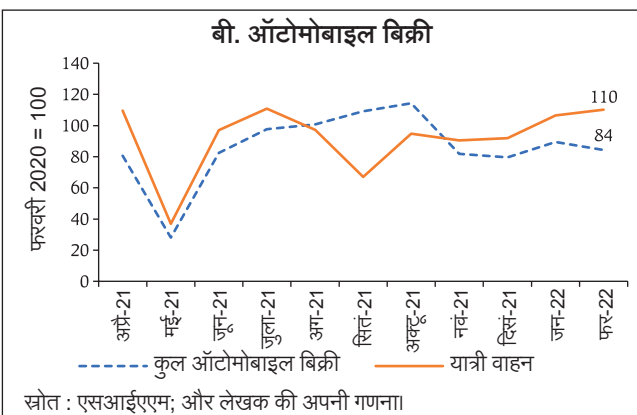
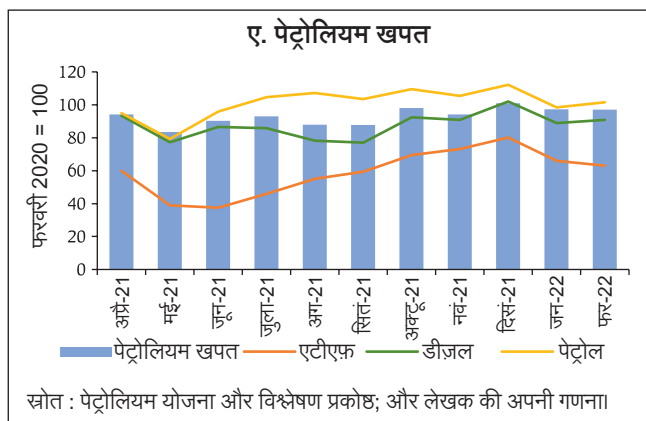


फरवरी 2022 में गतिशीलता की बहाली ने डीजल और पेट्रोल की खपत को बढ़ा दिया, हालांकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में गिरावट ने कुल पेट्रोलियम खपत को कम कर दिया (चार्ट 14ए)।

दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट के कारण फरवरी में ऑटोमोबाइल की बिक्री में नरमी आई, यहां तक कि मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से यात्री वाहनों के थोक प्रेषण में वृद्धि दर्ज

की गई (चार्ट 14बी)। सभी खंडों में ट्रकों के प्रेषण में भी सुधार हुआ, जो परिवहन क्षेत्र में निरंतर सुधार का संकेत देता है। इनपुट मुद्रास्फीति और उच्च खुदरा ईंधन की कीमतों से निपटने के लिए ओईएम द्वारा कीमत वृद्धि ने पूंजीगत उपकरणों के स्वामित्व की लागत में वृद्धि की है। वितरण में ज्यादा समय लगाने से पंजीकरण बाधित हुआ जिससे ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री स्थिर रही (चार्ट 14सी)। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के मामले में, फरवरी 2022 में

चार्ट 14 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

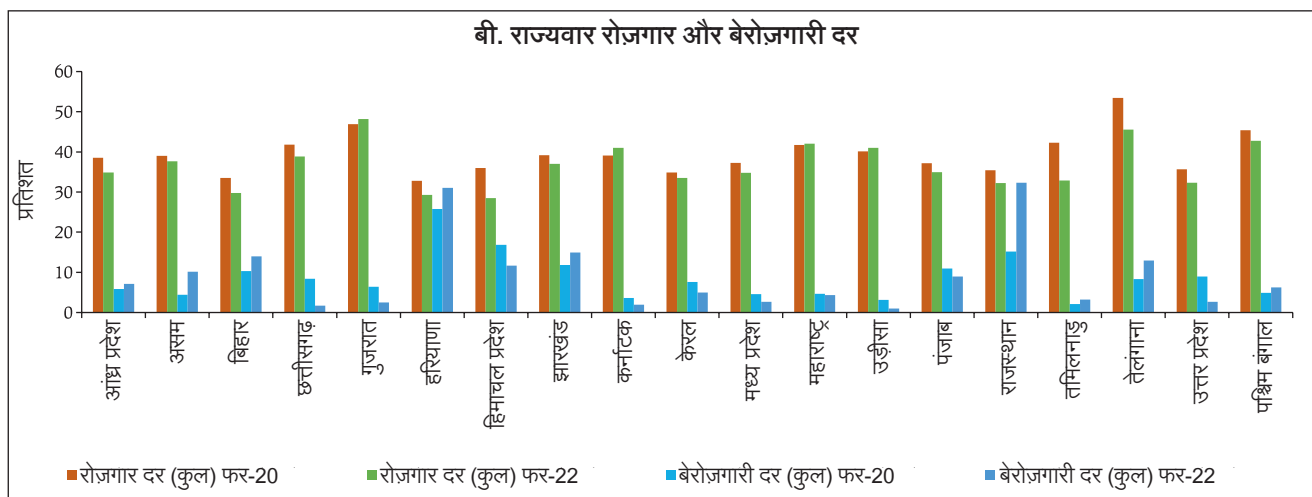
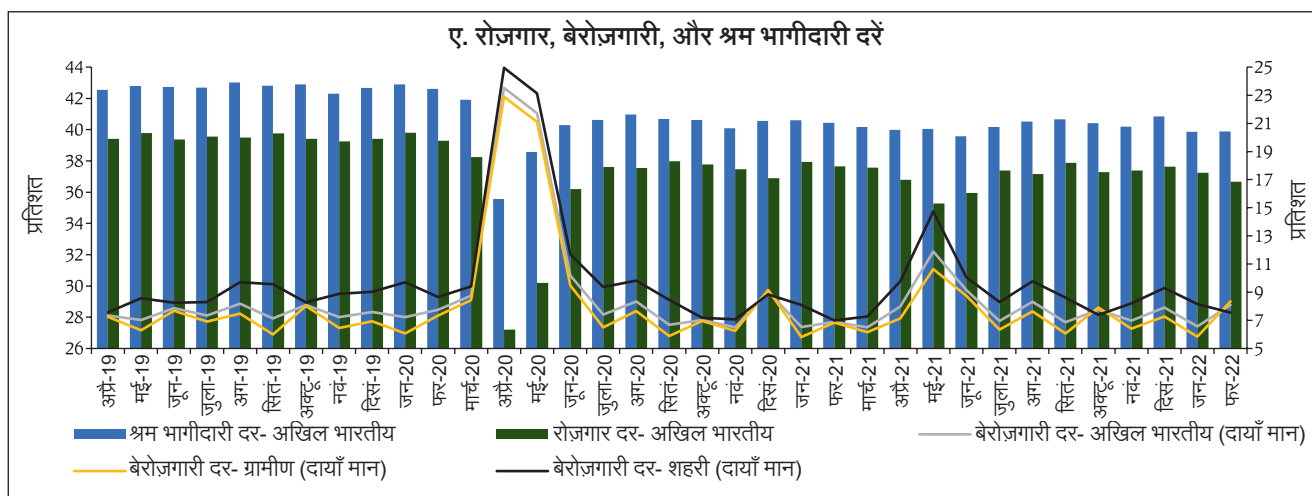


वाहन पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष दो राज्य थे (चार्ट 14डी)। इलेक्ट्रिक वाहन खंड ने बिक्री में कई गुना वृद्धि दर्ज की। दोपहिया और प्रवेश स्तर की कारों की वजह से ग्रामीण मांग में महामारी से पहले के स्तर के संकुचन के साथ नरमी दर्ज की गयी (चार्ट 14ई)।

जनवरी में सुस्त प्रदर्शन के बाद फरवरी 2022 में एफएमसीजी की मांग में तेजी आई। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बिजोम के मुताबिक, फरवरी में एफएमसीजी की बिक्री में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि पूरी तरह से वस्तुओं और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की उच्च बिक्री से हुई थी, जबकि घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल श्रेणियों में गिरावट आई थी।

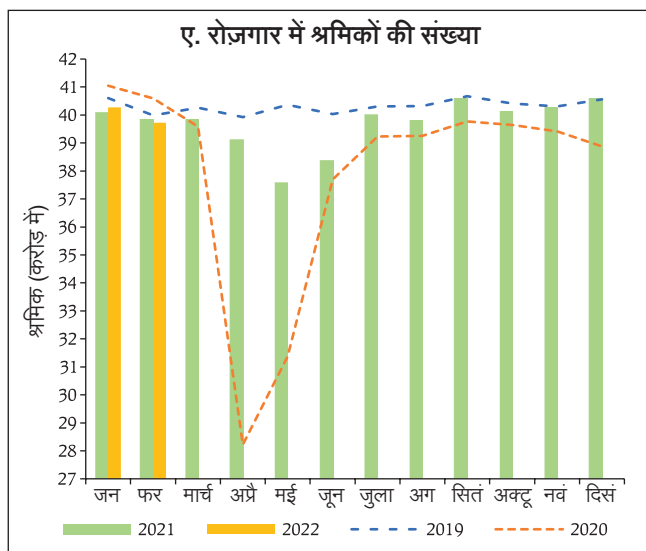
भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, फरवरी 2022 में श्रम भागीदारी दर में पिछले महीने की तुलना में तीन आधार अंकों की मामूली वृद्धि हुई। रोजगार दर (कामगार जनसंख्या अनुपात) में 58 आधार अंकों की गिरावट आई, जिसके कारण बेरोजगारी दर जनवरी में 6.6 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2022 में 8.1 प्रतिशत हो गई। सर्वेक्षण ने यह भी संकेत दिया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी गिर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है (चार्ट 15ए)। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों में रोजगार दर में सुधार का संकेत देखने को मिला (चार्ट 15बी)।

चार्ट 15: श्रम बाजार की स्थिति

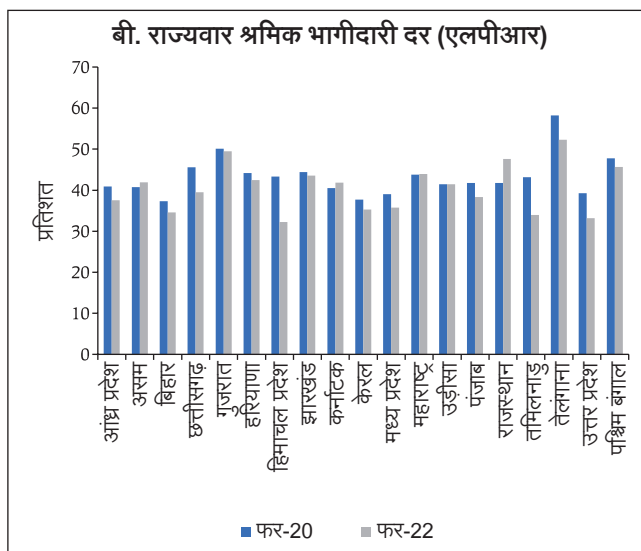


स्रोत : सीएमआईई

चार्ट 16: रोजगार में श्रमिकों की संख्या और एलईपीआर



स्रोत : सीएमआईई

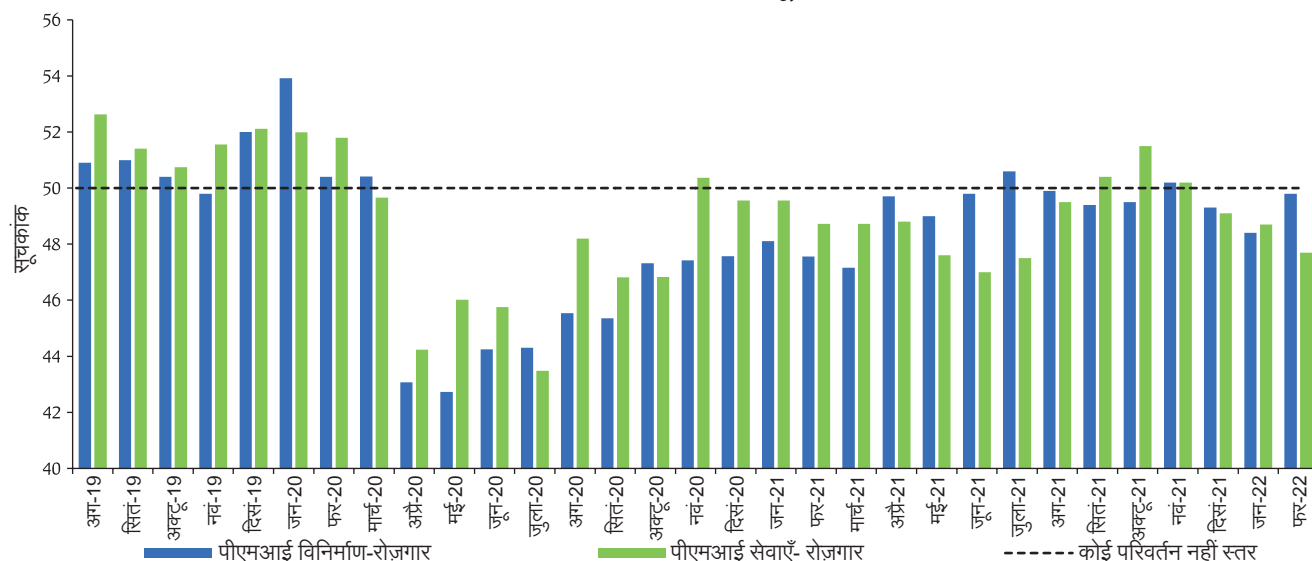


सीएमआईई के रोजगार आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने मामूली गिरावट के बाद फरवरी 2022 में श्रम बाजार को और नुकसान हुआ। पिछले महीने की तुलना में फरवरी में श्रमिकों की संख्या में 5.5 मिलियन की गिरावट के कारण नियोजित श्रमिकों की संख्या एक साल पहले के स्तर से नीचे चली गई (चार्ट 16ए)। हालांकि, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कई राज्यों में महामारी से पहले के स्तर के करीब लौट आई है। असम, कर्नाटक,

महाराष्ट्र और राजस्थान ने फरवरी 2020 की तुलना में फरवरी 2022 में एलएफपीआर को अपने महामारी के पहले के स्तर से ऊपर उठते हुए देखा है (सीएमआईई) [चार्ट 16बी]।

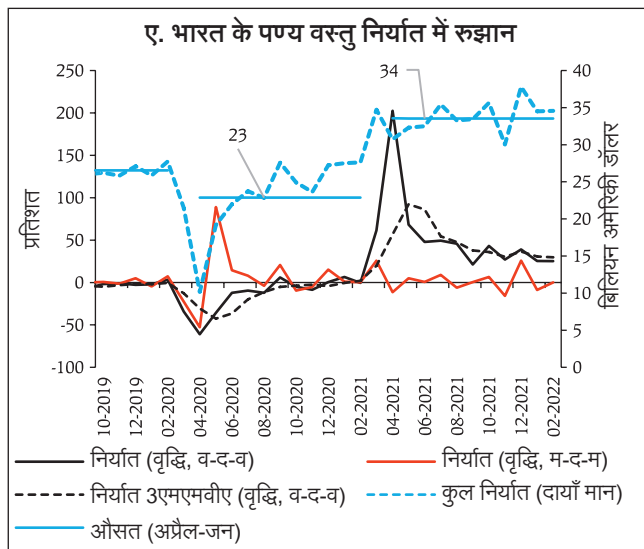
पीएमआई बताते हैं कि फरवरी 2022 में लगातार तीसरे महीने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के तहत रोजगार संकुचित हुआ (चार्ट 17)।

चार्ट 17: पीएमआई रोजगार सूचकांक

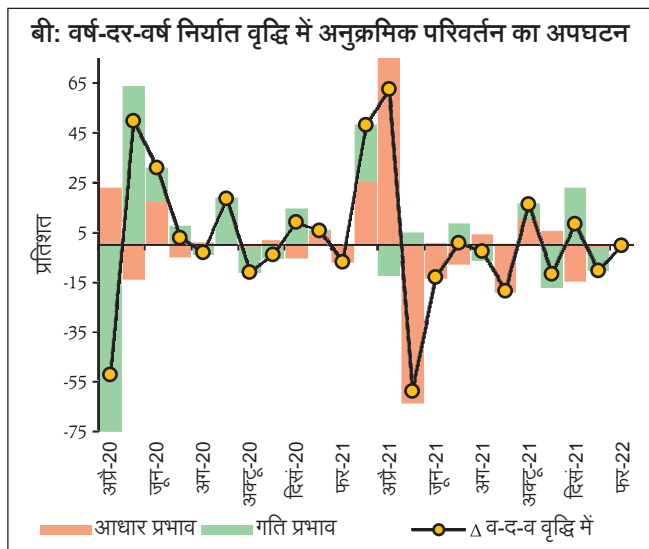


स्रोत : आईएचएस मार्किट

चार्ट 18: भारत का पण्य वस्तु निर्यात- फरवरी 2022



स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआईएस; और लेखकों की अपनी गणना।

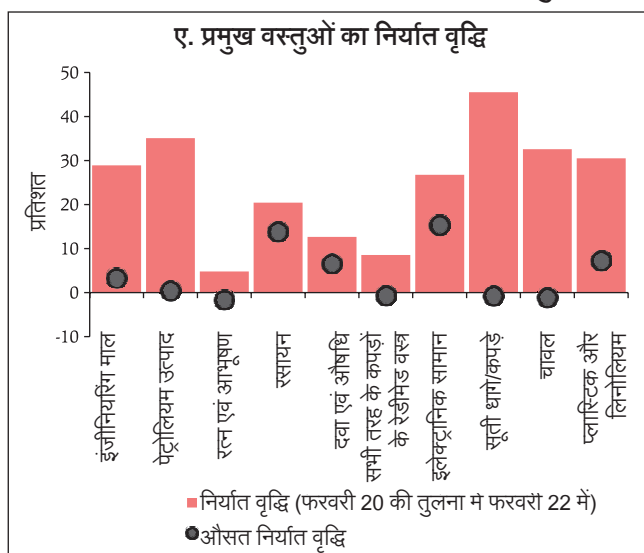


फरवरी 2022 में 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत का व्यापारिक निर्यात लगातार 12वें महीने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा। निर्यात ने साल-दर-साल आधार पर 25.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और कोविड के पहले के स्तरों (24.6 प्रतिशत) से अधिक है [चार्ट 18]। अप्रैल 2021 - फरवरी 2022 के दौरान, व्यापारिक निर्यात 374.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर

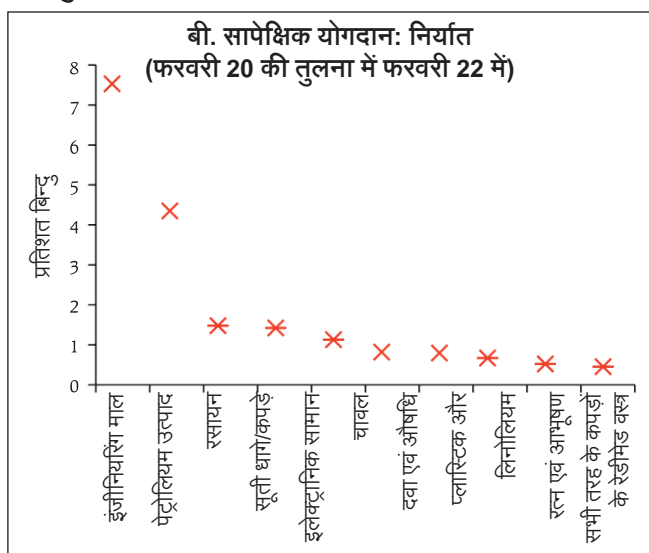
रहा, जो वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य का 93.7 प्रतिशत है।

निर्यात वृद्धि व्यापक-आधारवाली थी, जिसमें दस प्रमुख पण्य समूह कोविड-पूर्व स्तर से ऊपर के विस्तार के लगभग 80 प्रतिशत निर्यात हुआ करते थे (चार्ट 19ए)। निर्यात प्रदर्शन में सुधार इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के पोटलदान के उच्च मूल्य से हुआ (चार्ट 19बी)।

चार्ट 19: प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का विश्लेषण



स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआईएस और लेखकों की अपनी गणना।

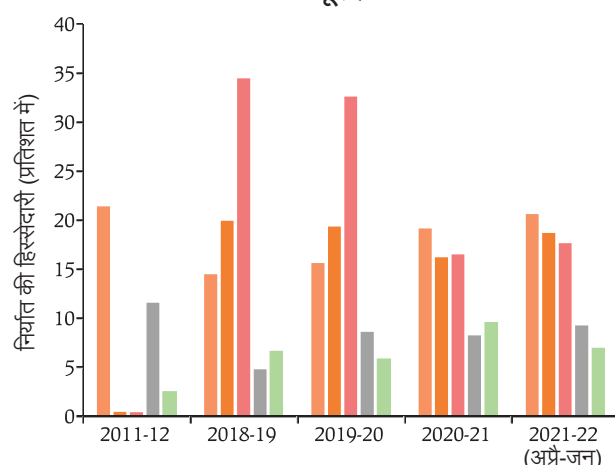


भारत ने हाल ही में रत्न और आभूषण, वस्त्र और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को लक्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले दशक में, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की संरचना में पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न और आभूषण निर्यात में तेज वृद्धि से काफी विस्तार हुआ है (चार्ट 20)।

फरवरी 2022 में 55.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक आयात लगातार छठे महीने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा, जिसमें महामारी से पहले के स्तर (फरवरी 2020) की तुलना में 46.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है [चार्ट 21]। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के आयात बिल को बढ़ा रही हैं क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति-पक्ष की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

मजबूत आयात मांग पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सोने की उच्च मांग से प्रेरित थी (चार्ट 22ए)। आयात वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें प्रमुख जिंस समूहों ने अपने कोविड-पूर्व स्तरों से ऊपर के विस्तार को दर्ज करते हुए 75

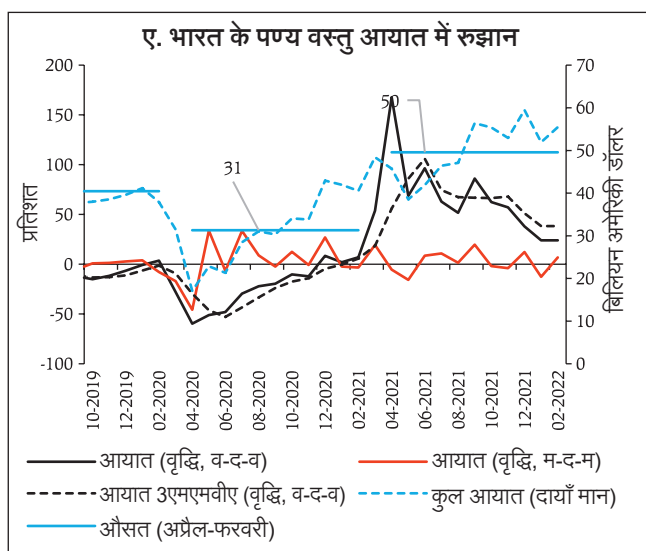
चार्ट 20: भारत का यूएई में पण्य निर्यात



स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआईएस और लेखकों की अपनी गणना।

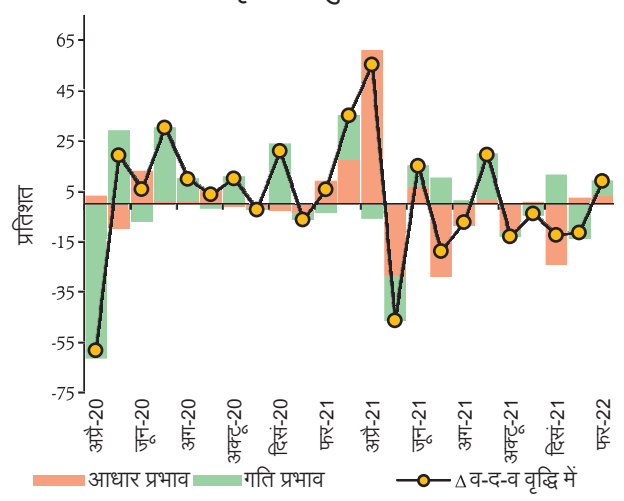
प्रतिशत से अधिक आयात किया (चार्ट 22 बी)। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को दर्शाते हुए, पूर्व-कोविड स्तरों पर फरवरी 2022 में कच्चे आयात में 41.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 21 : भारत का पण्य वस्तु आयात- फरवरी 2022

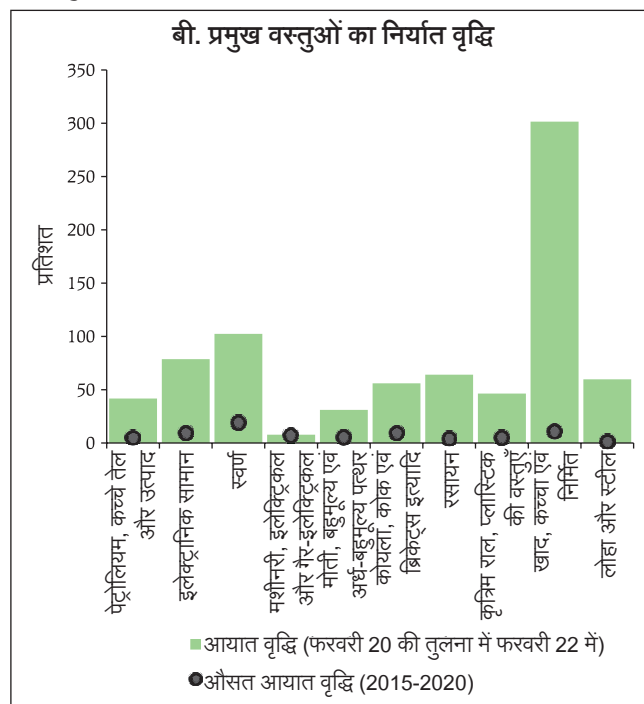
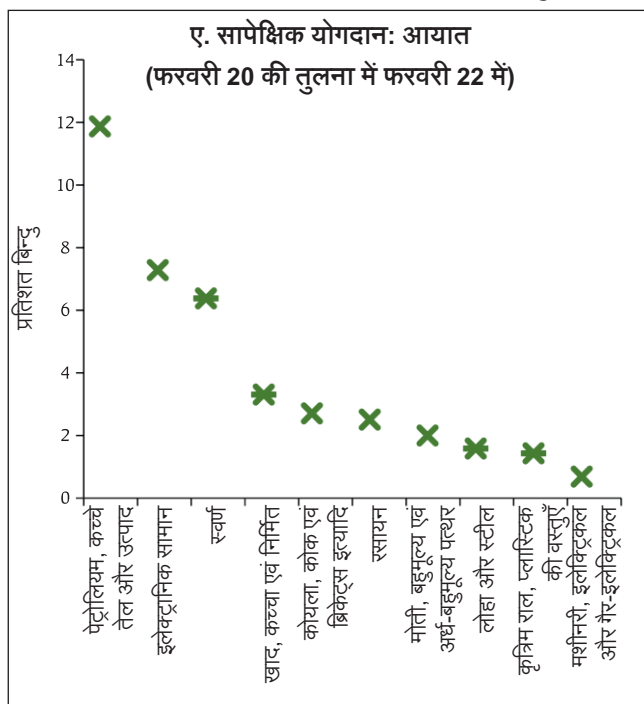


स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआईएस; और लेखकों की अपनी गणना।

बी: वर्ष-दर-वर्ष आयात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का अपघटन



चार्ट 22: प्रमुख आयातित वस्तुओं का विश्लेषण

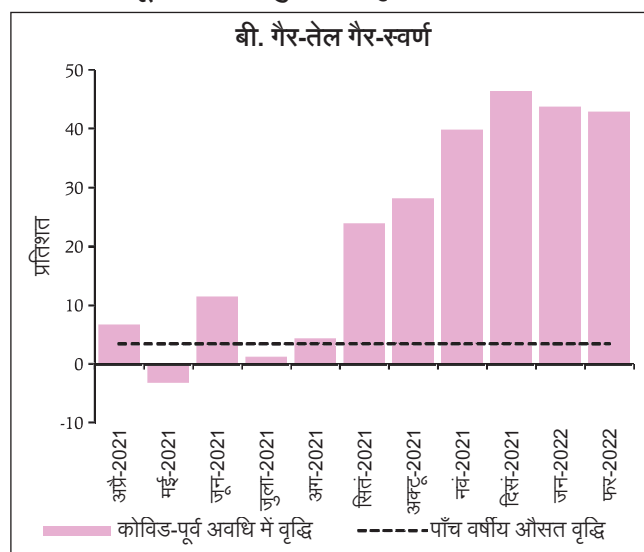
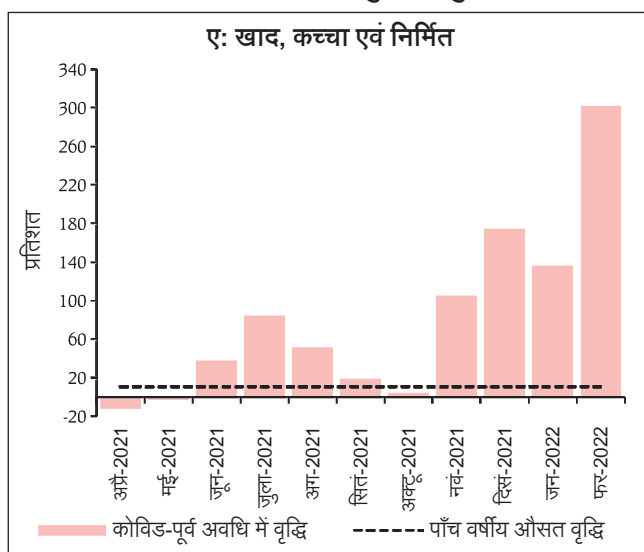


स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआई&एस और लेखकों की अपनी गणना।

फरवरी 2022 में उर्वरकों का आयात रिकॉर्ड स्तर पर रहा और महामारी से पहले की अवधि में 301.6 प्रतिशत से अधिक का विस्तार हुआ (चार्ट 23ए)। गैर-तेल गैर-सोने के आयात ने

फरवरी 2022 में लगातार नौवें महीने के लिए पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में मजबूत वृद्धि बनाए रखी (चार्ट 23 बी)।

चार्ट 23 : प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि (कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में वृद्धि)



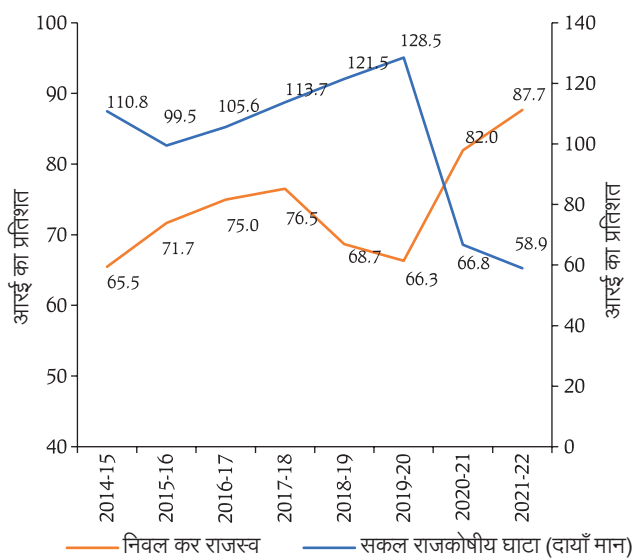
स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआई&एस और लेखकों की अपनी गणना।

जैसे-जैसे आयात निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ा, फरवरी 2022 में भारत का व्यापार घाटा (20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) बढ़ गया, जो बाद में दोनों (जनवरी 2022 में 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और साथ ही वर्ष-दर-वर्ष (फरवरी 2021 में 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) एवं कोविड-पूर्व स्तर (फरवरी 2020 में 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में वृद्धि हुई।

भारत के सेवा व्यापार के संबंध में जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 (वर्ष-दर-वर्ष) में भारत का 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात 24.2 प्रतिशत बढ़ गया। जनवरी (वर्ष-दर-वर्ष) के दौरान सेवाओं के निवल निर्यात में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 2022-23 हेतु सेवा क्षेत्र के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों (आरई) के लिए सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर जीडीपी का 6.7 प्रतिशत है। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ, जो निवल कर राजस्व आरई के 87.7 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान कुल व्यय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्रमशः 22.0 प्रतिशत

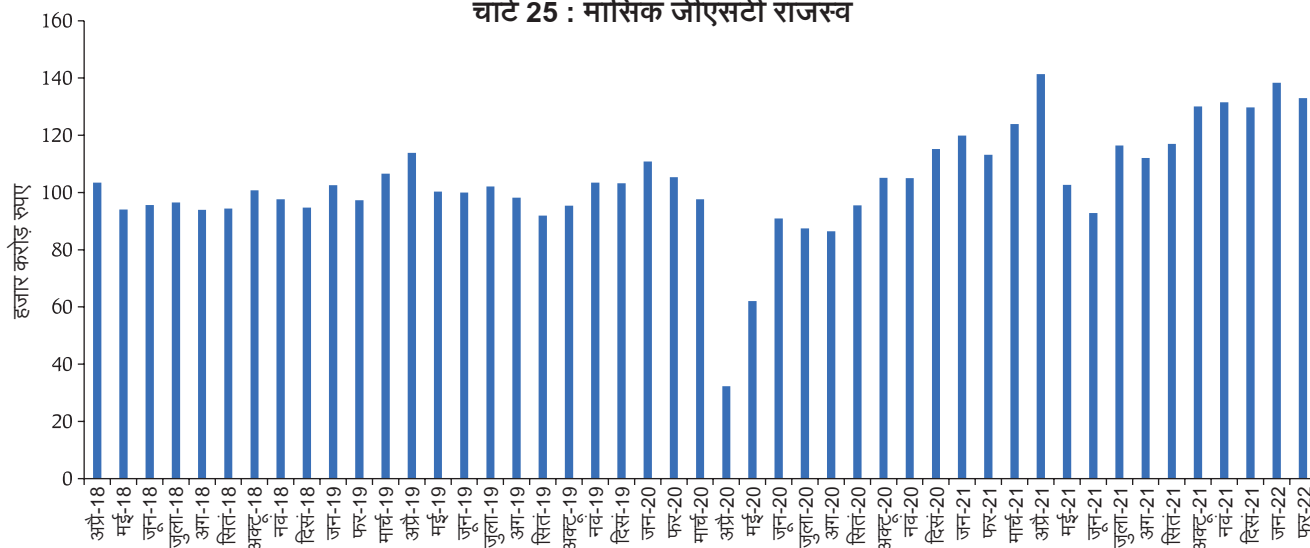
चार्ट 24 : अप्रैल-जनवरी के दौरान निवल कर राजस्व



स्रोत : भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

और 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा आरई के 58.9 प्रतिशत के सर्वकालिक निचले स्तर तक चला गया (चार्ट 24)। 14 मार्च 2022 को, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग का तीसरा और अंतिम खेप प्रस्तुत किया, जिसमें ₹1.07 लाख करोड़ के निवल नकद व्यय का प्रस्ताव है।

चार्ट 25 : मासिक जीएसटी राजस्व



स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो

फरवरी 2022 में, जीएसटी संग्रह में 17.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी, जो लगातार पांचवें महीने के लिए ₹1.3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया (चार्ट 25)। जीएसटी उपकर संग्रह लागू होने के बाद पहली बार 10,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।

25 राज्यों के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों में अप्रैल-दिसंबर 2021 (अप्रैल-दिसंबर 2020 में 10.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले) के दौरान 21.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी, जो मुख्य रूप से कर और गैर-कर राजस्व के कारण हुआ है (चार्ट 26)। बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों की राजस्व प्राप्तियों को वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में 32.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 29.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की जरूरत है।

अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय में क्रमशः 13.0 प्रतिशत और 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने 'पूँजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना' के तहत परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया। पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए 2021-22 के संशोधित अनुमानों में बजट का अनुमान ₹15,000 करोड़ है। इसके अलावा, कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के अलावा, केंद्र ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में कर हस्तांतरण की दो अग्रिम किस्तें जारी की हैं। राज्यों को 2021-22

की चौथी तिमाही में बजटीय व्यय प्राप्त करने के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 12.8 प्रतिशत और 27.3 प्रतिशत (2020-21 की चौथी तिमाही में 40.1 प्रतिशत और 53.9 प्रतिशत के मुकाबले) की अवशिष्ट वृद्धि की संभावना है।

सकल आपूर्ति

आपूर्ति पक्ष पर, मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापित कुल आपूर्ति में 2021-22 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.8 प्रतिशत थी। लचीला कृषि क्षेत्र के अलावा, औद्योगिक और सेवा दोनों क्षेत्रों में निरंतर पुनर्प्राप्ति ने इस वृद्धि को सुगम बनाया। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने अपने महामारी-पूर्व-के स्तर को पार कर लिया।

कृषि क्षेत्र में, रेकॉर्ड बुआई क्षेत्र ने एक साल पहले खरीफ (2.0 प्रतिशत) के साथ-साथ रबी (1.5 प्रतिशत) फसलों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया (चार्ट 27ए)।

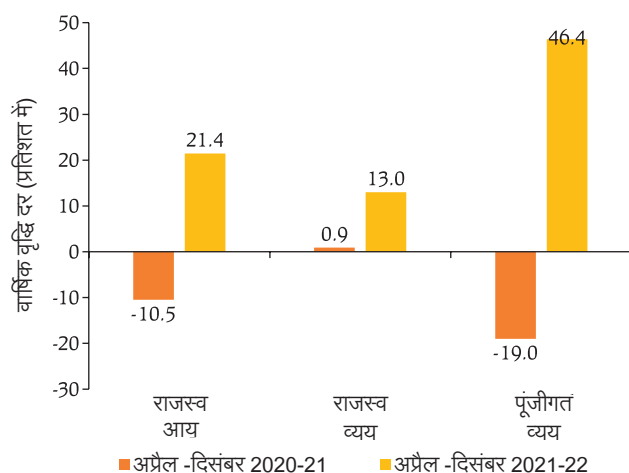
रबी और खरीफ के बीच मार्च से मई तक गर्मी या जायद का मौसम एक छोटी मध्य अवधि है। 04 मार्च, 2022 तक, कुल ग्रीष्मकालीन बुआई क्षेत्र 29.2 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष के स्तर से 0.4 प्रतिशत कम था, जिसका मुख्य कारण चावल (-3.5 प्रतिशत) और तिलहन (-20.7 प्रतिशत) (चार्ट 27बी) जैसे प्रमुख फसलों के तहत कम रकबा था। आने वाले हफ्तों में रोपाई की गति फिर से तेज होने की उम्मीद है।

08 मार्च, 2022 तक, चालू खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान चावल की कुल खरीद संचयी रूप से 489.2 लाख टन तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 451.9 लाख टन थी। इस पूरे सीजन में चावल खरीद का लक्ष्य 528.3 लाख टन है। त्रैमासिक बफर मानदंडों (जनवरी-मार्च) के अनुसार, चावल और गेहूं दोनों के लिए स्टॉक स्तर फरवरी 2022 के मध्य तक पर्याप्त (क्रमशः 7.8 और 1.9 गुना) रहता है।

मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग में 20.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई है, जो आंशिक रूप से ग्रामीण इलाकों में चल रहे रबी फसल संचालन को दर्शाता है (चार्ट 27C)।

औद्योगिक क्षेत्र में, 54.9 पर हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई फरवरी 2022 में एक महीने पहले के 54.0 से बढ़ कर विस्तार मोड में रहा। पीएमआई सेवाएं भी एक महीने पहले के 51.5 से

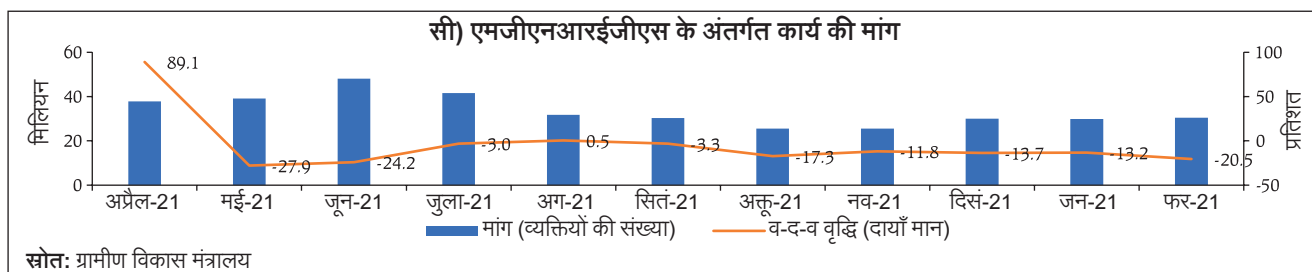
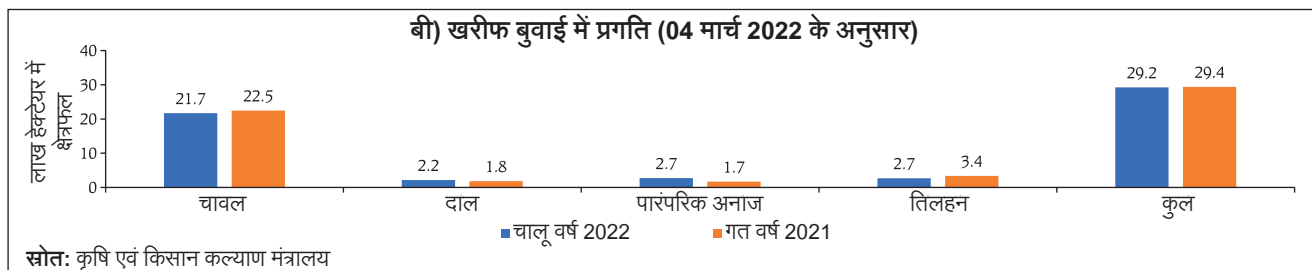
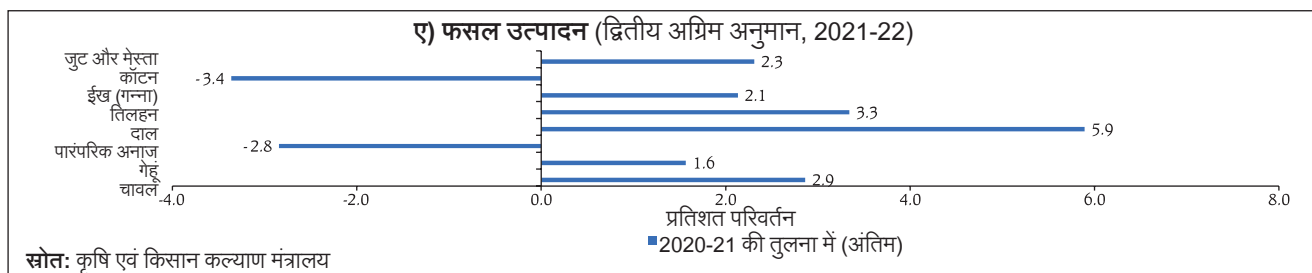
चार्ट 26: राज्य सरकार की आय और व्यय में वृद्धि



टिप्पण: आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं।

स्रोत: भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़

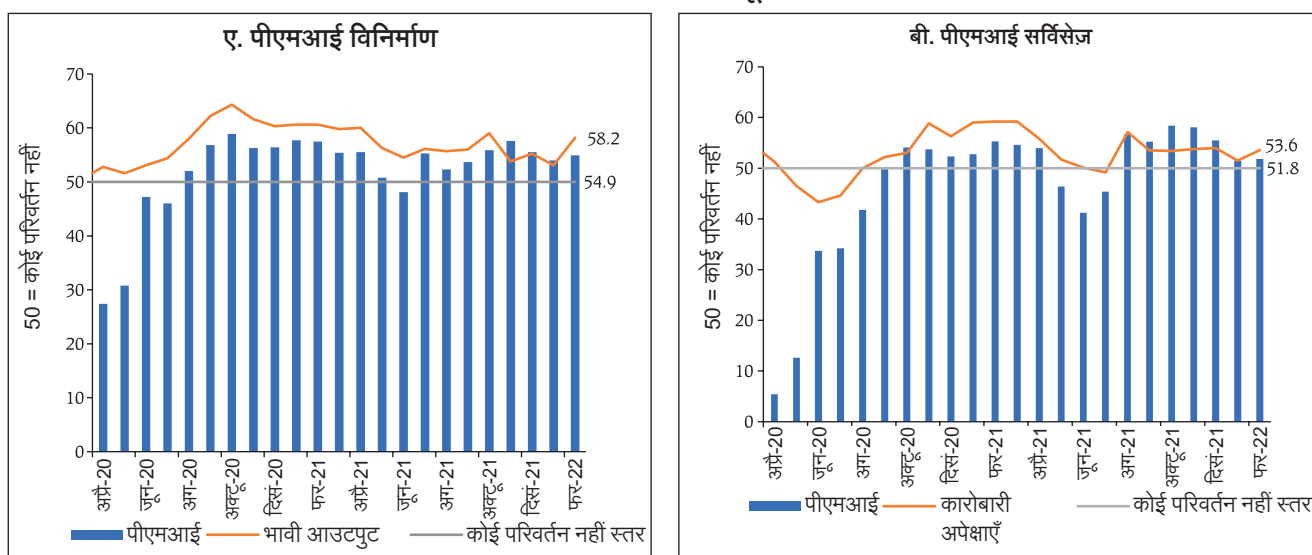
चार्ट 27: ग्रामीण अर्थव्यवस्था



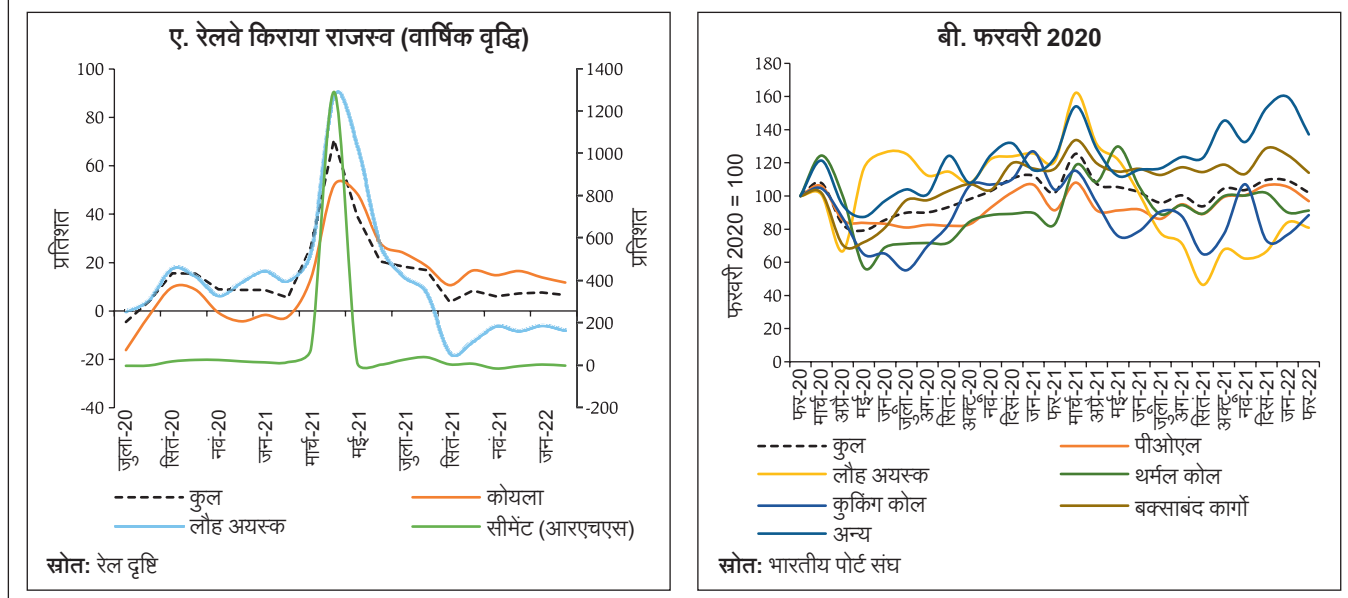
बढ़कर 51.8 के साथ विस्तार मोड़ में रही। सेवाओं के लिए कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) का फरवरी 2022 में

लगातार सातवें महीने विस्तार हुआ, किन्तु पण्य की कीमतों में वृद्धि (चार्ट 28) के बीच परिदृश्य अस्पष्ट बना हुआ है।

चार्ट 28: क्रेय प्रबंधक सूचकांक



चार्ट 29: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक

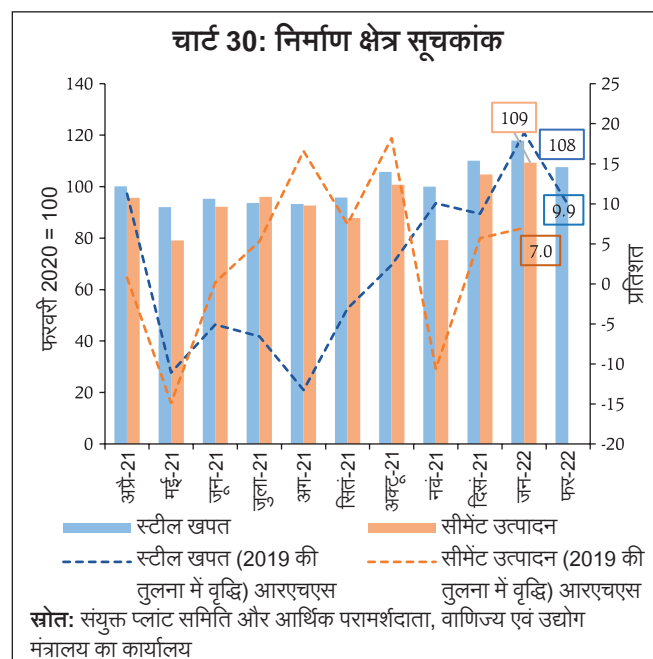


फरवरी 2022 में रेलवे माल ढुलाई में एक साल पहले के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 6.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि (चार्ट 29ए) के साथ सेवा क्षेत्र में परिवहन संकेतकों में वृद्धि दर्ज की गई। कोयले में माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की गई, यहां तक कि लौह-अयस्क और सीमेंट में एक साल पहले उच्च आधार पर गिरावट आई थी। फरवरी में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो भी सामान्य रहे, हालांकि यह पूर्व-महामारी रीडिंग के तुलनीय स्तरों पर था। सामान्य कंटेनरीकृत कार्गो और पोर्ट ऑफ लोडिंग (पीओएल) की वस्तुओं में गिरावट के कारण था, जो कुल कार्गो (चार्ट 29 बी) का 67 प्रतिशत है।

जनवरी-फरवरी 2022 के दौरान निर्माण क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में 2019 में इसी महीने (चार्ट 30) में सीमेंट उत्पादन और स्टील खपत में विस्तार के संकेतकों के साथ तेजी जारी रही। हालांकि जनवरी 2022 में लगातार दूसरे महीने सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन बढ़ती लागत इस क्षेत्र में सुधार के लिए एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।

उड्डयन क्षेत्र ने फरवरी 2022 में रिकवरी दर्ज की। दैनिक घरेलू हवाई अड्डे की औसत दैनिक आय पिछले महीने की तुलना में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.4 लाख रही है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या में भी क्रमिक रूप से 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कार्गो खंड में घरेलू कार्गो के लिए 0.1 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के लिए 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च के पहले पखवाड़े में घरेलू हवाई अड्डे की औसत दैनिक आय में 44.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



सारणी 2 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)								2019 की तुलना में वृद्धि			
क्षेत्र	संकेतक	सित-21	अक्तू-21	नव-21	दिस-21	जन-22	फर-22	नव 21/ नव 19	दिस 21/ दिस 19	जन 22/ जन 19	फर 22/ फर 19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	-8.1	-6.5	-14.8	-1.5	-9.2	-3.4
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-21.1	-27.3	-25.5	-4.2	-29.4	-35.7
	तीन पहिया वाहन बिक्री	53.8	19.1	-6.6	27.0	-8.5	-1.1	-59.7	-47.7	-55.4	-54.8
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	-32.6	-31.3	17.2	3.8	3.5	9.2
	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	24.5	0.9					-0.3			
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	रेलवे माल ढुलाई यातायात	3.6	8.4	6.1	7.2	7.7	6.6	15.6	16.5	20.1	19.7
	पोर्ट कार्गो यातायात	0.5	6.3	-0.2	-0.4	-2.9	-2.7	3.9	4.0	3.7	8.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	10.1	6.7	-1.7	2.0	-6.1		-11.4	-1.1	-14.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	18.1	23.8	11.7	10.5	5.2		-5.0	-3.6	-10.3	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	76.5	68.7	65.5	53.3	-16.2		-17.6	-12.5	-47.8	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	155.9	162.9	140.2	121.7	67.5		-58.6	-54.5	-61.2	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	18.3	14.5	5.9	11.6	9.5	3.5	14.5	29.3	34.9	32.0
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	15.6	14.1	7.3	13.4	11.4	5.1	17.6	33.0	42.5	38.8
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	22.3	15.1	3.9	8.9	6.6	1.0	10.1	24.0	24.5	22.7
	यात्री आगमन	278.8	337.0	255.0	235.5	140.4		-76.9	-75.2	-82.0	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	-3.2	-3.8	-7.1	-7.4	0.6	-3.3	10.1	8.7	18.9	9.9
	सीमेंट उत्पादन	10.8	14.5	-3.6	13.9	13.6		-10.6	5.7	7.0	
पीएमआई संकेतक	विनिर्माण	53.7	55.9	57.6	55.5	54.0	54.9				
	सेवाएँ	55.2	58.4	58.1	55.5	51.5	51.8				

स्रोत : सीएमआईई, सीईआईसी आंकड़े ; आईएचएस बाजार ; एसआईएम ; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त प्लान्ट समिति

हालांकि, संपर्क संवेदी होने के कारण विमानन और पर्यटन क्षेत्र लगातार पीछे रहे हैं। ग्रामीण मांग में गिरावट ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बिक्री को भी प्रभावित किया, क्योंकि दोपहिया वाहन क्षेत्र में संकुचन बढ़ता गया (तालिका 2)।

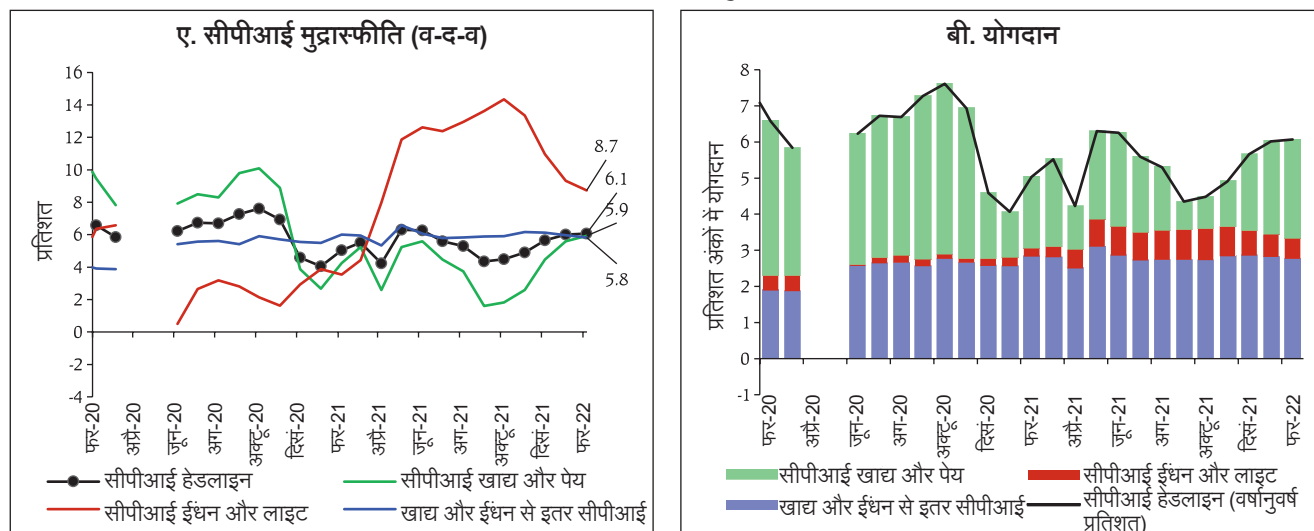
मुद्रा स्फीति

14 मार्च, 2022 को एनएसओ द्वारा जारी फरवरी के अनंतिम सीपीआई डेटा से पता चला है कि फरवरी 2022 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) जनवरी के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 31 ए)। फरवरी में 24 बीपीएस की एक सकारात्मक मूल्य गति (महीने-दर-महीने कीमतों में बदलाव) को आंशिक रूप से 19 बीपीएस के अनुकूल आधारभूत प्रभावों (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने

परिवर्तन) द्वारा ऑफसेट किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी और फरवरी के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में 5 बीपीएस की मामूली वृद्धि हुई।

खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति मुख्य चालक थी, जो जनवरी में 5.6 प्रतिशत के मुकाबले फरवरी में बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई। खाद्य कीमतों की गति में 12 बीपीएस की गिरावट 44 बीपीएस के प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव से अभिभूत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, अंडा, मांस और मछली, सब्जियों और मसालों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, खाद्य तेलों, दूध, गैर-मादक पेय और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति में नरमी आई जबकि दालों, फलों और चीनी में मुद्रास्फीति स्थिर रही।

चार्ट 31 : सीपीआई मुद्रास्फीति



नोट: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के आंकलन

ईंधन मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने, नरमी देखी गई - मुख्य रूप से एलपीजी मुद्रास्फीति में नरमी के कारण, यह फरवरी में जनवरी में 9.3 प्रतिशत से लगभग 5.9 बीपीएस घटकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जबकि मिट्टी के तेल (पीडीएस) के मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई। फरवरी में बिजली की कीमतें अपस्फीति में बनी रहीं। सीपीआई ईंधन (सीपीआई बास्केट में 6.84 प्रतिशत का भार) ने फरवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 9.6 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 31 बी)।

खाद्य और ईंधन¹ को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति अथवा मूल मुद्रास्फीति ने फरवरी में लगभग 15 बीपीएस से 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो एक महीने पहले 6.0 प्रतिशत थी (चार्ट 31 ए)। जहाँ पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, मनोरंजन और मनोरंजन, स्वास्थ्य और परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति कम हुई, तो दूसरी ओर कपड़ों और जूतों, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं तथा शिक्षा उप-समूहों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।

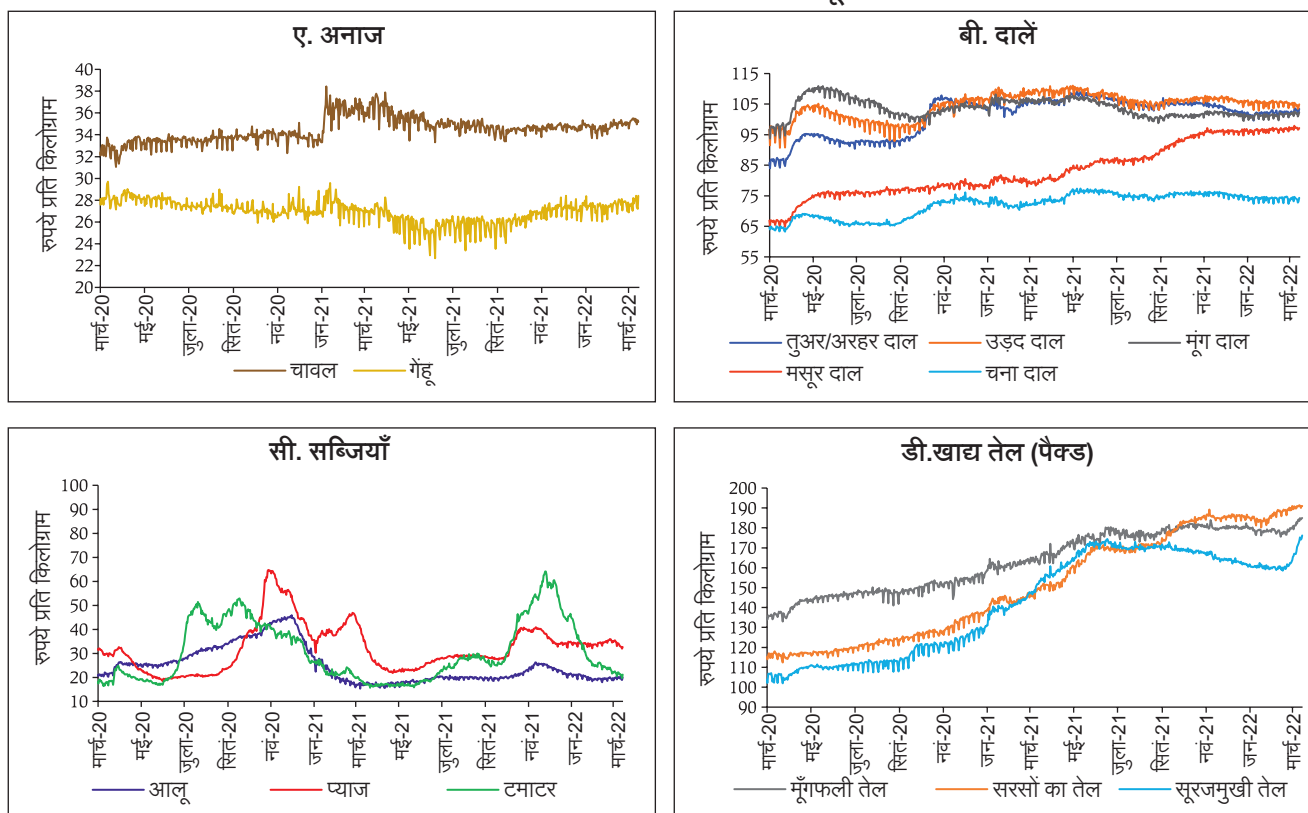
¹ सीपीआई, खाद्य और ईंधन को छोड़कर, हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर निकाला जाता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के मार्च (1-14 मार्च, 2022) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा अनाज की कीमतों में मामूली वृद्धि का संकेत देते हैं। दालों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई। टमाटर और प्याज की कीमतों में और मौसमी सुधार देखा गया, जबकि आलू की कीमतों में मार्च में अब तक वृद्धि हुई है (चार्ट 32)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य मार्च में अब तक (मार्च 1-14, 2022) अपरिवर्तित रहे। हालांकि एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं, मार्च की पहली छमाही में मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई (तालिका 3)।

फरवरी में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत में और वृद्धि हुई, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है। हालांकि, फरवरी में सभी विनिर्माण और सेवाओं में बिक्री कीमतों में मामूली वृद्धि हुई।

चार्ट 32 : डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य



स्रोत : उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ के आंकलन

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		मार्च-21	फर-22	मार्च-22 ^	फर-22	मार्च-22
पेट्रोल	₹/लीटर	93.20	102.87	102.87	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	85.11	90.51	90.51	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	29.37	42.17	46.87	15.4	11.2
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	829.63	910.13	910.13	0.0	0.0

^: 1-14 फरवरी, 2022 की अवधि के लिए।

नोट: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ आंकलन।

IV. वित्तीय स्थितियां

10 फरवरी, 2022 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा दोहराए गए उदार मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दैनिक चलनिधि अवशोषण जनवरी के दूसरे पखवाड़े से फरवरी 2022 के मध्य तक के ₹7.4 लाख करोड़ से बढ़कर फरवरी की दूसरी छमाही से मार्च 2022 तक (ऊपर) औसतन ₹8.4 लाख करोड़ रहा। राज्य चुनाव और रबी कटाई के मौसम से उत्पन्न उच्च रिसाव के बावजूद बढ़ा हुआ सरकारी खर्च इस अवधि में प्रचलन में मुद्रा में चलनिधि का प्रमुख स्वायत्त चालक बन गया। नियत दर रिवर्स रेपो विंडो के तहत औसत दैनिक अवशोषण ₹1.7 लाख करोड़ था, जबकि कुल अवशोषण का बड़ा हिस्सा परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों

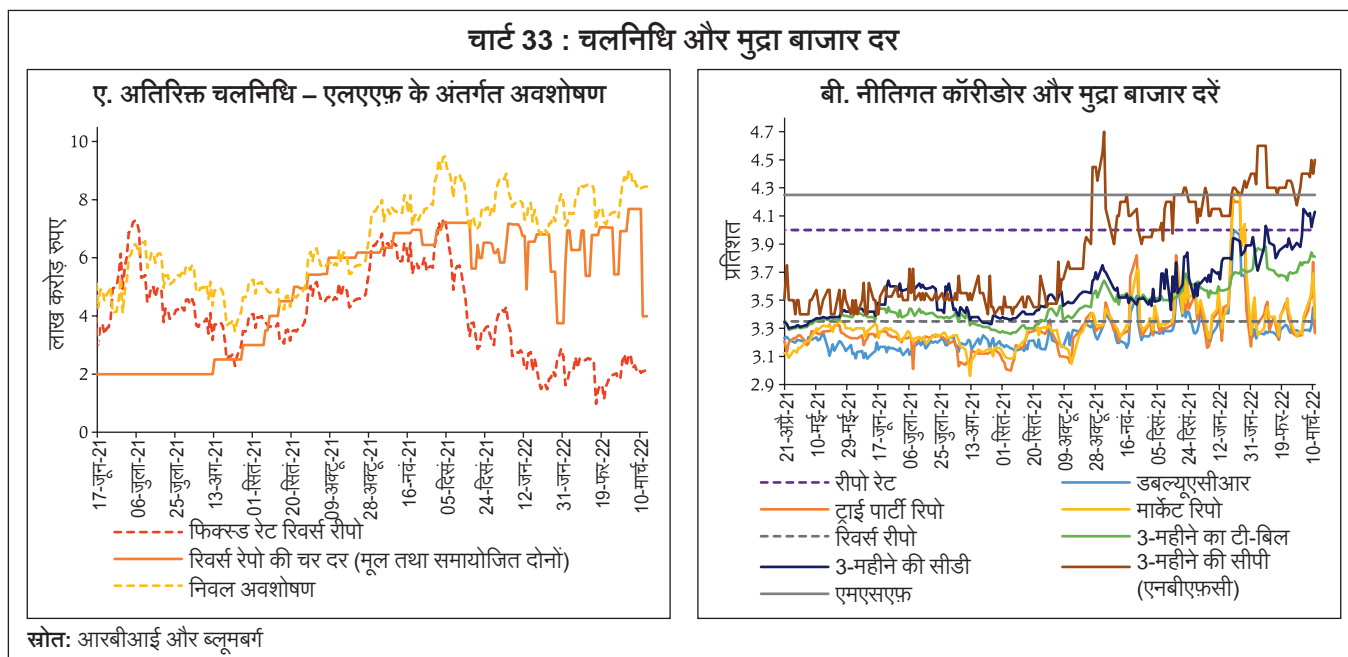
(मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से प्रभावित हुआ था, जो अधिशेष चलनिधि के दीर्घावधि (चार्ट 33ए) की ओर स्थानांतरित होने से चलनिधि पुनर्संतुलन को दर्शाता है।

बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), त्रि-पक्ष रेपो और बाजार रेपो दर रिवर्स रेपो दर के करीब होने के साथ, रातोंरात मुद्रा बाजार दरों को कम कर दिया। 3 महीने के टी-बिल और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जैसे लंबी अवधि के मुद्रा बाजार के लिखतों पर ब्याज दरें, हालांकि, फरवरी के दूसरे पखवाड़े से 11 मार्च, 2022 तक 38 बीपीएस और 60 बीपीएस के औसत रिवर्स रेपो दर पर उनके संबंधित फैलाव के साथ अधिक रही। इसी तरह, 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी)-एनबीएफसी दरें सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर (चार्ट 33 बी) से ऊपर बनी रहीं। सीडी और सीपी बाजारों में मजबूत प्राथमिक बाजार गतिविधि ने दरों को ऊंचा बनाए रखा है। ऋण चक्र में पुनरुद्धार के साथ, सीडी जारी करके निधि जुटाना अप्रैल-अक्तूबर 2021 के दौरान 61,983 करोड़ की तुलना में नवंबर 2021-जनवरी 2022 तक बढ़कर 65,298 करोड़ हो गया।

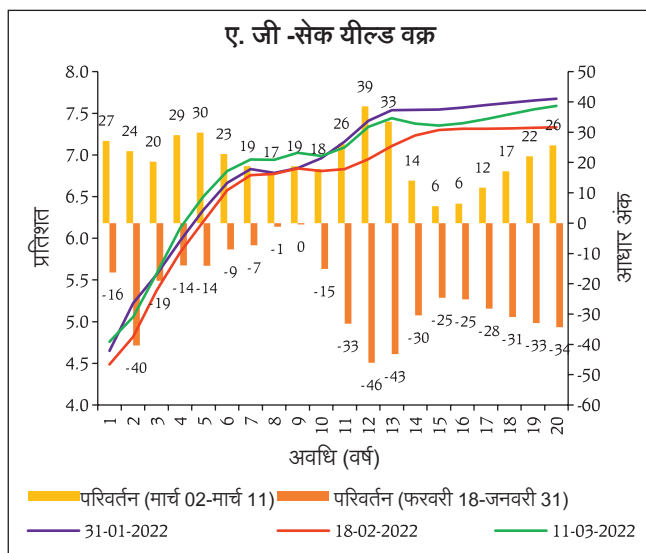
साप्ताहिक नीलामियों के निरस्त हो जाने के बाद बॉन्ड बाजार का लाभ कम हो गया। 10-वर्षीय बेंचमार्क जी सेक पर प्रतिफल 18 फरवरी (चार्ट 34a) के 6.6 प्रतिशत के निचले स्तर की तुलना में 11 मार्च, 2022 को 6.86 प्रतिशत तक दृढ़ हो गया। यूक्रेन संघर्ष से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल ने बाजार के रुख को हिला दिया। प्राथमिक बाजार में, सरकार ने 25 फरवरी को आयोजित अंतिम साप्ताहिक नीलामी के साथ 2021-22 के लिए अपना उधार कार्यक्रम पूरा किया। कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल दृढ़ होकर, जी-सेक प्रतिफल (चार्ट 34 बी) में परिवर्तन को ट्रैक करता है।

समग्र मौद्रिक और ऋण स्थितियों को देखें तो, आरएम का सबसे बड़ा घटक प्रचलन में मुद्रा के साथ, आरक्षित धन (आरएम) में, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 11 मार्च, 2022 (एक साल पहले 16.3 प्रतिशत) के अनुसार समान विकास दर (एक साल पहले 19.2 प्रतिशत) को बनाए रखते हुए 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। 25 फरवरी, 2022 (एक साल पहले 12.8 प्रतिशत) तक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बैंकों

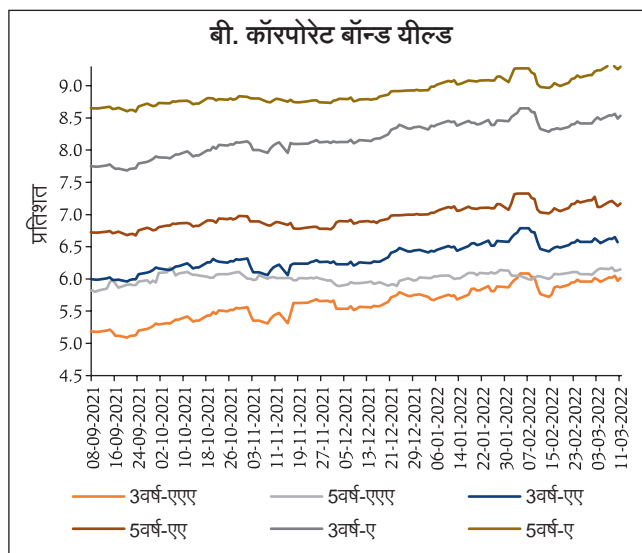
चार्ट 33 : चलनिधि और मुद्रा बाजार दर



चार्ट 34 : बॉन्ड यील्ड्स में परिवर्तन



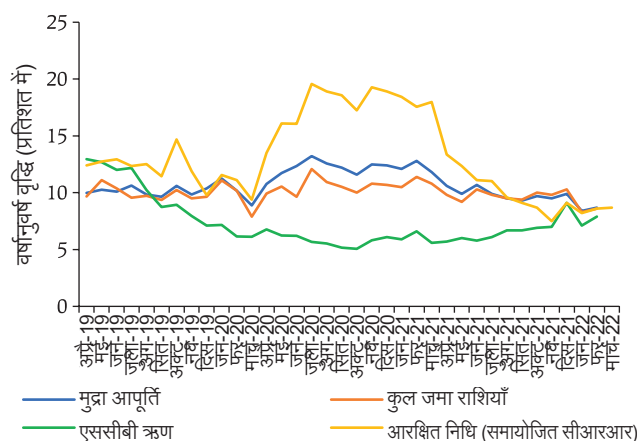
स्रोत : ब्लूमबर्ग।



के साथ कुल जमा में 8.6 प्रतिशत (एक साल पहले 11.4 प्रतिशत) की वृद्धि से प्रेरित थी। वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि अप्रैल 2020 के बाद पहली बार नवंबर 2021 में 7.0 प्रतिशत के स्तर को पार करते हुए, 25 फरवरी, 2022 को बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई (एक साल पहले 6.6 प्रतिशत प्रति वर्ष) [चार्ट 35]।

मार्च 2020 के बाद से, एससीबी की निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की एक साल की औसत सीमांत लागत में संघयी रूप से 95 बीपीएस की कमी आई है। 115 बीपीएस की रेपो दर में कटौती के जवाब में, मार्च 2020 से जनवरी 2022 (चार्ट 36) की अवधि के दौरान ताजा और बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 140 बीपीएस और 122 बीपीएस की गिरावट आई।

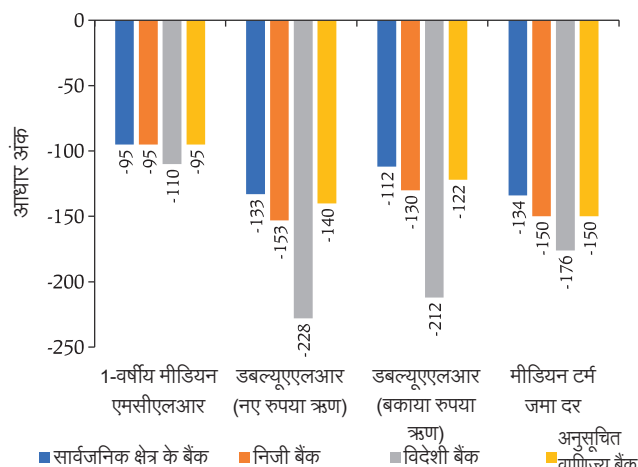
चार्ट 35 : मौद्रिक और ऋण कुल राशियाँ



नोट: 1. ये आंकड़े धन आपूर्ति, सकल जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शक्रवार से संबंधित हैं; और आरक्षित निधि के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शक्रवार से संबंधित हैं।
2. तथापि, मार्च के लिए आरक्षित निधि से संबंधित आंकड़े 11 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 36 : उधार और जमा दरों में प्रसार (मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक)

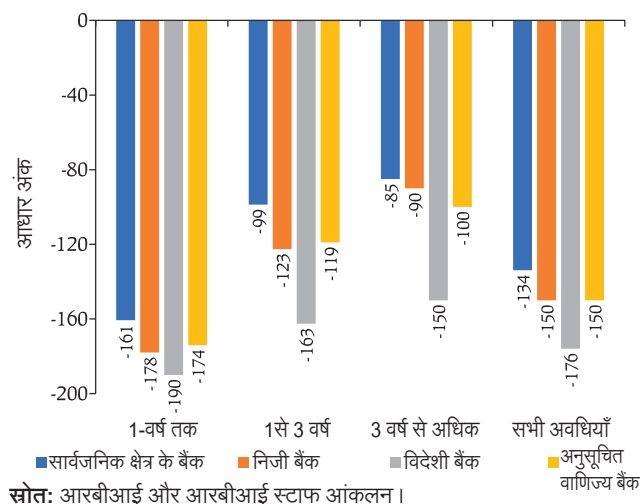


नोट: डब्ल्यूएलआर से संबंधित नवीनतम आंकड़े जनवरी 2022 से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ आंकलन।

ऋण माँग में वृद्धि के साथ ही, कुछ अनुसूचित सहकारी बैंकों ने सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। मार्च 2020 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मध्यावधि जमा दर (एमटीडीआर) में नीति दर में कमी के प्रभाव अंतरण की सीमा 154 बीपीएस रही, जो फरवरी 2022 में मामूली रूप से घटकर 150 बीपीएस हो गई। एक वर्ष तक की परिपक्वता की अल्पावधि जमाराशियों के मामले में 174 बीपीएस की प्रत्यक्ष गिरावट देखी जा सकती है। घरेलू बैंकों में, मजबूत जमा वृद्धि के कारण निजी बैंकों द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में सावधि जमा दरों में प्रभाव अंतरण को उच्च बनाए रखने में सक्षम किया है (चार्ट 37)।

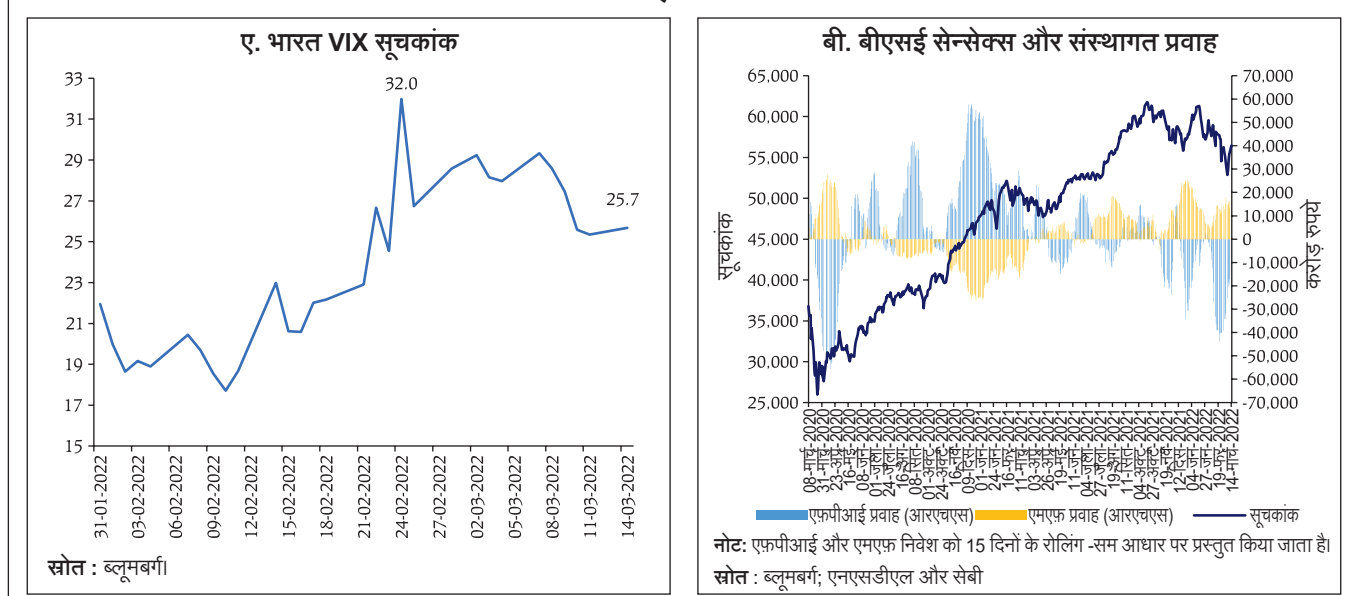
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा प्रशासित और निर्धारित की जाती हैं। ये प्रशासित ब्याज दरें एक अंतराल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल से जुड़ी होती हैं और तुलनीय परिपक्वता के सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल के ऊपर और 0-100 बीपीएस के फैलाव के आधार पर तिमाही अंतराल पर निर्धारित की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2022 को 2022-23 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत लिखतों (एसएसआई) पर ब्याज दरों की समीक्षा करने की उम्मीद है। एसएसआई पर मौजूदा ब्याज दरों को सूत्र-आधारित दरों के साथ संरेखित करने के लिए 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 9-118 बीपीएस की सीमा में कम करने की आवश्यकता है।

चार्ट 37 : मध्यवर्ती अवधि की जमा दरों में परिपक्वता के आधार पर प्रसार (मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक)



फरवरी 2022 में, घरेलू इक्विटी बाजार रूस-यूक्रेन संघर्ष के इर्द-गिर्द की घटनाओं के कारण वैश्विक इक्विटी बाजारों में उत्पन्न उथल-पुथल (चार्ट 38) के अनुसार उलझे हुए थे। 24 फरवरी, 2022 को तेज बिकवाली दर्ज करते हुए, घरेलू इक्विटी बाजार महीने की दूसरी छमाही में लगातार नीचे गिरा।

चार्ट 38: इक्विटी बाजार

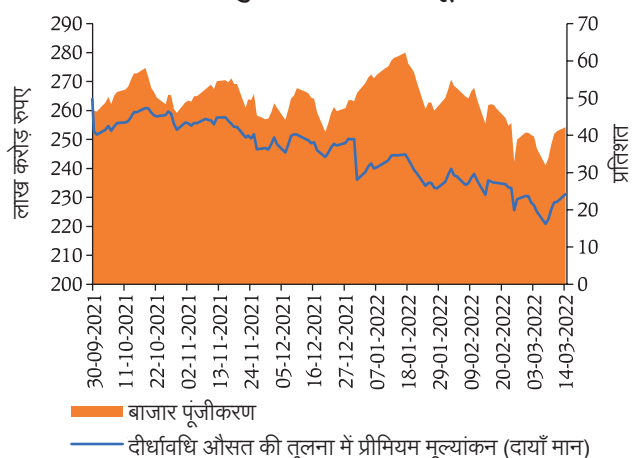


घरेलू इक्विटी दबाव में बने रहे और मार्च की शुरुआत में और गिरावट आई क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के दुष्प्रभावों और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से बाजार के रुख पर असर पड़ा। इसके बाद जिस कीमतों में मामूली नरमी के बीच बाजार में सुधार हुआ। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स जनवरी के अंत से 2.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 14 मार्च, 2022 को 56,486 पर बंद हुआ है।

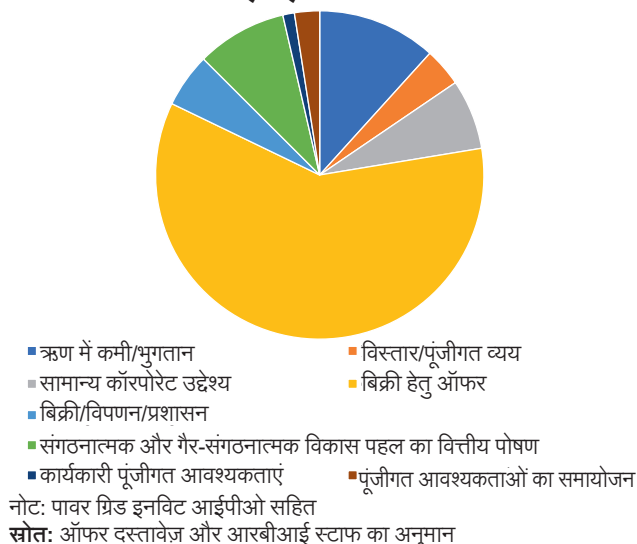
इक्विटी में हालिया गिरावट और कॉरपोरेट आय में लचीली वृद्धि के बाद, बीएसई सेंसेक्स के मूल्य-से-आय (पी / ई) अनुपात में गिरावट आई और इसके दीर्घकालिक औसत से मूल्यांकन प्रीमियम में कमी आई है। 24 फरवरी, 2022 को बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 26 अगस्त, 2021 (चार्ट 39) के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर आ गया।

प्राथमिक बाजारों में, कंपनियों ने अब तक (फरवरी 2022 तक) 148 पब्लिक / राइट्स इश्यू के माध्यम से ₹ 1.38 लाख करोड़ जुटाए। इस वित्तीय वर्ष में धन जुटाने वाली सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के माध्यम से मुख्य कंपनियों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि जुटाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तथापि आरंभिक संग्रहण ने कंपनियों को ऋण और वित्त विकास आवश्यकताओं को कम करने में सक्षम बनाया है। (चार्ट 40)।

चार्ट 39 : इक्विटी बाजार पूंजीकरण और दीर्घावधि औसत की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन



चार्ट 40 : 2021-22 में आईपीओ के माध्यम से उठाई गई राशि का प्रयोग

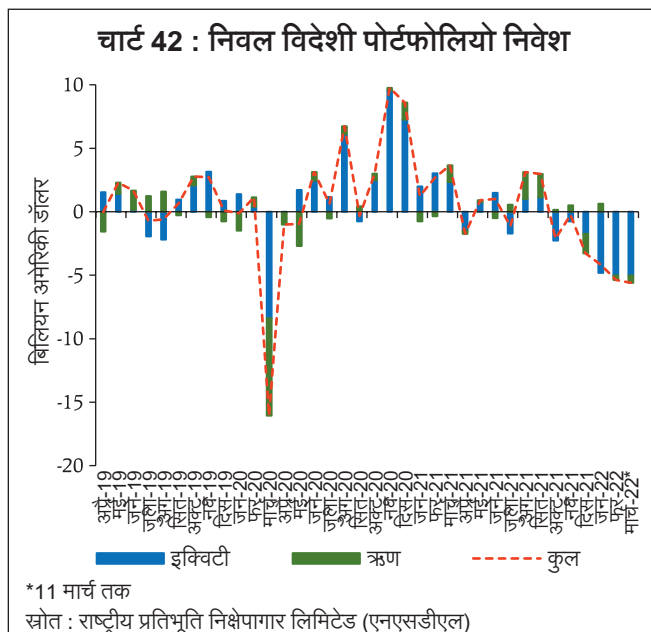
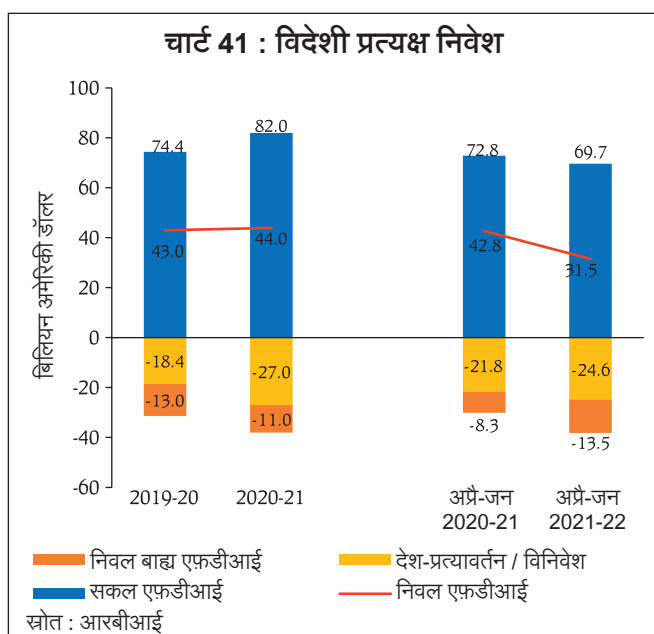


भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बहुप्रतीक्षित आईपीओ का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस हाल ही में बाजार नियामक के पास दायर किया गया था, जिसमें 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के 3,16,249,885 इक्विटी शेयरों तक के ओएफएस का संकेत दिया गया था। एलआईसी आईपीओ भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने के लिए तैयार है, और इसलिए, आईपीओ का सही समय महत्वपूर्ण है। निर्गम आकार का 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होने के कारण एलआईसी आईपीओ की सफलता के लिए उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। हाल ही में, घरेलू इक्विटी बाजारों में खुदरा भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिसका अनुमान इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जनवरी 2022) में खोले गए 289 लाख नए डीमैट खातों से लगाया जा सकता है। एलआईसी आईपीओ इक्विटी बाजारों की पहुंच को और अधिक गहरा करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। एलआईसी के विशाल पॉलिसीधारक आधार में बड़ी संख्या में नए निवेशकों को पूंजी बाजार में लाने की क्षमता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक बचत उत्पादों पर भरोसा किया है। सरकार की विनिवेश योजनाओं के लिए पूंजी बाजार का गहरा होना भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए, प्रमुख बाजार अवसंरचना संस्थानों में निवेशकों का विश्वास जगाना महत्वपूर्ण है।

² <https://www.financialexpress.com/market/ipo-news/lic-ipo-takes-equity-cult-deeper-in-india/2443069/>

मजबूत ताजा इक्विटी निवेश के कारण, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) जनवरी 2022 में 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जनवरी 2021 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ गया, जो कि वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी अंतर्वाह से काफी अधिक था। 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, सकल एफडीआई अंतर्वाह 69.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (चार्ट 41) के साथ मजबूत स्थिति में था। एक साल पहले के 42.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में निवल एफडीआई 31.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत से बढ़ते हुए एफडीआई को दर्शाता है। विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, और खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों में अधिकांश निवेश प्राप्त हुआ और यह 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) में कुल इक्विटी प्रवाह का 70.4 प्रतिशत हिस्सा था।

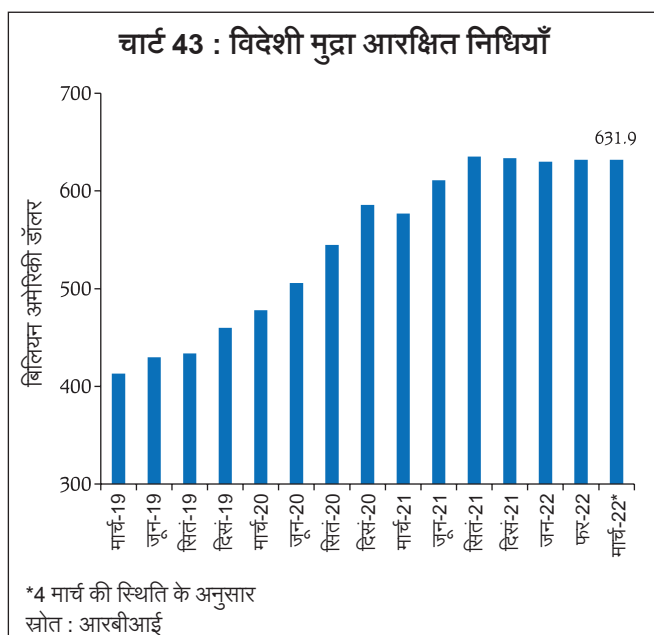
बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने घरेलू बाजार से धन निकालना जारी रखा। फरवरी में इक्विटी क्षेत्र में लगातार पांचवें महीने बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि जनवरी के दौरान निवल खरीदार रहने के बाद, एफपीआई फरवरी में ऋण बाजार में निवल विक्रेता बन गए। फरवरी 2022 में घरेलू बाजार से निवल एफपीआई बहिर्वाह 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट 42)।



अंतर-कंपनी उधारी को छोड़कर, भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) का निवल संवितरण, 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान निवल चुकोती दर्ज करने के बाद, जनवरी 2022 के दौरान 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। जनवरी 2021 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर-कंपनी उधार सहित निवल संवितरण 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। जनवरी 2022 के दौरान, उधार की एक बड़ी राशि का उपयोग कार्यकारी पूंजी, पुराने ईसीबी के लिए आगे उधार देने/उप-उधार और पुनर्वित्त के लिए किया गया था।

लगातार तीन महीनों तक संकुचन दर्ज करने के बाद फरवरी 2022 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। 4 मार्च, 2022 को US\$631.9 बिलियन के साथ, 2021-22 (चार्ट 43) के लिए उक्त भंडार अनुमानित लगभग 12.4 महीनों के आयात के बराबर था।

विदेशी मुद्रा बाजार में, एफपीआई बहिर्वाह पर अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच फरवरी 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) में 0.7 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई। 7 मार्च, 2022 को जब कच्चे तेल की कीमतें 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, तब INR 76.92 प्रति अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर तक गिर गया। भारतीय रुपये का

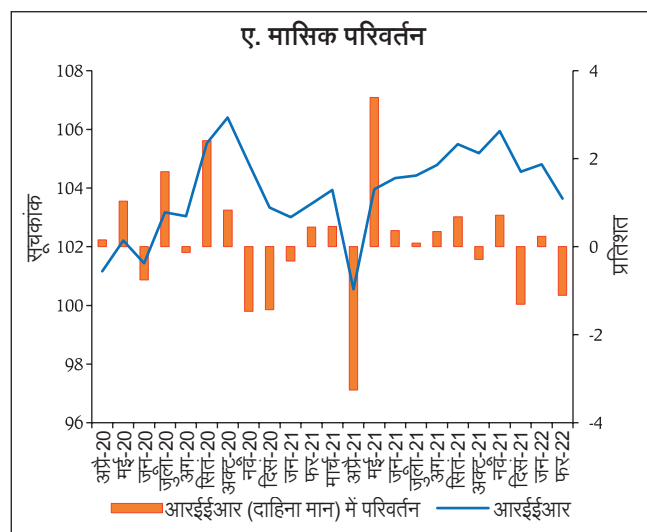


नाममात्र और वास्तविक दोनों प्रभावी स्थितियों (40-मुद्रा बास्केट) में मूल्यहास INR के उतार-चढ़ाव में परिलक्षित हुआ, जिसमें फरवरी 2022 में एक महीने पहले के स्तर से क्रमशः 0.8 और 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी (चार्ट 44ए और 44बी)।

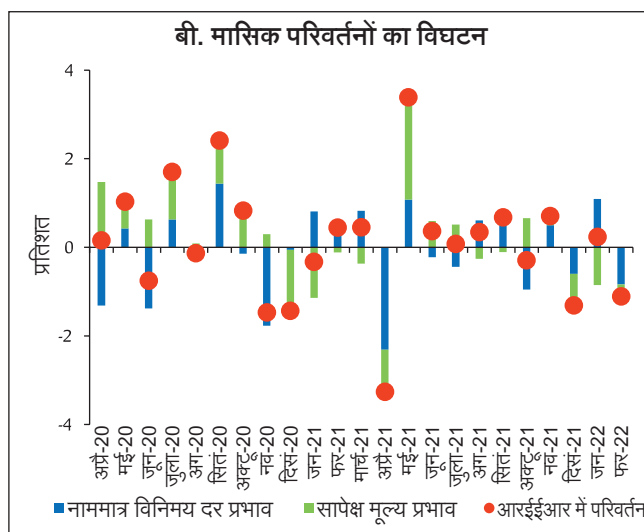
भुगतान प्रणाली

फरवरी और मार्च 2022 (11 मार्च तक) में डिजिटल भुगतान में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के लेन-देन में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में लगातार दो अंकों की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) होती रही, जो कि वर्तमान आर्थिक सुधार के अनुरूप है। खुदरा भुगतानों का सभी भुगतान माध्यमों में बहुत अधिक विस्तार हुआ (तालिका 4)। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने लेनदेन की मात्रा और मूल्य में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि को बनाए रखा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) ने भी उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन किया। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के तहत लेनदेन में मात्रा और मूल्य में तीन अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) में लगातार वृद्धि हुई। तीसरी लहर के बीच उपभोक्ता और व्यावसायिक व्यय में लचीलापन प्रदर्शित करते हुए, कार्ड लेनदेन³ के औसत टिकट आकार ने 22.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। तीसरी लहर की गिरावट के

चार्ट 44 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) में मासिक गतिविधियाँ (आधार : 2015-16 = 100)



नोट : फरवरी 2022 के आंकड़े अंतिम हैं
स्रोत : आरबीआई



³ यह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन के कुल मूल्य को दोनों प्रकार के कार्डों के माध्यम से लेनदेन की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।

सारणी 4 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

	लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)				लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)			
	जन- 2021	जन- 2022	फर- 2021	फर- 2022	जन- 2021	जन- 2022	फर- 2021	फर- 2022
आरटीजीएस	14.1	15.7	18.4	14.3	-7.2	13.9	0.7	14.1
एनईएफटी	10.3	26.2	13.6	28.8	12.3	12.8	15.1	15.1
यूपीआई	76.5	100.5	73.0	97.5	99.4	93.0	91.0	94.5
आईएमपीएस	33.5	27.0	28.7	32.0	33.1	34.1	28.3	39.7
एनएसीएच	-14.6	28.8	-18.4	28.0	11.6	26.4	-1.3	30.2
एनईटीसी	60.4	54.8	44.3	53.3	48.1	50.0	38.8	42.0
बीबीपीएस	84.0	130.2	89.1	121.2	106.0	148.8	115.7	136.2

स्रोत : आरबीआई

साथ व्यवसायों के नकदी प्रवाह में सुधार के कारण, एनएसीएच डेबिट बाउंस दर⁴ वर्ष-दर-वर्ष⁵ जनवरी 2022 में मूल्य के हिसाब से 400 बीपीएस घटकर 23.4 प्रतिशत हो गया। यह ऋण अपराध दर में कमी का संकेत हो सकता है। डिजिटल भुगतान अवसंरचना (जनवरी 2022 तक) के आंकड़ों में स्थिर यूपीआई त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड, और प्रीपेड भुगतान विलेख (पीपीआई) वॉलेट और कार्ड की संख्या में लगातार वृद्धि दिखाई। यूपीआई और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से पीपीआई की अंतर-परिचालन सुविधा के कारण, परिणामी समंजस्य के आधार पर इन तरीकों के माध्यम से लेनदेन में त्वरित वृद्धि होने की उम्मीद है।

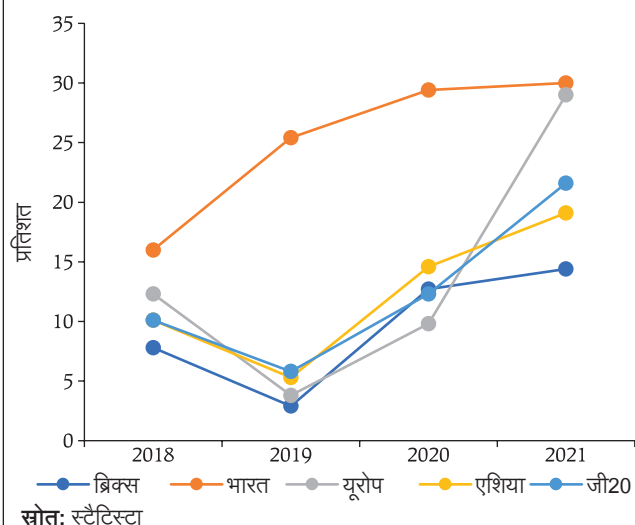
दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में, डिजिटल वाणिज्यिक लेनदेन मूल्य⁶ में भारत की वार्षिक वृद्धि 2018 (चार्ट 45) के बाद से लगातार अधिक रही है। 2021 में, भारत के डिजिटल वाणिज्य लेनदेन में 30 प्रतिशत की वृद्धि वैश्विक विकास दर⁷ से 760 बीपीएस अधिक थी। स्टार्टअप्स ने भारत के डिजिटलीकरण को

⁴ एनएसीएच इंटरबैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा के लिए एक वेब-आधारित समाधान है जो बारंबार और आवधिक प्रकृति के हैं। एनएसीएच डेबिट में ईएमआई, बीमा प्रीमियम आदि शामिल हैं। बाउंस दर असफल ऑटो-डेबिट लेनदेन का प्रतिशत है।

⁵ <https://www.npci.org.in/what-we-do/nach/product-statistics/2021-22/mtd-nach-analytics>

⁶ डिजिटल वाणिज्यिक क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से किए गए सभी उपभोक्ता लेनदेन शामिल हैं, जो सीधे उत्पादों और सेवाओं के लिए ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित हैं। ऑनलाइन लेनदेन विभिन्न भुगतान विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित भुगतानों को बाहर रखा गया है।

चार्ट 45: भारतीय डिजिटलीकरण का वैश्विक तुलना : डिजिटल वाणिज्यिक लेनदेन मूल्य में वृद्धि



आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 43 यूनिर्कॉर्न स्टार्टअप (12 फिनटेक सहित) के साथ भारत ने 2021 में यूनिर्कॉर्न क्लब में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया, जो केवल यूएस और चीन⁸ के बाद है।

वित्तीय साक्षरता हासिल करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 14-18 फरवरी 2022 के बीच “गो डिजिटल, गो सिक्क्योर” थीम के साथ अपना वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया। डिजिटल लेनदेन में सुविधा एवं सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। यह, वित्तीय जागरूकता, सकारात्मक धारणा, सुरक्षा और डिजिटल भुगतान अवसंरचना को अपनाने में अधिकाधिक विश्वास के महत्व को स्थापित करने वाले हालिया शोध द्वारा समर्थित है⁹। इन प्रयासों को एनपीसीआई के यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह¹⁰ के साथ जोड़ा गया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नेपाल¹¹ में प्लेटफॉर्म को सक्षम

⁷ <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-payments/digital-commerce/worldwide?comparison%5b%5d=india>

⁸ <https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/startups/start-up-perspectives-india-start-up-deals-tracker.pdf>

⁹ <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42786-020-00024-z.pdf>

¹⁰ <https://www.npci.org.in/PDF/npci/press-releases/2022/NPCI-Press-Release-NPCI-Announces-UPI-Safety-and-Awareness-Week-and-Month.pdf>

करके यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धी हासिल की थी।

V. निष्कर्ष

वर्तमान भू-राजनीतिक संकट ने वैश्विक समष्टि-आर्थिक वित्तीय परिदृश्य की अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, यहां तक कि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है।

तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और अस्थिर वित्तीय बाजार की स्थितियों ने अभी भी अपूर्ण वैश्विक सुधार के लिए नई बाधाएं खड़ी की हुई हैं। इस परीक्षा की घड़ी के बीच, भारत घरेलू मोर्चे पर लगातार प्रगति कर रहा है क्योंकि यह तीसरी लहर से उबर रहा है। भारत के समष्टि-आर्थिक आधार मजबूत बने हुए हैं। वैश्विक घटनाक्रम फिर भी स्पिलओवर के मामले में नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है।

¹¹ <https://www.npci.org.in/PDF/npci/press-releases/2022/NIPL-Press-Release-Gateway-Payment-Service-and-Manam-Infotech-join-hands-to-deploy-UPI-समाधान-इन-नेपाल.pdf>

केंद्रीय बजट 2022-23: कुछ सुखद राजकोषीय अंकगणित*

वर्ष 2022-23 के लिए बजट में विकास पर जोर दिया गया है, जो चक्रिय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटे में कमी में परिलक्षित होता है। फिर भी, सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत का शुद्ध राजकोषीय आवेग 2022-23 के अंत तक काम करना जारी रखेगा। पर्याप्त बफर्स के निर्माण की रणनीति 2022-23 के लिए निर्धारित बजटीय लक्ष्यों को सुरक्षित करने और वैश्विक स्पिलओवर से निपटने के लिए हेडरूम बनाने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हुए, राजकोषीय नीति रणनीति में ऋण में कमी को प्रमुखता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

परिचय

वित्त मंत्री का बजट भाषण और संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक निर्णायक क्षण होता है और समष्टि आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण के लिए एक धुरी प्रदान करता है। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट राजकोषीय समेकन के नवीनीकरण के साथ विकास पर जोर देने के अपने अभियान में उल्लेखनीय है। व्यापक विषय महामारी से उबरने को एक ठोस आधार पर रखना है। बजट अगले 25 वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि भी निर्धारित करता है जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष तक पहुंचेगा।

वर्ष 1981 में, एक मौलिक पत्र ने कुछ 'अग्रिय मुद्रावादी अंकगणित' (सार्जेंट और वालेस, 1981) को यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत किया कि राजकोषीय प्रभुत्व के तहत वृहद आर्थिक स्थिरता का नुकसान हुआ है। इसके विपरीत, बजट 2022-23 के केंद्र में कुछ 'सुखद' राजकोषीय अंकगणित के साथ वित्तीय समेकन पर बल दिया गया है और वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक - विकास को बढ़ावा देने के लिए कैपेक्स पुश प्रदान करते हुए

* इस लेख को आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के सक्षम सूद, इप्सिता पाढ़ी, विचित्रानंद सेठ और डॉ. समीर रंजन बेहरा ने डॉ. माइकल देवव्रत पात्र के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया है। लेखक डॉ. देव प्रसाद रथ और डॉ. सितीकंठ पटनायक को उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए धन्यवाद। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

12.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय में वृद्धि 0.9 प्रतिशत पर बजट की गई है।

वित्तीय बाजारों की अदूरदर्शी प्रतिक्रियाओं के समाप्त होने के साथ, बजट पर एक अधिक जानकारी प्रदान करने वाली टिप्पणी सार्वजनिक बहस में शामिल की जा अरही है। यह टिप्पणी में कुल मिलाकर तीन मुख्य व्यापक कारकों का हवाला देते हुए, बजट की सराहना की गई है: मान्यताओं और अनुमानों में यथार्थवाद; बजट लेखांकन में पारदर्शिता [अतिरिक्त-बजटीय संसाधन (ईबीआर) रूट का उन्मूलन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिये जाने वाले राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) ऋणों को बंद करना]; और विवेक के आधार पर एक विकास अभिमुखीकरण। इससे बजट की विश्वसनीयता बढ़ती है। इसमें विभिन्न स्तरों पर बफर्स के निर्माण की रणनीति को जोड़ा जा सकता है, भविष्य के झटकों से निपटने के लिए राजकोषीय प्राधिकरण को लैस करना और 2022-23 के लिए बजटीय लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना।

शेष आलेख छह खंडों में विभाजित है। निम्नलिखित खंड बजट की अंतर्निहित बातों की पड़ताल करता है। खंड III और IV क्रमशः बजटीय प्राप्ति और व्यय के विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। खंड V बकाया ऋण के वित्तपोषण और स्थिरता में मुद्दों की जांच करता है। खंड VI कुछ समापन टिप्पणियों को निर्धारित करता है।

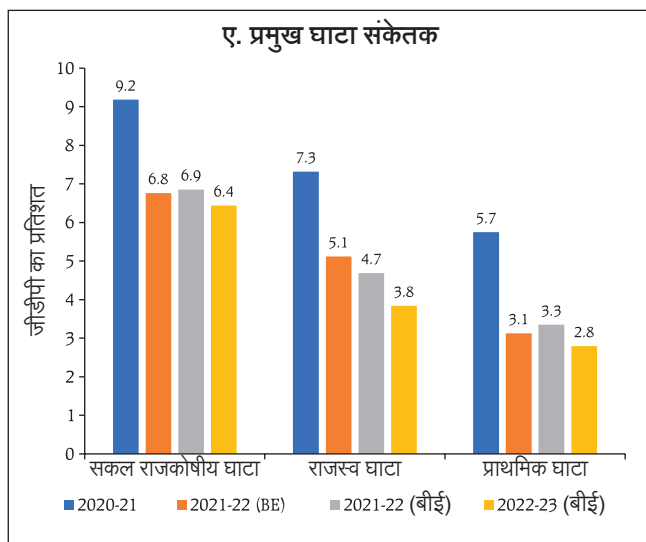
II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदान किए गए बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन के चरणबद्ध रोलबैक में दो साल की अवधि में जीडीपी¹ के 2.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट का अनुमान है। .

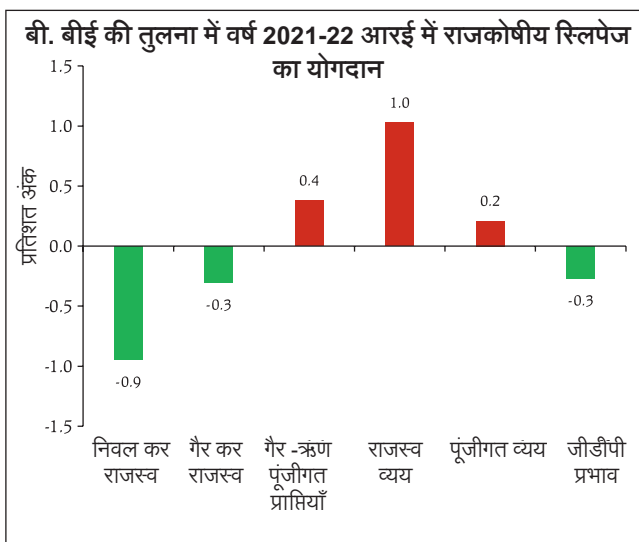
2021-22 (आरई) में, केंद्र सरकार का शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान (बीई) से ₹2.2 लाख करोड़ से अधिक था और गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से ₹70,763 करोड़ अधिक था,

¹ जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (बीई) में 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। बजट में, 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया गया है ₹2,58,00,000 करोड़, 2021-22 के लिए अनुमानित जीडीपी ₹2,32,14,703 करोड़ (पहले अग्रिम अनुमान) पर 11.1 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए। केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के बाद जारी किया गया दूसरा अग्रिम अनुमान ₹2,36,43,875 करोड़ से अधिक रखा गया है। हालांकि, यह लेख केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित दस्तावेजों में जारी आंकड़ों के साथ तुलना की सुविधा के लिए विश्लेषण के लिए 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमानों का उपयोग करता है।

चार्ट 1 : घाटा संकेतक और राजकोषीय स्लिपेज



स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़



इसके अलावा गैर-कर राजस्व बजट अनुमान में रिजर्व बैंक द्वारा बजट किए गए अधिशेष अंतरण भी जोड़े गए। दूसरी ओर, महामारी की दूसरी लहर (राजस्व और पूंजीगत व्यय, क्रमशः ₹ 2.38 लाख करोड़ और ₹ 48,475 करोड़ को पार गया) के मद्देनजर उच्च खर्च और विनिवेश प्राप्ति में ₹ 97,000 करोड़ की कमी ने जीएफडी-जीडीपी अनुपात (चार्ट 1ए और बी) में 0.1 प्रतिशत अंक की गिरावट के साथ थोड़ा योगदान दिया।

हेडलाइन राजकोषीय घाटा आम तौर पर एक ओर अंतर्निहित आर्थिक चक्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जिस पर बजटकर्ता का थोड़ा नियंत्रण होता है, और दूसरी ओर व्यापक मैक्रो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए असतत नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटे को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: व्यापार चक्र से संबंधित चक्रीय घटक (कर राजस्व और बेरोजगारी लाभ जैसे स्वचालित स्टेबलाइजर्स) और संरचनात्मक घटक, जो आर्थिक वातावरण से स्वतंत्र राजकोषीय नीति में विवेकाधीन परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शाता है।

चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक घाटे के पहले अंतर को राजकोषीय आवेग के रूप में जाना जाता है, यह एक उपाय है कि राजकोषीय नीति किस हद तक मांग को जोड़ रही है या वापस ले रही है। उत्पादन अंतराल के संबंध में राजस्व / व्यय की लोच -

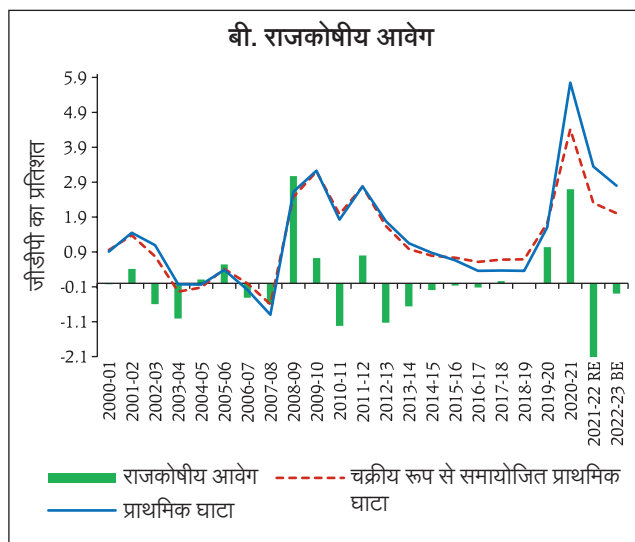
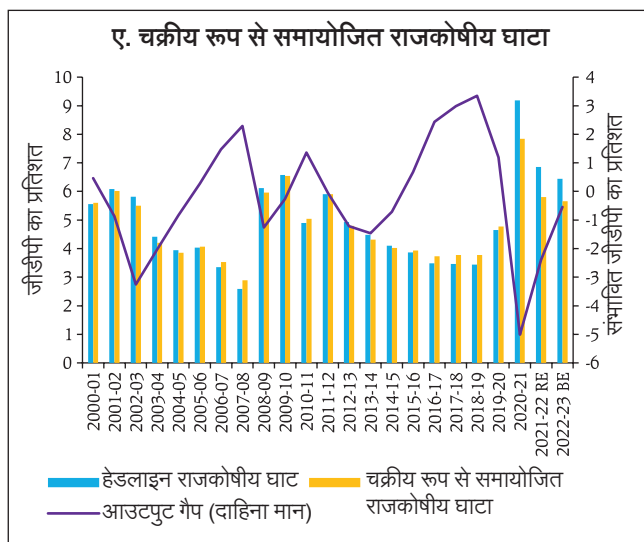
संभावित उत्पादन ² से वास्तविक उत्पादन का विचलन - चक्रीय प्रभाव ³ की ताकत को परिभाषित करता है।

भारत में, यह कर राजस्व है जो चक्रीयता प्रदर्शित करता है। गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति (ऋण/अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्ति शामिल हैं) व्यापार चक्र के लिए अभेद्य हैं। राजस्व लोच 1.5 पर अनुमानित है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उत्पादन अंतराल के अनुपात से अधिक प्रतिक्रिया करता है। व्यय से संबंधित स्वचालित स्टेबलाइजर्स (उन्नत देशों के विपरीत जहां बेरोजगारी लाभ सीधे व्यापार चक्र से जुड़े होते हैं) के अभाव में, व्यय लोच को शून्य माना जा सकता है, अर्थात्, सभी व्यय को विवेकाधीन के रूप में देखा जाता है। इन लोचों का उपयोग करते हुए, 2022-23 (बीई) में चक्रीय रूप से समायोजित जीएफडी 5.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो 2021-22 (आरई) में 5.8 प्रतिशत और 2020-21 में 7.8 प्रतिशत से कम है। इस

² संभावित उत्पादन को उत्पादन के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक अर्थव्यवस्था सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके मध्यम अवधि में स्थायी रूप से उत्पादन कर सकती है। आउटपुट गैप वास्तविक और संभावित आउटपुट के बीच का अंतर है (रबनाल, 2015)।

³ $R^* = R \left(\frac{Y^*}{Y} \right)^{\epsilon_r}$, $E^* = E \left(\frac{Y^*}{Y} \right)^{\epsilon_e}$ जहां आर और ई वास्तविक राजस्व और व्यय हैं; आर * और ई * चक्रीय रूप से समायोजित राजस्व और व्यय हैं; Y वास्तविक आउटपुट है; वाई * संभावित आउटपुट है और क्रमशः आउटपुट गैप (Fedelino et al., 2009) के संबंध में राजस्व और व्यय का लचीलापन हैं।

चार्ट 2 : चक्रीय रूप से समायोजित घाटा



स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़ और लेखक के आंकलन

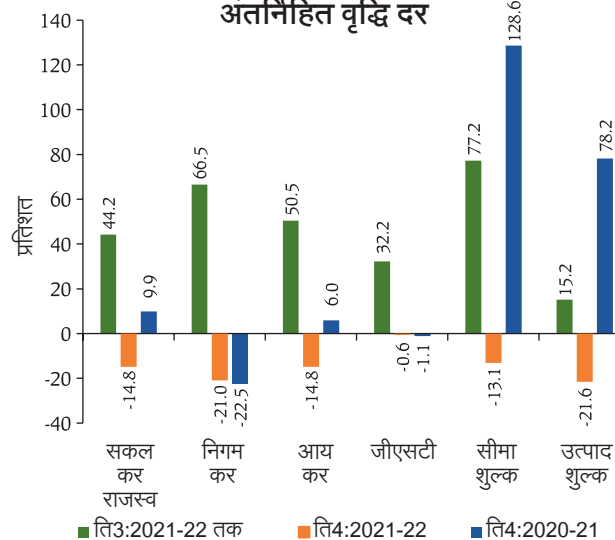
प्रकार, चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटे में दो वर्षों में 2.2 प्रतिशत अंक के क्रम में एक मॉडरेशन है (असमायोजित और व्यापक रूप से ज्ञात सकल राजकोषीय घाटे में कोर प्रतिक्रिया में कमी के तीन-चौथाई से अधिक), जो बजटकर्ता द्वारा वास्तविक समेकन को सुरक्षित करने के लिए निम्न द्वारा दृढ़ रणनीतिक कार्यों को इंगित करता है। फिर भी, सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत का शुद्ध राजकोषीय आवेग 2022-23⁵ (चार्ट 2ए और बी) के अंत तक काम करना जारी रखेगा।

III. प्रसियां

वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान सकल कर राजस्व की वृद्धि को 24.1 प्रतिशत (अनुबंध 1) पर रखते हैं। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) 44.2 प्रतिशत की वृद्धि पहले ही हासिल की जा चुकी है, जिसका अर्थ है कि सकल कर राजस्व 2021-22 की चौथी तिमाही⁶ (चार्ट 3) में 14.8 प्रतिशत घट जाना चाहिए! ऐतिहासिक रिकॉर्ड इंगित

करता है कि पिछली तिमाही में कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण अनुपात (औसतन 33.2 प्रतिशत, 12.0 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ) प्राप्त हुआ है। यह विश्वास प्रदान करता है कि

चार्ट 3 : वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के लिए अंतर्निहित वृद्धि दर



स्रोत : केंद्र सरकार के दस्तावेज़ और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीजीए)

⁴ आर्थिक सुस्ती (या नकारात्मक आउटपुट गैप) के 2022-23 में बने रहने का अनुमान है, जैसा कि 2020-21 और 2021-22 में है, और इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटे की संख्या की तुलना इन तीन वर्षों में राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में कम रहने की उम्मीद है।

⁵ 2020-21 के बाद से, संघीय राजकोषीय आवेग 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत था, जो 2021-22 में घटकर 0.6 प्रतिशत और 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत हो गया।

⁶ अप्रैल-जनवरी 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, आरई फरवरी-मार्च 2021-22 के दौरान सकल कर राजस्व में (-)18.4 प्रतिशत की अंतर्निहित वृद्धि का सुझाव देता है। फरवरी-मार्च 2021-22 के लिए निगम कर, आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में निहित वृद्धि क्रमशः (-)29.2 प्रतिशत, (-)26.5 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत, (-)2.3 प्रतिशत और (-)20.7 प्रतिशत है।

सारणी 1: कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 से 2018-19)	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	1.33	1.40	0.86
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.79	1.87	1.22
(i) निगम कर	0.92	1.80	2.25	1.20
(ii) आय कर	1.27	1.81	1.54	1.28
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.91	0.99	0.51
(i) जीएसटी	-	1.78	1.33	1.40
(ii) सीमा शुल्क	0.31	1.71	2.34	1.14
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	-0.57	0.03	-1.34

नोट: 2021-22 (बीई) के लिए उछाल की गणना 2020-21 (आरई) से की गई है

स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए केंद्रीय बजट दस्तावेजों के आधार पर लेखकों की गणना।

2021-22 के लिए आरई आवश्यकता से अधिक प्राप्त होने की संभावना है।

वर्ष 2022-23 (बीई) में, सरकार ने आर्थिक सुधार⁸ के वर्षों में 1.4 के औसत के मुकाबले सकल कर राजस्व उछाल⁷ का बजट 0.9 पर रखा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर उछाल का बजट वसूली वर्ष⁹ में क्रमशः 1.7 और 1.3 के औसत के मुकाबले 1.2 और 0.5 की गई है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में उछाल 11.1 प्रतिशत की मामूली सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की धारणा पर आधारित है, जिसके अधिक होने की संभावना है (सारणी 1)।

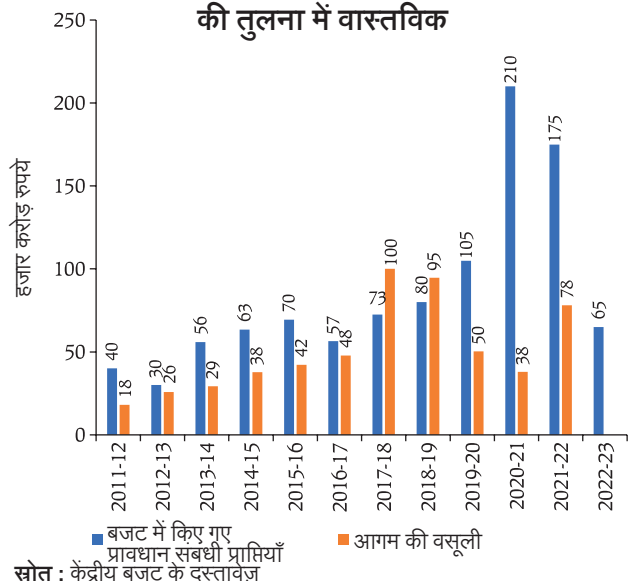
वर्ष 2021-22 (आरई) में, विनिवेश प्राप्तियां ₹78,000 करोड़ रखी गई हैं, जो बजटीय लक्ष्य ₹1.75 लाख करोड़ से 55.4 प्रतिशत कम है। इसमें से जनवरी 2022 तक केवल ₹12,068 करोड़ की वसूली की गई है। वर्ष 2022-23 (बीई) में, विनिवेश लक्ष्य वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग ₹66,000 करोड़ की औसत प्राप्ति के मुकाबले ₹65,000 करोड़ आंका गया है (चार्ट 4)।

⁷ कर उछाल नाममात्र जीडीपी में वृद्धि और कर नीतियों में विवेकाधीन परिवर्तनों के लिए कर राजस्व की प्रतिक्रिया का एक उपाय है (डुडाइन और जल्स, 2017)।

⁸ आर्थिक सुधार के वर्षों के रूप में लिया गया है 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2010-11 और 2013-14 को विकास मंदी (टी) के वर्ष के बाद 'टी+2' वर्ष के रूप में लिया गया है।

⁹ समग्र उछाल मुख्य रूप से ईंधन पर करों में कमी के कारण उत्पाद शुल्क में नकारात्मक वृद्धि के कारण मौन प्रतीत होता है।

चार्ट 4 : विनिवेश – बजट में किए गए प्रावधान की तुलना में वास्तविक



IV. व्यय

वर्ष 2022-23 में कुल खर्च में 4.6 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो एक साल पहले 7.4 फीसदी था। हालांकि, यह राजकोषीय ब्रेक व्यय की गुणवत्ता की कीमत पर नहीं है। राजस्व व्यय में केवल 0.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि का बजट 24.5 प्रतिशत (सारणी 2) है। पूंजीगत व्यय के तहत, प्रधान मंत्री गति शक्ति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले खंडों के लिए अनुपूरक वित्तपोषण, राज्यों के हिस्से के लिए समर्थन सहित अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण और अन्य उत्पादक पूंजी निवेश¹⁰ से संबंधित पूंजी निवेश करने के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पूंजीगत परिव्यय (पूंजीगत व्यय कम ऋण और अग्रिम) में वर्ष 2022-23 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट किया गया है, जो वर्ष 2021-22 (आरई) में 73.3 प्रतिशत की वृद्धि के शीर्ष पर है, जो बुनियादी ढांचे के खर्च, विशेष रूप से सड़कों और रेलवे में मजबूत वृद्धि के अनुसरण में है।

¹⁰ 15वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के बाद, केंद्र ने 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। इसके अलावा, राज्यों को कर हस्तांतरण में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 (आरई) में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2022-23 में 9.6 प्रतिशत की और वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये राज्यों को उच्च पूंजीगत व्यय करने के लिए वित्तीय स्थान प्रदान करेंगे।

सारणी 2: पूंजीगत व्यय

	₹ करोड़			साल दर साल वृद्धि	
	2020-21	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1. पूंजीगत व्यय (2+3)	4,26,317	6,02,711	7,50,246	41.4	24.5
2. पूंजी परिव्यय (जिसमें से):	3,15,826	5,47,457	6,10,189	73.3	11.5
2.1.1 प्रमुख अवसंरचना (जिनमें से):	1,30,496	3,02,504	3,73,440	131.8	23.4
सिंचाई	133	170	350	28.1	105.4
भारतीय रेल	29,926	1,17,100	1,37,100	291.3	17.1
सड़कें और पुल	92,294	1,13,876	1,80,301	23.4	58.3
संचार	4,929	5,525	53,651	12.1	871.0
2.1.2 उद्योग और खनिज	5,212	6,597	7,676	26.6	16.4
2.1.3 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	6,029	9,421	10,535	56.3	11.8
3. ऋण और अग्रिम (जिनमें से):	1,10,491	55,255	1,40,057	-50.0	153.5
3.1 राज्य सरकारों को ऋण	19,554	20,819	1,11,902	6.5	437.5

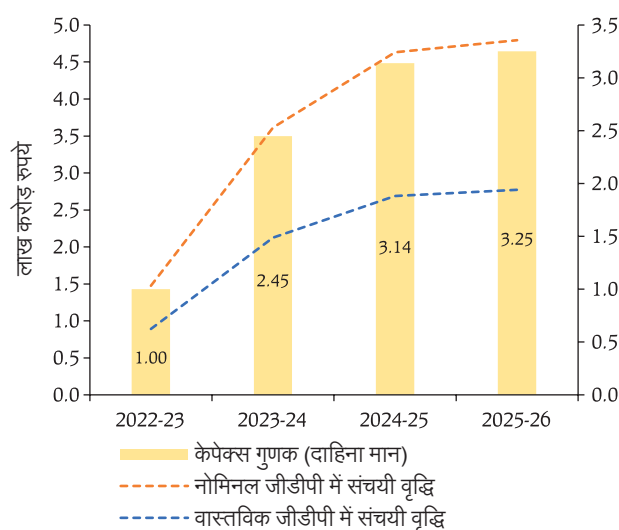
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

बजट परिव्यय वर्ष 2022-23 (बीई) में वर्ष 2021-22 (आरई) की तुलना में ₹1.48 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश जारी करेगा। गतिशील पूंजीगत व्यय गुणक के साथ वर्ष 2023-24 में 2.45, वर्ष 2024-25 में 3.14 और वर्ष 2025-26 में 3.25¹¹ पर पहुंचने के साथ, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक अतिरिक्त 1.4 - 1.9 प्रतिशत अंक तक बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में, ₹1.48 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश से वास्तविक रूप में या चार साल की अवधि में स्थिर कीमतों में ₹2.8 लाख करोड़ की अतिरिक्त जीडीपी का उत्पादन होगा जो कि पूंजीगत व्यय गुणक को चरम पर ले जाता है। मौजूदा कीमतों पर, उत्पादित अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद अगले चार वर्षों में ₹4.8 लाख करोड़ होगा (चार्ट 5)।

आर्थिक गतिविधि पर राजस्व और पूंजीगत व्यय का प्रभाव परिमाण और अवधि में भिन्न होता है। जबकि राजस्व व्यय मांग को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका प्रभाव एक वर्ष में समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले व्यापक आर्थिक आवेग पैदा करता है, जो तीन वर्षों में चरम पर होता है। राजस्व व्यय का पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) से अनुपात सार्वजनिक व्यय के विकास प्रभाव के एक अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करता है। अनुभवजन्य साक्ष्य इंगित करते हैं कि 7.5 के आरईसीओ के लिए एक सीमा है जिसके आगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ इसका

सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण जुड़ाव¹² समाप्त हो जाता है। वर्ष 2022-23 (बीई) में, यह अनुपात 5.2 पर रखा

चार्ट 5 : जीडीपी पर केपेक्स वृद्धि का गुणक प्रभाव

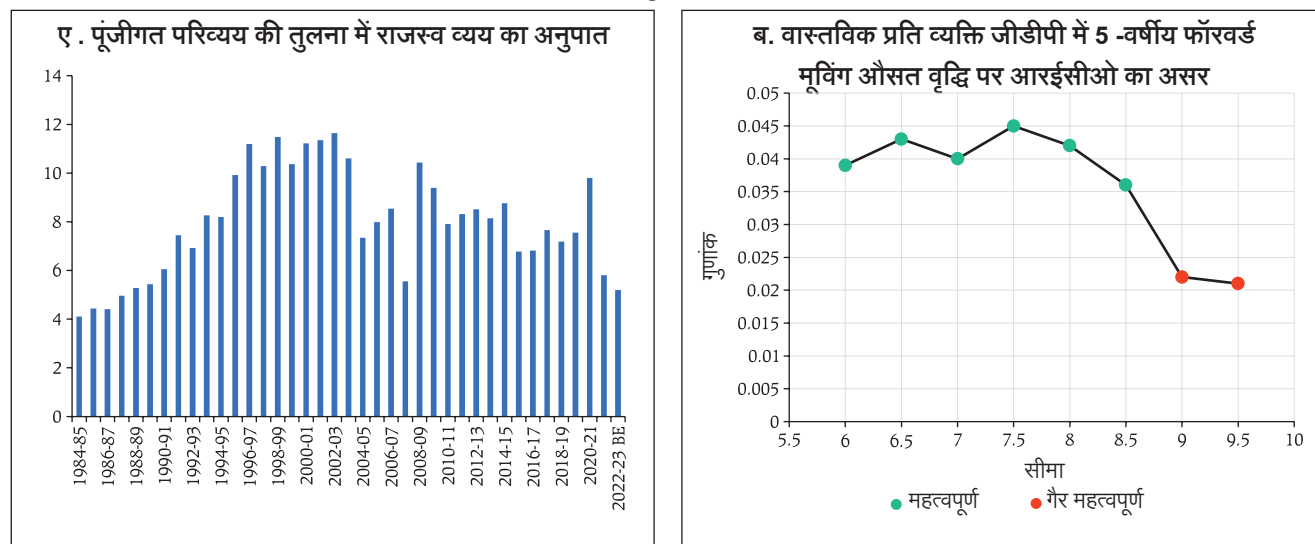


स्रोत : आरबीआई और लेखक के आंकलन

¹² वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीसीजीडीपीजी) में 5 साल आगे बढ़ने वाली औसत वृद्धि और केंद्र सरकार के लिए RECO एक साधारण कम से कम वर्गों (OLS) प्रतिगमन ढाँचे में उपयुक्त नियंत्रण और RECO के लिए विभिन्न श्रेणोल्ड स्तरों के साथ 6.0 से 9.5 तक की सीमा उत्पन्न करता है। हालांकि दो चर गैर-स्थिर हैं, उनका अवशिष्ट स्थिर है जो संयोग संबंध को दर्शाता है और इस प्रकार, ओएलएस चलाया जा सकता है। उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण चर निर्यात के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार और जीडीपी (टीआरडीजीडीपी) के प्रतिशत के रूप में आयात, मानव पूंजी के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में वयस्क साक्षरता दर (एएलआर) और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (टीईजीडीपी) व्यय के आकार के लिए प्रॉक्सी के रूप में कुल व्यय हैं। आरईसीओ में श्रेणोल्ड की पहचान करने के लिए, पारस्परिक रूप से अनन्य तरीके से 8 इंटरैक्टिव डमी चर का उपयोग किया गया है।

¹¹ भारतीय रिजर्व बैंक (2019)। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल।

चार्ट 6 : व्यय की गुणवत्ता – आरईसीओ



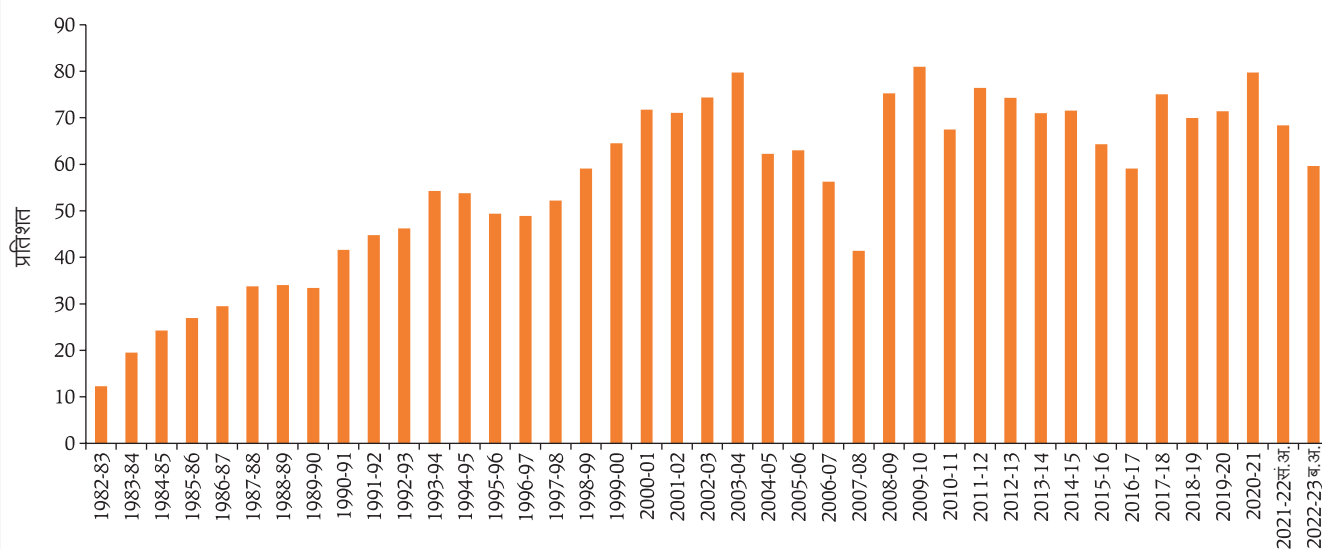
स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज और लेखक के आंकलन

गया है, जो दहलीज से काफी नीचे है और इसलिए, विकास-बढ़ाने वाले प्रभाव (चार्ट 6 ए और बी) जारी कर रहा है।

व्यय की गुणवत्ता के एक और संकेतक - सकल राजकोषीय घाटे (आरडीजीएफडी)¹³ के लिए राजस्व घाटे का अनुपात के

लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 (ब.अ.) में 59.6 प्रतिशत तक की कमी होना तय है, जबकि 2010-11 से 2019-20 के दौरान औसत 70.1 प्रतिशत था¹⁴ (चार्ट 7)। इस प्रकार केंद्रीय वित्त, व्यय मिश्र का संवर्धन करने वाली वृद्धि की ओर अग्रसर है।

चार्ट 7: सकल राजकोषीय घाटे के लिए राजस्व घाटे का अनुपात



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखकों के अनुमान।

¹³ यह संकेतक दर्शाता है कि राजस्व खाते और पूंजी खाते में कितनी उधार ली गई निधियां जा रही हैं। चूंकि दीर्घावधि आस्तियों में निवेश करने से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग उधार ली गई निधियों को चुकाने के लिए किया जा सकता है, इस अनुपात का कर्ज धारणीयता के लिए एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

¹⁴ ओएलएस फ्रेमवर्क (फुटनोट 12 में उल्लिखित) में आरईसीओ को आरडीजीएफडी अनुपात के साथ बदलना, अन्य सभी विशिष्टताओं के समान होने के साथ, 45 प्रतिशत की सीमा उच्च सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव देती है। आरडीजीएफडी अनुपात में सीमा की पहचान करने के लिए, पारस्परिक रूप से अनन्य तरीके से पांच इंटरैक्टिव डमी चरों का उपयोग किया गया है।

V. जीएफडी और कर्ज गतिकी का वित्तपोषण

2022-23 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार का बजट ₹14.95 लाख करोड़ है, जो बाजार की अपेक्षाओं से अधिक है। हालांकि 28 जनवरी 2022 को किए गए ₹63,648 करोड़ की राशि के स्विच परिचालन के लिए समायोजन, सकल उधार आवश्यकता ₹14.31 लाख करोड़ पर कम बनी रह सकती है। इसके अलावा, एनएचएआई द्वारा बाजार से प्रत्यक्ष उधार लेने की सामान्य प्रथा के बजाय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा ₹65,000 करोड़ की राशि उधार ली जाएगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान निवल बाजार उधार की हिस्सेदारी में 67.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ (2010-19 के दौरान 83.2 प्रतिशत के औसत और 2019 के दौरान 52.1 प्रतिशत की तुलना में) वित्त पोषण के महामारी-पूर्व स्वरूप की ओर प्रतिगमन भी की परिकल्पना की गई है; राजकोष बिल (टी-बिल) और एनएसएसएफ पर निर्भरता में कमी (एनएसएसएफ के माध्यम से वित्त पोषण 2019-22 के दौरान बढ़कर 29.8 प्रतिशत हो गया, जबकि 2010-19 के दौरान औसत 7.8 प्रतिशत था); और बाह्य सहायता की हिस्सेदारी में कमी (सारणी 3)। 2022-23 में सरकार के समग्र बाजार उधार के एक हिस्से के रूप में, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे, जिसकी प्राप्ति सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए नियोजित की जाएगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने, निवेशक आधार को व्यापक बनाने और उसका विविधीकरण करके बेहतर मूल्य निर्धारण या ग्रीन बॉन्ड प्रीमियम/ग्रीनियम की सुविधा प्रदान करने और हरित वित्त बाजार के विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं¹⁵। हालांकि, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को सफलतापूर्वक जारी करने का दारोमदार नियोजित प्रक्रियाओं और फ्रेमवर्क की सुदृढ़ता पर निर्भर करेगा, उदाहरण के लिए, हरित और सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार व्यय को वर्गीकृत करने के लिए एक विस्तृत बजट टैगिंग अभ्यास (जलवायु बांड पहल, 2021)।

¹⁵ अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, मित्र, लिथुआनिया, मैक्सिको, चिली ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं (अज़ालियेवा और अन्य, 2020)।

सारणी 3: जीएफडी वित्तपोषण

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	2020-21	2021-22 (ब.अ.)	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा	18,18,291 (100.0)	15,06,812 (100.0)	15,91,089 (100.0)	16,61,196 (100.0)
द्वारा वित्तपोषित:				
निवल बाजार उधारियां	10,32,907 (56.8)	9,24,708 (61.4)	7,75,771 (48.8)	11,18,612 (67.3)
निवल राजकोष बिल	2,83,205 (15.6)	50,000 (3.3)	1,00,000 (6.3)	50,000 (3.0)
लघु बचत पर जारी प्रतिभूतियां (निवल)	4,83,733 (26.6)	3,91,927 (26.0)	5,91,524 (37.2)	4,25,449 (25.6)
बाह्य सहायता	70,180 (3.9)	1,514 (0.1)	19,746 (1.2)	19,251 (1.2)
राज्य भविष्य निधि	18,514 (1.0)	20,000 (1.3)	20,000 (1.3)	20,000 (1.2)
आरक्षित निधियां	4,545 (0.2)	5,051 (0.3)	-1,675 (-0.1)	5,824 (0.4)
जमाराशियां और अग्रिम	25,682 (1.4)	28,868 (1.9)	32,945 (2.1)	34,029 (2.0)
नकद शेष राशि में आहरण द्वारा कमी	-7,188 (-0.4)	71,383 (4.7)	1,74,187 (10.9)	752 (0.0)
अन्य	-93,287 (-5.1)	13,361 (0.9)	-1,21,410 (-7.6)	-12,721 (-0.8)

टिप्पणी: 1. निवल बाजार उधारियों में केवल दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से प्राप्त उधारियां शामिल हैं।

2. निवल राजकोष बिल में 91-दिन, 182-दिन, 364- दिन और अन्य सभी राजकोष बिलों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3. अन्य में प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद (बायबैक), प्रतिभूतियों का स्विच ऑफ, बचत बॉन्ड, राहत बॉन्ड आदि शामिल हैं।

4. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े जीएफडी के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

कर्ज, यानी, राजकोषीय घाटे का अस्थायी संचय असुरक्षित माना जाता है, यदि मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य की संभावित नीतियों के तहत, एक अपरक्राम्य जोखिम हो कि कर्ज-जीडीपी अनुपात लगातार बढ़ेगा और किसी बिंदु पर चूक (डिफॉल्ट) हो जाएगी (ब्लैचर्ड, 2022)। महामारी के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार का कर्ज 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 63.1 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2022-23 में इसका बजट 60.4 प्रतिशत है। राजस्व के वर्तमान और नियमित स्रोतों से इस कर्ज की चुकौती के लिए सरकार की क्षमता का आकलन करने के लिए, हम कर्ज धारणीयता के तीन मुख्य संकेतकों की जांच करते हैं। सबसे पहले, वास्तविक ब्याज दर (आर) को

सारणी 4: संकेतक आधारित कर्ज धारणीयता विश्लेषण

	1981-82 से 1990-91	1991-92 से 2000-01	2001-02 से 2010-11	2011-12 से 2019-20	2019-20	2020-21	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
$r - g < 0$	-8.15	-5.47	-6.29	-4.25	0.37	7.38	-10.04	-5.89
पीबी/ जीडीपी > 0	-4.11	-1.32	-0.95	-1.10	-1.60	-5.75	-3.35	-2.79
आईपी/ आरआर	28.46	47.42	39.98	36.45	36.34	41.61	39.14	42.67

टिप्पणी: हरा रंग इंगित करता है कि शर्त पूरी की गई है और नारंगी रंग यह इंगित करता है कि शर्त का उल्लंघन किया गया है। आर(r) वास्तविक उत्पादन वृद्धि है, पीबी(PB) प्राथमिक शेष है, आईपी(IP) ब्याज भुगतान है, आरआर(RR) राजस्व प्राप्तियां हैं। सांकेतिक ब्याज दर की गणना t पर ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में $t-1$ पर कर्ज के रूप में की जाती है।

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

वास्तविक जीडीपी (जी) की वृद्धि दर से कम होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शेष सकारात्मक होना चाहिए। तीसरा, कर्ज चुकौती की लागत और राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के आधार पर ब्याज भुगतान, समय के साथ घटता जाना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए इन संकेतकों के विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक ब्याज दर सभी चरणों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रही है, लेकिन 2019-20 में यह विकास मंदी के कारण सकारात्मक हो गई और 2020-21 में महामारी के प्रभाव के कारण सकारात्मक हो गई। प्राथमिक शेष सभी चरणों में लगातार नकारात्मक बना रहा, हालांकि, यह अधिकतर नकारात्मक आर-जी बना रहा है¹⁶। केंद्र सरकार की बढ़ती उधारी आवश्यकताओं के कारण राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात 42 प्रतिशत से अधिक है (सारणी 4)।

विमुखी संकेतक आधारित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, आईएमएफ के कर्ज गतिकी साधन (डीडीटी) के आधार पर एक दूरदेशी कर्ज धारणीयता विश्लेषण भी किया गया है¹⁷। 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए केंद्र सरकार का कर्ज पथ पूर्वानुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे के सकल राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लिए अंतिम वर्ष 2025-26 निर्धारित किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मुद्रास्फीति, प्राथमिक शेष और प्रभावी ब्याज दर के उपलब्ध अनुमानों द्वारा वर्गीकृत प्रारंभिक स्थितियों पर आधारित है (सारणी 5)¹⁸। आधारभूत परिदृश्य में, केंद्र सरकार के कर्ज में 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 56.7 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान है।

सारणी 5: कर्ज गतिकी साधन- प्रमुख धारणाएं और परिणाम

	ऐतिहासिक					पूर्वानुमान (आधारभूत)			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
वास्तविक जीडीपी संवृद्धि	6.8	6.5	3.7	-6.6	8.8	7.8	6.6	6.3	6.2
जीडीपी अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति	4.0	3.9	2.4	5.6	7.7	4.8	4.7	4.7	4.7
सकल प्राथमिक संतुलन	-0.4	-0.4	-1.6	-5.7	-3.3	-2.7	-2.1	-1.5	-0.9
सांकेतिक प्रभावी ब्याज दर	6.9	6.9	6.5	6.4	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7
कर्ज	49.7	49.8	53.0	63.1	60.2	59.6	59.1	58.1	56.7

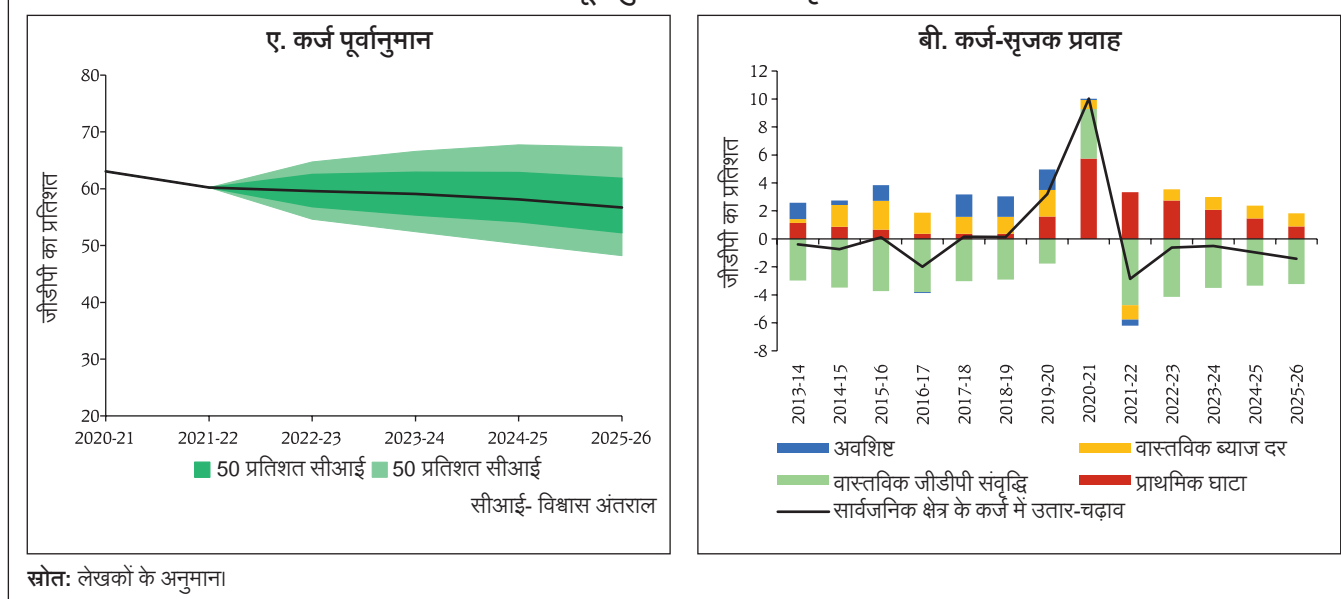
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

¹⁶ यदि संपूर्ण सार्वजनिक कर्ज घरेलू स्तर पर हो और स्टॉक-प्रवाह समायोजन नहीं होते हैं, तो कर्ज-जीडीपी अनुपात में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है: insert formula कर्ज समय के साथ घटेगा जब $r - g < 0$ और अर्थव्यवस्था में प्राथमिक अधिशेष हो, या जब $r - g < 0$ और दायें मान पर पहली अवधि किसी से प्राथमिक घाटे से अधिक हो।

¹⁷ डीडीटी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा विकसित एक एक्सेल-आधारित टेम्पलेट है जिसका उपयोग समष्टि-आर्थिक चर के एक लघु समूह का उपयोग करके सार्वजनिक कर्ज का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

¹⁸ वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि आरबीआई के पूर्वानुमानों और आगामी वर्षों के लिए डब्ल्यूईओ (अक्टूबर 2021) पर आधारित है। सकल कर राजस्व में वृद्धि का बजट 1.1 रखा गया है और कुल व्यय में वार्षिक 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इन मान्यताओं के आधार पर, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा, वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत तक संकुचित होने का पूर्वानुमान है। यह देखते हुए कि भारत का विदेशी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद से 3 प्रतिशत कम है; और कुल कर्ज का लगभग 5 प्रतिशत है, हमने एक सरल धारणा बना ली है कि सरकार का संपूर्ण कर्ज घरेलू स्तर पर आधारित है।

चार्ट 8: कर्ज पूर्वानुमान और कर्ज-सृजक प्रवाह



वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और प्राथमिक शेष के लिए आघात उत्पन्न करके केंद्र सरकार के कर्ज के लिए फैन चार्ट से पता चलता है कि वर्ष 2025-26 में 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल 52.3 प्रतिशत पर अनुमानित है, जो कि जीडीपी का 61.9 प्रतिशत है (चार्ट 8ए)। पूर्वानुमान अवधि में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, कर्ज समेकन की कुंजी रहेगी (चार्ट 8बी)।

VI. निष्कर्ष

महामारी के समय राजकोषीय नीति का संकट की स्थिति से बाहर निकलना, इसे इस स्थिति में जाने की तुलना में कष्टदायी रूप से बहुत अधिक कठिन है। इस संकट से बाहर निकलने संबंधी नीति निर्माताओं को कुआं और खाई के बीच चुनाव करने जैसी तलवार की धार पर चलने जैसी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर राजकोषीय समर्थन के हटने से अर्थव्यवस्था को तेज मंदी की ओर धकेलने का जोखिम है। दूसरी ओर, बहुत धीरे-धीरे समर्थन समाप्त किए जाने के रैंप प्रभाव से नैतिक खतरे का डर होता है, और नीतिगत प्रोत्साहन को वापस लेने में देरी के कारण दबाव समूहों का निर्माण होता है।

2022-23 के बजट में परस्पर विरोधी खींचतान की इस यात्रा की शुरुआत व्यवहार्य सटीकता के साथ विकास पर जोर

देने की कोशिश से हुई है। तदनुसार, इसने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में जीडीपी19 के 0.4 प्रतिशत की कमी के साथ इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत तक ले जाने का रास्ता चुना है। हालांकि इस कमी को बाद के वर्षों में बड़े पैमाने पर समेकन और भार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसका मूल्यांकन इस बात के लिए किया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था अब क्या सहन कर सकती है और जब रिकवरी मजबूत, स्थिर और आत्मनिर्भर होती है तो इसे सह सकती है। इस मुकाम तक पहुंचना एक मजबूत निवेश अभियान पर निर्भर है और पूर्व के मिसाल के सापेक्ष राजस्व व्यय वृद्धि को रोकते हुए बजट ने इसे प्राथमिकता देने की मांग की है। हमारी गणना से पता चलता है कि इस सबसे पहले- आधारभूत फ्रेमवर्क की कार्यनीति के लाभ कई वर्षों के लिए लाभांश प्रदान करेंगे, जो समेकन पथ पर अगले मील का पत्थर का वर्ष -2025-26 में चरम पर होगा। यहां प्रस्तुत राजकोषीय परिवर्तन के अनुमान बताते हैं कि समेकन के बावजूद, 2022-23 के अंत तक अर्थव्यवस्था में कुछ प्रोत्साहन शेष रहेगा। अब यह निजी निवेश के लिए है कि वह प्रतिक्रिया करे और रिकवरी में भाग ले।

¹⁹ जीएफडी-जीडीपी अनुपात के 2021-22 (सं.अ.) में 6.85 प्रतिशत से 2022-23 में घटकर 6.44 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

बजट ने कई स्तरों यथा - रूढ़िवादी राजस्व पूर्वानुमान; यथार्थवादी विनिवेश लक्ष्य; एनएसएसएफ और नकद शेष तथा रूढ़िवादी नाममात्र जीडीपी अनुमान के लिए प्रमुखता प्रदान करने के लिए जोखिम-न्यूनतमीकरण की रणनीति अपनाई है। ये बफ़र्स 2022-23 के लिए निर्धारित बजटीय लक्ष्यों को सुरक्षित करने में मदद करेंगे।

2019-21 के दौरान एक सफलता के बाद ऋण स्थिरता के प्रमुख संकेतकों में सुधार होना शुरू हो गया है। आगे चलकर, केंद्र सरकार का ऋण मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से नीचे स्थिर होने का अनुमान है, लेकिन उप-राष्ट्रीय ऋण के साथ तुलना करने पर यह लगभग 85 प्रतिशत है। जबकि महामारी के बाद का ऋण समेकन मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर निर्भर करेगा, इसे राजकोषीय समेकन द्वारा पूरक करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, 2022-23 के लिए केंद्र के जीएफडी में 0.4 प्रतिशत अंक की कमी एक मूल्यवान प्रारंभिक बिंदु है और राज्यों को भी इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

Azhgaliyeva, D., Kapoor, A., & Liu, Y. (2020). *Green bonds for financing renewable energy and energy efficiency*

in South-East Asia: a review of policies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 10(2), 113-140.

Blanchard, O. (2022). *Deciding When Debt Becomes Unsafe*. Finance and Development, International Monetary Fund, March.

Dudine, M. P., & Jalles, J. T. (2017). *How buoyant is the tax system? New evidence from a large heterogeneous panel*. International Monetary Fund.

Fedelino, A., Ivanova, A., & Horton, M. A. (2009). *Computing cyclically-adjusted balances and automatic stabilizers*. IMF Technical Notes and Manuals, 2009 (005).

Rabanal, P. (2015). *Q&A: Seven Questions on Potential Output*. IMF Research Bulletin, 2015(001).

Sargent, T.J. and Wallace, N (1981). *Some unpleasant monetarist arithmetic*. Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis, vol. 5.

Sovereign Green, Social, and Sustainability Bond Survey: The Ultimate Power to Transform the Market (2021). Climate Bonds Initiative.

अनुबंध 1: केंद्रीय बजट 2022-23: प्रमुख वित्तीय संकेतक

	₹ हजार करोड़ में					जीडीपी का प्रतिशत		विकास दर	
	2019-20	2020-21	2021-22 (ब.अ.)	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रत्यक्ष कर	1,050	945	1,108	1,250	1,420	5.4	5.5	32.3	13.6
(i) निगम	557	458	547	635	720	2.7	2.8	38.7	13.4
(ii) आय	480	470	549	595	680	2.6	2.6	26.5	14.3
2. अप्रत्यक्ष कर	961	1,082	1,109	1,266	1,338	5.5	5.2	17.0	5.7
(i) जीएसटी	599	549	630	675	780	2.9	3.0	23.0	15.6
(ii) सीमा शुल्क	109	135	136	189	213	0.8	0.8	40.3	12.7
(iii) उत्पाद शुल्क	241	392	335	394	335	1.7	1.3	0.6	-15.0
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2,010	2,027	2,217	2,516	2,758	10.8	10.7	24.1	9.6
4. राज्यों को समनुदेशन	651	595	666	745	817	3.2	3.2	25.2	9.6
5. एनसीसीडी स्थानांतरण	2	6	6	6	6	0.0	0.0	5.3	4.4
6. निवल कर राजस्व (3-4-5)	1,357	1,426	1,545	1,765	1,935	7.6	7.5	23.8	9.6
7. गैर-कर राजस्व	327	208	243	314	270	1.4	1.0	51.1	-14.1
(i) लाभांश और लाभ	186	97	104	147	114	0.6	0.4	52.1	-22.7
(ii) ब्याज प्राप्ति	12	17	12	21	18	0.1	0.1	22.1	-13.9
8. राजस्व प्राप्ति (6+7)	1,684	1,634	1,788	2,079	2,204	9.0	8.5	27.2	6.0
9. गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	69	58	188	100	79	0.4	0.3	73.5	-20.7
(i) विनिवेश प्राप्ति	50	38	175	78	65	0.3	0.3	105.8	-16.7
(ii) ऋणों की वसूली	18	20	13	22	14	0.1	0.1	11.4	-35.0
10. कुल प्राप्ति (उदा. उधार) (8+9)	1,753	1,692	1,976	2,179	2,284	9.4	8.9	28.8	4.8
11. राजस्व व्यय	2,351	3,084	2,929	3,167	3,195	13.6	12.4	2.7	0.9
(i) ब्याज भुगतान	612	680	810	814	941	3.5	3.6	19.7	15.6
(ii) प्रमुख सब्सिडी भोजन	228	708	336	433	318	1.9	1.2	-38.8	-26.6
उर्वरक	109	541	243	286	207	1.2	0.8	-47.1	-27.8
उर्वरक	81	128	80	140	105	0.6	0.4	9.5	-24.9
पेट्रोलियम	39	38	14	7	6	0.0	0.0	-83.1	-10.8
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	336	426	554	603	750	2.6	2.9	41.4	24.5
(i) पूंजी परिव्यय	311	316	514	547	610	2.4	2.4	73.3	11.5
(ii) ऋण और अग्रिम	24	110	40	55	140	0.2	0.5	-50.0	153.5
13. कुल व्यय (11+12)	2,686	3,510	3,483	3,770	3,945	16.2	15.3	7.4	4.6
14. सकल राजकोषीय घाटा (13-10)	934	1,818	1,507	1,591	1,661	6.9	6.4	-12.5	4.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

भारतीय बैंकों के लिए हरित संक्रमण जोखिम*

शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर संक्रमण से ऐसे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रियाओं में समायोजन की आवश्यकता होगी, जहां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग होता है। साथ ही, इन उद्योगों के लिए भारतीय बैंकों के एक्सपोजर के कारण, उन पर स्पिलओवर प्रभाव हो सकता है, जिसे इस आलेख में चिन्हांकित किया गया है। जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष एक्सपोजर वाले तीन क्षेत्रों - विद्युत, रसायन और ऑटोमोबाइल की समग्र औद्योगिक क्षेत्र के क्रेडिट में लगभग 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन कुल बकाया गैर-खुदरा बैंक क्रेडिट में केवल 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी, बैंकिंग व्यवस्था के लिए सीमित स्पिलओवर को दर्शाती है। हालांकि, कई अन्य उद्योग परोक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं और इसलिए हरित ऊर्जा के लिए कोई भी संक्रमण, उनकी आय पर और फलस्वरूप उनके ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) के लिए निहितार्थ हो सकता है। इसलिए, ऐसे उद्योगों का सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात हरित ऊर्जा संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकता है और समग्र बैंकिंग प्रणाली पर उनके प्रभाव की सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है।

भूमिका

हालिया वर्षों में, दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए आक्रामक तरीके से कदम उठा रही हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता (2015) और ग्लासगो सीओपी26 (2021) शामिल हैं। जलवायु जोखिम में कुछ लक्षणात्मक विशेषताएं हैं, जो इसे अन्य जोखिमों से अलग करती हैं। यह व्यापक, अरैखिक है, और इसके अधिकतर परिणाम अपरिवर्तनीय हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक नीतियों की आर्थिक लागत और लाभों को देखते हुए, वित्तीय जोखिमों सहित संबंधित समष्टि-आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण करना

* यह आलेख सौरभ घोष, सिद्धार्थ नाथ, अभिनव नारायणन और शतद्रु दास, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

अनिवार्य हो गया है। एक केंद्रीय बैंक के लिए, वित्तीय संस्थाओं के जलवायु जोखिम के एक्सपोजर की निगरानी करना और समष्टि-वित्तीय स्थिरता के लिए ऐसे जोखिमों के प्रभाव का परीक्षण करना विशेष महत्व रखता है। उभरती चुनौतियों को देखते हुए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने द्विवार्षिक अन्वेषण परिदृश्य विश्लेषण शुरू किया है; बांके डी फ्रांस एक क्षेत्रवार रेटिंग-आधारित मॉडल और वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है; बैंक ऑफ कनाडा अपने सकल घरेलू उत्पाद पर जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है; और बैंको सेंट्रल डी चिली डिफॉल्ट की संभावना का आकलन करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ पर ध्यान देने के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्टों और प्रकाशनों में हरित वित्त से संबंधित मुद्दों को उजागर करने में भी सक्रिय रहा है।

भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना या एनएपीसीसी तैयार की और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से 2011 में जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) की स्थापना की। इसके अलावा, इस दिशा में हाल ही में कई पहलें की गई हैं, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन; रेलवे में उत्सर्जन को कम करना; एलईडी बल्ब अभियान; और बीएस IV के भौगोलिक कवरेज का विस्तार करना (खंड III देखें)। भविष्य में उद्योगों, वाहनों और जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की बढ़ती चुनौती की उम्मीद की जा सकती है। भारत में इन क्षेत्रों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में कतिपय संक्रमणकालीन लागत वहन करने की संभावना है। ऐसे परिवर्तनों के प्रभावों को परिमाणित करने के लिए, मॉडलों की रेटिंग श्रेणी विभिन्न उद्योगों में चूक की संभाव्यता (पीडी) का उपयोग करती है। सामान्य संतुलन मॉडल के एक अन्य वर्ग में, संक्रमणकालीन आघातों को आपूर्ति पक्ष के आघात के रूप में देखा जाता है, जबकि भौतिक आघातों को मांग पक्ष के आघात के रूप में अधिक देखा जाता है।

इस आलेख में हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर औद्योगिक गतिविधियों के लिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर का विश्लेषण करते हैं: यदि उद्योग इनपुट उपयोग में एक बड़ा बदलाव होता है, तो इसका विश्लेषण किया जा सकता है और/या जीवाश्म

ईंधन उपयोग से इतर मार्ग के कारण उत्पादन प्रक्रियाएं- जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र में असुरक्षितता की सीमा मापी जा सके। प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन से संबंधित उद्योगों के अलावा, ऐसे कई अन्य उद्योग हैं जो भिन्न सीमा तक जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा पर निर्भर हैं और इसलिए इनमें परोक्ष रूप से एक्सपोजर माना जा सकता है।

इस आलेख के बाकी हिस्सों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है: खंड 2 में हम प्रचलित वैश्विक उत्सर्जन मानकों, मानदंडों और नीतियों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन लक्ष्य, जो विभिन्न देशों ने पेरिस जलवायु समझौते (2015) के अनुसार निर्धारित किए हैं, और भारत पर महत्व देने के साथ अब तक की प्रगति शामिल है। खंड 3 में हम उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करते हैं जो जीवाश्म-ईंधन जोखिमों के एक्सपोजर में आ सकते हैं। खंड 4 में हम उन क्षेत्रों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता पर अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं। खंड 5 में हम इन क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर पर चर्चा करते हैं। खंड 6 प्रमुख प्रेक्षकों के साथ समाप्त होता है।

II. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: वैश्विक रुझान और नीति

जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए, पेरिस समझौते को एक ऐतिहासिक जलवायु समझौते के रूप में अपनाया गया था, जो जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि¹ है। यह समझौता दिसंबर 2015 में 196 पक्षों द्वारा अपनाया गया था और नवंबर 2016 से लागू हुआ। समझौते का लक्ष्य पिछली सदी के औद्योगीकरण-पूर्व अवधि की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। पेरिस जलवायु समझौता मुख्य रूप से जलवायु कार्रवाई के लिए देश-विशिष्ट योजनाओं पर टिकी हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के रूप में जाना जाता है, और सभी देशों को 2020 तक प्रस्तुत करना था। अपने एनडीसी में, देश अपनी जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (प्रति व्यक्ति उत्सर्जन या उत्सर्जन-से-जीडीपी अनुपात) को 2030 तक पारस्परिक रूप से सहमत स्तर

सारणी 1: एनडीसी के अनुसार वर्ष 2030 के शर्त रहित लक्ष्य

देश	उत्सर्जन तीव्रता में कमी (आधार वर्ष से प्रतिशत में कमी)	जीएचजी तीव्रता - 2015-18 औसत (सीओ2 के समतुल्य/ जीडीपी 2017 पीपीपी \$ बिलियन किलोटन)
	1	2
भारत	30-35	399
चीन	60-65	624
इंडोनेशिया	29	318
यूरोपीय संघ	29	192
जापान	26	241
कनाडा	30	406
ब्राजील	6	348
रूस	25-30	657

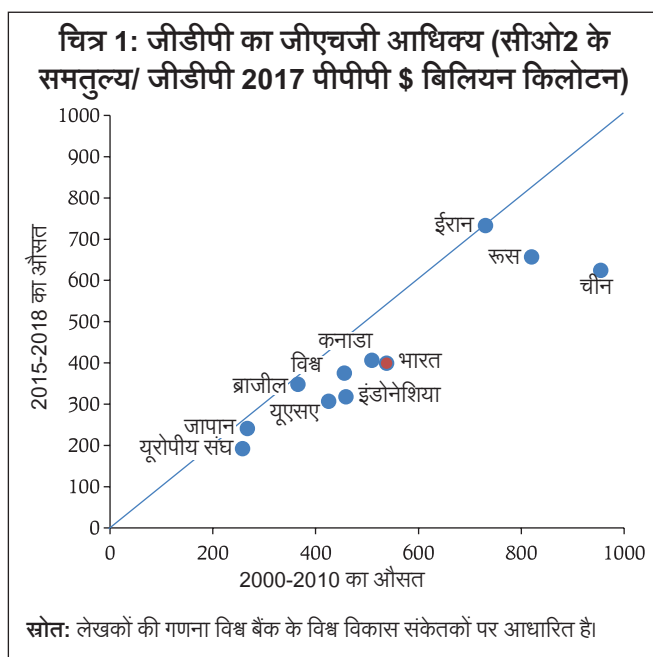
टिप्पणी: स्तंभ (1) के आंकड़े पेरिस जलवायु समझौते 2015 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद, इनमें से अधिकतर देश सीओपी26 शिखर सम्मेलन में इन लक्ष्यों को संशोधित करने पर सहमत हुए हैं। ये प्रतिबद्धताएं जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (जीएचजी उत्सर्जन/ जीडीपी) में प्रतिशत कमी के संदर्भ में हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, यहां सूचीबद्ध देश कुल जीएचजी उत्सर्जन (किलोटन सीओ2 के समतुल्य) के अनुसार शीर्ष उत्सर्जक हैं। प्रमुख उत्सर्जकों में अमेरिका और ईरान शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एनडीसी उपलब्ध नहीं थे क्योंकि देश पेरिस समझौते से हट गया था। स्रोत के पास ईरान के लिए एनडीसी पर भी डेटा उपलब्ध नहीं था। भारत, चीन, इंडोनेशिया और कनाडा के लिए संदर्भ वर्ष 2005 है। यूरोपीय संघ और ब्राजील के लिए संदर्भ वर्ष 2010 है। जापान और रूस के लिए संदर्भ वर्ष क्रमशः 2013 और 1990 हैं।

स्रोत: <https://climateactiontracker.org>

पर कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेरिस समझौते के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए देश अपने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को भी संचारित करते हैं। पेरिस समझौता, देशों द्वारा की जाने वाली तेजी से महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के पांच-वर्षीय चक्र पर काम करता है। एनडीसी का पहला समूह अब उपलब्ध है और सारणी 1 में प्रमुख देशों के लिए प्रस्तुत किया गया है। पेरिस समझौते के साथ, देशों ने देशीय-स्तर पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक उन्नत पारदर्शिता फ्रेमवर्क (ईटीएफ) स्थापित किया। 2024 से शुरू हुए ईटीएफ के तहत देश, किए गए कार्यों, जलवायु परिवर्तन शमन में हुई प्रगति, लागू अनुकूलन उपायों और पारदर्शी तरीके से प्रदान या प्राप्त समर्थन को रिपोर्ट करेंगे।

चित्र 1 से पता चलता है कि ईरान को छोड़कर, लगभग सभी देशों ने 2000-2010 और पेरिस समझौते के बाद के वर्षों के मध्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मापी गई जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में काफी प्रगति की है। यद्यपि जापान और ब्राजील के लिए 2015 से उत्सर्जन की तीव्रता 2010 से पहले के अपने स्तर के अपेक्षाकृत करीब है, वे इस संबंध में

¹ <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>



बाकी देशों/ क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहे हैं। विश्व के लिए, 2015-18 के बीच जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2000-10 के बीच के औसत से 18 प्रतिशत कम रही है। चीन ने 35 प्रतिशत की गिरावट देखी, उसके बाद इंडोनेशिया में 31 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। उक्त दो अवधियों के बीच जीएचजी उत्सर्जन में गिरावट भारत के लिए 26 प्रतिशत रही है, इसके बाद यूरोपीय संघ में 25 प्रतिशत की गिरावट आयी है। 2018 तक जीएचजी उत्सर्जन की तीव्रता के मामले में प्रगति ईरान और जापान को छोड़कर, एनडीसी के काफी समीप रही है। हालांकि, इन दो अवधियों के बीच विश्व के लिए पूर्ण जीएचजी उत्सर्जन 21 प्रतिशत अधिक था। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ 2000-10 की तुलना में 2015-18 के बीच अपने पूर्ण जीएचजी उत्सर्जन स्तर को कम करने में सक्षम रहे हैं। इसलिए, जीएचजी उत्सर्जन के प्रतिकूल प्रभावों से पूरी तरह से निपटने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरते देशों को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण सहित पेरिस समझौते से परे इसे और अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है।

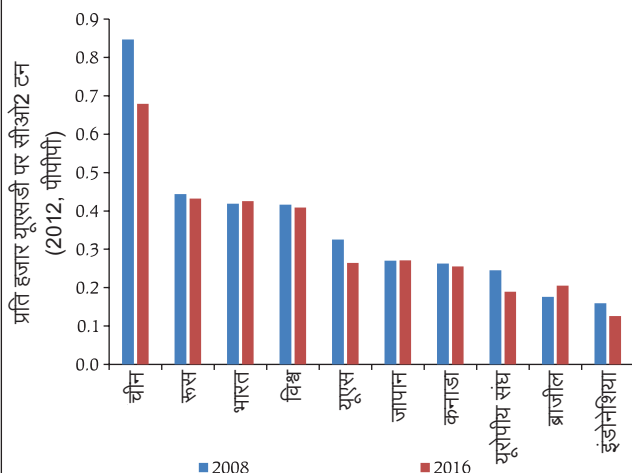
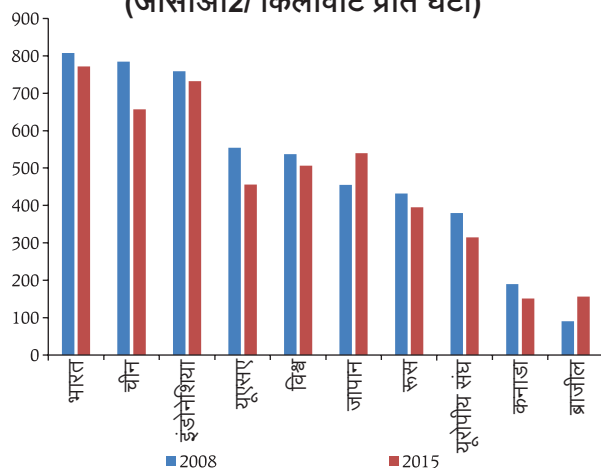
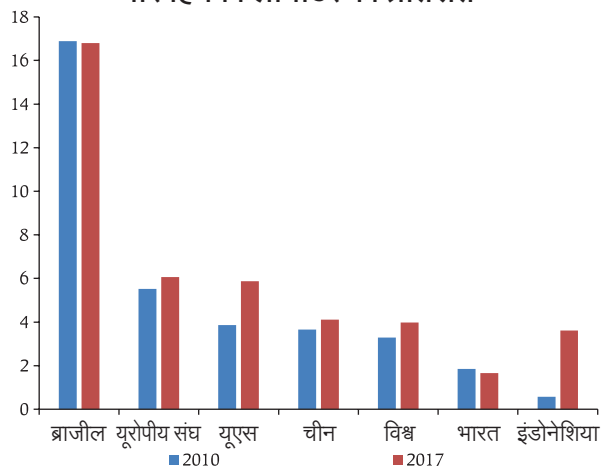
जहां तक उद्योगों से उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का संबंध है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का स्थान है (चित्र 2.1)। हालांकि, उभरते हुए देश, जो औद्योगिक उत्सर्जन तीव्रता के मामले में उच्च पायदान पर हैं, उन्हें उत्सर्जन

की तीव्रता को पर्याप्त रूप से कम करने के प्रयास करने बाकी हैं। इसके लिए उनके विकसित समकक्षों से उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अंतरण की आवश्यकता होगी, साथ ही तेजी से औद्योगिक विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रोटोकॉल लागू करना होगा। भारत और इंडोनेशिया, दोनों ही विद्युत उत्पादन से उत्सर्जन के मामले में उच्च पायदान पर बने हुए हैं, और उस क्षेत्र से 2008 और 2015 के बीच जीएचजी उत्सर्जन में बहुत कम गिरावट देखी गई है (चित्र 2.2)। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में विद्युत उत्पादन से जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता में उल्लेखनीय गिरावट आयी है, जबकि जापान और ब्राजील के लिए तीव्रता में वृद्धि हुई है। इसलिए भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे उभरते देशों और जापान जैसे विकसित देशों के लिए भी उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता के स्तर पर, भारत प्रमुख उत्सर्जक के बीच शून्य उत्सर्जन ईंधन द्वारा संचालित घरेलू परिवहन किलोमीटर के प्रतिशत के मामले में काफी नीचे है (चित्र 2.3)। वास्तव में, 2010 और 2017 के बीच उपयोग में मामूली गिरावट आयी है। इस संबंध में विश्व औसत में 2010 और 2017 के मध्य वृद्धि के लिए इंडोनेशिया, अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन उत्तरदायी थे।

चित्र 2.1, 2.2 और 2.3 एक साथ दर्शाते हैं कि भारत में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उत्सर्जन मानकों में सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कई नीतिगत साधन पहले से ही काम कर रहे हैं (घोष और अन्य देखें (2021))। कार्बन कराधान, सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक गारंटी, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली², फीबेट³ आदि सहित कई अन्य नीति उपकरण हैं जिनका अध्ययन अकादमिक और नीति मंचों (क्रोएस्टुप और ओमान (2019), आईएमएफ के राजकोषीय मॉनिटर (अक्टूबर 2019), दिलीप और कुंडू (2020)) में किया जा रहा है। वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग-प्रेरित बल संभावित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्रों को उजागर करता है जो ऊर्जा पर जोखिमों की हद तक अत्यधिक निर्भर हैं। अगले खंड में हम उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जो ऐसे जोखिमों के एक्सपोजर में हैं।

² फर्मों को अपने प्रत्येक टन उत्सर्जन के लिए एक भत्ता देने की आवश्यकता होती है और सरकार कुल उत्सर्जन पर एक उच्चतम सीमा निर्धारित करती है।

³ औसत से अधिक उत्सर्जन पर शुल्क लगाना और औसत से कम उत्सर्जन दरों पर रिबेट।

चित्र 2.1: प्रति जीवीए औद्योगिक उत्सर्जन तीव्रता**चित्र 2.2: बिजली उत्सर्जन तीव्रता (जीसीओ2/ किलोवॉट प्रति घंटा)****चित्र 2.3: शून्य उत्सर्जन ईंधन द्वारा संचालित देशी परिवहन किलोमीटर का प्रतिशत**

टिप्पणी: चित्र 2.1 में कनाडा के लिए आंकड़े 2015 से संबंधित हैं।
स्रोत:

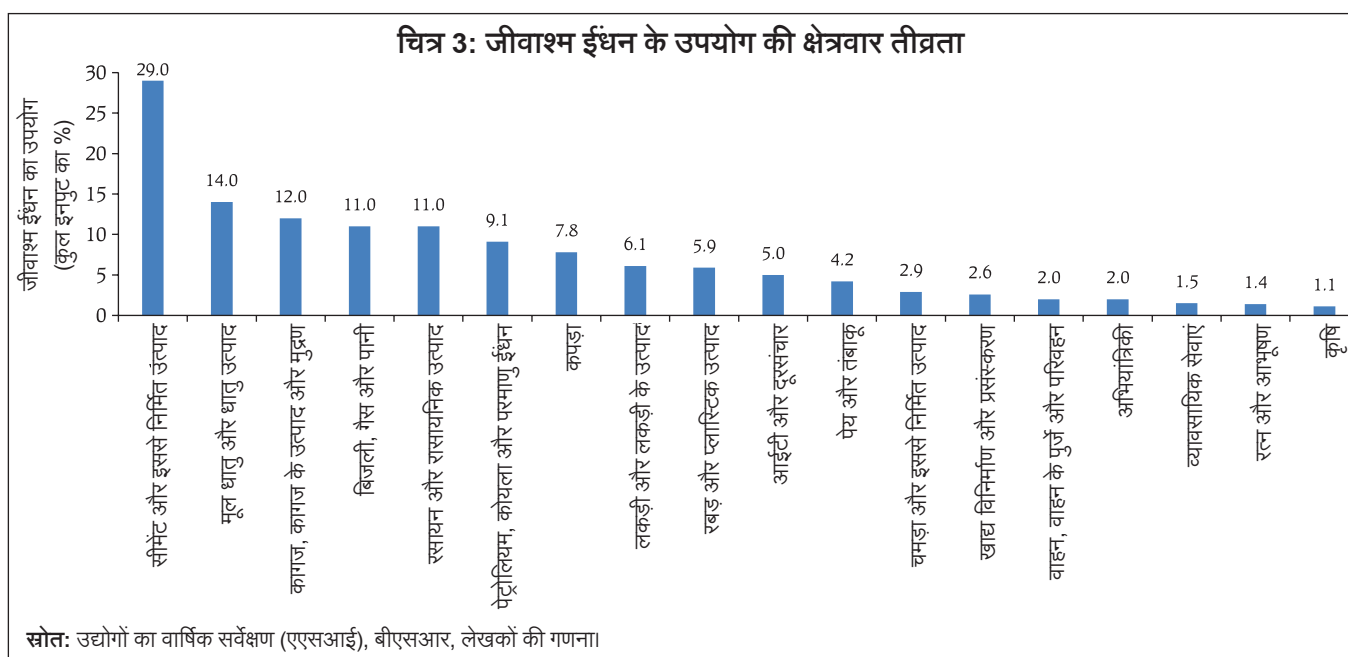
III. भारत का एक्सपोजर

(ए) जीवाश्म ईंधन

इस खंड में, हम पड़ताल करते हैं कि भारत किस हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई है। हम प्रत्येक क्षेत्र के लिए जीवाश्म ईंधन की तीव्रता की गणना करने के लिए वर्ष 2016-17 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एसआई) डेटा का उपयोग करते हैं। एसआई डेटा स्थापना स्तर पर उत्पादन प्रक्रियाओं और वित्त पर जानकारी प्रदान करता है। हम जीवाश्म ईंधन की तीव्रता की गणना के लिए इनपुट उपयोग की जानकारी का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से, हम किसी उद्योग विशेष द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल इनपुट के हिस्से के रूप में विद्युत, पेट्रोल/ डीजल, कोयले के मूल्य की गणना करते हैं (हम किसी विशेष उद्योग में सभी प्रतिष्ठानों का भारित योग लेते हैं)। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत के मूल्य को समायोजित करते हैं कि 37.8 प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा/ गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) द्वारा उत्पादित की जाती है। चित्र 3 अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कुल इनपुट में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को दर्शाता है। इससे हमें पता चलता है कि सीमेंट उत्पाद और मूल धातु जीवाश्म, ईंधन के दो सबसे अधिक एक्सपोजर-प्राप्त क्षेत्र हैं, क्योंकि कुल इनपुट में से क्रमशः 29 प्रतिशत और 14 प्रतिशत इनका हिस्सा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीमेंट उद्योग में हाल के वर्षों में उत्पादन प्रक्रिया में काफी तकनीकी प्रगति हुई है जिससे इसकी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में काफी कमी आयी है (अर्थव्यवस्था की स्थिति, दिसंबर 2021)।

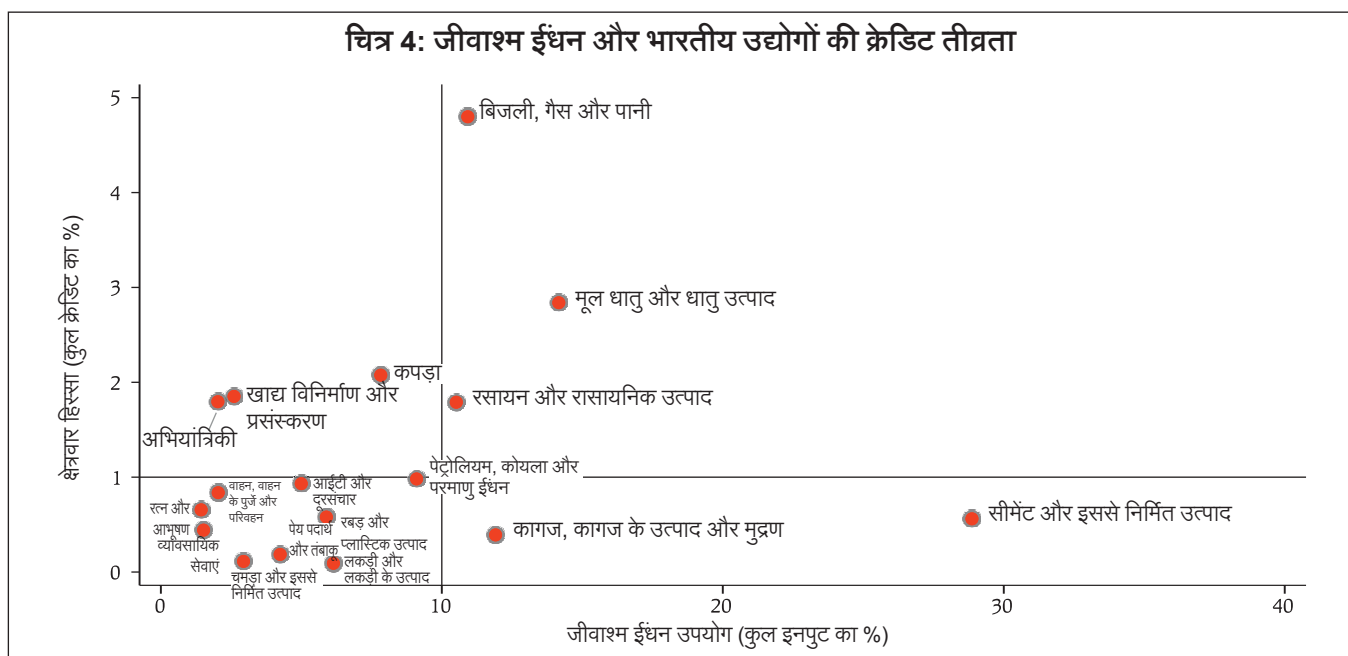
(बी) बैंक क्रेडिट

भारत एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था है, जहां प्रमुख कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा अपनी कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए बैंकिंग क्षेत्र की निधियों पर निर्भर है। हालांकि हाल के वर्षों में कॉरपोरेट डिलीवरेजिंग के कुछ प्रमाण पाये गए हैं, तब भी बैंकिंग क्षेत्र अधिकांश उद्योगों के लिए निधि का प्रमुख स्रोत बना हुआ है (हेरवाडकर, 2017)।



उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सर्वाधिक एक्सपोजर की पहचान करने के लिए भारतीय उद्योगों की ईंधन तीव्रता और क्रेडिट तीव्रता को मैप करते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्रता के लिए एएसआई डेटा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए बकाया

क्रेडिट पर बीएसआर डेटा (मार्च 2019 तक) इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र 4 y-अक्ष पर बकाया क्रेडिट में क्षेत्रवार शेयर और x-अक्ष पर क्षेत्रों की जीवाश्म ईंधन तीव्रता को दर्शाता है। विद्युत⁴ और मूल धातु जैसे क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा संवितरित



⁴ ऐसी फर्मों जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, एएसआई के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, एएसआई डेटा से गणना के अनुसार क्षेत्र की ऊर्जा तीव्रता को पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जा सकता है।

कुल क्रेडिट के महत्वपूर्ण अनुपात को अवशोषित करते हैं लेकिन जीवाश्म ईंधन के लिए मध्यम एक्सपोजर रखते हैं। सीमेंट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के लिए अधिक एक्सपोजर है, लेकिन उनके क्रेडिट शेयर कम हैं। इसलिए, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में व्यवधानों, यदि कोई हो, से बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी कमजोरियों के उभरने की उम्मीद नहीं है। जिन तीन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के लिए अधिक एक्सपोजर (10 प्रतिशत या अधिक) है और कुल बैंक क्रेडिट में अपेक्षाकृत अधिक (1 प्रतिशत या अधिक) क्षेत्रवार हिस्सेदारी है, वे विद्युत, मूल धातु और रसायन हैं। हालांकि, कुल मिलाकर वे कुल बकाया क्रेडिट के केवल 9 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, हम पहले ईंधन के स्वच्छ स्रोतों में संक्रमण के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र का विकास देखते हैं। लगभग सभी उत्पादन प्रक्रियाओं में एक आवश्यक इनपुट होने के कारण हम पहले विद्युत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, हम मूल धातुओं के विनिर्माण हेतु एसआई (डिवीजन 24) पर विचार करते हैं। मूल धातु श्रेणी के दो प्रमुख घटक मूल लौह और इस्पात का विनिर्माण और लौह एवं इस्पात की ढलाई है, जो एक साथ क्षेत्र के उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जुलाई 2021 लौह और इस्पात उद्योग का प्रभाव आकलन प्रस्तुत करती है (संक्षिप्त रूप में अनुबंध-1 में)। हम अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके कैपिटल और ऊर्ध्वाधर संबंधों पर विचार करते हुए रसायन और रासायनिक उत्पाद उद्योग में क्रेडिट वृद्धि का विश्लेषण करते हैं।

अंत में, हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। हालांकि हमारे पहचान ढांचा (आईडीएफआईफिकेशन मैट्रिक्स) में सेलेक्शन कौर्डिनेट्स के संदर्भ में ऑटोमोबाइल क्षेत्र शामिल नहीं है, इस क्षेत्र में हमारी रुचि मुख्य रूप से ऊर्जा दक्ष ईंधन द्वारा संचालित होने वाले भारत के घरेलू परिवहन किलोमीटर के निम्न प्रतिशत से प्रेरित है (चित्र 2.3 देखें) और इस क्षेत्र को हरित बनाने के लिए की गई अनेक नीतिगत पहलें (जैसे बीएस VI मानक, ईवी प्रोत्साहन आदि)। ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इन उपायों के प्रभाव पर खंड IV.सी में विस्तार से चर्चा की गई है।

विद्युत, रसायन और ऑटोमोबाइल उत्पादन के अलावा, अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्र परोक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं में विद्युत, पेट्रोल/डीजल, कोयले के उपयोग के आधार पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए, हम विभिन्न क्षेत्रों की परोक्ष निर्भरता के स्तर की भी जांच करते हैं।

IV. ईंधन स्रोत

ए. विद्युत

चित्र 5.1 तीन वर्षों 2010, 2020 और 2021 के लिए कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में विभिन्न प्रकार के संयंत्रों की हिस्सेदारी को दर्शाता है। हम देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों की हिस्सेदारी 2010 और 2021 के बीच बढ़ी है⁵। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसी अवधि के दौरान तापीय ऊर्जा संयंत्रों का हिस्सा अपरिवर्तित रहा है। इस प्रकार, आरईएस संयंत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि, जलीय और नाभिकीय जैसे अन्य प्रकार के संयंत्रों की कीमत पर हुई है, जिनकी हिस्सेदारी में 2010 और 2021 के बीच काफी कमी आयी है।

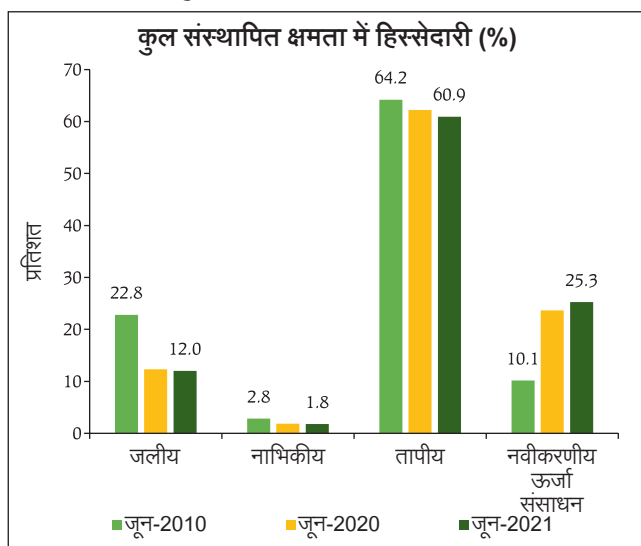
तापीय ऊर्जा संयंत्रों के भीतर (चित्र 5.2), ईंधन का मुख्य स्रोत कोयला रहा है और यह वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। वास्तव में, कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की हिस्सेदारी 2010 और 2021 के बीच 82.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.3 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, जबकि आरईएस संयंत्रों ने धीरे-धीरे वर्षों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है, अधिकांश विद्युत संयंत्र अभी भी तापीय हैं। विद्युत संयंत्र जो विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं।

बी. रसायन और रासायनिक उत्पाद

रासायनिक उत्पादों के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग, अन्य दो क्षेत्रों यथा विद्युत और मूल धातुओं की तुलना में सीमित हो सकता है। हालांकि, हर दूसरी औद्योगिक गतिविधि की तरह, यह क्षेत्र अपने मध्यवर्ती इनपुट के रूप में ऊर्जा का

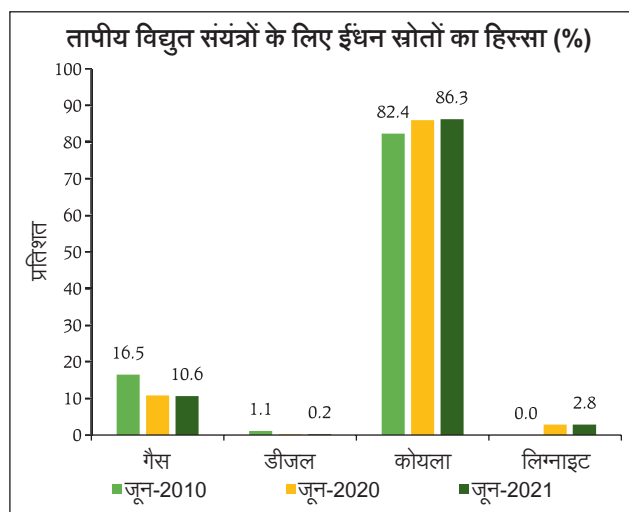
⁵ आरईएस से विद्युत उत्पादन पर डेटा केवल 2018 से उपलब्ध है। कुल उत्पादित विद्युत में आरईएस की हिस्सेदारी 2018 में 8.4 प्रतिशत, 2019 में 9.5 प्रतिशत, 2020 में 10.1 प्रतिशत और 2021 में 10.5 प्रतिशत थी।

चित्र 5.1: कुल संस्थापित क्षमता का वर्गीकरण



स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीईआईसी।

चित्र 5.2: तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन स्रोत

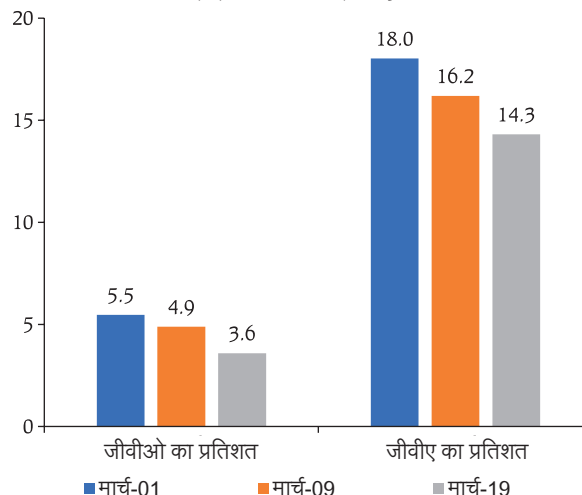


उपयोग करता है। चित्र 3.1 से पता चलता है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र मुख्य रूप से पारंपरिक या जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर निर्भर है। इस संबंध में, आगामी वर्षों में रासायनिक क्षेत्र को ऊर्जा उपयोग पोर्टफोलियो में किसी भी परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के एक्सपोजर से भी अवगत कराया जाएगा। चित्र 6 में हमारे अनुमान बताते हैं कि ऊर्जा संबंधी लागतों का हिस्सा इस क्षेत्र द्वारा उत्पादित सकल उत्पादन के मूल्य का लगभग 3.6 प्रतिशत है। हालांकि, इस सदी की शुरुआत के बाद से इसकी हिस्सेदारी में काफी कमी आयी है। योजित सकल मूल्य के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा उपयोग में भी इसी प्रकार की कमी आयी है (चित्र 6)।

सी. ऑटोमोबाइल: ईंधन स्रोत

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए स्वच्छ ईंधन स्रोतों को अपनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में स्पष्ट रोडमैप का पालन करने वाले उत्सर्जन मानक, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का केंद्र-बिंदु रहे हैं। भारत ने वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्सर्जन मानकों को बढ़ाने की दिशा में अपना एजेंडा भी निर्धारित किया है। भारत सरकार, यूरोपीय मानकों पर आधारित भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों (बीएस) के तहत दिशानिर्देश जारी करती है। बीएस-IV मानकों को 2017 से

चित्र 6: ऊर्जा इनपुट मूल्य सापेक्षता: रासायन और रासायनिक उत्पाद



टिप्पणी: जीवीओ= उत्पादन का सकल मूल्य; जीवीए= योजित सकल मूल्य
स्रोत: इंडिया क्लेम्स डेटाबेस का उपयोग करके लेखकों द्वारा की गई गणना।

पूरे भारत में लागू किया गया है। 2016 में भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत बीएस-V मानकों के बजाय बीएस-VI मानकों को अपनाएगा। हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीएस-IV पंजीकरण अप्रैल-2020 से बंद हो जाएंगे⁶।

⁶ <https://www.thehindu.com/news/national/sc-bans-sale-of-bs-iv-vehicles-from-2020/article25313685.ece>

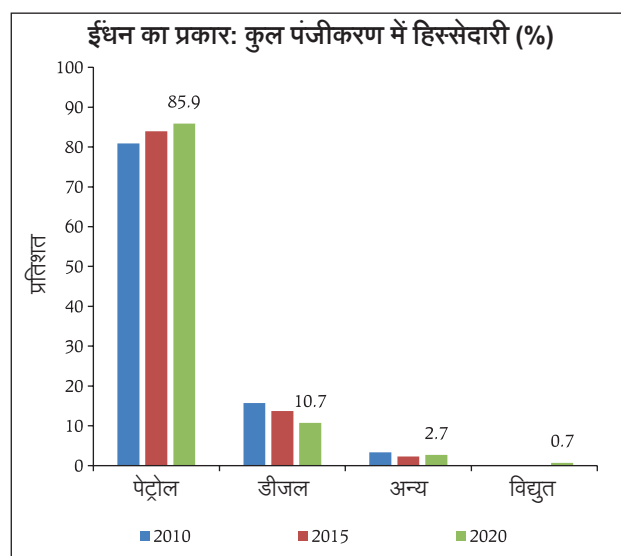
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी-जन्य लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र को कुछ राहत प्रदान की। इन छूटों ने विनिर्माताओं और डीलरों को बीएस-IV वाहनों के अपने स्टॉक को निकालने की अनुमति दी⁷। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का भी संकल्प किया है, जो उत्सर्जन मानकों के लिए ईंधन का एक स्वच्छ स्रोत हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत में कुल वाहनों का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा ही इलेक्ट्रिक होगा⁸। चित्र 4 सभी प्रकार के ईंधन में नए वाहन पंजीकरण की हिस्सेदारी को दर्शाता है। हम देखते हैं कि हालांकि कुल पंजीकरण में हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हुई है, अधिकांश वाहन पेट्रोल पर आधारित हैं। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अधिक जोर की जरूरत है, और यह रातोंरात नहीं हो सकता है। इसके अलावा, भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में

बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है (जैसा कि पिछले खंड में दिखाया गया है), जीवाश्म ईंधन की परोक्ष निर्भरता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हमारी राय में जीवाश्म ईंधन पर पूर्ण निर्भरता को कम करने के लिए, विद्युत-आधारित वाहनों की ओर रुख के साथ-साथ विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर एक समन्वित कदम होना चाहिए। हालांकि, सार्वजनिक नीति को इस तरह के संक्रमण के दौरान जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में रोजगार के परिणामी नुकसान का संज्ञान लेने और उचित उपायों के साथ इस अल्पकालिक समस्या को दूर करने की आवश्यकता है।

V.1 बैंक क्रेडिट: प्रत्यक्ष प्रभाव

मार्च 2020 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया बैंक क्रेडिट में विद्युत उत्पादन का हिस्सा क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत था (चित्र 8)। मार्च 2010 और मार्च 2020 के बीच सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बकाया ऋण में विद्युत की हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि हुई। दूसरी ओर,

चित्र 7: ईंधन के प्रकार पर आधारित ऑटोमोबाइल पंजीकरण

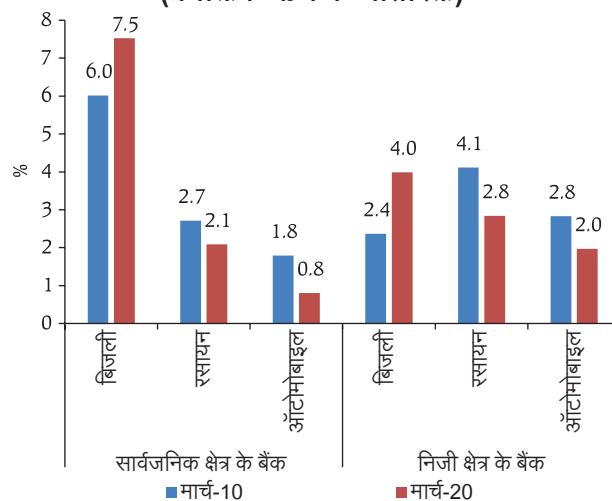


स्रोत: वाहन, सीईआईसी।

⁷ <https://www.financialexpress.com/auto/industry/supreme-court-extends-bs4-vehicle-registrations-ban-next-hearing-on-august-13-registerbharat-stage4-bs5-vehicle-after-april-2020-fada-dealership/2041054/>

⁸ <https://inc42.com/infocus/electric-vehicles-this-week/electric-vehicles-this-week-assessing-indias-2030-electric-mobility-goals-more/>

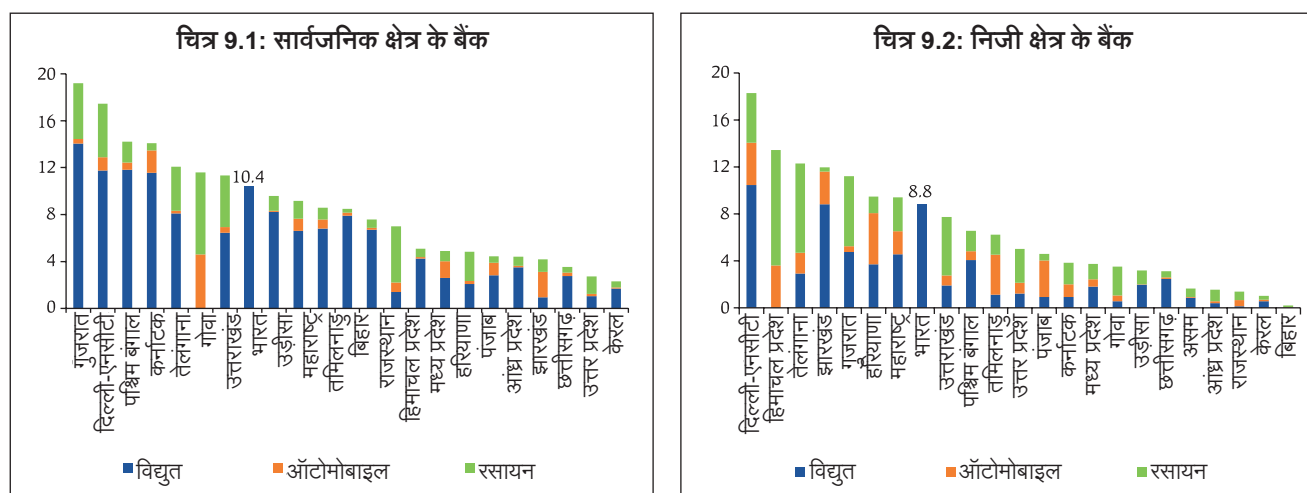
चित्र 8: कुल बकाया क्रेडिट में उद्योग की हिस्सेदारी (वैयक्तिक ऋण के अतिरिक्त)



टिप्पणी: बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल नहीं हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना, सीईआईसी।

चित्र 9: बकाया बैंक क्रेडिट- मार्च 2020 में बिजली, रसायन और ऑटोमोबाइल उत्पादन की हिस्सेदारी



टिप्पणी: बैंक क्रेडिट में वैयक्तिक ऋण शामिल नहीं हैं। बिजली में नवीकरणीय स्रोत सम्मिलित नहीं हैं।
स्रोत: लेखकों की गणना; डीबीआईआई, आरबीआई।

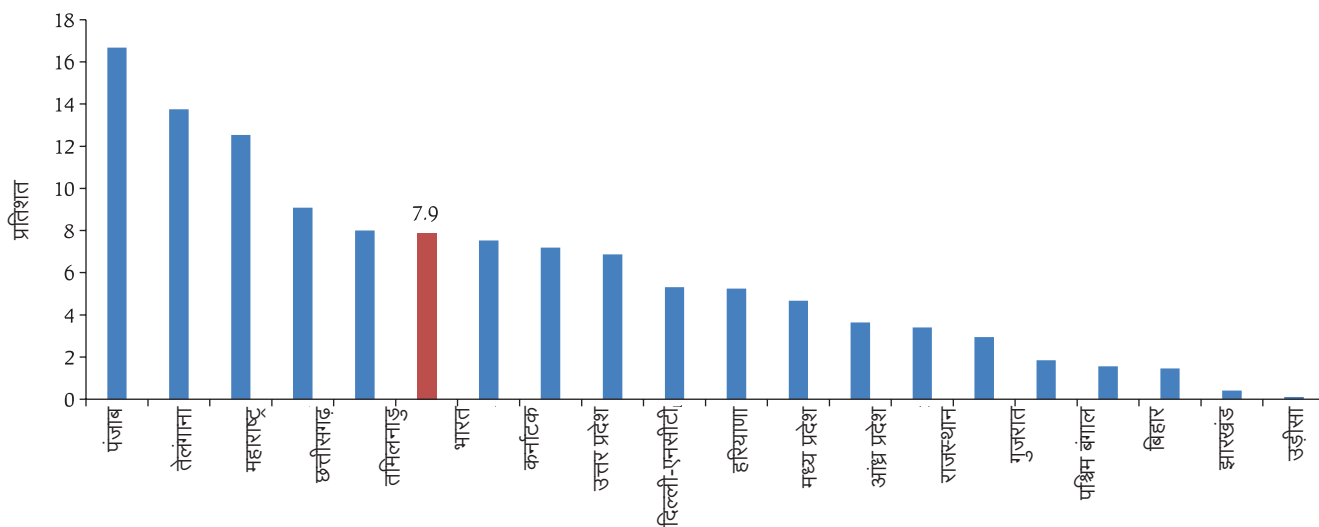
इसी अवधि के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए, मार्च 2020 के अंत में ऑटोमोबाइल उद्योगों में बैंक ऋण का हिस्सा क्रमशः 0.8 और 2.0 प्रतिशत पर सबसे कम था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी में 2010 से कमी आयी है।

इन क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर के संदर्भ में राज्यों में व्यापक भिन्नता मौजूद है (चित्र 9.1 और 9.2)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गोवा के मामले में इन तीन क्षेत्रों का कुल हिस्सा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इन राज्यों में गोवा को छोड़कर, विद्युत उत्पादन क्षेत्र हेतु बैंक क्रेडिट का हिस्सा सबसे अधिक है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विद्युत उत्पादन, हालांकि, राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्यों में केवल दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र के मामले में अन्य दो क्षेत्रों से अधिक है।

उपरोक्त चार्ट से, यह आकलन किया जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र का 3-जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष एक्सपोजर खतरनाक नहीं हो सकता है, यह देखते हुए कि कुल बैंक क्रेडिट में विद्युत उत्पादन, रासायनिक उत्पादों और ऑटोमोबाइल का संयुक्त हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लगभग 10 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लगभग 9 प्रतिशत है।

बैंकिंग क्षेत्र का एक्सपोजर अब तक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तक सीमित रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर, विद्युत उद्योग में नियोजित बैंक क्रेडिट का केवल 8 प्रतिशत हिस्सा गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए है (चित्र 10)। पंजाब में यह अनुपात 17 फीसदी से लेकर ओडिशा में 0.1 फीसदी तक है। हालांकि, उपयोगिता क्षेत्र के क्रेडिट में गैर-पारंपरिक ऊर्जा का हिस्सा निजी क्षेत्र के बैंकों (14.8 प्रतिशत) के लिए अधिक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 5.2 प्रतिशत है (सारणी 2)।

चित्र 10: गैर-पारंपरिक ऊर्जा वित्त का हिस्सा: मार्च 2020 की स्थिति में



स्रोत: लेखकों की गणना; डीबीआईआई, आरबीआई।

सारणी 2: मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए बकाया बैंक क्रेडिट

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	अन्य बैंक
बकाया राशि (भारतीय रुपये करोड़ में)	21,655	12,302	2,586
उपयोगिता क्षेत्र क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में	6.2%	11.9%	27.1%
कुल बैंक क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में	0.5%	0.5%	0.7%

टिप्पणी: उपयोगिता= बिजली, गैस और जल की आपूर्ति

स्रोत: बीएसआर, आरबीआई, लेखकों की गणना।

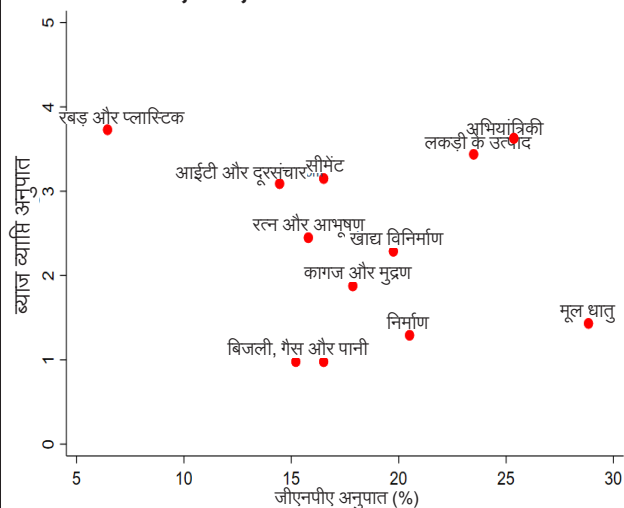
V.2 बैंक क्रेडिट: परोक्ष प्रभाव

पिछला खंड विद्युत क्षेत्र, रसायन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर पर चर्चा करता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के संबंध में नीति में किसी भी परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह इन तीन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आदानों में से एक है। तथापि, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में विद्युत, पेट्रोल/डीजल, कोयले का उपयोग करने के कारण परोक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन के एक्सपोजर में हैं। भारत में उत्पन्न कुल विद्युत का 62.2 प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है (बाकी नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म स्रोतों से)। विभिन्न उद्योगों के जीवाश्म ईंधन के परोक्ष जोखिम पर खंड III(ए) में चर्चा

की गई है। इस खंड में, हम ब्याज व्याप्ति अनुपात और जीएनपीए अनुपात के माध्यम से इस परोक्ष एक्सपोजर के लिए बैंकों की क्षेत्रीय संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हैं।

जिन क्षेत्रों में परोक्ष एक्सपोजर के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की उच्च इनपुट तीव्रता है, वे निम्न हैं: सीमेंट, मूल धातु, कागज के उत्पाद और वस्त्र (चित्र 3)। हम मानते हैं कि हरित ऊर्जा की

चित्र 11: ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) और जीएनपीए का क्षेत्रवार स्कैटरप्लॉट



स्रोत: लेखकों की गणना; सीआईआईसी।

⁹ स्रोत: सीईए, जून-2020 तक।

और संक्रमण और इनपुट मिश्रण में बदलाव के कारण, अल्पावधि में इन क्षेत्रों में इनपुट लागत पर कुछ दबाव हो सकता है। बाजार संरचनाओं और कीमत निर्धारण क्षमता के आधार पर, लागत में यह वृद्धि अंतिम उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती है या फर्मों द्वारा वहन की जा सकती है। दूसरे परिदृश्य में, प्रतिनिधि फर्म का ब्याज, कर और परिशोधन पूर्व अर्जन (ईबीआईटीए) में कमी आ सकती है जिससे ऋण सेवाक्षमता बिगड़ सकती है। यह बदले में, ऐसे क्षेत्रों के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि का कारण बन सकता है। चित्र 11 विभिन्न क्षेत्रों के ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) और मौजूदा जीएनपीए अनुपात को दर्शाता है। कुल मिलाकर, ऐसे सभी उद्योगों की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है जिनमें निम्न आईसीआर, उच्च जीएनपीए अनुपात और उच्च ऊर्जा इनपुट तीव्रता है ताकि व्यापक बैंकिंग क्षेत्र में स्पिलओवर को रोका जा सके।

VI. निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन और विभिन्न नीतिगत प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता के संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, यह आलेख भारतीय बैंकों के जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष और परोक्ष एक्सपोजर की जांच करता है। यह देखा गया है कि विद्युत, रसायन और ऑटोमोबाइल जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले तीन क्षेत्रों के बकाया बैंक क्रेडिट का संयुक्त हिस्सा सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के बैंकों के लिए कम है। दूसरी ओर, कई अन्य उद्योग परोक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं और बैंक ऋण के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ में इस समय कम आईसीआर और उच्च जीएनपीए

अनुपात है और इस प्रकार हरित ऊर्जा में संक्रमण के दौरान गहन निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

संदर्भ:

Dilip, A. and Kundu, S. (2020), "Climate Change: Macroeconomic Impact and Policy Options for Mitigating Risks", *Reserve Bank of India Bulletin*, April.

Ghosh, S. Nath, J. and Ranjan, A. (2021), "Green Finance in India: Progress and Challenges", *Reserve Bank of India Bulletin*, January.

Herwadkar, S. S (2017), "Corporate leverage in EMEs: did the global financial crisis change the determinants?", *BIS Working Papers*, No 681

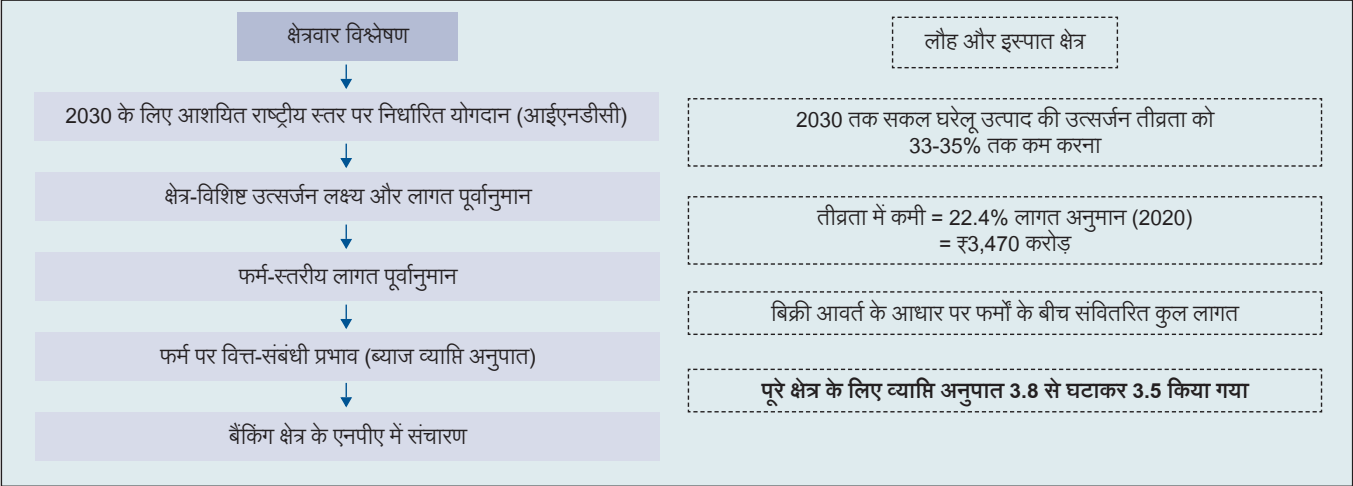
IMF (2019), "Fiscal Monitor-How to Mitigate Climate Change", October, Washington DC, USA.

Jain, S. (2020), "Financing India's Green Transition", *ORF Issue Brief No. 338, January 2020, Observer Research Foundation*

Krogstrup, S., W. Oman, (2019), "Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature", *IMF Working Paper*, No. 19/185

State of the Economy (2021), *Reserve Bank of India Bulletin*, December

अनुबंध



स्रोत: वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, जुलाई 2021 ।

एनबीएफसी के भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य अनुक्रम की व्याख्या*

यह आलेख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उनके उचित मूल्य अनुक्रम के संदर्भ में आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण में रुझानों की जांच करता है, जैसा कि इन कंपनियों द्वारा इंड एसएस प्रारूप में प्रकाशित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इंड एसएस ने चलनिधि की सीमा को दर्शाने के लिए उन आस्तियों/ देयताओं के उचित मूल्य अनुक्रम का प्रकटीकरण भी शुरू किया है जिन्हें सामान्य रूप से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। विशेष रूप से, आलेख स्तर 3 की आस्तियों को देखता है जिन्हें चलनिधि के रूप में नहीं माना जाता है और ऐसी कंपनियों जिनके वित्तीय विवरणों में उनका प्रसार होता है। विशेष रूप से, आलेख एनबीएफसी के लिए स्तर 2 और 3 के अनुक्रमों के बीच काफी हद तक अतिव्यापन का अवलोकन करता है।

1. भूमिका

वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण लेखांकन विकास भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एसएस) का अनुप्रयोग है, जो भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय विवरणों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत रिपोर्टिंग मानकों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप हैं। इंड-एसएस का एक अनिवार्य तत्व आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन के लिए उचित मूल्य की अवधारणा का अनुप्रयोग है। यह आलेख इंड एसएस 113 पर केंद्रित है जो आस्ति और देयताओं के उचित मूल्य-माप और एनबीएफसी के लिए इसके प्रभाव से संबंधित है। किसी आस्ति का उचित मूल्य आमतौर पर बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसलिए उतार-चढ़ाव के अधीन होता है। यह लगभग सबसे अच्छी कीमत भी प्रदान करता है जो एक आस्ति को बाजार में बेचने से मिलेगा या वर्तमान में एक देयता को समाप्त करने के लिए भुगतान करने

की आवश्यकता का सबसे अच्छा अनुमान प्रदान करता है, यही वह आसान रास्ता है जिसके साथ उन्हें तरलीकृत (संपत्ति) या परिसमाप्त (देयता) किया जा सकता है। वर्तमान समय में ऐतिहासिक लागतों को कम किया जाता है, क्योंकि वे अधिग्रहण लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और शायद समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं और इंड-एसएस 113 का गहन अध्ययन करते हैं, आईएनडी-एसएस के तहत मानक जो उचित मूल्य और उसके अनुक्रम के विषय से संबंधित है, यह समझना आसान होगा कि लेखा मानक क्यों चाहते हैं कि लेखाकार उन आस्तियों/ देयताओं जिनका उचित मूल्य नहीं हो सकता है, उनके निकटतम उचित या वर्तमान मूल्यों को भी दर्शाये।

इंड एसएस 113 के तहत, आस्तियों और देयताओं को उद्धृत कीमतों की उपलब्धता और अवलोकनीय बाजार निविष्टियों के आधार पर तीन स्तरों के तहत वर्गीकृत किया जाता है - स्तर 1, 2 और 3। यह आलेख स्तर 3 की आस्तियों और देयताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिसके लिए माप की तारीख पर बहुत कम या कोई बाजार गतिविधि नहीं होती है, जिससे ऐसी आस्तियों और देयताओं के लिए निविष्टियां अनवलोकनीय हो जाती हैं।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के तत्काल बाद, बाजार की कीमतों की खोज और “मार्क टू मार्केट” पर जोर जल्द ही चिंता में बदल गयी जब आस्तियों को वैश्विक मंदी में बाजार मूल्य नहीं मिल सका। उचित मूल्यों के मूल्यांकन को भारी नुकसान हुआ और उपयोग किए गए मैट्रिक्स और फॉर्मूले की सत्यता पर आक्षेप लगाए गए, जोखिमपूर्ण आवासीय आस्तियों के मूल्य के लिए अपनाई गई आंतरिक पद्धतियां, जिन्हें तुलनीय मूल्य नहीं मिला। इनमें से अधिक प्रमुख स्तर 3 की आस्तियां थीं जिन्हें उचित मूल्य के निर्धारण के लिए कुछ मान्यताओं, अनुमानों और मॉडलों की आवश्यकता थी।

इसलिए, एक संभावित निवेशक जो एक एनबीएफसी की पूंजी की सदस्यता लेना चाहता है के दृष्टिकोण से स्तर 1, 2 या 3 के तहत आस्तियों को वर्गीकृत करने के पीछे तर्क को समझना आवश्यक है। ऐसे निवेशक निवेशिती कंपनी की चलनिधि और शोधन क्षमता में रुचि लेंगे और यहीं पर इस तरह के वर्गीकरण के लिए पर्याप्त औचित्य प्रासंगिक हो सकता है। इस तरह का औचित्य लेखा परीक्षकों और नियामकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा,

* यह आलेख आर केशवन, आरबीआई, कोलकाता और सैयद मुशरफ अली, आरबीएससी, आरबीआई, चेन्नई द्वारा लिखा गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आलेख में महत्वपूर्ण योगदान/सुझावों के लिए एम. श्रीरामुलु, आरबीएससी के प्रति बहुत आभार।

खासकर जब आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अनिवार्य कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास करता है:

- ए. क्या उचित मूल्य समय पर सभी बिंदुओं पर निर्धारित किया जा सकता है?
- बी. क्या ऐसी आस्तियां जिनका उचित मूल्य नहीं हो सकता, कुछ फायदे और/या नुकसान के साथ आती हैं?
- सी. क्या एक मॉडल के रूप में लागत उचित है जब उपलब्ध बाजार मानदंड के संबंध में उचित मूल्यों को नहीं मापा जा सकता है?
- डी. क्या कंपनियां किसी आस्तियों से नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए कुछ मॉडलों (उदाहरण के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ)) की ओर झुक रही हैं?
- इ. क्या व्यापार मॉडल में बदलाव के कारण स्तरों के अनुक्रम में कोई बदलाव आया है?
- एफ. क्या स्तर 2 और 3 अनुक्रमों के बीच ओवरलैप हैं और ऐसे ओवरलैप को कैसे हल किया जाए?
- जी. तुलन पत्र पर स्तर 3 की आस्तियों के सार को निकालने में प्रकटीकरण कितने उपयुक्त हैं?
- एच. क्या एनबीएफसी के व्यापार मॉडल और उनकी स्तर 3 की आस्तियों की सीमा के बीच कोई संबंध है?

आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के लिए इंड 113 के तहत उचित मूल्य अनुक्रम के लिए कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है। खंड 2 अध्ययन के लिए तैयार किए गए एनबीएफसी के नमूने का विवरण देता है, जबकि खंड 3 अध्ययन के लिए उपयोग किए गए नमूने के विवरण पर चर्चा करता है। खंड 4 मुख्य निष्कर्ष प्रदान करता है और खंड 5 निष्कर्ष है।

2. इंड एसएस के तहत उचित मूल्य अनुक्रम

इंड एसएस 113 के तहत उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने से प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को

स्थानान्तरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। इंड एसएस आस्ति और देयताओं को उचित मूल्य अनुक्रम के तीन स्तरों के तहत वर्गीकृत करता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

1. **स्तर 1-** वित्तीय आस्तियां (देयताएं) को समान आस्तियों (देयताओं) के लिए सक्रिय बाजारों में असमायोजित उद्धृत कीमतों के संदर्भ में मापा जाता है।
2. **स्तर 2-** उचित मूल्य को स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो आस्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमत) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) देखे जाते हैं। जैसे क्रेडिट स्प्रेड, प्रतिफल वक्र का उपयोग करके मूल्यांकन करना।
3. **स्तर 3-** उचित मूल्य को ऐसी निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अनवलोकनीय निविष्टि) पर आधारित नहीं होते हैं। इसके बजाय, उचित मूल्यों का निर्धारण उन मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके किया जाता है जो न तो अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं। जैसे गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन।

जाहिर है, उनकी अंतरलता के कारण, स्तर 3 की आस्तियों को मापना या मूल्य निर्धारण करना मुश्किल है। इन आस्तियों का अक्सर व्यापार नहीं किया जाता है, और इसलिए उन्हें एक विश्वसनीय और सटीक बाजार मूल्य प्रदान करना मुश्किल है।

3. अध्ययन के लिए प्रयुक्त एनबीएफसी का नमूना

इस अध्ययन के लिए, हमने दस एनबीएफसी की पहचान की, जिन्होंने 2018-19 और 2019-20 के दौरान इंड-एसएस का पालन करते हुए अपने वित्तीय विवरण प्रकाशित किए। हमारे नमूने में विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी को शामिल करने का भी एक सचेत प्रयास किया गया था। इन दस चयनित एनबीएफसी की कुल आस्ति का आकार मार्च 2020 के अंत तक एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्ति का 6.2 प्रतिशत है। इन दस एनबीएफसी में से पांच 'ऋण कंपनियां', तीन 'निवेश कंपनियां', एक 'आस्ति वित्त कंपनी' और 'प्रमुख-निवेश कंपनी' है। 22 फरवरी, 2019 के आरबीआई परिपत्र के तहत एनबीएफसी श्रेणियों के सामंजस्य के बाद, 'ऋण कंपनी (एलसी)', 'निवेश कंपनी (आईसी)' और 'एसएट फाइनेंस

कंपनी (एएफसी) की इन श्रेणियों को एक नई श्रेणी 'निवेश और क्रेडिट कंपनी (आईसीसी)' में विलय कर दिया गया है।

4. अध्ययन से निष्कर्ष

i. **प्रकटीकरण के लिए सामान्य प्रारूपों का अभाव** - हालांकि इन कंपनियों के इंड-एस के तहत वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग शुरू करने के बाद से दो साल बीत चुके हैं, उनमें से अधिकांश ने सामान्य प्रारूपों और जानकारी को प्रकट करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा था।

ii. **उचित मूल्य को मापने के लिए एक प्रमुख विधि के रूप में “लागत” का उपयोग** - इंड एस उचित मूल्य को मापने के तीन अलग-अलग तरीकों को संदर्भित करता है: (i) लागत पर मापन यानी वर्तमान प्रतिस्थापन लागत; (ii) परिसर के आधार पर कुछ मूल्यांकन मॉडल का अनुप्रयोग जो अपेक्षित नकदी प्रवाह और उनके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने में मदद करते हैं - इस श्रेणी के तहत उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि “रियायती नकदी प्रवाह” विधि है (जिसे आय दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है); (iii) उपलब्ध बाजार मूल्यों (जिसे बाजार दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है) के आधार पर, जो उचित मूल्यों का बेहतर माप प्रदान करता है।

हमारे नमूने में, कंपनियों को आम तौर पर अपने कई निवेशों के उचित मूल्य माप के लिए “ऐतिहासिक लागत” को अपनाते हुए देखा गया था। उनमें से सबसे प्रमुख गैर-उद्धृत लिखत और वरीयता शेयर थे। इन लिखतों को एक आसान मानदंड नहीं मिलता है जिससे उनके मूल्यों की तुलना की जा सके और इसलिए लागत पर मूल्य दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर कंपनियों में इन्हें स्तर 3 की आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, “ऐतिहासिक लागत” पर मापी गई आस्तियों/देयताओं को गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार, इंड-एस

113 के महत्वपूर्ण नियमों में से एक यह है कि लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय पर स्तर 3 की आस्ति के प्रभाव को अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना चाहिए¹।

“लागत” मॉडल के नुकसान दो आयामी हैं। तुलनीय उत्पादों पर पर्याप्त बाजार जानकारी के अभाव में, यह पता लगाना लगभग असंभव हो सकता है कि ऐसे लिखतों का उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से अधिक है या उससे कम है। यह मानते हुए कि यह नीचे है, निवेश वास्तव में “नुकसान प्रावधान” के योग्य गैर-निष्पादित होगा; यदि यह “लागत” से ऊपर है, तो कंपनी शायद लाभ के एक महत्वपूर्ण स्रोत से चूक रही है। किसी भी तरह से सभी स्तर 3 की आस्तियों की जांच करना समझ में आता है जब उनका मूल्य “लागत” पर होता है।

iii. **स्तर 2 और स्तर 3 की आस्तियों के बीच ओवरलैप** - हमने देखा कि स्तर 3 की आस्तियों का स्तर 2 की आस्तियों पर बिना ध्यान दिए या इसका संदर्भ लिए बिना अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों का सीमांकन करने वाली रेखा काफी बारीक थी। अनुक्रम के निर्धारण के लिए ज़रूरी है कि मूल्यांकन पद्धति को पर्याप्त रूप से समझा जाए। हालांकि, उपयोग की गयी निविष्टियों के आधार पर स्तर 2 और स्तर 3 के बीच अनुक्रम के स्तर बदलते रहते हैं²।

iv. **मानकीकृत और स्पष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता** - उपयोग की जाने वाली अप्राप्य निविष्टियों की सीमा आस्तियों के उचित मूल्य अनुक्रम को तय करती है। उदाहरण के लिए, बाजार के अवलोकन योग्य डेटा जैसे द्वितीयक बाजार मूल्य का उपयोग करने में स्तर 2 निर्धारण की कुछ डिग्री है। हालांकि, यदि नकदी प्रवाह के आकलन में धारणाओं के रूप में महत्वपूर्ण अदृश्य निविष्टियाँ हैं जो छूट दर के आकलन के लिए आधार बनाते हैं, तो यह आस्ति/देयताओं को मुख्य रूप से स्तर 3 का बना देते हैं। यह ऋणों के मामले में अधिक स्पष्ट है (विशिष्ट “परिशोधन लागत” आस्तियाँ) जिनके उचित मूल्य प्रतिपक्षकारों के क्रेडिट जोखिम को

¹ केपीएमजी कार्यान्वयन गाइड (2021 में अद्यतन किया गया) [<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2021/03/ind-as-itfg-interpretations-application-issues.pdf>]

² पीडबल्यूसी इंड-एस प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण जांचसूची [<https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2018/ind-as-presentation-and-disclosure-checklist-2018.pdf>]

शामिल करते हुए बाजार दरों का उपयोग करके छूट वाले संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार हम दो प्रकार के आदानों का संगम देखते हैं - बाजार दरों के रूप में स्तर 1 या 2 निविष्टियां और स्तर 3 की अनवलोकनीय निविष्टि जो प्रतिपक्ष के क्रेडिट जोखिम के निर्धारण में जाते हैं जहां किसी इकाई को उपयुक्त क्रेडिट जोखिम स्प्रेड तक पहुँचाने के लिए अपने स्वयं के मॉडल का उपयोग करना पड़ता है। यही तर्क उधार (देयताओं) पर इसके विपरीत लागू होता है। स्पष्ट रूप से, एनबीएफसी द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधियों को समझने के लिए मानकीकृत और स्पष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

हमने देखा कि निवेश संपत्ति, जो कि किराये की आय अर्जित करने के लिए नियोजित आस्ति है या निवेश की सराहना के लिए रखी गई है, को मूल्यांकन में जाने वाले अनवलोकनीय निविष्टि की सीमा के आधार पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा अलग-अलग उचित मूल्य अनुक्रमों पर रखा गया था। निवेश संपत्ति को स्तर 3 के वर्गीकरण पर रखा गया था क्योंकि जब एक बाहरी विशेषज्ञ या दलाल ने संपत्ति का मूल्यांकन किया तो मॉडल निविष्टि बाहरी थी। हालांकि, निवेश संपत्ति जब उचित मूल्य स्तर 3 के रूप में मूल्यांकित होती है, तो काफी उच्च मूल्य दर्ज किया जाता है। कुछ कंपनियों ने इस आस्ति को स्तर 2 की श्रेणी में रखा था जब समान संपत्ति की संबंधित कीमतों पर बाजार डेटा के रूप में अवलोकन योग्य निविष्टियां उपलब्ध थीं।

- v. मूल्यांकन के लिए अनवलोकनीय निविष्टियों को समझने की आवश्यकता-** हमने स्तर 3 की आस्तियों को मापने और प्रकट करने में उपयोग की गई निविष्टि के गहन विश्लेषण और समझने की आवश्यकता देखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतिम बिक्री मूल्य आवश्यक रूप से स्तर 3 का उपयोग करके अनुमानित मूल्य से मेल नहीं खाता था। इससे इस तरह के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की गई निविष्टि पर संदेह पैदा हुआ। इसलिए, समाधान उपयोग की गई निविष्टि की समीक्षा करने में है, खासकर जब अनुमान परिणाम से असहमत हो जाते हैं। निविष्टियों को बेहतर बनाना और विशिष्ट निविष्टि का उपयोग करने के लिए सहायक साक्ष्य होना भी आवश्यक है।

- vi. छूटप्राप्त नकद प्रवाह पद्धति (डीसीएफ): स्तर 3 आस्तियों के मूल्यांकन के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका** - डीसीएफ पद्धति स्तर 3 की आस्ति मूल्यांकन के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका था। अधिकांश कंपनियों ने ऋण प्रतिभूतियों और अन्य उधारों के उचित मूल्यों की गणना करने के लिए इस विधि का उपयोग किया, जो आमतौर पर उचित मूल्यांकन पर नहीं ले जाती। डीसीएफ पद्धति पर विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है। नमूना कंपनियों में से किसी ने भी समायोजित वर्तमान मूल्य (एपीवी) विधि या पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) जैसी किसी अन्य विधि का उपयोग नहीं किया है। हालांकि, डीसीएफ पद्धति काफी हद तक मान्यताओं पर आधारित है और इसलिए अधिक से अधिक खुलासे की आवश्यकता है।

- vii. व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य अनुक्रम में बदलाव³** - व्यापार मॉडल में एक परस्पर क्रिया हो रही थी जो कंपनियों को मूल रूप से उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ आस्तियों / देयताओं को “परिशोधित लागत” मॉडल में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करती थी। उदाहरण के लिए, यह देखा गया कि कुछ कंपनियों ने शुरू में ऋणों को अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया क्योंकि व्यवसाय मॉडल ने आंशिक समनुदेशन ही सही ऋणों की बिक्री की परिकल्पना की थी। इसलिए, इस तरह के ऋणों को मूल रूप से एफवी अनुक्रम स्तर 2 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो बाजार के आंकड़ों जैसे अवलोकन योग्य निविष्टियों पर आधारित था। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों परिशोधन लागत लिखत और एफवीओसीआई लिखतों में आम तौर पर संविदात्मक नकदी प्रवाह को “इकट्ठा करने के लिए रोकने” की विशेषताएं होती हैं, बाद वाला एक अतिरिक्त कारक, यानी “आस्तियों की बिक्री” के कारण भिन्न होता है। इसके बाद, कंपनियों ने अपनी ऋण आस्तियों के लिए एक परिशोधित लागत वर्गीकरण को अपनाने का विकल्प चुना जिसके परिणामस्वरूप स्तर 3 पर वर्गीकरण हुआ क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि वे अब बिक्री के लिए ऋण नहीं रखेंगे (सारणी 1)।

³ इंड एस 109 के पैराग्राफ 8.4.4.1 के संदर्भ में, व्यवसाय मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है।

सारणी 1: एफवीओसीआई आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋणों की तुलनात्मक स्थिति -व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन

विवरण	उचित कीमत माप (31 मार्च, 2020 तक)			कुल
	सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
एफवीओसीआई के तहत निर्दिष्ट ऋण	-		-	-
(₹ करोड़)				
विवरण	उचित कीमत माप का उपयोग कर (31 मार्च, 2019 तक)			कुल
	सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
एफवीओसीआई के तहत निर्दिष्ट ऋण	-	4962	-	4962

इसके अलावा, ऐसे कुछ उदाहरण थे जब कंपनियों ने व्यवसाय मॉडल में बदलाव के साथ अनुक्रम को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने का विकल्प चुना। इस शीर्ष के तहत देखे गए रुझानों को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम “परिशोधन लागत”, “एफवीओसीआई” के रूप में वर्गीकृत और “लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)” पर मापे जाने वाले वित्तीय लिखतों की सटीक विशेषताओं को समझ लें। वर्गीकरण और बाद की माप आवश्यकताओं को अनुबंध 2 में संक्षेपित किया गया है।

इस प्रकार, हम दो परिवर्तनों के उद्भव को देखते हैं, एक वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण में, दूसरा उचित मूल्य अनुक्रम में।

बेशक, ये बदलाव तार्किक लग रहे थे। इसका कारण यह है कि एफवीओसीआई आस्तियां वे हैं जहां सामान्य रूप से अन्य व्यापक आय के विवरण में उचित मूल्य परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं (और इस प्रकार निवल मूल्य/इक्विटी में वृद्धि हो सकती है), जबकि नियमित ब्याज धाराएं लाभ और हानि खाते से गुजरती हैं। कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल में बदलाव को समझा जा सकता था क्योंकि ऋणों को परिशोधन लागत लिखतों के रूप में सबसे अच्छी तरह दर्शाया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि कंपनी ने ऐसे ऋणों की बिक्री/समनुदेशन को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। दूसरे, स्तर 2 (पहले एफवीओसीआई में मापा गया ऋण) से स्तर 3 तक एक संभावित बदलाव, अपेक्षित नुकसान जैसे अप्राप्य निविष्टियों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी तार्किक दिखाई दिया।

हालाँकि, दिलचस्प बात यह थी कि मूल धारक कंपनी ने इन ऋणों को एफवीओसीआई - स्तर 2 (सारणी 2) के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा। एक ही समूह की कुछ कंपनियां दूसरों की तुलना में एक ही आस्ति के लिए वर्गीकरण के एक रूप को क्यों बरकरार रखती हैं, इस सवाल को अधिक गहन विश्लेषण की आवश्यकता है।

सारणी 2: स्तर 3 की आस्तियों की मूल कंपनी का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

उचित कीमत पर मापे गए वित्तीय लिखतों के लिए उचित कीमत माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण (31 मार्च, 2020)					
विवरण	डेटा मूल्यांकन	उचित कीमत माप			कुल
		सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
एफवीटीपीएल के तहत व्यापार के लिए धारित निवेश	31 मार्च, 2020	14439	-	-	14439
एफवीओसीआई के तहत डिजाइन किया गया इक्विटी लिखत (उद्धृत नहीं)*	31 मार्च, 2020	-	-	262	262
एफवीओसीआई के तहत डिजाइन किया गया इक्विटी लिखत (उद्धृत)	31 मार्च, 2020	150	-	-	150
एफवीओसीआई के तहत नामित अन्य निवेश	31 मार्च, 2020	2765	-	-	2765
एफवीओसीआई के तहत नामित ऋण	31 मार्च, 2020	-	21660	-	21660
व्युत्पन्न आस्ति	31 मार्च, 2020	-	172	-	172
		17354	21832	262	39448

स्रोत: एनबीएफसी के एक नमूने की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

viii. अनुक्रम के स्तरों को निर्धारित करने की विषयवस्तु:

एफवीटीपीएल के तहत निवेश को सभी अनुक्रमों के तहत वर्गीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए, इक्विटी शेयर और शेयर प्रीमियम को स्तर 3 की आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो दर्शाता है कि ऐसी वित्तीय आस्ति को उद्धृत नहीं किया गया था। हालांकि, कुछ कंपनियों ने उन्हें स्तर 1 की आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया, जो उस पर बाजार डेटा की उपलब्धता का संकेत देता है। इसलिए, लिखतों के चयन के मामले में अधिक विवेकपूर्ण विकल्प (अधिक स्तर 1 या 2) ऐसी कंपनियों के चलनिधि प्रबंधन में विश्वास को प्रेरित कर सकता है (सारणी 3)। ट्रेडिंग के लिए धारित निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी।

स्तर 3 की आस्तियों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता “सुरक्षा रसीदे (एसआर)” हैं। इनके संबंध में नकदी प्रवाह अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से वसूलियों पर निर्भर है। चूंकि इसमें पिछले प्रदर्शन के मद्देनजर कुछ अनुभवजन्य अनुमान शामिल हैं, यह स्तर 2 और 3 की निविष्टियों के मिश्रण की व्याख्या कर

सकता है। हालांकि, ज्यादातर कंपनियों ने उन्हें स्तर 2 के अनुक्रम में रखा है। एसआर के मूल्यांकन के विषय पर आरबीआई का दिशानिर्देश (प्रतिभूतिकरण कंपनी/ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी एसआर के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा पर दिशानिर्देश) मानता है कि इनका मूल्य निर्धारण आसान नहीं है क्योंकि ये इक्विटी के साथ-साथ ऋण के तत्वों को जोड़ते हैं और आमतौर पर निजी तौर पर रखे होते हैं और असूचीबद्ध होते हैं। इसके अलावा, इन्हें आदर्श रूप से इस तरह से रेट किया जाना चाहिए कि रेटिंग अंतर्निहित आस्तियों से प्रत्याशित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करने में सक्षम हो।

ix. स्तर 3 के तहत कुछ प्रकार की आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण पर विवरण: उधारकर्ताओं के क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल, गैर-निष्पादन की सीमा और चूक जोखिम के तत्वों के रूप में ऋण की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, जो प्रत्येक उधारकर्ता के लिए अद्वितीय हो सकती हैं। इसलिए, उन्हें समान विशेषताओं वाले किसी भी ज्ञात कर्ज के साथ बेंचमार्क नहीं किया जा सकता है, जो आवश्यक रूप से स्तर 3 के अंतर्गत आता है। इसी तरह, अल्पकालिक आस्ति /

सारणी 3: पदानुक्रम के अनुसार आस्तियों का वितरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार				31 मार्च 2019 के अनुसार			
	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल
वित्तीय आस्तियां								
1. एफवीटीपीएल में निवेश:								
इक्विटी शेयर (शेयर आवेदन राशि सहित)	3	-	475	478	8	-	477	485
प्राथमिकता शेयर	-	-	89	89	-	-	100	100
म्यूचुअल फंड	745	-	-	745	2064	-	-	2064
सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1	-	1	-	1	-	1
डिबेंचर	-	-	860	860	-	-	866	866
प्रतिभूति रसीद	-	-	2499	2499	-	-	791	791
निधि की इकाइयाँ	-	-	106	106	-	-	189	189
2. व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	-	155	-	155	-	7	-	7
3. ऋण	-	-	24878	24878	-	-	24396	24396
4. एफवीटीओसीआई में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
डिबेंचर	-	1162	-	1162	-	2265	-	2265
सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	38	-	38
प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र	-	-	7	7	-	-	8	8
इक्विटी शेयर	32	-	-	32	-	-	-	-
निधि की इकाइयाँ	-	1	-	1	-	1	-	1
कुल वित्तीय आस्तियां	780	1319	28914	31013	2072	2312	26827	31211

स्रोत: एक नमूना एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20

सारणी 4: स्तर 3 के रूप में अल्पकालिक देयताओं/आस्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

उचित मूल्य पर नहीं मापे गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य (31 मार्च, 2020)					
अचल आस्तियां	मूल कीमत	उचित कीमत माप			कुल
		सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
नकद और नकद समकक्ष	675	675	-	-	675
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	5	5	-	-	5
व्यापार प्राप्तियां	867	-	-	867	867
ऋण	113417	-	-	114211	114211
निवेश	20	-	-	20	20
अन्य वित्तीय संपत्ति	350	-	-	350	350
	115333	679	-	115449	116128

स्रोत: एक नमूना एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

देयताओं को स्तर 3 आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें व्यापार प्राप्तियां शामिल हैं, जो उचित मूल्यांकन के किसी भी प्रशंसनीय तरीके से खुद को उधार नहीं देती हैं (सारणी 4)। यही तर्क अल्पकालिक देयताओं के लिए भी है।

इसके अलावा, कुछ हद तक समान स्थिति को देयता पक्ष के साथ-साथ स्तर 2 के देयताओं के रूप में वर्गीकृत “जमा” के साथ देखा जाता है (सारणी 5), जबकि कुछ मामलों में इन्हें स्तर 3 की देयताओं के रूप

सारणी 5: स्तर 2 देयताओं के रूप में वर्गीकृत जमाशियाँ

(₹ करोड़)

मद	मूल राशि	उचित कीमत माप			कुल
		सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
वित्तीय आस्तियां					
नकद और नकद समकक्ष	675	675	-	-	675
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	5	5	-	-	5
व्यापार प्राप्तियाँ	867	-	-	867	867
ऋण	113417	-	-	113211	113211
निवेश	20	-	-	20	20
अन्य वित्तीय आस्तियां	350	-	-	350	350
कुल वित्तीय आस्तियां	115334	680	-	115448	116128
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देनदारियां	637	-	-	637	637
अन्य देनदारियां	179	-	-	179	179
ऋण प्रतिभूतियां	41714	-	42333	-	42333
ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उधार	36923	-	-	36923	36923
जमा	21427	-	21502	-	21502
अधीनस्थ कर्ज़	4142	-	4351	-	4351
अन्य वित्तीय देयताएँ	670	-	-	670	670
कुल वित्तीय देयताएँ	105692	-	68186	38409	106595

स्रोत: एक नमूना एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

सारणी 6: एकाधिक अनुक्रम वाली आस्तियां/देयताएं -कर्ज प्रतिभूतियां

(₹ लाख)

मद	मूल कीमत	उचित कीमत माप			कुल
		सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देनदारियाँ	10.22			10.22	10.22
ऋण प्रतिभूतियाँ	150	150			150
ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उधार	1912.30			1912.30	1912.30
अन्य वित्तीय देयताएँ	28.55			28.55	28.55
कुल वित्तीय देयताएँ	2101.07	150		1951.07	2101.07

स्रोत: एक नमूना एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

में दिखाया जाता है। यह दिलचस्प है क्योंकि सावधि परिपक्वता जमाओं का उचित मूल्य समान परिपक्वता वाली समान जमाराशियों के लिए दरों से पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए, यह जांचना उचित होगा कि जमाराशियों में स्तर 3 के वर्गीकरण में कौन-सी गैर-अवलोकन योग्य निविष्टियाँ योगदान करती हैं।

ऋण प्रतिभूतियाँ, स्वभाव से, बाजार के आंकड़ों के आधार पर उचित मूल्यांकन के साथ उधार देती हैं। यह

स्पष्ट है क्योंकि कई कंपनियों में स्तर 1 या 2 की विशेषताएं हैं (सारणी 6)।

आम तौर पर, कर्मचारियों को ऋण बाजार दरों से कम दरों पर होते हैं और इसलिए उनके उचित मूल्य को तुलनीय ऋण के लिए बाजार दर पर नकदी प्रवाह में छूट देकर मापा जाना चाहिए (सारणी 7)। हालांकि, कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को ऋणों को वहन करने वाली राशि पर महत्व दिया और इसे उचित मूल्य के रूप में माना (स्तर 3)।

सारणी 7: कर्मचारी ऋणों का मूल्यांकन

(₹ लाख)

मद	मूल राशि	उचित कीमत माप			कुल
		सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अनवलोकनीय निविष्टियाँ (स्तर 3)	
वित्तीय आस्तियाँ					
नकद और नकद समकक्ष	46.34	46.34	-	-	46.34
उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	8.24	8.24	-	-	8.24
व्यापार प्राप्तियाँ	1.77	-	-	1.77	1.77
ऋण					
कर्मचारियों को ऋण	0.43	-	-	0.43	0.43
ऋण - एसएमई और सीएफ	3055.23	-	-	3055.23	3055.23
सहायक कंपनियों में निवेश - इक्विटी शेयर	175	-	-	175	175
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	1.61	-	-	1.62	1.61
कुल वित्तीय आस्तियाँ	3288.62	54.57	-	3234.05	3288.62
वित्तीय देयताएं					
व्यापार देनदारियाँ	10.22	-	-	10.22	10.22
ऋण प्रतिभूतियाँ	150	150	-	-	150
ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उधार	1912.30	-	-	1912.30	1912.30
अन्य वित्तीय देयताएं	28.55	-	-	28.55	28.55
कुल वित्तीय देयताएं	2101.07	150	-	1951.07	2101.07

स्रोत: एक नमूना एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

- x. **म्यूचुअल फंड निवेश में एकाधिक उचित मूल्य अनुक्रम:** हमने म्यूचुअल फंड के दो समूहों को देखा, जिनमें से एक को स्तर 1 विशेषता मिली और दूसरे को स्तर 3 के तहत वर्गीकृत किया गया (सारणी 8)। जब निवेश एक गैर-सूचीबद्ध निरंतर-स्वरूप फंड में था, ऐसे निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए समान फंडों के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) में कुछ समायोजन की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में, निविष्टियों ने स्तर 3 अनुक्रम का नेतृत्व किया।

- xi. **स्तर 3 की आस्तियों और व्यापार मॉडल के बीच सहसंबंध की सीमा** - हमने पता लगाया कि क्या समान व्यापार मॉडल वाली कंपनियों के पास स्तर 3 की आस्ति रखने के समान स्वरूप थे। परिणाम सारणी 9 में संक्षेपित हैं।

सारणी 9 में निम्नलिखित दर्शाया गया है:

- i. निवेश और क्रेडिट कंपनियों के पास स्तर 3 की आस्तियों की एक महत्वपूर्ण मात्रा थी।
- ii. मुख्य रूप से निवेश वाले आईसीसी के मामले में, हमने कुछ संस्थाओं के साथ मिश्रित स्वरूप देखा, जिनके पास स्तर 3 की आस्तियों का उच्च अनुपात था, जबकि अन्य में बहुत कम अनुपात था। इससे पता किया जा सकता है कि स्तर 3 की आस्ति के कम अनुपात वाली कंपनियां अधिक बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को प्राथमिकता देंगी और हो सकता है कि वे अंतरल निवेश के लिए बहुत उत्सुक न हों।

सारणी 9: विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी में -स्तर 3 की आस्तियों की मात्रा

(₹ करोड़)

एनबीएफसी का नाम	एनबीएफसी का प्रकार	स्तर 3 की आस्तियों की मात्रा	कुल आस्तियां	कुल आस्तियों में स्तर 3 की आस्तियों का प्रतिशत
1) एनबीएफसी 1	सीआईसी	28,914	31,012	93%
2) एनबीएफसी 2	आईसी	262	39,447	0.66%
3) एनबीएफसी 3	एलसी	0.95	1827	0.05%
4) एनबीएफसी 4	एएफसी	28,264	28,825	98%
5) एनबीएफसी 5	आईसी	526	7,963	7%
6) एनबीएफसी 6	एलसी	3,234	3,289	98%
7) एनबीएफसी 7	एलसी	6,443	7,101	91%
8) एनबीएफसी 8	आईसी	13,836	22,260	62%
9) एनबीएफसी 9	एलसी	3	54826	#
10) एनबीएफसी 10	एलसी	262	15135	1.73%

लगभग शून्य प्रतिशत, इसलिए नगण्य।

- iii. कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने उन आस्ति/देयताओं के लिए उचित मूल्य अनुक्रम प्रस्तुत नहीं किया जिनकी अग्रणीत राशि उनके उचित मूल्य के रूप में मानी गई थी। आस्तियों/देयताओं और उनके उचित मूल्य अनुक्रमों का सही प्रतिनिधित्व तब तक कठिन हो सकता है जब तक कि प्रकटीकरण एक समान न हो जाए। इस तरह की एकरूपता के अभाव में, विभिन्न वित्तीय विवरणों में मौजूद स्तर 3 की आस्तियों/देयताओं की सीमा की तुलना करना सार्थक नहीं होगा।

5. निष्कर्ष

चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों की संवीक्षा से उभरे मुख्य निष्कर्षों का सार संक्षेप में निम्नानुसार है:

- ए. **मूल्यांकन के तरीकों का खुलासा करना:** स्तर 3 के मूल्यांकन में विश्वास को बेहतर प्रकटीकरण के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। जब तक इस तरह के खुलासे नहीं किए जाते, तब तक लेखापरीक्षकों और पर्यवेक्षकों को डीसीएफ जैसे विभिन्न मूल्यांकन विधियों के तहत अनुमानों का अधिक गहनता से मूल्यांकन करना होगा। डीसीएफ के अलावा अन्य मॉडलों को भी आजमाने की जरूरत है। वास्तव में, इंड एस 113 अनिवार्य रूप से किसी विशिष्ट तकनीक या मॉडल की अनुशंसा नहीं करता है।

सारणी 8: म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण

(₹ लाख)

विवरण	उचित मूल्य अनुक्रम	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वित्तीय आस्तियां			
व्युत्पन्नी	स्तर 1	81.92	75.28
निवेश			
म्यूचुअल फंड्स	स्तर 1	1884.22	352.69
म्यूचुअल फंड्स	स्तर 3	1	-
वैकल्पिक निवेश कोष	स्तर 1	131.88	105.13
इक्विटी लिखत	स्तर 2	0.19	0.14
वरीयता प्रतिभूतियां	स्तर 3	2.98	-

टिप्पणी: स्तर 2 और स्तर 3 के अनुसार वर्गीकरण के लिए बाजार निविष्टियों के आधार पर उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है

बी. अनवलोकनीय निविष्टियों का विश्लेषण: आगे चलकर, गैर-अवलोकन योग्य निविष्टियों की एक सूची की सिफारिश की जा सकती है, जिनका उपयोग आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह आदानों के मानकीकरण में मदद करेगा और व्यक्तिपरकता को कम करेगा। यह इस विषय पर उपयुक्त नियामक या लेखा परीक्षा मार्गदर्शन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

सी. स्तर 2 और 3 अनुक्रमों के बीच ओवरलैप: यह स्पष्ट था कि स्तर 2 और 3 अनुक्रमों के बीच का सीमांकन बहुत बारीक था। आस्तियों का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य निविष्टियाँ हमेशा स्तर 3 अनुक्रम की ओर ले जाएंगी।

डी. स्तर 3 की मदों की गहन जांच: यह भी जांच के लायक होगा कि कंपनियाँ क्या “बाजार के लिए अंकन” से बचने के लिए जानबूझकर कुछ आस्तियों को स्तर 3 अनुक्रम के तहत रखती हैं। यह संभावित लगता है क्योंकि निवेश संपत्ति जैसी संपत्ति जब स्तर 3 मूल्यांकन के अधीन होती है तो उनकी वहन राशियों की तुलना में काफी अधिक मूल्य होते हैं।

इ. प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण: स्तर 3 की आस्तियों/देयताओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण में एकरूपता की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संबंध में

निम्नलिखित निष्कर्ष विशेष रूप से निकाले जा सकते हैं:

- i. स्तर 3 की आस्तियों पर अतिरिक्त प्रकटीकरण उन आस्तियों/देयताओं के संबंध में प्रदान किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से उचित मूल्य माप के अधीन नहीं होते हैं। यह वित्तीय विवरणों में मौजूद चलनिधि के एक अनुमानित मूल्य पर पहुंचने में सक्षम होगा।
- ii. अधिकांश मामलों की प्रस्तुति जो वित्तीय हैं, उनमें तीन चीजें शामिल हैं - (i) वित्तीय तत्व की मान्यता, (ii) इसका माप और (iii) प्रकटीकरण। जबकि तीनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, नमूना एनबीएफसी के विश्लेषण से पता चलता है कि “प्रकटीकरण” अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

एफ. लेखा परीक्षक की भूमिका: लेखा परीक्षकों की भूमिका का बेहतर लाभ उठाया जा सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से इस पर टिप्पणी करते हैं कि क्या कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई स्तर 3 की आस्तियों का मूल्यांकन, विभिन्न आस्तियों का एफवी अनुक्रम सही और उचित है या नहीं। वास्तव में, आईएसए 200 के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा मानकों क्या कहता है, इस पर विचार करते हुए, सभी समझदार लेखा परीक्षक, स्तर 3 आस्तियों पर जितना संभव हो उतना लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करके “लेखापरीक्षा जोखिम” को कम करना चाहते हैं।

अनुबंध 1:

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट प्राप्त नकद प्रवाह (डीसीएफ)

- ए. कई कंपनियां गैर-उद्धृत लिखतों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करती हैं। कुछ कंपनियां ऋण और देयता मदों जैसे ऋण प्रतिभूतियों और अन्य उधार जैसी आस्ति मदों के उचित मूल्यों की गणना करने के लिए इस पद्धति को अपनाती हैं।
- बी. उदाहरण के लिए, आस्तियों के उचित मूल्यों का अनुमान उचित छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट के द्वारा लगाया जाता है।
- सी. वह अंकगणितीय समीकरण जो रियायती नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के निर्धारण का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करता है, $PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$; है; जहां पीवी भविष्य के नकदी प्रवाह एफवी का रियायती वर्तमान मूल्य है, एफवी भविष्य की अवधि में नकदी प्रवाह राशि का नाममात्र मूल्य है; आर ब्याज दर या छूट दर है, एन भविष्य के नकदी प्रवाह के आने से पहले के वर्षों में समय है।
- डी. एक आस्ति के उचित मूल्य की पहचान करने के लिए डीसीएफ की प्रभावशीलता को 2009 में पेनमैन द्वारा सबसे अच्छा सारांशित किया गया है - “जब गैर-अवलोकन योग्य निविष्टि की बात आती है, जब स्तर 3 के उचित मूल्य लेखांकन के अनुसार उचित मूल्य की रिपोर्ट करने की बात आती है, तो कंपनियों के पास एक विकल्प होता है डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो (डीसीएफ)। उचित मूल्य लेखांकन के बारे में जिस समस्या पर चर्चा की गई है वह यह है कि स्तर 3 में गणना अनुमानों पर आधारित है। हालाँकि, निवेशकों और वित्तीय विवरणों के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम कम करने के लिए नए आईएफआरएस 13 के साथ प्रकटीकरण हैं, जब वे अपने निवेशक बना रहे होते हैं। संयोग से, इंड-एस 113 लगभग आईएफआरएस 13 के समान है और डीसीएफ को ‘वर्तमान मूल्य’ पद्धति के रूप में संदर्भित करता है।

अनुबंध 2:**इंड-एएस के तहत वित्तीय आस्तियों (देयताओं) का वर्गीकरण**

- ए. यदि वित्तीय आस्तियों को केवल संविदात्मक नकदी प्रवाह, जैसे प्राप्त, ऋण एकत्र करने के लिए रखा जाता है, तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को “परिशोधन लागत” पर मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे नकदी प्रवाह मूलधन और/या ब्याज के रूप में हों। वित्तीय आस्तियां जिन्हें आम तौर पर “परिशोधन लागत” पर मापा जाता है, परिपक्वता तक आयोजित निश्चित आय लिखत हैं; ये बिक्री के लिए नहीं हैं।
- बी. यदि परिशोधन लागत के नकदी प्रवाह परीक्षण को पूरा करने वाली वित्तीय आस्तियों को उपरोक्त रूप में नकदी के संविदात्मक प्रवाह को एकत्र करने और अंततः आस्तियों को बेचने के लिए नियोजित किया जाता है, तो ऐसी आस्तियों को “अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य” पर मान्यता दी जाती है।
- सी. वित्तीय आस्तियां जो उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के बावजूद उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- डी. भले ही कोई लिखत परिशोधन लागत या एफवीओसीआई पर मापी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता हो, इंड एस 109 प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों को एफवीटीपीएल के रूप में नामित करने का विकल्प देता है, यदि ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति (‘बेमेल लेखांकन’) समाप्त हो जाती है या काफी कम हो जाती है।
- इ. प्रारंभिक मान्यता पर एफवीओसीआई के रूप में एक इक्विटी लिखतों को वर्गीकृत करने के लिए एक इकाई के पास एक अपरिवर्तनीय विकल्प है।
- एफ. व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताओं को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अन्य सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत पर मापा जाता है जब तक कि उचित मूल्य विकल्प लागू नहीं किया जाता है।

क्या भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति है?*

यह आलेख जनवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति की पड़ताल करता है। अंधानुकरण की गतिविधि का परीक्षण करने के लिए, हम तीन स्वतंत्र आँकड़ा-समूह अर्थात् स्मॉल-कैप, मिड-कैप और लार्ज-कैप स्टॉक का उपयोग करते हैं। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि मिड-कैप शेयरों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति मौजूद है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि ऋणात्मक बाजार प्रतिफल की अवधि और निवल ऋणात्मक विदेशी संस्थागत अंतर्वाह के दिनों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति अधिक पाई गई है।

परिचय

बाजार में अंधानुकरण ऐसी प्रक्रिया है जहां निवेशक, अपने विश्वासों या जानकारी पर ध्यान दिए बिना पिछले निवेशकों के निर्णयों और कार्यों की नकल करते हुए एक ही दिशा में ट्रेड करते हैं (बिखचंदानी और शर्मा, 2000)। इस विषय पर आनुभविक साहित्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि बाजार सहभागियों की अंधानुकरण प्रवृत्ति आधार (अंडरलाइंग) शेयरों के मूल्य को विकृत कर सकती है और अस्थिरता को बढ़ा सकती है (फुरमैन और स्टिग्लिट्ज़, 1998; मॉरिस और शिन, 1999)। इसलिए, हाल की अवधि में, विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में विभिन्न परिदृश्यों और मान्यताओं को नियोजित कर वित्तीय बाजारों में अंधानुकरण प्रवृत्ति के परीक्षण पर तेजी से शोध किया गया है। हालांकि, कुछ अध्ययनों को छोड़कर, अधिकांश अध्ययन क्रिस्टी और हुआंग (1995) और चांग एवं अन्य द्वारा विकसित मॉडलों पर आधारित हैं। (2000)। ये मॉडल मुख्य रूप से प्रतिफल प्रसार, विशेष रूप से प्रतिफल के क्रॉस-सेक्शनल निरपेक्ष विचलन के आधार पर अंधानुकरण प्रवृत्ति की पहचान करते हैं।

बाजार में अंधानुकरण कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच) की वैधता पर सवाल उठाता है, जिसके अनुसार सभी निवेशक

तार्किक सोच वाले हैं और समान जानकारी रखते हैं, और इसी तरह अपेक्षित स्टॉक मूल्य की भविष्यवाणी करते हैं। नतीजतन, स्टॉक की कीमत को बाजार में उपलब्ध जानकारी और प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य को दर्शाना चाहिए। हालांकि, भेड़-चाल में, निवेशक तार्किक नहीं रहते, और वे अपने ज्ञान और विश्वास का उपयोग कर स्टॉक मूल्य नहीं निकाल पाते हैं। वे अन्य निवेशकों के कार्यों को देख और अपनाकर मूल्य जान पाते हैं जबकि सभी बाजार सहभागी सूचना से पूरी तरह लैस नहीं होते। इस वजह से, अंधानुकरण, प्रतिभूतियों के मूल्य को उनके मौलिक मूल्य से अलग कर बाजार की गतिविधियों को बाधित करता है (डेमिरर और कुटन, 2006)।

इस आलेख का उद्देश्य तिहरा है। इस आलेख में हमारी पहली प्राथमिकता चांग और अन्य (2000) द्वारा प्रस्तुत और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति को अपनाकर भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की उपस्थिति का पता लगाना है। इन तीन श्रेणियों - लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में अंधानुकरण की जाँच की जाएगी।¹ इन तीन श्रेणियों में अंधानुकरण की जाँच, एशिया में सबसे पुराना, तेजी से विकसित होने वाला और सबसे जीवंत बाजारों में से एक - भारतीय शेयर बाजार में सूचना विषमता, यदि कोई हो, की पहचान उपयोगी होगा।² इसलिए भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण की जांच करने से विनियामकों और नीति निर्माताओं को बाजार की दक्षता और विकास को समझने में काफी मदद मिल सकती है।

¹ सेबी के अनुसार:

- बाजार पूंजीकरण के आधार पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों को लार्ज-कैप कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों को मिड-कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है।
- बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वें स्थान से आगे की कंपनियों को स्मॉल-कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है।

² गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों का बाजार पूंजीकरण यूके और मध्य पूर्व को पार कर जाने की संभावना है और देश 2024 तक दुनिया में 5 वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा (<https://www.firstpost.com/business/goldman-sachs-says-india-could-overpass-uk-as-worlds-fifth-largest-stock-market-by-2024-9984671.html>)।

* इस आलेख को अनिकेत रंजन, सुमन सौरव और एम. श्रीरामुलु ने तैयार किया है। शाहबाज खान से प्राप्त मूल्यवान इनपुट कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किए गए हैं। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरा, हम धनात्मक और ऋणात्मक बाजार प्रतिफल की अवधि के दौरान अंधानुकरण गतिविधि का परीक्षण करते हैं, और तीसरा, हम जांच करते हैं कि क्या अंधानुकरण उन दिनों के दौरान मौजूद है जब विदेशी इक्विटी निवेशों का निवल बहिर्वाह और निवल अंतर्वाह होता है।³ शेष आलेख को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है: खंड II में अंधानुकरण पर साहित्य की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की गई है। खंड III अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़ा और आनुभविक पद्धति का वर्णन करता है। खंड IV परिणामों पर चर्चा करता है, और अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ हैं।

II. साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण

वित्तीय बाजारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर पिछले शोध में मिले-जुले परिणाम मिले। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अंधानुकरण की प्रवृत्ति अधिक आम-फहम है। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बाजार में सूचना विषमताएं आम तौर पर निवेशकों को निवेश निर्णय लेने के दौरान अपने साथियों के कार्यों की नकल करने के लिए मजबूर करती हैं। चांग और अन्य, (2000) द्वारा पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, जापान, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया में बाजारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति की जांच की गई है। लेखकों को दक्षिण कोरिया और ताइवान में अंधानुकरण के मजबूत सबूत मिले, जबकि जापान के मामले में कमजोर सबूत और अमेरिका और हांगकांग के बाजारों में कोई सबूत नहीं मिला।

विभिन्न तरीकों को नियोजित कर, तेजी और मंदी (ह्वांग और अन्य, 2004) के दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरियाई बाजारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। इसी तरह, चीनी दोहरे सूचीबद्ध शेयरों (टैन और अन्य, 2008) में निवेशकों के बीच अंधानुकरण की प्रवृत्ति दिख रही है। इसके विपरीत, चीन में अंधानुकरण का कोई सबूत नहीं मिला है (डेमिरर और अन्य,

2006)। चियांग और झोंग (2010) द्वारा 18 उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के नमूनों का उपयोग कर अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर एक व्यापक अध्ययन किया गया है। लेखक, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी बाजारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति का कोई सबूत नहीं देते हैं; हालांकि, उन्होंने पाया कि एशियाई बाजारों में निवेशकों ने तेजी और मंदी के दौरान कुछ हद तक अंधानुकरण दिखाया। इसी तरह, अंधानुकरण के समर्थन में चार विकसित यूरोपीय बाजारों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके में सबूत पाए जाते हैं (फिलिपस और अन्य, 2011)। कापरेली और अन्य, (2004) द्वारा चरम बाजार स्थितियों के दौरान इतालवी शेयर बाजार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति देखी गई।

कुछ अध्ययनों में पाया गया कि विदेशी निवेशक स्थानीय निवेशकों की तुलना में अधिक अंधानुकरण करते हैं (बोवे और डोमुटा, 2004)। चियांग और अन्य, (2010) द्वारा वैश्विक स्तर पर अंधानुकरण प्रसार-प्रभावों की भी जांच की गई है। लेखकों ने संकट की अवधि के दौरान बाजारों के बीच संक्रामक प्रभावों की उपस्थिति पाई है। इसी तरह, उच्च अस्थिरता (क्लेन, 2013) की अवधि के दौरान बाजारों में पाए जाने वाले प्रभावों पर तीव्र अंधानुकरण फैल गया। लेखक ने विभिन्न बाजारों के बीच सहसंबंध की जांच के लिए मार्कोव स्विचिंग मॉडल का इस्तेमाल किया।

भारतीय संदर्भ में, अध्ययनों के मिश्रित परिणाम मिलते हैं, कुछ लेखकों को अंधानुकरण की प्रवृत्ति के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला, जबकि कुछ लेखकों ने भारतीय शेयर बाजारों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति पाई (जिंदल (2014), पॉशकवाले और अन्य, 2014)। आस्ति की कीमतों पर संस्थागत अंधानुकरण के प्रभाव की जांच (दासगुप्ता और अन्य, 2010) द्वारा की गई है। लेखकों ने पाया कि संस्थागत अंधानुकरण दीर्घकालिक प्रतिफल की ऋणात्मक भविष्यवाणी करते हैं लेकिन अल्पकालिक प्रतिफल की धनात्मक भविष्यवाणी करते हैं। गैर-पेशेवर और पेशेवर निवेशकों के बीच सूचना-आधारित अंधानुकरण की जांच में, वेनेज़िया और अन्य, (2011) ने पाया कि पेशेवर निवेशकों के मामले में अंधानुकरण की प्रवृत्ति कम है। लेखक यह भी अनुमान लगाते हैं कि अंधानुकरण लगातार जारी है, और यह प्रतिफल में अस्थिरता से जुड़ा हुआ है।

³ यह जांच करते हुए कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करते समय अंधानुकरण और सकारात्मक फीडबैक ट्रेडिंग प्रदर्शित करते हैं, तायदे और अन्य, (2011) ने पाया कि विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर बाजार के विभिन्न चरणों के दौरान अंधानुकरण और सकारात्मक प्रतिक्रिया कारोबार का प्रदर्शन करते हैं। यह देखा गया व्यवहार प्रमुख है लेकिन लार्ज कैप शेयरों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि उनके पास अधिक चलनिधि होती है।

III. आँकड़ा और कार्यप्रणाली

अनुभवजन्य अनुमानों के लिए, हमने तीन अलग-अलग स्रोतों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) और सीईआईसी से आँकड़ा का इस्तेमाल किया। बाजार प्रतिफल की गणना एनएसई वेबसाइट से एकत्रित निफ्टी50 सूचकांक से की जाती है। स्मॉल-कैप, मिड-कैप और लार्ज-कैप शेयरों की जानकारी सीएमआईई प्रोवेस आँकड़ा-आधान से निकाली गई है। कुल मिलाकर, हम विश्लेषण में 91 स्मॉल-कैप, 95 मिड-कैप और 83 लार्ज-कैप शेयरों को शामिल कर सकते हैं। निवल विदेशी इक्विटी निवेश (एफईआई) पर आँकड़ा सीईआईसी आँकड़ा-आधान से निकाला गया है⁴ इस विश्लेषण के लिए चुनी गई नमूना अवधि जनवरी 2019 से मार्च 2020 है⁵

यह जांचने के लिए कि क्या अंधानुकरण गतिविधि बाजार में उतार-चढ़ाव से प्रेरित है, हम नमूना अवधि को चार अलग-अलग उप-अवधियों में विभाजित करते हैं, यानी (i) धनात्मक बाजार प्रतिफल के साथ कारोबारी दिन (तेजी) (ii) ऋणात्मक बाजार प्रतिफल के साथ कारोबारी दिन (मंदी), (iii) निवल धनात्मक विदेशी इक्विटी निवेश के साथ कारोबारी दिन और (iv) निवल ऋणात्मक विदेशी इक्विटी निवेश के साथ कारोबारी दिन।

बाजार-रुझान की ओर अंधानुकरण का पता लगाना

अंधानुकरण, बाजार सहभागियों को बाजार की आम सहमति की ओर ले जा सकता है। ऐसे मामले में, यदि बाजार सहभागियों के व्यवहार को बाजार प्रतिफल का साथ मिल जाता है, तो औसत बाजार प्रतिफल के आसपास जुटने की उनकी प्रवृत्ति के कारण प्रसार कम हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण गतिविधि का पता लगाने के लिए, हम चांग और अन्य, (2000) द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली को अपनाते हैं और यह बाद में गैलारियोटिस और अन्य, (2015) और लिन और अन्य, (2015) द्वारा संशोधित किया जाता है। चांग और अन्य, (2000) के अनुसार, उनके क्रॉस-सेक्शनल औसत के आसपास प्रतिफल का

कम प्रसार इंगित करता है कि बाजार के निवेशक बाजार के औसत के आसपास के कारोबारी रुझानों की नकल करने की कोशिश करते हैं और अपनी पूर्व मान्यताओं और सूचनाओं को त्याग देते हैं। प्रतिफल के प्रसार की गणना क्रॉस-सेक्शनल एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ रिटर्न्स (सीएसएडी) द्वारा निम्नानुसार की जाती है:

$$CSAD_t = \frac{\sum_{i=1}^N |R_{i,t} - R_{m,t}|}{N} \quad \dots(1)$$

जहां, $R_{i,t}$ समय i पर स्टॉक पर प्रतिफल है और $R_{m,t}$ समय पर कुल बाजार पोर्टफोलियो में N प्रतिफल का क्रॉस-सेक्शनल औसत है। चांग और अन्य, (2000) की परिकल्पना है कि मानक आर्स्टि-मूल्य निर्धारण मॉडल सीएसएडी और पूर्ण बाजार प्रतिफल के बीच की कड़ी की भविष्यवाणी धनात्मक और रैखिक के रूप में करते हैं। दूसरी ओर, बाजार की आम सहमति के आसपास अंधानुकरण प्रवृत्ति के रैखिक संबंध को एक गैर-रैखिक स्वरूप में बदल देता है। सीएसएडी और बाजार प्रतिफल के बीच गैर-रैखिक संबंध निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

$$CSAD_t = \alpha + \beta_1 |R_{m,t}| + \beta_2 R_{m,t}^2 + \varepsilon_t \quad \dots(2)$$

जहां α अवरोधन है, β_1 और β_2 प्रतिगमन गुणांक हैं, और ε_t एरर टर्म है। समीकरण (2) में, गैर-रैखिक संबंध को स्क्वायर मार्केट प्रतिफल ($R_{m,t}^2$) द्वारा कैप्चर किया जाता है। यदि कोई अंधानुकरण प्रवृत्ति नहीं है, तो समीकरण (2) β_1 को धनात्मक मानता है और β_2 या तो शून्य के बराबर या β_2 शून्य से बड़ा है। ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण β_2 मान अंधानुकरण प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

IV. परिणाम और चर्चा

स्मॉल-कैप, मिड-कैप और लार्ज-कैप शेयरों के वर्णनात्मक आँकड़े सारणी 1 में बताए गए हैं। यह देखा गया है कि अध्ययन की अवधि के दौरान दैनिक प्रतिफल का औसत मूल्य लार्ज-कैप शेयरों के लिए सबसे अधिक है, इसके बाद मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक हैं। इससे पता चलता है कि लार्ज-कैप शेयरों ने औसतन अन्य दो समूहों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि, हमें लार्ज-कैप शेयरों में उच्च अस्थिरता भी मिलती है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स की अस्थिरता के सबसे करीब है। स्मॉल-कैप के प्रतिफल की विषमता धनात्मक है जबकि अन्य समूहों के लिए यह ऋणात्मक है। मिड-कैप और लार्ज-कैप प्रतिफल वितरण दोनों लेप्टोकुर्टिक हैं (कुटोसिस 3 से अधिक है), जबकि स्मॉल-कैप शेयरों का प्रतिफल

⁴ विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवल इक्विटी निवेश।

⁵ हमने जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों का चयन किया है, क्योंकि इस अवधि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि बजट घोषणाएं, आम चुनाव, कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती, कोविड-19 का आगमन आदि, जो शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं।

सारणी 1: वर्णनात्मक आँकड़े

प्रतिफल	माध्यिका	मानक विचलन	विषमता	कर्टोसिस	न्यून	अधि
बाजार (निफ्टी50)	0.02%	1.55%	-2.36	21.62	-12.98%	6.62%
स्मॉल कैप स्टॉक	-0.13%	1.25%	0.38	1.02	-3.36%	4.16%
मिड कैप स्टॉक	-0.004%	1.47%	-2.72	21.48	-12.67%	5.64%
लार्ज कैप स्टॉक	0.003%	1.55%	-1.98	15.45	-11.92%	5.61%
मार्केट-अप	0.50%	0.99%	3.51	14.88	0.01%	6.62%
बाजार में गिरावट	-0.55%	1.53%	-4.95	30.48	-12.98%	0.00%
धनात्मक एफईआई	0.03%	0.87%	-0.69	4.43	-4.38%	2.89%
ऋणात्मक एफईआई	-0.01%	1.93%	-2.53	15.99	-12.98%	5.83%

वितरण प्लेटीकुरटिक (3 से कम) है। तेजी और निवल धनात्मक एफईआई के एपिसोड के दौरान मेडियन प्रतिफल धनात्मक है। बाजार में उतार-चढ़ाव और निवल ऋणात्मक एफईआई के साथ अवधियों में अस्थिरता बहुत भिन्न होती है, जिससे उच्च स्तर की अस्थिरता का संकेत मिलता है कि ऋणात्मक समाचार बाजार को अधिक से अधिक प्रभावित करता है।

इसके अलावा, सीएसएडी माप के संबंध में वर्णनात्मक आंकड़े सारणी 2 में बताए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्मॉल-कैप और मिड-कैप शेयरों की तुलना में लार्ज-कैप शेयरों के लिए औसत सीएसएडी अधिक है। प्रसार की प्रवृत्ति सूचना विषमता की परिकल्पना के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि लार्ज कैप शेयरों में अधिक कवरेज और आँकड़ा की उपलब्धता होती है, इसलिए माध्य से अधिक प्रसार होता है। इसी तरह, लार्ज-कैप स्टॉक के लिए सीएसएडी का मानक विचलन अन्य दो समूहों की तुलना में अधिक है।

सारणी 2: सीएसएडी पर वर्णनात्मक आँकड़े

मद	स्मॉल-कैप स्टॉक्स	मिड-कैप स्टॉक्स	लार्ज कैप स्टॉक्स
माध्य (प्रतिशत)	1.45	1.50	2.00
माध्यिका (प्रतिशत)	1.29	1.38	1.85
मानक विचलन (प्रतिशत)	0.63	0.52	0.67
विषमता	2.97	2.74	1.28
कुटोसिस	10.52	9.79	1.35
न्यूनतम (प्रतिशत)	0.68	0.80	1.10
अधिकतम (प्रतिशत)	4.69	4.23	4.29

प्रतिफल प्रसार

सारणी 3, बाजार में अंधानुकरण के संबंध में प्रतिगमन समीकरण (2) के परिणामों की रिपोर्ट दिखाती है। हमारे परिणामों से संकेत मिलता है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशक केवल मिड-कैप शेयरों में अंधानुकरण है, जबकि स्मॉल और लार्ज-कैप शेयरों के मामले में हमें अंधानुकरण गतिविधि के पक्ष में कोई सबूत नहीं मिलता है।

बाजार की चाल और अंधानुकरण

यह जांच करने के लिए कि क्या शेयर बाजार के प्रतिफल निवेशकों को भेड़-चाल (अंधानुकरण) के लिए प्रेरित करते हैं, 'तेजी' दिनों और 'मंदी' के दिनों के बीच अंतर करने का प्रयास किया जाता है और इन दो समूहों के बीच अंधानुकरण की गतिविधि का परीक्षण किया जाता है। यह वर्गीकरण एक और सिद्धांत का पालन करने में मदद करता है यानी, क्या ऋणात्मक प्रतिफल धनात्मक प्रतिफल की तुलना में अंधानुकरण को प्रेरित करने की अधिक संभावना है। परिणाम मिड-कैप शेयरों के मामले में केवल उन दिनों जब बाजार में गिरावट होती है (यानी, ऋणात्मक बाजार प्रतिफल) के मामले में अंधानुकरण गतिविधि की उपस्थिति

सारणी 3: पूर्ण नमूने के लिए प्रतिगमन परिणाम

	स्मॉल-कैप		मिड-कैप		लार्ज कैप	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	β_1	β_2	β_1	β_2	β_1	β_2
पूर्ण नमूना	0.037	8.54***	0.43***	-1.40***	0.49***	1.71***
p -मान	0.7786	0.0211	0.0000	0.0001	0.0000	0.00028
R^2	0.01		0.57		0.53	

सारणी 4: बाजार उतार-चढ़ाव और अंधानुकरण

	स्मॉल-कैप		मिड-कैप		लार्ज कैप	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	β_1	β_2	β_1	β_2	β_1	β_2
बाजार में तेजी	0.34**	2.09	0.28***	4.33***	0.30***	3.94***
पी – मान	0.0583	0.6382	0.0007	0.0117	0.0005	0.0142
आर ²	0.18		0.58		0.61	
बाजार में गिरावट	-0.36	19.54	0.35***	-0.89***	0.41***	1.27***
पी – मान	0.2407	0.1915	0.0000	0.0314	0.0000	0.02710
आर ²	0.02		0.64		0.52	

टिप्पणी: बाजार में तेजी का मतलब है कि जब निफ्टी प्रतिफल (दैनिक) धनात्मक देखा जाता है और बाजार में गिरावट का मतलब है कि जब निफ्टी प्रतिफल ऋणात्मक होता है

का संकेत मिलता है। हमारे परिणाम क्रिस्टी और हुआंग (1995) के अनुरूप हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के तनाव की स्थितियों में एक 'अंधानुकरण' होने की अधिक संभावना है। हमें स्मॉल और लार्ज-कैप शेयरों के ऊपर या नीचे बाजार के लिए अंधानुकरण का कोई सबूत नहीं मिला।

विदेशी प्रवाह और अंधानुकरण

यह जांचने के लिए कि अंधानुकरण की गतिविधि विदेशी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से प्रेरित है या नहीं, हम कारोबारी दिनों को दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं - (i) दिन जब निवल विदेशी अंतर्वाह होते हैं और (ii) निवल विदेशी बहिर्वाह वाले दिन। परिणाम उन दिनों के दौरान अंधानुकरण गतिविधि की पुष्टि करते हैं जब मिड-कैप शेयरों के संबंध में विदेशी इक्विटी निवेश (एफईआई) का निवल बहिर्वाह होता है। हमें स्मॉल और लार्ज-कैप शेयरों के मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अंधानुकरण की गतिविधि के साक्ष्य की कमी एक समान कार्यप्रणाली (ग्लिसन और अन्य (2004) का उपयोग कर विभिन्न बाजारों में किए गए पहले के अध्ययनों के अनुरूप है।

सारणी 5: प्रतिगमन मॉडल के परिणाम

	स्मॉल-कैप		मिड-कैप		लार्ज कैप	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	β_1	β_2	β_1	β_2	β_1	β_2
धनात्मक एफईआई	-0.0620	19.17	-0.05	16.86***	-0.16	18.58***
पी – मान	0.8310	0.1384	0.65	0.003	0.12	0.000
आर ²	0.09		0.24		0.41	
ऋणात्मक एफईआई	-0.045	9.71***	0.48***	-1.87***	0.52***	2.12***
पी – मान	0.8127	0.0319	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003
आर ²	0.14		0.66		0.57	

टिप्पणी: मार्केट-अप का मतलब है कि जब निफ्टी प्रतिफल (दैनिक) धनात्मक देखा जाता है और मार्केट-डाउन का मतलब है कि जब निफ्टी प्रतिफल ऋणात्मक होता है

V. निष्कर्ष

इस आलेख ने जनवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण गतिविधि की जांच की। चांग और अन्य (2000) द्वारा प्रस्तुत पद्धति अर्थात् क्रॉस-सेक्शनल एक्सोसल्यूट डिविजन (सीएसएडी) का उपयोग बाजार में अंधानुकरण गतिविधि के परीक्षण के लिए किया जाता है। परिणाम बताते हैं कि कुल मिलाकर, भारतीय शेयर बाजार में निवेशक मिड-कैप शेयरों में अंधानुकरण के कुछ सबूतों को छोड़कर, अंधानुकरण गतिविधि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा, ऋणात्मक बाजार प्रतिफल वाले दिनों और विदेशी इक्विटी निवेश के निवल बहिर्वाह वाले दिनों के दौरान निवेशकों का नकलची व्यवहार अधिक ध्यान देने योग्य है। हालांकि अन्य श्रेणियों में भेंड़-चाल नहीं पाया गया था, हमें सीएसएडी और लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों के लिए बाजार प्रतिफल के बीच गैर-रैखिक संबंध का सबूत मिला, जो कि अधिक व्यक्तिगत निर्णय लिए जाने का संकेत देता है।

संदर्भ

- Arne, C. K. , (2013), "Time-variations in herding behaviour: Evidence from a Markov switching SUR model", *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol-26, pp-291-304.
- Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2000), "Herd behaviour in financial markets, *IMF Staff Papers*", Vol-47-3, pp-279–310.
- Bikhchandani, S., David, H., Welch, I. (1992), "A Theory of Fads, Fashion, Custom and Cultural Change as Informational Cascades", *Journal of Political Economy*, Vol-100, pp-992–1026.
- Bowe, M., Domuta, D., (2004), "Investor herding during financial crisis: A clinical study of the Jakarta Stock Exchange", *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol-12, pp-387-418.
- Caparrelli, F., Maria, A., Cassuto, A., (2004), "Herding in the Italian Stock Market: A Case of Behavioural

Finance", *The Journal of Behavioural Finance*, Vol- 5, pp-222-230.

Chang, E. C., Cheng, J. C., Khorana, A. (2000), "An examination of herd behaviour in equity markets: An international perspective", *Journal of Banking and Finance*, Vol-24, pp-1651-1679.

Chiang, T. C., Zheng, D. (2010), "An empirical analysis of herding behaviour in global stock markets", *Journal of Banking and Finance*, Vol-34-8, pp-1911-1921.

Christie, W. G., Huang, R. D., (1995), "Following the pied piper: Do individual returns herd around the market?", *Financial Analysts Journal*, Vol-51, p-31-37.

Cipriani, M., Guarino, A., (2005), "Herd Behaviour in a Laboratory Financial Market", *American Economic Review*, Vol-95, pp-1427-1443.

Cipriani, M., Guarino, A., (2005a), "Noise Trading in a Laboratory Financial Market: A Maximum Likelihood Approach", *Journal of the European Economic Association*, Vol-3-2, pp-315-321.

Dasgupta, A., Prat, A., Verardo, M., (2010), "The Price Impact of Institutional Herding. C.E.P.R. Discussion Papers", *CEPR Discussion Papers*, Vol-24.

Demirer, R., Kutun, A. M., (2006), "Does herding behaviour exist in Chinese stock market?", *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol-16, pp-123-142.

Drehmann, M., Oechssler, J., Roider, A., (2005), "Herding and Contrarian Behaviour in Financial Markets: An Internet Experiment", *The American Economic Review*, Vol-95-5, pp-1403-1426.

Economou, F., Philippas, N., Kostakis, A., (2011), "Cross-country effects in herding behaviour: Evidence from four south European markets", *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol-21, pp-443-460.

Froot, K.A., Scharfstein, D.S., Stein, J.C., (1992), "Herd on the street: information inefficiencies in a market

with short-term speculation", *The Journal of Finance*, Vol-47, pp-1461-1484.

Furman, J., Stiglitz, J.E., (1998), "Economic crises: evidence and insights from East Asia", *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol-2, pp-1-136.

Garg, A., Jindal, K., (2014), "Herding Behaviour in an Emerging Stock Market: Empirical Evidence from India," *The IUP Journal of Applied Finance*, Vol.-20-2, pp- 18-36.

Gavriilidis, K., Kallinterakis, B., Ferreira, M., (2013), "Institutional Industry Herding: Intentional or Spurious", *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol-26

Galaritis, E., Rong, W., Spyrou, S., (2015), "Herding on fundamental information: A comparative study", *Journal of Banking & Finance*, Vol-50, pp-589-598.

Gleason, K.C., Mathur, I., Peterson, M.A., (2004). Analysis of intraday herding behaviour among the sector ETFs, *Journal of Empirical Finance*, Vol-11, pp-681-694.

Hsieh, S., (2013), "Individual and institutional herding and the impact on stock returns: Evidence from Taiwan stock market", *International Review of Financial Analysis*, Vol-29, pp- 175-188.

Huang, T., Lin, B., Yang, T., (2015), "Herd behaviour and idiosyncratic volatility", *Journal of Business Research*, Vol-68.

Lakonishok, J., Schleifer, A., Vishny, R.W., (1992), "The impact of institutional trading on stock prices", *Journal of Financial Economics*, Vol-32, pp-23-43.

Morris, S., Shin, H.S., (1999), "Risk management with interdependent choice", *Oxford Review of Economic Policy*, Vol-15, pp-52-62.

Nofsinger, J. R., Sias, R. W., (1999), "Herding and feedback trading by institutional and individual investors", *The Journal of Finance*, Vol-54, pp-2263-2295.

Park, A., Sabouralni, H., (2011), "Herding and contrarian behaviour in financial markets", *Econometrica*, Vol-79, pp-973–1026.

Pierdzioch, C., Rülke, J., Stadtmann, G., (2012), "A Note on Forecasting Emerging Market Exchange Rates: Evidence of Anti-Herding", *Review of International Economics*, Vol-20.

Poshakwale, S., Mandal, A., (2014), "Investor Behaviour and Herding: Evidence from the National Stock Exchange in India", *Journal of Emerging Market Finance*, Vol-13-2, pp-197-216.

Tan, L., Chiang, T. C., Mason, J. R., Nelling, E., (2008), "Herding behaviour in Chinese stock market: An

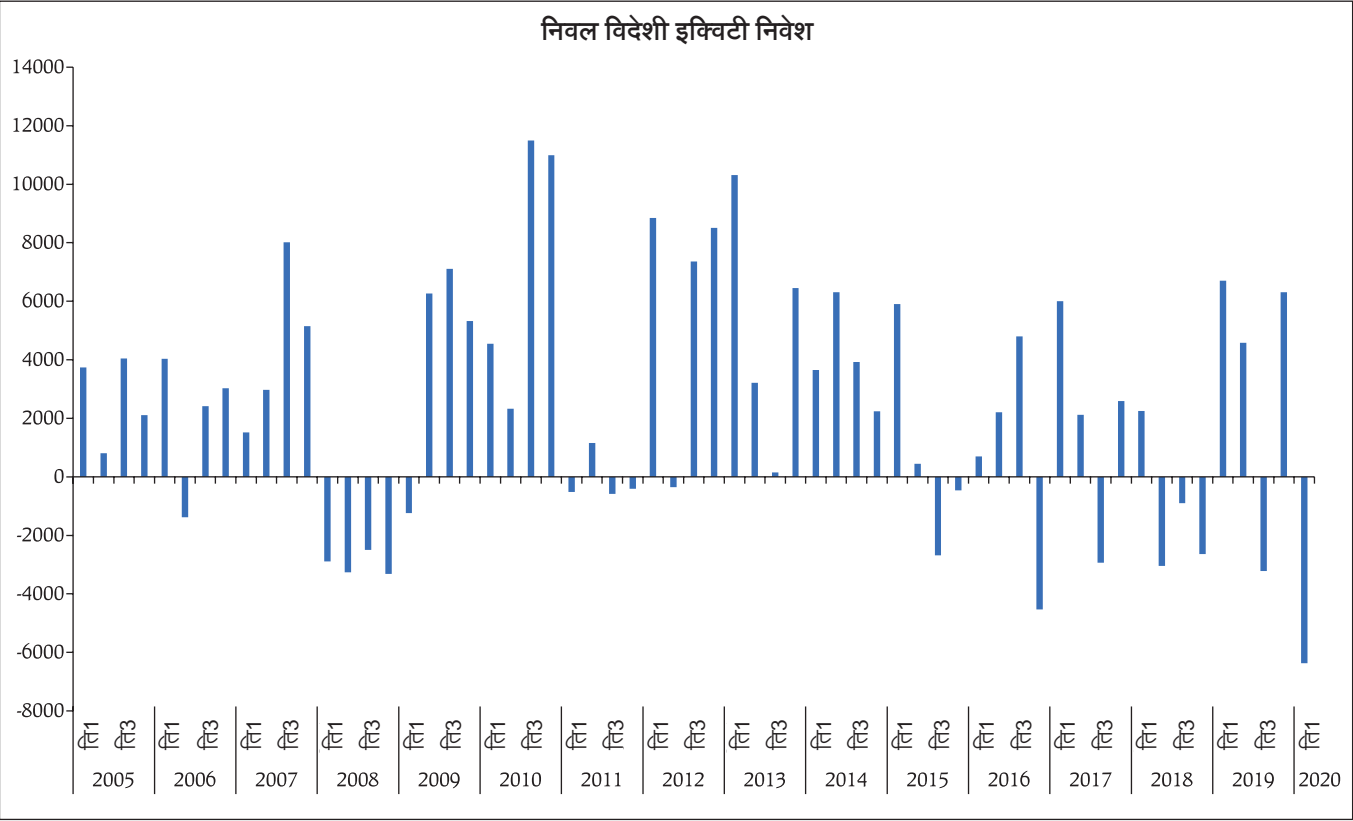
examination of A and B shares", *Pacific Basin Financial Journal*, Vol-16, pp-61–77.

Tayde, Mangesh & Rao, S.V.D.. (2011), "Do Foreign Institutional Investors (FIIs) Exhibit Herding and Positive Feedback Trading in Indian Stock Markets?", *International Finance Review*, Vol-12, pp-169-185

Venezia, I., Nashikkar, A., Shapira, Z., (2011), "Firm Specific and Macro Herding by Professional and Amateur Investors and Their Effects on Market Volatility", *Journal of Banking & Finance*, Vol-35, pp-1599-1609.

Zhou, T., Lai, R., (2009), "Herding and information based trading", *Journal of Empirical Finance*, Vol-16-3, pp-388-393.

अनुबंध-I:



वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाज़ार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	97
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	98
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	99
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	100
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	101
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	101
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	102
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	103
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	104
9	कुल चलनिधि राशियां	104
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	105
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	105
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	106
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	106
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	107
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	108
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	109
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	110
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	111
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	111
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	111
21	थोक मूल्य सूचकांक	112
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	116
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	116
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	117
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	117
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	118
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	119
28	वाणिज्यिक पत्र	119
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	119
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	120

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	121
32	विदेशी मुद्रा भंडार	121
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	121
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	122
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	122
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	123
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	124
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	125
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	126
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	127
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	128
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	129
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	130
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	132
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	133
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	134
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	135
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	136
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	137
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	138
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	141

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2020-21		2021-22	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-4.8	-5.9	2.1	8.4	4.7
1.1.1 कृषि	3.3	3.2	4.1	3.7	2.6
1.1.2 उद्योग	-1.8	3.0	6.2	6.6	1.4
1.1.3 सेवाएं	-7.8	-10.4	0.04	10.0	6.7
1.1ए अंतिम खपत व्यय	-4.5	-10.8	0.4	10.1	6.5
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.4	-4.5	-0.6	14.6	2.0
	2020-21	2020	2021	2022	
		दिसं.	जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	2.2	-0.6	0.7	1.3
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	10.8	11.1	10.3	8.3
2.1.2 ऋण	5.6	6.2	5.9	8.2	7.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	6.2	5.9	8.3	7.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	17.3	18.8	2.8	3.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	14.9	14.5	14.7	13.5
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	12.4	12.1	11.4	8.4
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.7	3.8	5.0	4.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	73.1	72.3	71.3	71.5
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	23.5	26.9	56.1	56.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	30.4	29.9	28.4	28.6
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	72.0	56.2	12.9	12.8
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.25/8.80	7.25/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.55/7.10	6.55/7.05	6.50/7.00	6.45/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.60	5.00/5.60
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.24	3.23	3.32	3.72
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	3.08	3.35	3.66	3.71
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.34	3.56	3.97	4.18
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.46	3.68	4.27	4.51
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	5.89	5.96	6.47	6.69
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	73.58	72.95	74.30	74.95
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	89.81	88.30	84.05	83.60
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिया 1-माह (%)	6.80	3.84	4.19	3.96	3.84
3-माह (%)	5.64	3.75	5.48	4.15	4.88
6-माह (%)	5.47	4.35	5.13	4.71	4.66
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	4.6	4.1	5.7	6.0
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	3.7	3.2	5.6	5.8
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	2.0	2.5	14.3	13.0
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	-0.6	-1.6	13.8	13.9
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-6.1	-3.8	38.1	32.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	4.5	5.5	10.7	9.4
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-16.91	8.4	2.1	39.3	23.5
7.2 निर्यात	-6.88	0.4	6.5	44.2	25.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2021	2022				
		फर.	जन. 28	फर. 4	फर. 11	फर. 18	फर. 25
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2809858	3004604	3025718	3046152	3049374	3052620
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	21	16	15	12	17	14
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2831738	2809879	3004619	3025733	3046165	3049391	3052634
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	110589	114864	113400	117356	119865	123775
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2698474	2889257	2911857	2928356	2929094	2928450
1.2.3 रुपया सिक्का	746	816	498	476	453	432	409
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1532207	1929291	1909969	1898744	1913737	1911791
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	101	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	542693	462156	681336	689302	645967	702886	664473
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5257	7560	7356	7044	7637	6900
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2430	3766	3836	3977	3872	3916
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	27383	36681	36944	37379	37425	36947
2.1.1.8 अन्य	895440	1018787	1139410	1121522	1146815	1082200	1119484
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	16050	60395	50866	57419	79572	79928
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1415428	1300073	1288249	1333336	1308371	1333412
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2848367	2947634	3229365	3198218	3232080	3222108	3245202
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	21	16	15	12	17	14
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1314777	1387051	1359892	1363932	1331592	1350827
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	3938	716	8418	8872	4065	186
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	90275	84651	94286	94793	95159	95015	96123
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	35	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	26848	24770	24853	24853	24853	24853
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	6678	6662	811	77	77	77	77
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	29509	30404	30415	37209	60080	64052
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	1331671	1322118	1497144	1486669	1503217	1503593	1499600
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	159077	194167	193086	198750	202816	209471
2.2.6.1 स्वर्ण	146572	149649	181597	180005	186071	190049	196025

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन एवं	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो ₹	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+ 11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन- शील रिपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जन. 1, 2022	-	67494	-	-	1005	-	-	-	-	-	-	-	-	-66489
जन. 2, 2022	-	5285	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-5216
जन. 3, 2022	-	262625	-	200014	1575	-	-	2225	-	-	-	-	-	-463289
जन. 4, 2022	-	186727	-	200021	30	-	-	1685	-	-	-	-	-	-388403
जन. 5, 2022	-	173550	-	-	22	-	-	260	-	-	-	-	-	-173788
जन. 6, 2022	-	138377	-	198755	170	-	-	1445	-	-	-	-	-	-338407
जन. 7, 2022	-	93317	-	-	10	-	-	20	160	-	-	-	-	-93167
जन. 8, 2022	-	3724	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-3517
जन. 9, 2022	-	2611	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-2566
जन. 10, 2022	-	75259	-	183592	345	-	-	-	70	-	-	-	-	-258436
जन. 11, 2022	-	109173	-	175042	15	-	-	520	-	-	-	-	-	-284720
जन. 12, 2022	-	108934	-	-	230	-	-	520	-	-	-	-	-	-109224
जन. 13, 2022	-	287209	-	-	12	-	-	325	-	-	-	-	-	-287522
जन. 14, 2022	-	78411	-	431426	484	3000	-	865	-	-	-	-	-	-507218
जन. 15, 2022	-	26114	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-26070
जन. 16, 2022	-	2653	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-2645
जन. 17, 2022	-	76070	-	-	4	-3000	-	75	260	-	-	-	-	-78881
जन. 18, 2022	-	64376	-	200029	192	-	-	335	-	-	-	-	-	-264548
जन. 19, 2022	-	40925	-	-	4350	-	-	105	-	-	-	-	-	-36680
जन. 20, 2022	-	46079	50003	-	1654	-	-	-	-	-	-	-	-	5578
जन. 21, 2022	-	43201	75005	-	590	1383	-	-	-	-	-	-	-	33777
जन. 22, 2022	-	3317	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-3231
जन. 23, 2022	-	2416	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-2395
जन. 24, 2022	-	56394	75009	-	525	50	-	-	-	-	-	-	-	19190
जन. 25, 2022	-	76606	-	120255	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-196501
जन. 26, 2022	-	5725	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-5664
जन. 27, 2022	-	79468	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-79436
जन. 28, 2022	-	270488	-	327902	38	-699	-	-	-	-	-	-	-	-599051
जन. 29, 2022	-	37021	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-36777
जन. 30, 2022	-	5173	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-5152
जन. 31, 2022	-	353403	-	-	160	-230	-	-	-	-	-	-	-	-353473

टिप्पणी: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन।

ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

& ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

₹ 07 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार। 18 जून 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डेटा में राशि शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशोर / ऑफशोर में परिचालन

मद	2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	2854	-2917	-771
1.1 क्रय (+)	162479	18225	7475	6548
1.2 विक्रय (-)	94164	15371	10392	7319
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	21486	-20809	-4816
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	68315	75233	37413	36642
(करोड़ ₹)	510516	560113	285996	281180
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	72751	47383	49106	49877

ii) मुद्रा वायदा भाग में परिचालन

मद	2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	1962	0	0
1.2 विक्रय (-)	12118	1962	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	690	2196	0	0

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**

मद	31 जनवरी 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	5946	5175	771
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	14288	10020	4268
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	44838	0	44838
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	65072	15195	49877

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2021					2022
		फर. 26	सितं. 24	अक्टू. 22	नव. 19	दिसं. 31	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	58	152	461	7201	8176	38
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त	—	—	—	—	—	—	—
2.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—
2.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.1 सीमा	—	0	0	0	0	0	734
3.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	75000	75000	76000	76000	76000	76000	76000
4.1 सीमा	32387	32842	25396	21696	24196	24401	24401
4.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	32900	25548	22157	31397	32577	25173

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2707213	2881115	2934712	2930965
1.1 संचलन में नोट	2826851	2780045	2959237	3006151	3004604
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	26004	26921	26921	27021
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	99579	105786	99103	101403
2 जनता की जमा राशियां	2042471	1857491	2257098	2016778	2103135
2.1 बैंकों के पास मांग जमा राशियां	1995120	1814269	2206052	1967141	2050497
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	47351	43222	51045	49637	52638
3 एम₁ (1 + 2)	4794299	4564704	5138213	4951490	5034100
4 डाकघर बचत बैंक जमा राशियां	170025	165101	170025	170025	170025
5 एम₂ (3 + 4)	4964324	4729805	5308238	5121515	5204125
6 बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां	14050278	13841962	14975823	14955857	14912628
7 एम₃ (3 + 6)	18844578	18406666	20114036	19907347	19946728
8 कुल डाकघर जमा राशियां	509544	494606	509544	509544	509544
9 एम₄ (7 + 8)	19354122	18901272	20623580	20416891	20456272

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5735482	6100716	6084344	5934151
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	1058048	1194335	1161054	1058706
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1312493	1526753	1519853	1496295
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1307724	1520076	1505878	1495578
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	4769	6677	13975	716
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	237615	254445	332418	358799	437589
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	254403	332375	358757	437546
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4677434	4906381	4923290	4875445
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11668466	11361490	12389335	12209282	12174904
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	8601	2094	5140	2874
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659757	11352889	12387240	12204142	12172030
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949509	10703752	11680480	11496877	11468977
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	639026	688991	689131	685155
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	10111	17769	18134	17898
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	4578846	4609126	4924971	4911792	4916853
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	4279192	4550652	4537473	4542534
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	4279437	4550897	4537718	4542779
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	245	245	245	245
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	329934	374319	374319	374319
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26747	27664	27664	27764
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3280021	3326178	3328650	3325735	3106944
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1436430	1307042	1301909	1291916
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923362	1889748	2021608	2023826	1815029
एम₃ (1+2+3+4-5)	18844578	18406666	20114036	19907347	19946728

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794299	4564704	5138213	4951490	5034100
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048277	10719166	11814892	11619131	11681954
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936051	18484350	20245248	20044207	20078698
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2707213	2881115	2934712	2930965
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892848	15490852	17043116	16784121	16823507
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995121	1814269	2206052	1967141	2050497
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	13676583	14837063	14816980	14773010
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	6154462	6676679	6667641	6647855
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	63159	84894	98722	100092
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7522121	8160385	8149339	8125156
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	43222	51045	49637	52638
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	243063	269971	275737	271587
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18518950	18047710	19479623	19292142	19107911
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5735481	6100716	6084344	5934151
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	1058048	1194335	1161054	1058706
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4677434	4906381	4923290	4875445
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12668575	12312228	13378907	13207799	13173759
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	34782	26864	29910	27644
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12634441	12277447	13352043	13177889	13146115
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	914781	958477	963648	964488
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26747	27664	27664	27764
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	4486180	4755068	4746501	4771073
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4279192	4550652	4537473	4542534
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	206988	204416	209028	228539
2.4 पूंजी खाता	2775245	2839875	2976588	2989279	3005732
2.5 अन्य मदें (निवल)	1272767	1236411	1040519	1032823	822319

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2021			2022
		जन.	नव.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	18936051	18484350	19761139	20245248	20078698
2 डाकघर जमाराशियां	509544	494606	509544	509544	509544
3 एल₁ (1 + 2)	19445595	18978956	20270683	20754792	20588242
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	34795	26861	24644	27058
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	2645	3631	1984	2138
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	28865	18175	15360	17560
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3285	5054	7299	7360
5 एल₂ (3 + 4)	19478774	19013751	20297544	20779435	20615300
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	..	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	19510679	..	..	20811340	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 31
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2806792	2986901	3033815	3032368
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	511901	764828	731205	729343
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	651748	476349	716432	683105	681336
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	43222	51045	49637	52638
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3361915	3802775	3814657	3814348
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	492406	531501	551429	535966
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	1058048	1194335	1161054	1058706
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	1053321	1187700	1147121	1058032
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	—	—	—	—	—
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1306845	1519509	1505350	1495081
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1306845	1519509	1505350	1495081
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	879	567	528	498
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	254403	332375	358757	437546
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	4727	6634	13932	674
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-600423	-689698	-639534	-550384
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-574242	-664928	-614764	-525614
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	34782	26864	29910	27644
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	734
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	26181	24770	24770	24770
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26747	27664	27664	27764
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4279192	4550652	4537473	4542534
2.3.1 सोना	247723	264803	292779	294839	296461
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	4014406	4257890	4242651	4246090
2.4 पूंजी खाता	1173033	1250074	1221533	1230643	1244373
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	186356	85509	71266	47542

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021		2022			
		दिसं. 29	जन. 31	जन. 7	जन. 14	जन. 21	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा							
(1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3361915	3802775	3760210	3814657	3794592	3814348
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2806792	2986901	3017562	3033815	3036653	3032368
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	511901	764828	692390	731205	706377	729343
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	43222	51045	50259	49637	51562	52638
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1058048	1194335	1169468	1161054	1051849	1058706
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-574242	-664928	-689400	-614764	-529430	-525614
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	8601	2094	2131	5140	3523	2874
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4279192	4550652	4533654	4537473	4540700	4542534
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26747	27664	27664	27664	27664	27764
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1436430	1307042	1283307	1301909	1299714	1291916

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960961	14637387	16103094	15844101	15892908
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861193	1691559	2066651	1828349	1912237
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12945828	14036443	14015752	13980671
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5825622	6316400	6307088	6291302
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	63159	84894	98722	100092
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	7120205	7720044	7708663	7689369
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	243063	269971	275737	271587
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16378019	16054242	17244818	17087709	17015040
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4432986	4607365	4624647	4579446
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11916387	11621256	12637453	12463061	12435594
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949509	10703752	11680480	11496877	11468977
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10616642	11591800	11411196	11386587
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	23633	10040	6589	10362	9861
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1646	869	1137	1231
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	905819	949514	954686	955525
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	206988	204416	209028	228539
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	428781	418116	420304	443146
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	165378	138760	138878	139618
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	56415	74940	72398	74988
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	1140062	1475543	1385329	1296725
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	476349	716432	683105	681336
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	89471	94182	87459	89774
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-574242	-664928	-614764	-525614
2.4 पूंजी खाता	1578041	1565630	1730885	1734464	1737188
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	843995	955212	820827	827763	638621
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593095	553165	559684	507565	530821
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	80681	73358	29767	27716	35577

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2021		2022	
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4434632	4608235	4625784	4580677
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	74509	53140	49347	51659
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	12011	8397	8422	8411
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	69780	73060	73179	73112
3.3 अन्य	5210	5450	5007	5000	5020
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	126329	115386	113746	113382
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	311745	341692	343142	338716
4.3 अन्य	149325	140989	147470	147822	147862
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	30469	38153	45840	49961
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	134474	167086	168188	167402

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति						
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
	2020-21	2021		2022	2020-21	2021	
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	208	212	211	133	132	136
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	259530	261259	254662	270636	254589	256374	250071
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	202813	190557	189586	195866	198144	186315
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	41913	37900	56311	40880	41913	37883
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	16533	26204	24738	17843	16316	25873
2 अन्य के प्रति देयताएं	16457782	16089999	17590424	17345113	16014145	15655408	17144557
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	15221717	16670399	16452526	15113512	14802765	16241854
2.1.1 मांग	1899343	1728459	2109712	1954627	1861193	1691559	2066651
2.1.2 मीयादी	13640809	13493258	14560688	14497899	13252320	13111206	14175203
2.2 उधार	248271	247395	274394	275942	244025	243063	269971
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	620887	645630	616644	656607	609580	632732
3 रिजर्व बैंक से उधार	90275	84597	102489	94286	90275	84597	102489
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	90275	84597	102489	94286	90275	84597	102489
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	650745	581938	830772	790665	633440	565820	810615
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	91572	96489	92106	90748	89471	94182
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	490366	734284	698559	542693	476349	716432
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	265729	254569	288521	304279	197541	193056	226892
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	174179	192939	205548	143294	140128	156132
5.1.1 चालू खाते में	16796	16068	19597	33165	14226	13638	16055
5.1.2 अन्य खातों में	162634	158111	173342	172383	129068	126491	140077
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	32342	32002	30454	10654	10113	12048
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	19319	30206	33966	16764	17286	28572
5.4 अन्य आस्तियां	29675	28730	33373	34312	26829	25529	30139
6 निवेश	4598924	4566898	4752766	4721946	4462526	4434632	4608235
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4558728	4745699	4714750	4461632	4432986	4607365
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	8170	7067	7196	894	1646	869
7 बैंक ऋण	11297014	11046037	11938940	11822460	10949509	10703752	11582087
7क खाद्यान्न ऋण	91653	117510	124497	118207	61254	87109	88680
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10865787	11716596	11600105	10736491	10525542	11361984
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	23728	34172	34140	30531	23465	34159
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	128831	108219	136359	137848	127883	107357	135027
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	17722	20865	19331	20394	17357	20446
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	30581	30947	31036	34210	30031	30471

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2021		2022	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 28	2021-22	2022
		1	2	3	4	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10949509	10703752	11683413	11582442	5.8	8.2
II. खाद्यान्न ऋण	61254	87110	88680	82390	34.5	-5.4
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10616642	11594733	11500052	5.6	8.3
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1334656	1298294	1417969	1432743	7.3	10.4
2. उद्योग	2958092	2864224	2985278	3046833	3.0	6.4
2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	402798	387891	447566	464420	15.3	19.7
2.2 मझौले	138473	127877	224255	223376	61.3	74.7
2.3 बड़े	2416821	2348457	2313458	2359037	-2.4	0.5
3. सेवाएं	2764171	2707543	2848108	2904619	5.1	7.3
3.1 परिवहन परिचालक	143159	140706	141056	155422	8.6	10.5
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19706	18059	19712	20344	3.2	12.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	50578	49384	52760	54461	7.7	10.3
3.4 शिपिंग	7254	7223	7026	6871	-5.3	-4.9
3.5 नौवहन	25739	25518	12229	23407	-9.1	-8.3
3.6 पेशेवर सेवाएं	107357	104971	105280	111576	3.9	6.3
3.7 व्यापार	628726	600582	644771	672389	6.9	12.0
3.7.1 थोक व्यापार	318011	287812	329918	333226	4.8	15.8
3.7.2 खुदरा व्यापार	310715	312770	314853	339163	9.2	8.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	272663	268810	270860	275661	1.1	2.5
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	956486	915781	1002081	1014179	6.0	10.7
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	218704	201156	229942	232739	6.4	15.7
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78987	76145	108035	122375	54.9	60.7
3.10 अन्य सेवाएं ³	552504	576510	592334	570309	3.2	-1.1
4. व्यक्तिगत ऋण	2946819	2850050	3087845	3180477	7.9	11.6
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	17327	16825	13115	25744	48.6	53.0
4.2 आवास	1489722	1443145	1521439	1552989	4.2	7.6
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	64143	59820	73011	70009	9.1	17.0
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4439	4033	4820	5017	13.0	24.4
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	129742	129197	124743	141254	8.9	9.3
4.6 शिक्षा	64063	64575	63213	63057	-1.6	-2.4
4.7 वाहन ऋण	280180	274650	279485	281518	0.5	2.5
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60835	52323	70871	69521	14.3	32.9
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	836368	805482	937148	971366	16.1	20.6
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1272495	1251626	1346408	1354691	6.5	8.2
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1161616	1187176	1253505	1244132	7.1	4.8
5.3 मध्यम उद्यम ⁶	211903	193818	276485	275363	29.9	42.1
5.4 आवास	488435	488802	468623	480738	-1.6	-1.6
5.5 शिक्षा ऋण	48262	49915	46884	46303	-4.1	-7.2
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1175	1377	1764	1965	67.3	42.7
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2661	2470	2333	2447	-8.1	-0.9
5.8 निर्यात ऋण ⁷	24231	19954	20067	24418	0.8	22.4
5.9 अन्य	16385	18473	19273	39788	142.8	115.4
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	864897	818870	897351	875210	1.2	6.9

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2021	2021	2022	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन. 29	दिसं. 31	जन. 28	2019-20	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	2958092	2864224	2985278	3046833	3.0	6.4
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	46661	45918	52100	47827	2.5	4.2
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	157855	161985	164290	165796	5.0	2.4
2.2.1 चीनी	26263	28504	20748	21895	-16.6	-23.2
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19180	19043	19369	18320	-4.5	-3.8
2.2.3 चाय	4713	4991	5155	5108	8.4	2.3
2.2.4 अन्य	107699	109446	119017	120473	11.9	10.1
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16846	16240	15794	16646	-1.2	2.5
2.4 वस्त्र	206225	213871	212884	218010	5.7	1.9
2.4.1 सूती वस्त्र	91366	93927	91792	93860	2.7	-0.1
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	2808	2672	2995	3026	7.8	13.3
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38881	37355	42667	42145	8.4	12.8
2.4.4 अन्य वस्त्र	73171	79917	75430	78979	7.9	-1.2
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	10749	10692	10868	11159	3.8	4.4
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13922	13903	14259	14737	5.9	6.0
2.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	36172	35484	38234	38468	6.3	8.4
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	68358	54071	86527	75420	10.3	39.5
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196414	187672	198293	195326	-0.6	4.1
2.9.1 उर्वरक	32359	40992	30236	27348	-15.5	-33.3
2.9.2 औषधि और दवाइयां	53552	51779	54700	56452	5.4	9.0
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45661	36741	42497	37394	-18.1	1.8
2.9.4 अन्य	64843	58160	70860	74132	14.3	27.5
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	55775	52952	65349	68172	22.2	28.7
2.11 कांच और कांच के सामान	6671	7075	5810	5957	-10.7	-15.8
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55361	60178	46586	47090	-14.9	-21.7
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	332107	331857	286405	288814	-13.0	-13.0
2.13.1 लोहा और स्टील	234986	242618	187331	187808	-20.1	-22.6
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	97121	89240	99074	101007	4.0	13.2
2.14 सभी अभियांत्रिकी	152309	147370	155875	160233	5.2	8.7
2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	35319	33649	37587	38310	8.5	13.9
2.14.2 अन्य	116991	113721	118289	121924	4.2	7.2
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	86003	86006	84887	88936	3.4	3.4
2.16 रत्न और आभूषण	64459	69371	67881	74261	15.2	7.0
2.17 निर्माण	96349	99895	95644	97176	0.9	-2.7
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1105348	1043122	1135536	1168376	5.7	12.0
2.18.1 पावर	572950	565481	591639	595469	3.9	5.3
2.18.2 दूरसंचार	112195	91049	114040	127432	13.6	40.0
2.18.3 सड़क	242831	213847	248869	262531	8.1	22.8
2.18.4 हवाई अड्डा	7327	7161	7510	6459	-11.9	-9.8
2.18.5 बंदरगाह	7586	8036	7268	7112	-6.3	-11.5
2.18.6 रेलवे	11263	11454	10079	10151	-9.9	-11.4
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	151197	146094	156131	159223	5.3	9.0
2.19 अन्य उद्योग	250505	226562	248056	264428	5.6	16.7

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020	2021					
		दिसं. 25	अक्टू. 29	नव. 05	नव. 19	नव. 26	दिसं. 03	दिसं. 17
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	125859.6	128069.6	128013.9	127248.2	126843.4	126631.3	126775.8	126250.1
2 मांग और मीयादी देयताएं								
2.1 मांग देयताएं	23736.9	22701.0	25243.2	26361.0	24421.0	23568.9	24362.4	24175.7
2.1.1 जमा राशियां								
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	4320.8	5539.9	6114.8	5879.7	5294.8	5644.8	5476.8
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13899.7	14672.8	14884.2	13527.1	13473.5	13711.9	13239.2
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	80.0	309.8	174.9	150.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	4480.4	4950.5	5052.1	4839.4	4650.6	5005.7	5459.6
2.2 मीयादी देयताएं	179957.5	174092.7	171867.5	172989.1	174852.8	175629.1	174844.3	176049.4
2.2.1 जमा राशियां								
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	57412.6	56659.6	58734.0	58455.0	59386.8	58648.8	59937.1
2.2.1.2 अन्य	111960.2	114169.8	113341.1	112364.0	113316.3	113157.7	113063.8	113010.9
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	630.0	927.5	910.1	910.1	910.1	910.1	900.5
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	1880.4	939.3	980.9	2171.4	2174.4	2221.5	2200.8
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	58860.6	58096.5	57950.6	60487.7	62398.8	62643.7	62867.4
4.1 मांग	15691.8	13515.1	12222.9	11745.3	12210.4	12380.4	12696.3	13148.7
4.2 मीयादी	47868.0	45345.5	45873.6	46205.3	48277.2	50018.4	49947.4	49718.6
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	8151.1	7125.5	9282.9	9058.6	9268.7	9075.7	9590.4	9918.8
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	568.6	722.8	631.3	722.6	691.6	636.1	673.2
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6556.9	8560.1	8427.3	8546.1	8384.1	8954.3	9245.6
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1148.1	990.4	1299.6	1283.3	1280.3	1215.4	1245.1	1141.8
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	64455.2	61776.2	71010.3	71104.6	71886.2	73814.2	73860.5	72595.8
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	28835.7	25995.4	20265.8	20550.8	22786.2	21853.7	21465.8	23039.9
9 बैंक ऋण (10.1+11)	114631.6	111808.2	107241.8	107467.1	107529.9	107879.4	108518.7	109958.7
10 अग्रिम								
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	114612.1	111788.9	107221.4	107446.6	107509.4	107858.5	108497.9	109938.2
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	86450.6	95223.9	95541.5	97554.3	99264.9	99615.8	100260.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	19.3	20.4	20.5	20.5	20.8	20.9	20.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जन. '21	दिसं. '21	जन. '22(अ)	जन. '21	दिसं. '21	जन. '22(अ)	जन. '21	दिसं. '21	जन. '22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	156.7	161.1	158.3	155.7	165.8	164.1	160.8	172.2	170.3	157.6	168.2	166.4
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	142.9	147.4	148.2	147.8	151.6	152.1	144.5	148.7	149.4
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	186.1	197.0	196.9	192.5	202.2	202.1	188.4	198.8	198.7
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	174.4	176.5	178.0	175.7	180.0	180.1	174.9	177.9	178.8
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	154.1	159.8	160.5	154.4	160.0	160.4	154.2	159.9	160.5
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	159.7	195.8	192.6	148.5	173.5	171.0	155.6	187.6	184.7
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	147.9	152.0	151.4	153.1	158.3	156.4	150.3	154.9	153.7
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	157.1	172.3	159.3	182.8	219.5	203.9	165.8	188.3	174.4
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	158.6	164.5	164.0	160.2	164.2	163.8	159.1	164.4	163.9
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	112.9	120.6	119.3	115.5	121.9	121.2	113.8	121.0	119.9
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	165.1	171.7	173.3	163.0	168.2	169.8	164.4	170.5	172.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	158.5	169.7	169.8	147.7	156.5	156.5	154.0	164.2	164.2
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	165.1	175.1	175.8	168.5	178.2	179.0	166.7	176.5	177.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	181.8	188.7	183.6	185.8	190.8	190.7	192.7	196.8	196.4	187.6	192.4	192.2
3 कपड़ा और जूते	155.6	149.7	153.3	157.5	171.2	172.7	151.0	160.7	162.3	154.9	167.0	168.6
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	158.2	171.8	173.2	153.4	163.3	164.7	156.3	168.5	169.9
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	153.1	167.3	169.3	137.9	146.7	148.5	146.8	158.7	160.7
4 आवास	-	157.2	157.2	-	-	-	158.9	163.4	164.5	158.9	163.4	164.5
5 ईंधन और लाइट	149.1	140.9	146.0	152.9	165.6	165.8	145.7	161.7	161.5	150.2	164.1	164.2
6 विविध	153.9	146.1	150.2	156.7	166.0	166.6	148.5	157.8	158.6	152.7	162.0	162.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	154.3	163.9	164.9	146.0	156.0	156.8	150.4	160.2	161.1
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	163.5	174.0	174.7	155.2	165.1	166.1	160.4	170.6	171.4
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	148.7	160.1	161.0	138.2	151.8	152.7	143.2	155.7	156.6
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	156.1	164.5	164.8	146.4	157.6	158.4	150.6	160.6	161.2
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	163.1	169.7	169.9	156.8	160.6	161.1	159.4	164.4	164.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	156.9	162.8	163.2	158.3	162.4	162.8	157.5	162.6	163.0
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	156.1	154.4	155.3	156.8	167.0	166.4	155.8	165.2	165.0	156.3	166.2	165.7

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2021		2022
				जन.	दिसं.	
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	118.2	125.4	125.1
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1038	1097	1095
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1040	1045	1106	1105

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	49612	47890	47960
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	66785	61280	62038

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	100.000	123.4	126.5	143.7	142.4	142.9
1.1 प्राथमिक वस्तुएँ	22.618	145.7	144.9	168.4	167.8	165.0
1.1.1 खाद्य वस्तुएँ	15.256	160.7	155.8	178.3	176.5	171.9
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	157.2	164.7	165.1	165.5
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	158.3	234.4	227.0	202.0
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	154.0	157.5	157.3	157.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.2	150.3	163.0	161.3	165.1
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	151.5	161.7	165.8	168.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएँ	0.948	162.0	166.0	168.6	167.0	171.9
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएँ	4.119	130.5	137.7	156.5	164.2	164.8
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	126.1	161.1	166.8	172.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	171.0	202.3	210.1	210.8
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएँ	1.960	109.0	114.2	121.0	121.9	122.2
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	228.7	228.7	309.8	292.2
1.1.3 खनिज	0.833	164.9	172.8	198.6	178.7	198.5
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	159.8	168.3	194.7	169.4	194.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.1	188.5	212.1	211.2	211.9
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	70.4	78.7	115.5	115.4	109.5
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	94.0	100.7	136.0	128.2	133.2
1.2.1 कोल	2.138	126.6	127.0	130.4	130.9	130.9
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.9	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	200.5	212.6	212.6
1.2.2 खनिज तेल	7.950	79.2	87.4	139.3	131.9	133.0
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	116.9	131.5	116.7	135.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	121.5	125.3	136.6	136.4	137.1
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	141.4	145.2	157.6	156.6	157.0
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.2	138.7	142.6	143.8	142.7
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	140.3	150.3	143.6	148.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	121.1	122.0	121.7	122.4
1.3.1.4 सब्जियों और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.5	159.0	184.2	181.1	180.9
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.9	147.0	148.0	147.8	148.7
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	142.0	146.7	146.6	147.0
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	118.9	136.3	138.1	141.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	138.6	148.1	149.2	150.6
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.4	116.8	125.5	125.2	124.7
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	128.0	128.4	130.3	133.0	132.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	130.2	133.4	131.4	142.3
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.5	158.3	172.0	172.8	171.3
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.0	149.1	158.0	157.7	162.4
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.2	132.4	135.5	136.4	137.0
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.9	138.8	154.3	153.1	153.0
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.5	172.6	197.1	197.6	199.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	124.5	123.8	127.3	127.2	127.2
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	120.2	119.7	123.9	123.8	123.9
1.3.2.2 माल्ट लिंकर और माल्ट	0.225	126.5	124.6	131.5	131.7	131.5
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	129.1	128.7	128.5	128.4
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	157.2	157.7	159.1	161.5	161.0
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	157.7	159.1	161.5	161.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.6	123.1	138.1	139.1	140.0
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.6	114.4	132.6	133.4	134.8
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	135.2	147.9	149.6	149.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.2	115.6	126.8	127.0	128.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	133.9	140.0	141.1	142.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	160.6	170.9	167.1	167.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	115.7	128.2	128.2	128.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.6	139.5	144.2	144.0	144.6
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर बुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	138.6	142.8	142.4	143.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	139.8	141.8	148.0	148.5	148.2
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	117.9	118.6	118.7	119.3	121.1
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.1	100.2	102.2	102.5	102.4
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	138.6	142.1	142.5	143.7
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.6	122.1	120.6	121.3	124.2
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	134.6	136.3	142.1	143.0	142.3
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	122.3	131.4	131.6	131.4
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.6	138.2	143.0	144.1	142.9
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	189.6	194.4	194.5	194.6
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	127.2	134.2	134.4	135.2
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.7	124.0	139.6	140.8	141.6
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	124.1	126.3	144.4	145.3	144.5
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	122.2	126.8	138.0	138.2	140.6
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.4	117.2	133.4	136.2	137.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	153.8	155.6	158.4	161.5	163.4
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	155.6	158.4	161.5	163.4
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	118.2	120.8	136.4	136.9	137.4
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.6	122.9	150.0	149.5	149.6
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.6	123.6	129.6	131.1	133.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.7	122.5	144.3	142.3	141.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	124.4	125.3	131.4	133.9	135.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.9	117.1	134.1	137.0	137.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	121.8	129.9	130.8	131.1
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	116.5	134.0	134.0	135.3
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.7	97.7	109.2	109.2	108.8
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	130.9	131.5	136.2	137.3	137.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	131.5	136.2	137.3	137.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	111.3	116.1	127.6	127.0	127.1
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	99.4	104.9	106.5	105.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	94.4	103.9	104.8	104.1
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.3	127.5	141.8	140.0	140.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	117.6	117.4	125.3	125.1	125.7
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	129.4	138.1	141.1	145.2
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.5	110.9	116.7	118.8	119.0
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	108.4	119.0	120.9	131.3
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	111.1	112.2	114.3	116.2
1.3.13.5 सीमेंट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.9	119.0	128.9	127.7	126.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएँ	0.292	125.3	126.0	129.2	129.5	129.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	121.1	123.2	122.6	120.4	121.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	81.9	97.2	96.6	99.0
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	111.4	122.8	143.6	141.5	142.8
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	123.2	163.6	153.3	155.8
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	113.3	128.0	150.4	145.2	149.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.8	107.2	119.3	118.3	119.9
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	125.6	140.4	139.1	139.3
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	136.8	163.5	160.6	156.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	120.6	133.6	131.1	136.2
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.7	126.1	139.5	142.7	144.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	134.7	160.1	161.8	163.9
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	119.2	143.1	142.8	145.3
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.1	112.8	118.7	119.2	120.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएँ	0.271	145.7	147.6	160.2	160.6	165.1
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.9	119.7	132.4	133.6	133.7
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	119.7	124.1	126.9	124.6
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	127.8	134.4	160.7	161.4	160.9
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	98.9	97.2	97.6	97.6	98.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.7	96.0	122.7	120.0	125.0
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	103.9	109.7	109.7	109.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	125.0	127.8	136.9	139.2	140.6
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	109.8	110.1	113.9	113.2	114.3
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	99.8	106.8	106.7	108.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	134.4	134.9	134.9	134.8
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	115.1	120.5	119.8	121.3
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.5	99.1	103.1	100.9	102.3
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	108.8	107.1	108.5	109.2
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	141.8	145.6	146.5	145.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.8	101.5	106.1	107.1	107.1
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.7	95.2	98.4	98.4	99.5
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	113.6	115.7	123.2	123.5	124.4
1.3.17.1 विद्युतमोर्टर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	113.2	115.3	120.3	121.0	120.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	115.6	123.1	124.1	125.6
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	101.6	103.8	100.6	104.1
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.9	122.5	142.2	141.7	144.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.4	115.6	115.5	115.7
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	121.0	129.6	130.4	131.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	109.8	113.2	113.4	115.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	114.0	115.3	120.8	120.8	121.6
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	108.4	120.7	121.5	121.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	120.1	123.8	122.1	123.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	112.4	116.1	116.0	116.6
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	111.9	117.4	118.0	119.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.2	82.5	73.1	73.0	72.7
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	115.6	121.6	121.3	124.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	130.6	132.9	130.6	133.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	122.7	129.8	130.1	131.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	108.2	116.0	115.8	115.8
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	76.6	78.7	78.7	78.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	132.4	131.8	131.0	130.7
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	122.4	126.2	126.2	128.0
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	129.6	134.8	135.7	136.0
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	66.0	66.3	66.8	66.9
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	117.8	118.7	124.0	123.9	124.7
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	120.9	123.6	123.8	124.3
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	116.2	124.4	124.1	125.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	126.2	128.3	132.7	133.0	133.6
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.9	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	104.6	104.9	103.8	105.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	127.1	132.2	132.6	133.2
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	130.3	134.3	137.9	138.0	138.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	129.3	137.7	137.4	138.6
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	133.2	136.7	150.4	151.4	154.6
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	136.7	150.4	151.4	154.6
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	132.4	133.7	136.6	137.1	138.3
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	131.9	134.6	135.2	136.5
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	175.1	192.6	195.7	195.0
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	134.2	142.1	142.6	144.0
1.3.22.4 खेल और खेलौने	0.005	142.4	143.0	151.6	151.1	149.4
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	168.9	172.9	171.1	170.8
2 खाद्य सूचकांक	24.378	153.4	151.8	170.6	169.0	166.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2019-20	2020-21	अप्रैल- दिसंबर		दिसंबर	
				2020-21	2021-22	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	111.7	128.7	137.4	138.0
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	92.6	107.4	117.3	120.3
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	110.8	128.5	139.0	138.8
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	154.8	169.3	158.0	162.5
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	112.6	125.9	130.1	133.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	68.3	84.8	95.8	91.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	117.1	141.2	150.3	150.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	116.4	144.2	151.0	153.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	92.6	111.5	124.9	121.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	139.0	146.5	161.1	160.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जनवरी			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	2078936	1838921	1242959	88.5	79.9
1.1 कर राजस्व (निवल)	1765145	1547436	1101855	87.7	82.0
1.2 करेतर राजस्व	313791	291485	141104	92.9	67.0
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्ति	99975	32595	40355	32.6	86.8
2.1 ऋण की वसूली	21975	20527	15804	93.4	109.0
2.2 अन्य प्राप्ति	78000	12068	24551	15.5	76.7
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2178911	1871516	1283314	85.9	80.1
4 राजस्व व्यय	3167289	2367698	2155210	74.8	71.6
4.1 ब्याज भुगतान	813791	614626	519597	75.5	75.0
5 पूंजी व्यय	602711	441686	362108	73.3	82.5
6 कुल व्यय (4+5)	3770000	2809384	2517318	74.5	73.0
7 राजस्व घाटा (4-1)	1088352	528777	912251	48.6	62.7
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1591089	937868	1234004	58.9	66.8
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	777298	323242	714407	41.6	61.8

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021			2022			
		जन. 29	दिसं. 24	दिसं. 31	जन. 7	जन. 14	जन. 21	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5158	2964	12767	9354	7834	7232	6179	4606
1.2 प्राथमिक व्यापारी	15686	20930	29687	26882	19596	20064	20650	23278
1.3 राज्य सरकारें	53546	62912	102016	103016	102899	97904	92809	89751
1.4 अन्य	77882	92430	100679	106541	107418	102457	97846	92332
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	62566	68922	58141	56154	53625	52152	53310	53165
2.2 प्राथमिक व्यापारी	52764	31222	34421	32988	35996	39824	43400	46518
2.3 राज्य सरकारें	9826	3816	6318	6458	5453	5428	5524	4026
2.4 अन्य	53438	68945	27631	19711	24906	29727	30924	32920
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	119467	154467	119885	115964	117370	115765	118211	112628
3.2 प्राथमिक व्यापारी	127426	136064	111859	117965	114057	114598	119860	127319
3.3 राज्य सरकारें	22851	15855	17843	21643	22001	21981	21981	23136
3.4 अन्य	122944	135156	97357	99125	104838	109545	105238	106626
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	315325	193438	156242	139739	101003	92655	210638	224416
4.4 अन्य	1524	198	60	761	1123	743	1263	724
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	723556	793683	718603	715802	715994	716679	715931	716307

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 29	10000	149	66767	5051	32	9949	5051	15000	99.10	3.6570
जन. 5	5000	92	31520	1	6	4999	1	5000	99.12	3.5594
जन. 12	5000	88	30152	2201	27	4999	2201	7200	99.12	3.5671
जन. 19	5000	102	25393	3201	21	4999	3201	8200	99.09	3.6856
जन. 25	5000	82	20841	6313	28	4997	6313	11310	99.08	3.7080
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 29	3000	100	12645	1029	29	3000	1029	4028	98.06	3.9699
जन. 5	10000	165	47323	20	29	9980	20	10000	98.04	4.0175
जन. 12	10000	158	44187	0	42	10000	0	10000	98.03	4.0281
जन. 19	10000	103	19487	1	71	9999	1	10000	97.99	4.1242
जन. 25	10000	99	21073	700	68	10000	700	10700	97.96	4.1789
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
दिसं. 29	7000	116	22770	3800	46	7000	3800	10800	95.92	4.2650
जन. 5	11000	153	23959	528	90	10996	528	11523	95.85	4.3400
जन. 12	11000	123	22457	35	75	10965	35	11000	95.81	4.3800
जन. 19	11000	128	22775	0	98	11000	0	11000	95.73	4.4727
जन. 25	11000	126	27590	1136	55	10964	1136	12100	95.70	4.5053

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
जनवरी	1, 2022	2.70-3.70	3.27
जनवरी	3, 2022	2.00-3.50	3.29
जनवरी	4, 2022	2.00-3.50	3.28
जनवरी	5, 2022	2.00-3.45	3.21
जनवरी	6, 2022	2.00-3.45	3.21
जनवरी	7, 2022	2.10-3.65	3.26
जनवरी	10, 2022	2.10-3.60	3.31
जनवरी	11, 2022	2.10-3.65	3.36
जनवरी	12, 2022	2.10-3.55	3.33
जनवरी	13, 2022	2.10-3.45	3.27
जनवरी	14, 2022	2.10-4.10	3.41
जनवरी	15, 2022	2.65-3.60	3.07
जनवरी	17, 2022	2.10-3.75	3.41
जनवरी	18, 2022	2.10-4.53	3.61
जनवरी	19, 2022	2.10-4.50	3.66
जनवरी	20, 2022	2.10-4.65	3.98
जनवरी	21, 2022	2.20-4.55	3.99
जनवरी	24, 2022	2.20-4.50	3.96
जनवरी	25, 2022	2.20-4.15	3.67
जनवरी	27, 2022	2.20-4.25	3.68
जनवरी	28, 2022	2.20-4.00	3.55
जनवरी	29, 2022	2.70-3.25	2.89
जनवरी	31, 2022	2.00-3.40	3.22
फरवरी	1, 2022	2.20-3.60	3.25
फरवरी	2, 2022	2.20-3.80	3.30
फरवरी	3, 2022	2.20-3.50	3.22
फरवरी	4, 2022	2.20-3.60	3.27
फरवरी	5, 2022	2.70-3.25	2.92
फरवरी	8, 2022	2.20-3.50	3.26
फरवरी	9, 2022	2.20-3.60	3.28
फरवरी	10, 2022	2.00-3.60	3.27
फरवरी	11, 2022	2.20-3.55	3.28
फरवरी	14, 2022	2.20-3.60	3.27
फरवरी	15, 2022	2.00-3.45	3.26

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021			2022	
	जन. 29	दिसं. 17	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	62026.32	73298.30	84702.40	101151.87	99706.14
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	530.14	12506.20	17497.20	17328.85	2343.76
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.82-4.72	3.53-4.72	3.74-5.31	3.57-4.98	3.78-5.09

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021			2022	
	जन. 31	दिसं. 15	दिसं. 31	जन. 15	जन. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	410651.90	446975.40	350068.65	386159.90	395881.00
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	89040.60	161701.60	87182.55	64665.30	71201.95
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.18-11.32	3.38-12.34	3.50-12.31	3.39-13.45	3.47-12.32

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2021			2022			
		जन. 29	दिसं. 24	दिसं. 31	जन. 7	जन. 14	जन. 21	जन. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	17057	17695	13822	13780	15648	15138	13113
2 नोटिस मुद्रा	2604	4876	616	3125	276	4159	368	4614
3 मीयादी मुद्रा	757	576	735	640	484	357	334	376
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	589855	665034	834645	687648	811201	612806	800727
5 बाजार रिपो	337341	363896	337263	402671	370324	428782	380765	420810
6 कॉर्पोरेट बांड में रिपो	2990	2957	234	0	52	208	371	389
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	86840	70064	75085	56953	69453	63714	87352
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	36158	48074	37640	36648	35242	43016	34980
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	5991	5237	6397	5010	4688	5883	6719
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	2970	5688	4503	6141	2724	2689	1941
10.2 182-दिवसीय	4870	5074	1149	1706	6182	3837	2833	1733
10.3 364-दिवसीय	4010	4138	2815	2120	6260	4294	2656	3642
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	54330	62963	52366	60242	50784	57077	49015
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	—	242	892	1662	1766	685	201	155

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2020-21 (अप्रै-जन.)		2021-22 (अप्रै-जन.)*		जन. 2021		जन. 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	74	102062	49	89771	135	130898	2	381	11	815
1ए प्रीमियम	73	97648	49	86081	127	129017	2	374	10	728
1.1 पब्लिक	53	38004	32	28783	102	105585	1	300	6	715
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	32	25871	101	104395	1	295	6	670
1.2 राइट्स	21	64059	17	60988	33	25311	1	81	5	99
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	17	60210	26	24622	1	79	4	58
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	16	5806	13	4690	24	10717	3	819	—	—
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	13	4690	24	10717	3	819	—	—
3.1.1 पब्लिक	16	5806	13	4690	24	10717	3	819	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3)	90	107868	62	94461	159	141614	5	1200	11	815
4.1 पब्लिक	69	43809	45	33473	126	116302	4	1119	6	715
4.2 राइट्स	21	64059	17	60988	33	25311	1	81	5	99

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2021					2022
			जन.	सित.	अक्टू.	नव.	दिसं.	जन.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2159043	201331	248750	267628	237089	295762	256833
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	291808	27538	33814	35724	31825	39240	34501
1.1 तेल	करोड़ ₹	190896	15616	38219	40177	41314	51466	31042
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	25804	2136	5195	5363	5546	6828	4170
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1968147	185715	210531	227451	195775	244296	225791
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	266004	25402	28619	30361	26280	32412	30331
2 आयात	करोड़ ₹	2915958	307279	415507	400348	394180	450924	386538
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	394436	42030	56483	53440	52913	59826	51925
2.1 तेल	करोड़ ₹	611353	68900	125153	93949	109325	124324	89028
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	82684	9424	17013	12541	14675	16495	11959
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2304605	238379	290354	306399	284855	326600	297511
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	311752	32606	39470	40899	38237	43331	39966
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-756914	-105949	-166758	-132720	-157092	-155162	-129705
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-102627	-14492	-22669	-17716	-21087	-20586	-17424
3.1 तेल	करोड़ ₹	-420457	-53284	-86934	-53772	-68012	-72858	-57986
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-56880	-7288	-11818	-7178	-9129	-9666	-7789
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-336458	-52664	-79824	-78948	-89080	-82304	-71720
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-45748	-7203	-10851	-10538	-11958	-10920	-9634

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021	2022					
		फर. 26	जन. 21	जन. 28	फर. 4	फर. 11	फर. 18	फर. 25
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	4294511	4719835	4727298	4720099	4752438	4725881	4755726
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	584554	634287	629755	631953	630190	632952	631527
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	3986598	4238297	4249350	4244871	4265109	4233784	4253494
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	542615	569582	566077	568329	565565	567060	564832
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	260239	300149	296461	293405	303427	309914	319800
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	35421	40337	39493	39283	40235	41509	42467
	मात्रा	687.85	755.42	755.42	757.28	757.62	757.62	757.96
	(मैट्रिक टन)							
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड़ ₹	11145	142511	142706	142719	144590	143069	143381
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	1517	19152	19011	19108	19173	19162	19040
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	36529	38878	38780	39104	39312	39114	39051
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5001	5216	5174	5233	5217	5221	5187

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2021		2022	2020-21	2021-22
		जन.	दिसं.	जन.	अप्रै.-जन.	अप्रै.-जन.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141,895	141,623	141,908	140,485	8,003	2,720
1.1 एफसीएनआर (बी)	20,473	21,506	18,154	18,089	-2,738	-2,384
1.2 एनआर (ई) आरए	102,579	101,981	102,916	101,543	9,017	2,440
1.3 एनआरओ	18,842	18,136	20,838	20,852	1,724	2,664

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2021		2022
		अप्रै.-जन.	अप्रै.-जन.	जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43955	42758	31515	1482	934	5905
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	54927	51079	45017	1902	2249	6831
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	81973	72839	69662	4545	6670	8913
1.1.1.1.1 इक्विटी	61088	55371	50756	2836	4037	6517
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	906	1620	585	25	45
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51597	47427	35340	1789	3044	4694
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	5844	12602	332	842	1649
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1452	1194	1194	129	126	129
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16935	13923	14635	1506	1464	1506
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3950	3545	4271	202	1169	890
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	27046	21760	24646	2643	4421	2082
1.1.1.2.1 इक्विटी	26983	21720	23589	2631	4314	1586
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	40	1057	11	107	496
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	10972	8321	13502	420	1315	925
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5583	4655	7326	268	846	691
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3013	2511	2567	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6688	4325	6043	472	390	133
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	3170	2434	571	172	150
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	36137	35075	-6958	6218	-3613	-4919
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	—	—	—	—	—	—
1.2.2 एफआईआई	38725	37057	-4923	6522	-3275	-4186
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	—	—	—	—	—	—
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2589	1982	2035	303	338	733
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	80092	77833	24557	7700	-2680	987

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2020-21	2021			2022
		जन.	नव.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	12684.40	1253.63	1547.41	1773.56	2018.31
1.1 जमाराशियां	680.37	40.85	50.40	56.64	66.27
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	5.64	11.01	10.77	8.58
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	34.89	57.68	54.30	73.53
1.4 उपहार	1586.24	134.16	206.21	214.59	200.23
1.5 दान	12.59	0.67	0.94	2.69	1.53
1.6 यात्रा	3239.67	356.92	456.31	884.10	989.05
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	216.64	267.22	281.46	315.61
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	2.56	3.30	3.33	3.77
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	455.51	482.35	253.69	345.76
1.10 अन्य	85.03	5.79	11.99	11.99	13.98

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2019-20	2020-21	2021	2022	
			फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	94.24	94.53	93.74
1.2 रीर	103.20	103.46	103.46	104.80	103.64
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.78	94.71	93.91
2.2 रीर	102.88	102.96	103.06	104.31	103.16
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.87	88.46	87.90	87.60	86.91
1.2 रीर	103.56	101.87	101.18	103.17	102.36
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	93.24	92.66	92.33	91.61
2.2 रीर	100.00	98.36	97.70	99.62	98.84

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	95	139	81
1.2 राशि	26799	3744	4374	3879
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	0	1	4
2.2 राशि	8456	0	1175	4100
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	95	140	85
3.2 राशि	35255	3744	5549	7979
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	7.50	5.30	15.18
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	2.74	1.01	1.81
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.25	0.00-10.25	0.00-11.20

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12827	468	442	5783
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	9985	872	2584	843
ए) परिवहन	636	0	109	0
बी) ऊर्जा	2713	71	959	708
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	151	0	0	5
डी) संचार	757	0	5	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	1761	0	0	0
एफ) अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	1346	0	1100	130
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2622	801	411	0
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1894	109	291	34
IV. अन्य संस्थाएं	1026	1000	500	0
ए) एसई जेड में इकाई	26	0	0	0
बी) सिडबी	0			
सी) एक्विजिशन बैंक	1000	1000	500	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	2110	0	0	0
VII. एनबीएफसी	6934	1252	1690	1315
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	6024	1250	1275	1225
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	84	0	17	0
सी) एनबीएफसी - अन्य	827	2	398	90
VIII. गैर-सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	8	0	0	0
X. अन्य	470	43	42	4

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	296176	264608	31568	404597	373408	31189
1 चालू खाता (1.1+1.2)	150791	135541	15250	194275	203886	-9611
1.1 पण्य	75591	90407	-14816	104842	149265	-44423
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	75200	45134	30066	89434	54621	34813
1.2.1 सेवाएं	49793	28707	21086	61421	35836	25585
1.2.1.1 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.2.1.2 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.2.1.3 बीमा	590	537	53	796	575	220
1.2.1.4 जीएनआईई	144	190	-46	217	198	19
1.2.1.5 विविध	41554	20458	21096	50678	22962	27716
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	24791	2769	22021	29965	3184	26781
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	661	355	306	766	275	491
1.2.2 अंतरण	20421	2035	18386	21154	2239	18915
1.2.2.1 आधिकारिक	36	270	-233	18	315	-297
1.2.2.2 निजी	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.2.3 आय	4986	14391	-9405	6859	16546	-9688
1.2.3.1 निवेश आय	3541	13695	-10154	5362	15792	-10430
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	145010	129067	15943	209579	169522	40057
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	97296	65874	31422	132378	119040	13338
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	30502	6077	24424	20447	10987	9461
2.1.1.1 भारत में	29527	2450	27078	19281	6475	12806
2.1.1.1.1 इक्विटी	23794	2445	21350	13940	6259	7681
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4117		4117	4482	0	4482
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1617	5	1611	859	216	643
2.1.1.2 विदेश में	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
2.1.1.2.1 इक्विटी	974	1202	-228	1167	2060	-894
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	781	-781
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1672	-1672	0	1670	-1670
2.1.2 संविभाग निवेश	66794	59796	6998	111931	108054	3877
2.1.2.1 भारत में	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1 एफआईआई	66420	58684	7736	110448	105904	4544
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	55007	48183	6824	95335	94718	618
2.1.2.1.1.2 ऋण	11413	10501	912	15112	11186	3926
2.1.2.1.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	375	1113	-738	1483	2150	-666
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	20645	24532	-3887	25555	17965	7590
2.2.1 बाह्य सहायता	3209	1323	1886	2420	1303	1117
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	14	30	-15
2.2.1.2 भारत को	3199	1302	1897	2406	1273	1132
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8775	12731	-3956	9114	5004	4110
2.2.2.1 भारत द्वारा	769	1005	-235	282	249	33
2.2.2.2 भारत को	8005	11726	-3721	8832	4755	4077
2.2.3 भारत को अल्पावधि	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8662	9770	-1108	9615	11658	-2043
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	709	-709	4407	0	4407
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	18762	30025	-11263	20817	20457	360
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	18749	30025	-11276	20473	20457	17
2.3.1.1 आस्तियां	7207	16747	-9539	10097	9858	239
2.3.1.2 देयताएं	11541	13279	-1737	10376	10598	-222
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10311	8377	1934	8574	9357	-783
2.3.2 अन्य	13	0	13	344	0	344
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	8307	8633	-327	30829	12059	18770
3 भूल-चूक	375	375	0	742	0	742
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	31568	-31568	0	31189	-31189
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		31568	-31568	0	31189	-31189

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2203029	1968215	234814	2997726	2766643	231083
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1121622	1008187	113435	1439417	1510625	-71208
1.1 पण्य	562264	672468	-110205	776788	1105928	-329140
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	559358	335719	223639	662629	404696	257932
1.2.1 सेवाएं	370373	213533	156840	455079	265514	189566
1.2.1.1 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.2.1.2 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.2.1.3 बीमा	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.2.1.4 जीएनआईई	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.2.1.5 विविध	309085	152168	156917	375483	170133	205350
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	184399	20598	163801	222016	23589	198426
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4914	2638	2275	5676	2035	3641
1.2.2 अंतरण	151896	15140	136756	156732	16588	140144
1.2.2.1 आधिकारिक	269	2006	-1737	137	2334	-2198
1.2.2.2 निजी	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.2.3 आय	37089	107046	-69956	50817	122594	-71777
1.2.3.1 निवेश आय	26339	101868	-75528	39725	117005	-77280
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1078616	960028	118588	1552809	1256019	296790
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	723708	489983	233725	980814	881990	98824
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	226877	45202	181675	151499	81403	70095
2.1.1.1 भारत में	219632	18223	201410	142854	47973	94880
2.1.1.1.1 इक्विटी	176987	18184	158803	103281	46371	56909
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	30620	0	30620	33210	0	33210
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	12025	39	11987	6364	1602	4761
2.1.1.2 विदेश में	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
2.1.1.2.1 इक्विटी	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5603	-5603	0	5789	-5789
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	12437	-12437	0	12375	-12375
2.1.2 संविभाग निवेश	496831	444780	52050	829315	800587	28729
2.1.2.1 भारत में	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1 एफआईआई	494044	436504	57540	818325	784660	33664
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	409153	358396	50757	706356	701779	4577
2.1.2.1.1.2 ऋण	84891	78108	6783	111968	82881	29087
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2786	8276	-5490	10991	15927	-4936
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	153564	182478	-28914	189343	133104	56239
2.2.1 बाह्य सहायता	23866	9840	14026	17930	9654	8276
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	106	220	-114
2.2.1.2 भारत को	23795	9687	14108	17824	9434	8390
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	65268	94694	-29426	67525	37075	30451
2.2.2.1 भारत द्वारा	5722	7473	-1751	2087	1844	242
2.2.2.2 भारत को	59545	87221	-27675	65439	35231	30208
2.2.3 भारत को अल्पावधि	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	64430	72671	-8241	71239	86375	-15136
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	5273	-5273	32649	0	32649
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	139558	223336	-83778	154236	151566	2670
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	139459	223336	-83877	151690	151566	124
2.3.1.1 आस्तियां	53611	124564	-70953	74810	73041	1769
2.3.1.2 देयताएं	85848	98771	-12923	76881	78525	-1645
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाशियां	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
2.3.2 अन्य	99	0	99	2545	0	2545
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	61787	64217	-2430	228416	89344	139073
3 भूल-चूक	2791	0	2791	5500	0	5500
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	234814	-234814	0	231083	-231083
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	234814	-234814	0	231083	-231083

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जुला.-सित. 2020			जुला.-सित. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	150790	135515	15275	194275	203856	-9581
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	125384	119114	6270	166263	185101	-18838
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	75591	90407	-14816	104842	149265	-44423
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	75243	84319	-9076	104327	133243	-28916
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	348	0	348	515	0	515
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		6088	-6088		16022	-16022
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	49793	28707	21086	61421	35836	25585
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	68	11	56	75	16	59
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	35	204	-169	74	418	-345
1.अ.ख.3 परिवहन	5368	4759	609	7584	8181	-597
1.अ.ख.4 यात्रा	2138	2764	-626	2147	3919	-1772
1.अ.ख.5 निर्माण	589	563	26	716	715	0
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	590	537	53	796	575	220
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1003	1107	-104	1303	1463	-160
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	313	1456	-1143	202	2189	-1987
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	25515	3290	22225	30823	3651	27172
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11624	12354	-730	13858	12457	1401
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	530	817	-287	713	1243	-530
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	144	190	-46	217	198	19
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1875	655	1220	2915	811	2105
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4986	14391	-9405	6859	16546	-9688
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1445	696	749	1497	754	743
1.आ.2 निवेश आय	2753	13394	-10641	4349	15572	-11223
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1272	8131	-6859	1983	9630	-7647
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	49	2126	-2076	111	2859	-2748
1.आ.2.3 अन्य निवेश	78	3137	-3059	62	3082	-3020
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1354	1	1353	2193	1	2193
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	788	301	487	1012	220	792
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20419	2009	18410	21153	2209	18944
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20385	1766	18619	21135	1924	19212
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	19711	1287	18424	20237	1356	18881
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण						
1.इ.2 सामान्य सरकार	674	479	195	899	568	331
2 पूँजी खाता (2.1+2.2)	35	243	-209	18	285	-267
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	109	198	-88	189	210	-20
2.2 पूँजी अंतरण	8	100	-92	62	132	-71
3 वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	101	97	4	128	77	50
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	144902	160464	-15562	209391	200531	8859
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	30502	6077	24424	20447	10987	9461
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	29527	2450	27078	19281	6475	12806
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	27911	2445	25466	18422	6259	12163
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23794	2445	21350	13940	6259	7681
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4117		4117	4482		4482
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1617	5	1611	859	216	643
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1617	5	1611	859	216	643
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	974	3627	-2653	1167	4512	-3345
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	974	1955	-981	1167	2842	-1675
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	974	1202	-228	1167	2060	-894
3.1.आ.2 ऋण लिखत		753	-753		781	-781
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	1672	-1672		1670	-1670
3.2 संविभाग निवेश		1672	-1672		1670	-1670
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	66794	59796	6998	111931	108054	3877
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	66420	58684	7736	110448	105904	4544
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	55007	48183	6824	95335	94718	618
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	11413	10501	912	15112	11186	3926
3.3 वित्तीय डे रिजर्व (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	375	1113	-738	1483	2150	-666
3.4 अन्य निवेश	2858	3936	-1078	5367	5806	-439
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	44749	59086	-14337	71646	44496	27150
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	0	0	0	0	0	0
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	10325	8377	1948	8918	9357	-439
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13	0	13	344	0	344
3.4.2.3 सामान्य सरकार	10311	8377	1934	8574	9357	-783
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)			0			
3.4.3अ भारत को ऋण	20421	35702	-15281	23433	17406	6026
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	19642	34677	-15035	23137	17128	6009
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	779	1025	-246	296	279	17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	78	62	16	55	13	42
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	8662	10479	-1817	14021	11658	2364
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	5263	4466	797	7356	6062	1295
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	31568	-31568	0	31189	-31189
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.			0			
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.			0		17862	-17862
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)			0			
4. कुल आस्तियां / देयताएं	0	31568	-31568	0	13326	-13326
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	144902	160464	-15562	209391	200531	8859
4.2 ऋण लिखत	87202	57694	29508	121829	111787	10042
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	52437	66736	-14299	62343	51494	10849
5. निवल भूल-चूक	5263	36034	-30771	25219	37251	-12032
टिप्पणी: पौ: प्रारंभिक	375	375	375	742	742	742

Note : P : Preliminary

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2020			जुला.-सितं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1121609	1007991	113618	1439413	1510403	-70990
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	932637	886001	46635	1231868	1371442	-139574
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	562264	672468	-110205	776788	1105928	-329140
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	559675	627181	-67506	772976	987218	-214242
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	2588	0	2588	3812	0	3812
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	45287	-45287	0	118711	-118711
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	370373	213533	156840	455079	265514	189566
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	505	85	420	558	118	440
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	263	1519	-1256	546	3100	-2554
1.अ.ख.3 परिवहन	39926	35397	4528	56188	60613	-4425
1.अ.ख.4 यात्रा	15903	20559	-4657	15905	29037	-13132
1.अ.ख.5 निर्माण	4383	4186	197	5302	5299	3
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4385	3994	391	5896	4263	1633
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7462	8233	-771	9652	10836	-1184
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2330	10833	-8503	1499	16220	-14721
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	189787	24472	165315	228370	27051	201318
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	86464	91890	-5426	102675	92295	10380
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3944	6078	-2135	5279	9207	-3928
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1074	1414	-339	1607	1467	141
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	13948	4871	9077	21601	6006	15595
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	37089	107046	-69956	50817	122594	-71777
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10750	5178	5572	11092	5589	5503
1.आ.2 निवेश आय	20478	99630	-79152	32225	115376	-83151
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9463	60481	-51018	14692	71350	-56658
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	366	15810	-15445	820	21184	-20364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	579	23331	-22752	461	22836	-22375
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10070	7	10063	16251	5	16246
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5861	2238	3623	7500	1629	5871
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	151883	14944	136939	156729	16367	140361
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तरेत निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	151627	13134	138492	156596	14254	142342
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	146616	9573	137043	149936	10045	139891
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5011	3561	1450	6659	4209	2451
1.इ.2 सामान्य सरकार	257	1810	-1553	133	2113	-1980
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	813	1471	-658	1402	1553	-151
2.1 अनुत्पादित वित्तरेत आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	62	747	-685	457	981	-524
2.2 पूंजी अंतरण	751	725	27	946	572	374
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1077815	1193566	-115751	1551410	1485770	65641
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	226877	45202	181675	151499	81403	70095
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	219632	18223	201410	142854	47973	94880
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	207607	18184	189423	136490	46371	90119
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	176987	18184	158803	103281	46371	56909
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	30620	0	30620	33210	0	33210
3.1.अ.2 ऋण लिखत	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	12025	39	11987	6364	1602	4761
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	7245	26980	-19735	8645	33430	-24785
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7245	14543	-7298	8645	21055	-12410
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7245	8940	-1695	8645	15265	-6620
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5603	-5603	0	5789	-5789
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	12437	-12437	0	12375	-12375
3.2 संविभाग निवेश	496831	444780	52050	829315	800587	28729
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	494044	436504	57540	818325	784660	33664
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	409153	358396	50757	706356	701779	4577
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	84891	78108	6783	111968	82881	29087
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2786	8276	-5490	10991	15927	-4936
3.3 वित्तीय डेसिग्रेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	21257	29276	-8019	39762	43017	-3256
3.4 अन्य निवेश	332850	439493	-106643	530835	329679	201155
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	76798	62311	14486	66075	69328	-3253
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	99	0	99	2545	0	2545
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	76699	62311	14387	63530	69328	-5798
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	151894	265558	-113664	173616	128967	44649
3.4.3अ भारत को ऋण	146100	257932	-111832	171423	126903	44520
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	5793	7626	-1833	2193	2064	128
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	580	462	117	405	97	308
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	64430	77945	-13515	103887	86375	17512
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	39149	33218	5932	54505	44912	9592
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	132346	0	132346
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	234814	-234814	0	231083	-231083
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.	0	0	0	0	132346	-132346
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	234814	-234814	0	98737	-98737
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1077815	1193566	-115751	1551410	1485770	65641
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	648628	429138	219490	902649	828246	74403
4.2 ऋण लिखत	390038	496397	-106359	461910	381529	80382
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	39149	268031	-228882	186851	275995	-89145
5. निवल भूल-चूक	2791	0	2791	5500	0	5500

टिप्पणी: पी: प्राथमिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020		2021			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482226	188243	455981	199440	493763	202785	506723
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	121267	430714	125397	467990	127072	480697
1.2 अन्य पूंजी	71203	25278	66976	25267	74043	25773	75713	26026
2 संविभाग निवेश	7936	274104	5041	244308	7912	272859	8578	276375
2.1 इक्विटी	2340	177278	1906	149095	3146	176203	4590	177034
2.2 ऋण	5596	96826	3136	95213	4766	96657	3988	99341
3 अन्य निवेश	80606	454253	64785	440252	76828	455000	80317	475775
3.1 व्यापार ऋण	5644	100337	2792	102187	7875	102117	11879	100267
3.2 ऋण	13335	197773	9038	189705	13622	197443	10131	201213
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	143760	34864	138822	35904	143096	41102	142904
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19191	12384	18092	9538	19427	12344	17205	31391
4 रिज़र्व्स	576984		544687		611075		635363	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	859454	1210583	802757	1140541	895254	1221622	927043	1258873
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-351129		-337784		-326368		-331830

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2021		2022	विव 2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
		1	2	3		6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	2.32	3.13	2.54	161943141	15723500	20703988	17839802
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	0.93	1.10	0.93	110634315	10875915	14801512	12892869
1.1.1 आउटराइट	6.28	0.48	0.48	0.40	10032187	657843	651103	569722
1.1.2 रेपो	2.84	0.22	0.30	0.26	43751173	3848935	5075401	4348558
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.24	0.31	0.28	56850956	6369137	9075009	7974589
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.35	1.96	1.52	48903961	4576570	5516604	4470518
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.04	0.07	0.09	2404865	271015	385873	476415
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	—	—	—	—	—	—	—	—
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	156.68	192.78	181.29	105599849	9170162	12966991	10449109
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	155.07	191.50	180.08	91008367	7854553	11418233	9285159
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.61	1.29	1.21	14591482	1315609	1548758	1163950
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317867.74	31708.24	56422.79	57362.63	33504226	2990835	4076395	3803991
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.31	1.09	0.65	0.55	623	65	36	29
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	1224.28	1082.20	1106.32	111001	8500	14987	18048
2.3 आईएमपीएस	32783.47	3465.52	4429.86	4401.73	2941500	288538	396411	387007
2.4 एनएसीएच जमा \$	16465.44	1115.13	1483.71	2053.44	1216535	96681	113132	124228
2.5 एनईएफटी	30927.89	2874.93	3763.38	3629.03	25130910	2165869	2724980	2442686
2.6 यूपीआई @	223306.64	23027.28	45662.99	46171.56	4103658	431182	826848	831993
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.92	1.12	0.81	172	15	16	11
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10456.54	928.08	1064.54	1059.01	865520	79372	91163	91554
3.1 भीम आधार पे @	160.84	10.29	19.59	24.47	2580	214	611	728
3.2 एनएसीएच नामे \$	9645.75	839.08	937.92	934.07	862027	79044	90426	90703
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	78.71	107.03	100.47	913	113	126	123
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57786.60	5443.74	5611.80	5151.05	1291799	127894	160398	147794
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1744.20	2112.59	1958.05	630414	64737	93907	87769
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	926.09	1093.48	960.63	280769	29409	36713	32735
4.1.2 अन्य \$	8952.25	818.11	1019.10	997.43	349645	35328	57195	55034
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40145.54	3699.54	3589.21	3193.00	661385	63157	67591	60025
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20773.50	2132.37	2292.51	1924.51	377630	39189	44162	37274
4.2.2 अन्य \$	19372.04	1567.18	1296.71	1268.48	283755	23969	23429	22752
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49742.55	4427.00	7008.24	5865.60	197696	19419	26896	26105
5.1 वॉलेट	39987.01	3499.66	5661.02	4613.76	152065	13577	21220	19789
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9755.54	927.34	1347.22	1251.85	45631	5842	5676	6316
5.2.1 पीओएस आधारित \$	607.15	61.52	99.63	114.11	10591	1433	1893	2307
5.2.2 अन्य \$	9148.39	865.83	1247.59	1137.73	35040	4410	3784	4009
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	657.01	660.33	596.99	5627190	551207	640955	557721
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.54	657.01	660.33	596.99	5625941	551207	640955	557721
6.2 अन्य	1.17	—	—	—	1249	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442557.14	43164.07	70767.70	70035.28	41486430	3768727	4995808	4627165
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	444149.06	43320.75	70960.48	70216.58	147086278	12938889	17962798	15076275
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437445.36	42663.74	70300.15	69619.59	141459089	12387683	17321843	14518553

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2021		2022	वि. व. 2020-21	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	258033.70	27644.30	49877.80	50122.59	9201212	1020313	1433961	1422869
1.1 इंटर-बैंक \$	25220.71	2571.61	3927.19	3879.91	1871390	212336	254443	250455
1.2 इंटर-बैंक \$	232812.99	25072.69	45950.61	46242.68	7329822	807977	1179518	1172414
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32493.63	3084.98	3117.10	3091.31	41581497	4158234	4531114	4008361
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	617.29	611.14	598.61	20601554	2184556	2082236	1723484
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	2467.69	2505.96	2492.69	20979943	1973678	2448878	2284877
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.81	5734.25	5928.20	5562.33	2889826	267500	280372	262539
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	5.04	5.90	5.49	2560	251	295	269
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	5704.78	5893.54	5527.49	2878025	266315	279100	261279
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	24.43	28.76	29.36	9240	934	977	990
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.77	32.47	3.89	2.36	1533	137	42	35
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.50	30.62	3.71	2.08	1484	135	35	20
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	1.84	0.18	0.28	49	2	7	16
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	777.16	940.20	1125.54	225420	21700	25208	28582
5.1 एईपीएस @	9460.43	777.16	940.20	1125.54	225420	21700	25208	28582

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021 तक	2021		2022
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	9491.63	10066.90	10111.81
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	610.98	689.49	702.52
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8880.65	9377.42	9409.29
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21952.60	21212.16	26426.15	26898.31
2.1 वॉलेट @	20052.10	19461.26	23828.54	24231.94
2.2 कार्ड @	1900.51	1750.90	2597.62	2666.37
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.49	2.51
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.09	2.19	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.25	0.30	0.30
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	3.73	5.91	6.46
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	46.55	54.98	56.20
6 भारत क्यूआर @	35.70	33.60	46.47	46.97
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	805.89	1440.10	1521.05

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2020		2021	
			फर.	दिसं	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	159573	16911	16781	14261	14405
	बकाया	1078535	1046766	1196084	1210379	1224772
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	116389	11460	12407	9820	10143
	बकाया	734807	716363	827156	836976	847119
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	2690	3307	2049	2252
	बकाया	166140	156258	190437	192486	194738
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	-20	-21	-26	-23
	बकाया	3143	2939	3086	3060	3037
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	-3	-3	0	57
	बकाया	9	-23	-17	-17	40
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1887	1053	1162	1135
	बकाया	209168	207059	217980	219142	220277
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	2131	2014	1886	1950
	बकाया	76042	73728	90914	92800	94750
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	4494	4330	3952	3798
	बकाया	166087	161115	195847	199799	203597
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	90327	104601	105928	107099
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6970	7324	7375	7418
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7464	7330	7285	7267
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	56354	76592	79211	81813
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	281	1727	797	974
	बकाया	114222	115291	128912	129709	130683
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	0
	बकाया	-25	-25	-24	-24	-24
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	30170	3937	3941	3909	3647
	बकाया	252190	248022	274905	278848	282483
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	2619	1923	1903	1843
	बकाया	117987	115127	129270	131173	133016
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	1	-1	-1	0
	बकाया	162	-288	158	157	157
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1120	-669	-603	-470
	बकाया	1135	3949	-5121	-5724	-6194
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	2452	2677	2610	2274
	बकाया	122602	118507	140538	143148	145422
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	8	0	0
	बकाया	-155	-180	-147	-147	-147
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	-15	3	0	0
	बकाया	-106	-99	-103	-103	-103
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	11006	10310	10344	10332
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	13014	1514	433	532	615
	बकाया	91538	82381	94023	94555	95170

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	7357111	7635902	7882533	8235318	8439811
1. वाणिज्यिक बैंक	37.81	37.77	35.99	37.82	35.40
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.25	0.27	0.34	0.35	0.27
3. बीमाकृत कंपनियां	25.64	25.30	25.83	24.18	25.74
4. म्यूच्युअल फंड	2.62	2.94	2.82	2.91	3.08
5. सहकारी बैंक	1.83	1.82	1.82	1.50	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	1.00	1.00	1.43	1.17	1.69
7. कॉरपोरेट	1.05	1.06	1.39	0.72	1.37
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.10	1.87	1.79	1.81	1.66
9. भविष्य निधियां	4.61	4.44	4.04	3.77	4.33
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.71	16.20	17.11	16.98	16.92
11. अन्य	7.37	7.33	7.43	8.79	7.73
11.1 राज्य सरकार	1.76	1.69	1.67	1.67	1.69

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3721573	3879982	4028849	4153508	4257578
1. वाणिज्यिक बैंक	34.19	33.69	33.75	35.94	34.41
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.36	0.48	0.39	0.44	0.40
3. बीमाकृत कंपनियां	30.25	30.04	29.67	27.50	28.85
4. म्यूच्युअल फंड	1.92	1.82	1.74	1.97	1.91
5. सहकारी बैंक	4.11	4.05	4.12	3.60	4.07
6. वित्तीय संस्थाएं	1.88	1.86	1.79	1.72	1.73
7. कॉरपोरेट	0.45	0.49	1.45	1.32	1.70
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
9. भविष्य निधियां	21.20	22.00	21.09	18.27	20.66
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.81	0.77	0.88	0.85	0.83
11. अन्य	4.82	4.77	5.10	8.38	5.40
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19

खजाना बिल					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	839729	690646	901327	763582	692869
1. वाणिज्यिक बैंक	54.75	55.54	52.25	50.22	47.01
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.65	2.82	1.82	1.33	1.53
3. बीमाकृत कंपनियां	4.50	5.61	4.75	4.12	6.29
4. म्यूच्युअल फंड	18.98	17.80	19.93	17.72	13.72
5. सहकारी बैंक	1.61	2.43	1.60	1.32	1.49
6. वित्तीय संस्थाएं	1.11	1.24	2.56	2.12	2.36
7. कॉरपोरेट	2.01	3.16	3.00	2.40	3.13
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.15	0.72
9. भविष्य निधियां	0.09	0.22	0.10	0.37	0.85
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.68	0.49	2.58	2.63	0.00
11. अन्य	14.63	10.70	11.42	17.62	22.89
11.1 राज्य सरकार	13.27	5.98	7.97	12.64	18.92

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	4265969	4515946	5040747	5410887	6523916	7160694
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	4288432	4528422	5023352	5734166	6489736	7039032
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	1064704	997097	1102729	1449230	2634928	2277532
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.7	26.4	26.7	26.6	33.0	32.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.9	26.5	26.6	28.2	32.9	31.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.3	19.8	20.1	18.9	19.4	21.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	17.0	17.4	17.4	15.9	16.1	17.2
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	5.8	5.8	7.1	13.3	10.2

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज़

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	368	24	2055	23	1517	19
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	37	3	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1161	26	1009	18
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	79	2	627	2	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	98	1	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	298	30	198	26
17	मेघालय	97	19	273	19	151	16
18	मिज़ोरम	-	-	131	19	32	2
19	नगालैंड	55	20	210	15	22	6
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	28	1	-	-	-	-
23	राजस्थान	3657	19	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	399	23	1614	19	1701	11
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9162	905	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1985	3	--	-
3	असम	2691	60	--	-
4	बिहार	6198	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5476	--	1	4300
6	गोवा	677	343	--	-
7	गुजरात	6954	529	--	2000
8	हरियाणा	860	1340	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2500
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	496	--	--	-
12	कर्नाटक	7409	--	--	26500
13	केरल	2368	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	1014	--	-
15	महाराष्ट्र	49137	911	--	25000
16	मणिपुर	170	111	--	-
17	मेघालय	803	46	9	-
18	मिज़ोरम	388	52	--	-
19	नगालैंड	1826	37	--	-
20	उड़ीसा	12406	1619	94	31773
21	पुदुचेरी	339	--	--	1276
22	पंजाब	2021	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	6300
24	तमिलनाडु	7350	--	40	16165
25	तेलंगाना	6265	1368	--	-
26	त्रिपुरा	575	10	--	1100
27	उत्तराखंड	1023	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3806	150	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9939	692	214	-
	कुल	140324	9190	674	116914

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021 -22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						नवंबर		दिसंबर		जनवरी			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	2000	840	3250	3250	2500	1920	38500	29909
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	-	-	163	163	563	563
3	असम	12906	10996	15030	14230	1000	500	2800	1800	653	153	9953	7953
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	4000	4000	3000	2281	2000	719	25000	22000
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	-	-1000	-	-	-	-	4000	2500
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	100	-100	400	300	100	100	1800	1300
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	-	-1000	-	-1500	4500	4500	22054	10554
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	-	-500	-	-	1500	750	18000	12950
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	2000	1795	1000	800	-	-250	4000	3245
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	400	225	1800	1100	-	-	6400	4825
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	-	-	-	-	-	-	1500	500
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	4000	2500	12000	9500	20000	17500	42000	35500
13	केरल	18073	12617	28566	23066	-	-	1000	-1000	-	-1380	20000	13620
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	4000	4000	-	-	4000	1500	18000	12500
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	3000	3000	3000	1000	5500	-500	60250	42250
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	200	200	90	90	59	59	1236	1086
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	-	-50	328	328	200	100	1528	1218
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	-	-	-	-	150	150	584	334
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	-	-	298	148	-	-	1287	1037
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-500	-	-473	-	-	-	-3973
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	125	125	250	250	390	390	889	889
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	-	-500	1500	1150	4532	3932	18314	7614
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	1500	617	3669	2669	4500	3883	40269	32187
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	-	-	177	137	201	201	1129	1089
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	4000	2260	5000	5000	2900	-300	54900	44700
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	3000	2160	5500	5500	6187	5767	39687	33478
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-	-	-	-	-50	300	100
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	5000	2513	5000	2922	12500	11500	57500	41213
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-	500	350	500	400	2200	1100
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	3500	2500	9500	6950	6500	4700	54000	33477
	कुल	634521	487454	798816	651777	37825	23585	60062	42552	79535	55907	545843	395718

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए) हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2018-19				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	274259.3	321740.3	253754.5	642691.2	1492445.3
जीडीपी का प्रतिशत	6.0	6.9	5.2	13.4	7.9
I. वित्तीय आस्तियां	358515.3	576730.6	391939.2	936505.3	2263690.4
जीडीपी का प्रतिशत	7.9	12.4	8.1	19.5	12.0
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-53701.5	302123.2	22607.1	539383.9	810412.8
(ए) बैंक जमाराशि	-63806.9	292541.5	13060.8	535297.3	777092.6
i. वाणिज्यिक बैंक	-62127.0	289468.1	10634.6	490680.6	728656.4
ii. सहकारी बैंक	-1679.9	3073.4	2426.2	44616.6	48436.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	10105.5	9581.7	9546.4	4086.6	33320.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	91771.1	98477.3	89395.1	112489.6	392133.2
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ सहित)	98655.9	98158.9	99709.9	103561.9	400086.7
4. मुद्रा	111196.6	-32134.4	102656.5	96153.4	277872.1
5. निवेश	58281.3	57793.7	25258.8	32604.6	173938.4
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	49798.2	49798.2	23816.6	28146.8	151559.9
(बी) इक्विटी	2001.2	3054.4	471.0	855.8	6382.4
6. छोटी बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	51259.6	51259.6	51259.6	51259.6	205038.3
II. वित्तीय देयताएँ	84255.9	254990.3	138184.7	293814.1	771245.0
जीडीपी का प्रतिशत	1.8	5.5	2.8	6.1	4.1
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	84085.7	254820.0	138014.4	293643.8	770563.9
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	42852.5	171884.2	141026.9	248612.6	604376.2
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	39005.8	170252.0	141845.9	227069.5	578173.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	41233.1	82935.8	-3012.4	45031.2	166187.7
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	15057.0	52605.2	-3755.8	28952.6	92859.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23560.2	28328.8	-786.8	14118.7	65220.9
iii. बीमा कंपनियाँ	2615.9	2001.9	1530.1	1959.9	8107.8
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. केंद्र सरकार	136.5	136.5	136.5	136.5	546.0

सं. 50 (ए) हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी..)

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	252658.0	513118.4	400437.3	446254.3	1612468.0
जीडीपी का प्रतिशत	5.1	10.6	7.8	8.7	8.0
I. वित्तीय आस्तियां	413192.2	604322.7	538186.1	843385.9	2399086.9
जीडीपी का प्रतिशत	8.4	12.4	10.5	16.4	12.0
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	13020.4	299089.8	138131.8	473183.4	923425.5
(ए) बैंक जमाराशि	-9769.4	280588.7	130328.0	465529.7	866677.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	3524.4	11113.2	63661.3	19523.0	97822.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117394.9	107731.0	109895.6	37236.1	372257.5
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ सहित)	110601.0	113593.0	113676.0	117235.0	455104.9
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटी	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. छोटी बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	65930.8	65930.8	65930.8	65930.8	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	160534.2	91204.3	137748.8	397131.6	786618.9
जीडीपी का प्रतिशत	3.2	1.9	2.7	7.7	3.9
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कॉर्पोरेशन (ए+बी)	160500.7	91170.8	137715.2	397098.1	786484.7
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	141332.5	58250.2	121754.0	200413.2	521749.9
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कॉर्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. केंद्र सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

50 (ए) हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	623053.8	592327.3	506558.3	581769.1	2303708.6
जीडीपी का प्रतिशत	16.1	12.5	9.3	10.1	11.6
I. वित्तीय आस्तियां	828447.4	630907.1	676131.6	973510.9	3108997.0
जीडीपी का प्रतिशत	21.4	13.4	12.4	16.9	15.7
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297376.2	278589.7	158113.5	533651.5	1267730.9
(ए) बैंक जमाराशि	281155.1	264523.3	147037.2	535157.5	1227873.0
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2144.6	2489.6	3478.6	63426.6	71539.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	122369.1	141443.4	155516.3	100812.3	520141.0
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ सहित)	121582.5	124106.5	124949.5	130185.5	500824.0
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. छोटी बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	77381.6	77381.6	77381.6	77381.6	309526.3
II. वित्तीय देयताएँ	205393.5	38579.8	169573.3	391741.8	805288.5
जीडीपी का प्रतिशत	5.3	0.8	3.1	6.8	4.1
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कॉर्पोरेशन (ए+बी)	205436.7	38623.0	169616.5	391785.8	805462.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211005.3	13211.7	139387.5	304100.8	667705.3
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	87685.1	137756.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1022.9	2556.6
2. गैर-वित्तीय कॉर्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. केंद्र सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

टिप्पणी: 1. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

2. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2018	सित-2018	दिस-2018	मार्च-2019
वित्तीय आस्तियाँ (ए+बी+सी+डी)	14490526.2	14891219.6	15112941.4	15957967.7
जीडीपी का प्रतिशत	82.1	82.1	80.9	84.5
(ए) बैंक जमाशियाँ (i+ii)	8000655.6	8293197.1	8306257.8	8841555.1
i. वाणिज्यिक बैंक	7354053.7	7643521.8	7654156.4	8144837.0
ii. सहकारी बैंक	646601.9	649675.3	652101.4	696718.1
(बी) जीवन बीमा निधि	3483557.7	3585786.7	3646756.6	3785298.5
(सी) मुद्रा	1782923.3	1750788.9	1853445.4	1949598.8
(डी) म्यूचुअल फंड	1223389.6	1261446.9	1306481.6	1381515.3
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	5643303.3	5898123.3	6036137.8	6329781.5
जीडीपी का प्रतिशत	32.0	32.5	32.3	33.5
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	4565448.5	4737332.7	4878359.6	5126972.2
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	3993574.8	4163826.9	4305672.8	4532742.3
ii. सहकारी बैंक	474552.2	475903.1	475218.4	487445.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1077854.8	1160790.6	1157778.2	1202809.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	374640.0	427245.2	423489.4	452442.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	614618.4	642947.2	642160.4	656279.2

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी..)

(राशि करोड़ में)

Item	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020
वित्तीय आस्तियाँ (ए+बी+सी+डी)	16130869.8	16439609.3	16829228.1	17002698.8
जीडीपी का प्रतिशत	83.7	84.4	85.3	84.7
(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)	8831785.7	9111489.5	9239027.3	9688573.4
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	700242.5	710470.8	771341.9	774881.4
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	6490282.2	6581453.0	6719168.2	7116266.3
जीडीपी का प्रतिशत	33.7	33.8	34.0	35.4
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5268304.7	5326554.9	5448308.9	5648722.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	513013.7	513764.2	542994.4	529720.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि करोड़ में)

Item	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021
वित्तीय आस्तियाँ (ए+बी+सी+डी)	17850174.9	18408441.6	19129606.6	19979862.7
जीडीपी का प्रतिशत	93.9	97.6	99.7	100.9
(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)	9969728.5	10234251.8	10381289.0	10916446.4
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	777026.0	779515.6	782994.2	846420.7
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	7321703.0	7360326.0	7529942.6	7921728.4
जीडीपी का प्रतिशत	38.5	39.0	39.3	40.0
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5859727.5	5872939.2	6012326.7	6316427.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	558551.1	558545.6	557545.8	608703.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605301.0
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है (बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफसी और एचएफसी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत

कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

--: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (काउंटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।

